राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का ४०वां दिवस [संख्या २८

बुधवार, ६ अप्रेल, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[खादी ग्रामोद्योग, स्वास्थ्य एवं जन चिकित्सा, स्वायत्त शासन, श्रम, कृषि, पशु-पालन, पंचायत, सहकारी, वन, यातायात, एवं सिंचाई-विभाग]

प्रश्न संख्या ८३८.

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार।

(अनुपस्थित)

खादी ग्रामोद्योग मंडल द्वारा प्रदत्त ऋण एवं सहायता

८३९. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(क) राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल ने सन् १९५४ से ३१ अगस्त, १९५७ तक कितनी धनराशि, किन २ संस्थाओं को और कब कब ऋण के रूप में दी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल ने सहायता (सबसिडी) की राशि भी वितरित की है ? यदि हां, तो कितनी और किन २ संस्थाओं को और कब कब ? इसकी भी सूची सदन की मेज पर रखें।

खादी ग्रामोद्योग मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ५५-५६ से ३१-८-५७ तक दिये गये ऋण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री मूलचन्द डागा : सूची मिली नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : बाद में दे देना।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (२) ऋण के अतिरिक्त उस समय में दी गई सहायता की सूची भी उक्त तालिका में अंकित कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा ऋण देने के बाद क्या सरकार जांच करती है कि जो ऋण या सहायता दी गई है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हिसाब किताब ऑडिट होता है, इन्सपेक्टर्स जाते हैं, देखते हैं और रिपोर्ट देते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : हिसाब-किताब की रिपोर्ट आती है तो क्या सरकार उसको देखती है और स्कृटिनि करती है और निरीक्षक भेजती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नियम बने हुए हैं, उनके अनुसार सब कुछ करते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि खादी संस्थाओं में जिन्हें एड और सबसिडी देते हैं उनमें घोटाला होता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसी सूचना हमारे पास नहीं आई, समय समय पर सुनते हैं कान से, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं आई।

डॉ० चन्द्रकला : कान से सुनते हैं तो क्या सुन कर दूसरे कान से निकाल देते हैं या सरकार कोई कार्यवाही भी करती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सुनी-सुनाई बात पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री मूलचन्द डागा : कुल कितनी धन-राशि आज तक दी जा चुकी है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

प्रश्न संख्या ८५०.

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सूबेदारसिंह।

सदर हॉस्पिटल धौलपुर की एक्सरे मशीन

८५१. श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : क्या स्वास्थ्य एवं जन चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) सदर हॉस्पिटल धौलपुर में एक्सरे मशीन किस तारीख से खराब पड़ी है ?

(ख) उक्त एक्सरे मशीन कब खरीदी गई, कितनी बार खराब हुई, तथा इसकी कितने कितने दिनों बाद मरम्मत की गई ? सबसे ज्यादा दिन तक कब बन्द रही ?

(ग) १ जनवरी, १९५९ से ३१ जुलाई, १९५९ तक कितने मरीजों का उक्त मशीन ने एक्सरे किया ?

स्वास्थ्य एवं जन चिकित्सा मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) मशीन ठीक हालत में है।

Page No.3

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ख) उक्त मशीन नवम्बर १६४६ में लगाई गई थी तथा अब तक केवल दो बार अगस्त १६५६ व जनवरी १६६० में खराब हुई व क्रमशः दिसम्बर १६५६ व मार्च १६६० में मरम्मत की गई। यह पुरानी मशीन है, इसके पुराने पार्ट्स न मिलने के कारण खराब रही। अगस्त १६५६ से दिसम्बर १६५६ तक अधिक समय खराब रही।

(ग) १ जनवरी १६५६ से ३१-७-५६ तक कुल १६६ एक्सरे व ४६५ स्कीनिंग लिये गये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): अब इस मशीन की पोजीशन क्या है, ठीक है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मेरी सूचना यह है कि मशीन ठीक है।

श्री सूबेदारसिंह: अब मशीन खराब पड़ी है, मैं आपको बताऊं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: दुबारा खराब हो गई होगी। मैंने सूचना मांगी थी तब सूचना मिली कि ठीक है।

श्री सूबेदारसिंह: इस मशीन को ठीक करने में सुस्ती क्यों रहती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मैंने निवेदन किया कि यह पुरानी मशीन है, इसके पार्ट्स नहीं मिलते, इसके पार्ट्स मंगाने में दिक्कत होती है। इसकी एक ही स्पेशल कम्पनी है, उसको लिखना पड़ता है।

श्री सूबेदारसिंह: जब सरकार यह महसूस करती है कि यह पुरानी मशीन है, तो नई मशीनें खरीद कर दे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: कभी कभी पुरानी मशीन अच्छी होती है, काम पूरा करती है।

श्री सूबेदारसिंह: पार्ट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं ? नई मशीन खरीदना नहीं चाहते और पुरानी को बन्द रखना चाहते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: पार्ट्स मंगवा कर ठीक कराई गई है।

डॉ० बहादुरसिंह: मशीन खराब होने का कारण यह है कि टैक्निशियन जयपुर में रहता है और उसको समय कम मिलता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: राजस्थान के लिए टेक्निशियन की एक जगह है।

श्री अध्यक्ष: श्री मूलचन्द डागा।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना नहीं आई है। सूचना आने पर जवाब दे देंगे।

डॉ० चन्द्रकला: सिम्पल क्वेश्चन है, अध्यक्ष महोदय।

प्रश्न संख्या ८४३.

श्री अध्यक्ष: श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन।

Page No.4

लूणकरणसर (बीकानेर) में रेल द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था पर खर्चा

८४४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

कस्बा लूनकरणसर, जिला बीकानेर में रेल द्वारा पीने का पानी पहुंचाने हेतु राजस्थान निर्माण के बाद से अब तक प्रति–वर्ष कितना खर्चा किया जा चुका है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार बीकानेर से लूणकरणसर पानी पहुँचाने के वास्ते लाखों रुपये खर्च करती है तो क्या यह वाजिब नहीं समझती कि लूणकरणसर में वाटर वर्क्स बना दिया जाय ?

श्री सम्पतराम : I completely agree with the Hon'ble Member but the only difficulty is that water is not availably there.

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर के १० मील पर गांव है, वहां कुंए में बहुत पानी है और मीठा पानी है, तो क्या वहां से पानी देने की योजना सरकार बना सकती है ?

श्री सम्पतराम : We will see if it is possible.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : वहां पाइप्ड लाइन से वाटर सप्लाई का इन्तजाम क्यों नहीं करती है ?

श्री सम्पतराम : Water is not available there.

श्री पी. के. चौधरी : क्या रेल्वे पुल के पास मीठा पानी है, उसमें से पानी सप्लाई क्यों नहीं करती ?

श्री सम्पतराम : The Railway cannot supply so much water.

प्रश्न संख्या ८४५

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८४६

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' ।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

चाकसू नगरपालिका का पंचायत में परिवर्तन

८४७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री **यह** बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि चाकसू की जनता द्वारा नगरपालिका से पंचायत में

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

परिवर्तन करने के अनेक प्रार्थना-पत्र सरकार को प्रेषित हुए हैं ? अगर हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया ?

(ख) चाकसू की जन-संख्या क्या है ? क्या उक्त जन संख्या के आधार पर वहां नगरपालिका का रहना उचित है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पत राम) : सिर्फ नगर विकास मण्डल का एक प्रार्थना-पत्र आया था । अभी कोई नहीं किया गया है ।

(ख) सन् १६५१ की जन-गणना के अनुसार चाकसू की जन-संख्या ५,६६२ है । इस वक्त जन संख्या ६,५०० है ।

नये एक्ट के अनुसार ८००० से कम जन-संख्या वाला कस्बा नगरपालिका नहीं बन सकता, परन्तु पहले जो नगरपालिकायें बन चुकी थीं उनकी नये एक्ट की धारा के अनुसार राय ली जाने पर ही उनको नगरपालिका रहने दिया है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : नगर विकास मण्डल का प्रार्थना पत्र कब आया था ?

श्री सम्पतराम : तारीख मेरे पास नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : तारीख आपके पास नहीं है, निर्णय अभी लिया नहीं गया है, आखिर फिर किस बात पर सोच विचार कर रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : जब यह बात सामने आई तो नगरपालिका की ओपिनियन के लिए भेजा कि पापूलेशन कम बताई जाती है, तो आपकी क्या राय है । उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया कि पंचायत में तब्दील नहीं होना चाहते । वैसे भी वहां की जन संख्या ६ हज़ार से ज्यादा हो गई है ।

डॉ० चन्द्रकला : फिर सोच विचार की स्टेज क्या है ? जब जन-संख्या ६ हज़ार से ज्यादा हो गई है, तो ठीक हैं कि वहां पर पंचायत नहीं बनेगी, नगरपालिका ही रहेगी ।

श्री सम्पतराम : मेरा जवाब सुन लिया होता तो ये प्रश्न पैदा नहीं होते ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह ।

श्रम विभाग के सहायक जिला नियोजन अधिकारी

८४८. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : क्या श्रम मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) श्रम विभाग में सहायक जिला नियोजन अधिकारियों के कितने स्थान हैं और उन पर कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो जन-सेवा आयोग से एप्रूव्ड हैं ? जन सेवा आयोग से ये अनएप्रूव्ड व्यक्ति कितने समय से इन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि जन सेवा आयोग ने १४ जनवरी, सन् ६० को सहायक जिला नियोजन अधिकारियों के जिन ६ स्थानों के लिए सलेक्शन किया था

Page No.6

(श्री श्रीभानसिंह)

उसमें विभाग द्वारा इन पदों पर लगाये हुए छओं व्यक्ति रिजेक्ट हुए थे ? क्या यह भी सही है कि जन सेवा आयोग से रिजेक्ट हो जाने के बावजूद भी ये छओं व्यक्ति अब भी ज्यों के त्यों उन पदों पर आरूढ़ हैं ?

(ग) क्या जन सेवा आयोग ने १४ जनवरी, सन् १९६० को सहायक जिला नियोजन अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्त किये जाने के लिए ५ नामों का पैनल बनाया और उसकी सूचना सरकार के पास भेजी थी ? यदि हां, तो फिर अब तक पैनल के व्यक्तियों को रिक्त स्थानों पर नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि पैनल की अवधि, जो ६ मास की होती है, उसे सरकार किसी तरह विलम्ब करके समाप्त कर देना चाहती है, ताकि विभाग द्वारा इन स्थानों पर नियुक्त व्यक्तियों को, जो राजस्थान जन सेवा आयोग से १४ जनवरी, सन् १९६० को इन स्थानों के लिये रिजेक्ट हो गये थे, उन्हें यथावत इन पदों पर अनिश्चित काल तक बनाया रक्खा जा सके ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) विभाग में सहायक नियोजन अधिकारियों के कुल स्थान २५ हैं । इन स्थानों पर १९ अधिकारी इस वक्त कार्य कर रहे हैं तथा ६ स्थान अभी रिक्त हैं । कार्य करने वाले अधिकारियों में से १५ जन-सेवा आयोग द्वारा चुने हुए हैं, ६ का सलेक्शन और हुआ है । वे ४ अधिकारी जो जन-सेवा आयोग से चुने हुए नहीं है क्रमशः ता. १२. १०. ५७, २१.१.५९, १४.३.५९ और ६. ७. ५९ से कार्य कर रहे हैं ।

(ख) यह सही है कि जन सेवा आयोग ने १४. १. ६० को ६ सहायक नियोजन अधिकारियों का सलेक्शन किया था । ऐसे अधिकारियों की संख्या जो पहले से कार्य कर रहे थे और आयोग द्वारा नहीं चुने जा सके, ४ हैं । क्योंकि जन सेवा आयोग द्वारा चुने हुए कुछ व्यक्तियों ने नियुक्ति पत्र भेजे जाने के बावजूद कार्यभार नहीं सम्भाला है ऐसी हालत में वे चारों अधिकारी जिनका सलेक्शन नहीं हो सका अभी तक कार्य कर रहे हैं ।

(ग) यह सही है कि जन सेवा आयोग ने ५ अतिरिक्त नामों का पैनल बनाया था । सरकार ने आयोग से ये नाम मांगे हैं ।

(घ) जी नहीं ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : चार आदमी काम कर रहे थे, तो क्या उस वक्त ११ स्थान खाली थे, जब सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन से नाम मांगे थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उस वक्त एक्चुअली खाली थे....

डॉ० बहादुरसिंह : पैनल में नाम थे, उनको स्थान नहीं दिया गया । जो काम कर रहे थे उनको क्यों किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पी. एस. सी. से सलेक्शन होकर जनवरी में आया, उनको जोइन करने का ऑर्डर दे दिया है ।

डॉ० बहादुरसिंह : पैनल में नाम दिये गये हैं, उनको नियुक्त क्यों नहीं किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पैनल का सवाल कहां है, पैनल उन्होंने भेजा नहीं था। छः नाम भेजे थे । पैनल उनके पास है । उन छः हों के लिए अपॉइन्टमेंट ऑर्डर्स भेज दिये हैं, लेकिन उन्होंने जोइन नहीं किया है। उनके जोइन करने के बाद मालूम होगा कि कितनी जगह खाली हैं।

श्री श्रीभानसिंह : क्या पी. एस. सी. ने गवर्नमेंट को इन्टीमेट कर दिया था कि पैनल बना लिया है और जो गवर्नमेंट के पास एडीशनल वेकेन्सी हो, अगर गवर्नमेंट उन पर अपॉइन्टमेंट करना चाहे तो पैनल को कॉल कर ले और अपॉइन्ट कर दे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पैनल के लिए हमने लिखा है कि पैनल भेजो We have already asked the P. S. C. to send the penal.

डॉ० बहादुरसिंह : जो आदमी काम कर रहे थे उनका नाम भी पैनल में था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पैनल के नाम आये नहीं। पी. एस. सी. ने इन्टीमेंट किया है कि पैनल बनाया है । हमने उनको कहा है कि पैनल भेज दो ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जब पी. एस. सी. ने इन्फोर्म कर दिया है कि हमारे पास एप्रूव्ड पैनल है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने नोन सलेक्टेड केन्डीडेट्स को अपॉइन्टमेंट ऑर्डर्स क्यों भेजे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो ऑलरेडी टेम्पोरेरी अपॉइन्टेड थे, उनको पी० एस० सी० से पूछ कर अपॉइन्ट किया है। पैनल में नाम कहां से आयेगा ?

श्री पी० के० चौधरी : उनको कितने दिन के लिए अपॉइन्ट किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब तक पी० एस० सी० से सलेक्शन नहीं हो।

श्री श्रीभानसिंह : जो आपने बताया कि ६ व्यक्तियों का सलेक्शन हुआ है, इनमें ऐसे व्यक्ति हैं जो पी० एस० सी० के सामने नहीं गये और उनको अपॉइन्ट कर दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पी० एस० सी० के पास बाद में गया है, वे व्यक्ति पहले से अपॉइन्टेड थे ।

श्री श्रीभानसिंह : जब टेम्पोररी अपॉइन्टमेंट था। तो जब पी० एस० सी० को इन्टीमेट किया ६ वेकेन्सी के लिए, तो ये छहों व्यक्ति पी० एस० सी० के द्वारा इन्टरव्यू में रिजेक्ट कर दिये गये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह नहीं कहा जा सकता कि पैनल में नाम किस किस के हैं ? क्यों पैनल नहीं आया है।

श्री श्रीभानसिंह : मैं पैनल के लिए नहीं कह रहा हूं। जिन छः व्यक्तियों के नाम पी० एस० सी० ने सलेक्ट करके भेजे हैं, उनमें, जो टेम्परेरीली वर्क कर रहे थे उनके नाम इन्क्लूडेड नहीं थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : होते तो झगड़ा क्या था ? इनका सलेक्शन हो गया होता तो झगड़ा किस बात का था ? जिन छः व्यक्तियों के नाम भेजे उनको ऑर्डर भेज दिये हैं, लेकिन उन्होंने अभी जोइन नहीं किया है। पैनल आने के बाद पोज़ीशन फाइनल होगी।

श्री श्रीभानसिंह : जिन्होंने जोइन नहीं किया है, उनको ऑर्डर कब भेजे गये थे, गवर्नमेंट ने इन छःहों व्यक्तियों को इन्टीमेट कब किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास इत्तिला आने के बाद ही अपॉइन्टमेंट ऑर्डर्स भेज दिये थे। उसमें डिले नहीं हुई, There is no delay of a single day. उन्होंने जोइन नहीं किया है। इसके साथ ही जिन छः व्यक्तियों को सलेक्ट करने के लिए कहा था, उनमें एक शिड्यूल्ड ट्राइब्स का व्यक्ति होना चाहिए था। उन्होंने ऐसा व्यक्ति भेजा नहीं है। यह डिफेक्ट रह गया है, फिर भी हमने ऑर्डर इश्यू कर दिये हैं।

श्री श्रीभानसिंह : आपने दिक्कत बताई, तो क्या आप बता सकते हैं कि जिन्होंने एप्लाई किया पी० एस० सी० के सामने, उनमें शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति ने भी एप्लाई किया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्वालीफाइड आदमी हैं, उन्होंने एप्लाई किया था। उनको सलेक्ट नहीं किया। हम उनसे पूछ रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : क्या आप यह बता सकते हैं कि जो शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी काम कर रहा है, तो जो छः व्यक्ति आपने बतलाये उनके साथ ही वह भी पी० एस० सी० के सामने एपिअर हुआ था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, एपिअर हुआ था, पी० एस० सी० ने सलेक्ट नहीं किया। हमने छः व्यक्तियों के लिए ऑर्डर जारी कर दिये और पी० एस० सी से पूछा है कि शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी सलेक्ट करना चाहिए था, वह क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : श्री धन्नालाल हरित।

कोटा जिले में रबी की फसल में लगे 'फड़का' की शिकायत पर कार्यवाही

८४६. श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा सु०) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) कोटा ज़िले में कौन कौनसी तहसीलों में गत रबी की फसल में 'फड़का' लगने की शिकायत सरकार के पास आई ?

(२) सरकार द्वारा इस कीड़े से फसल को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि उपमंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) कोटा ज़िले की किसी भी तहसील से इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ८५०

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ८५१

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री धन्नालाल हरित।

पशु नस्ल सुधार योजना के अन्तर्गत बारां विकास खंड द्वारा प्रदत्त अनुदान एवं ऋण

८५२. श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा-सु०) : क्या पशु-पालन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) पशु नस्ल सुधार योजना के तहत बारां विकास खंड से अब तक कितने व्यक्तियों को कितना २ एवं कौन २ से सन् में अनुदान एवं कर्ज दिया गया ?

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों ने उक्त योजना को समय के अन्दर ही चालू कर दिया एवं कितनों ने अब तक चालू नहीं किया ?

(ग) जिन व्यक्तियों ने उक्त योजनाओं को चालू किया है उनके फार्म कहां २ पर हैं एवं उनमें से प्रत्येक फार्म में कितने पशु कौन २ सी नस्ल के हैं ?

(घ) जिन व्यक्तियों ने उक्त योजना को अभी तक चालू नहीं किया उनको कब अनुदान एवं कर्ज दिया गया था ? उनसे रकम वसूली की कार्यवाही कब से हुई एवं इस समय उनमें से प्रत्येक की कार्यवाही किस स्टेज पर है ? कृपया सूची सदन की मेज़ पर रखें।

पशु-पालन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) पशु नस्ल सुधार योजना के तहत बारां विकास खण्ड से अब तक सन् १९५८-५९ में चार व्यक्तियों को ३०००) रु० प्रति व्यक्ति एवं १९५९-६० में दो व्यक्तियों को २५००) रु० एवं २०००) रु० कर्ज दिया गया है एवं दो व्यक्तियों को ६२५) रु० व ४००) रु० अनुदान दिया है।

(ख) केवल ३ व्यक्तियों ने ही इस योजना को चालू किया है। शेष तीन ने अभी तक चालू नहीं किया है।

(ग) जिन व्यक्तियों ने उक्त योजना को चालू किया है उसका विवरण इस प्रकार है :

नाम	कार्य का स्थान	नस्ल	संख्या पशु
१	२	३	४
१. श्री नूरमोहम्मदजी	बिसरा	मालवी	६ गाय
२. श्री आनन्दीलालजी	संदुलक	,,	१ सांड १२ गाय
३. श्री मन्नालालजी	कोटड़ी	,,	६ गाय

(घ) जिन व्यक्तियों को कर्ज दिया गया और उन्होंने इस योजना को अभी तक चालू नहीं किया वे ये हैं :

Page No.10

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नाम	कब दिया	रकम
१	२	३
१. श्री सूरजमलजी	३०।१०।५८	३०००)
२. श्री गणपतलालजी	३१।१०।५८	३०००)
३. श्री रामनारायणजी	३०।६।५६	२०००)

इनमें क्रमांक १ व २ से रकम की वसूली के हेतु पी. डी. आर. के तहत कार्यवाही पांच माह से जारी है। एवं क्रमांक ३ को रिकवरी का नोटिस दिया जा चुका है। सबसीडी किसी को नहीं दी गई।

श्री धन्नालाल हरित : ५ महीने से कार्यवाही जारी है तो अब तक वसूली नहीं होने का क्या कारण है?

श्री नाथूराम मिर्धा : पी. डी. आर. के मातहत कार्यवाही चल रही है, प्रोसीज़र से कार्यवाही होती है।

श्री धन्नालाल हरित : क्या उनसे एक मुश्त रकम वसूली होगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : पी. डी. आर. के मातहत जिस प्रकार संभव होगा उसी तरह वसूली होगी।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : एक के खिलाफ कार्यवाही चल रही है उसका क्या रिजल्ट रहा?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने अर्ज किया कि रिकवरी का नोटिस दिया गया है।

प्रश्न संख्या ८५३

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल'।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८५४

श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

डॉ० चन्द्रकला।

जोरपुरा पंचायत में हुए गबन एवं भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही

८५५. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने भी कृपा करेंगे :—

(क) जोरपुरा (जोबनेर) की वर्तमान पंचायत कब बनी? इसके सरपंच इस समय कौन हैं तथा वे कब से इस पद पर कार्य कर रहे हैं?

(ख) क्या यह सच है कि जोरपुरा पंचायत में गबन एवं भ्रष्टाचार के कार्य हुए हैं? यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं?

(ग) क्या यह भी सच है कि पंचायत के कागजात कुछ महीने पहिले कुंए में डलवा दिये गये थे, जहां से वे बरामद किये गये?

Page No.11

(डॉ० चन्द्रकला)

यदि हां, तो कब, और ये कागज कुंए में क्यों डलवाये गये ?

(घ) क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करके क्या शीघ्र कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) सन् १६५७ में बनी, श्री देवीलाल सरपंच हैं और १६५७ के त्रिवर्षीय निर्वाचन के समय से ही काम कर रहे हैं।

(ख) ऐसी कोई शिकायत होना पाया नहीं गया।

(ग) सरपंच ने कागजात चोरी चले जाने की शिकायत तार द्वारा दिनांक २२।१०।५६ को की तथा उसी दिन कागजात कुंए में मिल जाने की सूचना दे दी। यह मामला पुलिस स्टेशन फुलेरा में भी सरपंच द्वारा सूचना दिये जाने पर चल रहा है जहां से अन्तिम परिणाम की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला : किस तारीख को कागज़ात मिले थे और किस तारीख को चोरी गये थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : २२।१०।५६ को तार द्वारा इत्तिला मिली कि कागजात चोरी चले गये और दूसरे रोज यह इत्तिला की गई कि कागजात कुंए में मिल गये।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार महसूस नहीं करती कि इतने से मामले में इतना अधिक समय लग गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : २२।१०।५६ की सूचना है। पुलिस में कार्यवाही कायदे से ही होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्धनसिंह।

भरतपुर गांधी पार्क में रेडियो की पुनः व्यवस्था

८५६. श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि भरतपुर में नगरपालिका द्वारा गांधी पार्क में एक रेडियो, मय माइक्रोफोन, जनता के मनोरंजन के वास्ते लगाया गया था ? यदि हां, तो उसे एक लम्बे समय से क्यों हटा लिया गया है ?

(ख) सरकार अब कब तक उक्त रेडियो को, मय माइक्रोफोन के, वहां लगवाने की व्यवस्था करेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): (क) जी हां। बिल्कुल खराब हो जाने के कारण हटाया गया है।

(ख) जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

प्रत्येक जिले में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियों का कार्यालय एवं सहकारी बैंक खोलने की योजना

८५७. श्री शीशराम ओला (खेतड़ी): क्या सहकारी मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(श्री शीशराम ओला)

(क) क्या सरकार की हर ज़िले में एक सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियों का कार्यालय तथा सहकारी बैंक खोलने की कोई योजना है ?

(ख) यदि हां, तो झुंझुनूं ज़िले में सहायक रजिस्ट्रार का कार्यालय तथा सहकारी बैंक न खोले जाने का क्या कारण है ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद तथा राज्य सहकारी मंत्रियों के सम्मेलन में, जो जुलाई सन् १९५९ में मैसूर में हुआ था उसमें यह निर्णय लिया गया था कि ज़िले में कम से कम ५०० सहकारी समितियां हों वहां सहायक रजिस्ट्रार का कार्यालय रखा जावे परन्तु झुंझुनूं जिले में अभी तक २९२ सहकारी समितियां हैं इस कारण उक्त निर्णय के अनुसार इस जिले में पृथक सहायक रजिस्ट्रार का कार्यालय नहीं खोला गया है।

इस जिले में इस वर्ष सहकारी बैंक खोले जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री शीशराम ओला : कब तक खोल दिया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस फाइनेन्शियल इयर में बैंक के लिये विचाराधीन है, पर क्योंकि २९२ सहकारी समितियां ही हैं इस लिये सहायक रजिस्ट्रार का कार्यालय खोला जाना मुश्किल है ।

श्री शीशराम ओला : कब खोलने का विचार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा(आसीन): इसी वर्ष में ।

श्री परसराम मदेरना : राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां इस योजना के अनुसार सहकारी बैंक नहीं खुले है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां तक मुझे याद पड़ता है ४ जिले हैं ।

प्रश्न संख्या ८५८

श्री अध्यक्ष : श्री एन० एल० जोशी

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८५९

श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८६०

रावराजा श्री सरदारसिंह

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८६१

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री शीशराम

भूतपूर्व झुन्झुनूं जिला बोर्ड के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान

८६२. **श्री शीशराम ओला** (खेतड़ी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व झुंझुनूं जिला बोर्ड के कुछ कर्मचारियों को अब तक वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): जी हां। वेतन न मिलने का कारण यह है कि विघटित जिला बोर्ड से नकद परिसम्पत्तियां कम प्राप्त हुई तथा उसके विरुद्ध दायित्व अधिक थे।

श्री शीशराम ओला : वेतन नहीं मिलने का कारण मेरी समझ में नहीं आया, साफ बताने की कृपा करें।

श्री परसराम मदेरना (आसीन): The Hon'ble Member has not understood your reply.

श्री सम्पतराम : जिस समय जिला बोर्ड खत्म किया गया और एडमिनिस्ट्रेटर ने चार्ज लिया उस समय जिला बोर्ड के पास रुपया कम था और लाएबिलिटीज ज्यादा थीं, इसलिये वेतन नहीं दिया जा सका।

श्री शीशराम ओला : क्या यह सही है कि जिस समय जिला बोर्ड समाप्त हुआ अनाप-शनाप रुपया बांटा गया और बहुत से कर्मचारियों को आठ आठ महीने की तनख्वाह बाकी रहने पर भी तनख्वाहें नहीं दी गई और दूसरे ढंग से रुपया खर्च किया गया ?

श्री सम्पतराम : अनाप-शनाप रुपया दिये जाने की सूचना तो मेरे पास नहीं है, पर कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया यह बात सही है।

श्री शीशराम ओला : जिस समय जिला बोर्ड भंग हुआ उससे दो महीने पहले की अवधि में जिला बोर्ड के पास कितना रुपया था ?

श्री सम्पतराम : इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री शीशराम ओला : फिर इन्कम्प्लीट जवाब से क्या मतलब ?

श्री अध्यक्ष : जवाब तो बकाया तनख्वाह के बारे में है।

श्री शीशराम ओला : नहीं नहीं, अध्यक्ष महोदय, लोगों को तनख्वाह आठ आठ महीने से नहीं मिल रही है, कर्मचारी बराबर चिल्लाते रहे, वह रुपया दूसरे आइटम्स में खर्च होता रहा और वे लोग तनख्वाह के लिये रोते रहे। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिला बोर्ड जिस दिन खत्म हुआ है उससे दो महीने पहले जिला बोर्ड के पास कितना रुपया था ?

श्री सम्पतराम : फाइनेन्शियल पोजिशन के बारे में अलग प्रश्न पूछिये। कर्मचारियों की ५८-५६ की तनख्वाह बाकी है।

Page No.14

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या सरकार इस पोजिशन में है कि एक डेफिनिट डेट निश्चित कर दे कि फलां तारीख तक उन लोगों को तनख्वाह दे दी जायगी ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : कितने कर्मचारियों की कितनी तनख्वाह बाकी है ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आने दीजिये।

श्री परसराम मदेरना : ऐसे कितने कर्मचारी थे जिनको....

श्री अध्यक्ष : इसका भी उत्तर आने दीजिये।

(हंसी)

one by one please.

डॉ० बहादुरसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार कोई तारीख निश्चित करने की पोजिशन में है कि फलां तारीख तक सबका पेमेंट कर दिया जायगा ?

श्री सम्पतराम : तारीख देने की पोज़िशन में तो नहीं पर उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेअरमैन थे उनके पर्सनल अकाउन्ट में ६ हजार से ज्यादा रुपया था, ए० जी० की ऑथिरिटी आने पर कुछ का पेमेंट हो जायगा, इसके बाद कोई वाया मीडिया निकाल कर तनख्वाह चुकाने का प्रबन्ध किया जायगा। जिस दिन जिला बोर्ड को भंग किया उस समय उसके पास १३,३२३ रुपया था और ७३,३०२ रुपयों की लॉएबिलिटीज थीं।

श्री शीशराम ओला : ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिली है ?

श्री सम्पतराम : नवम्बर ५८ में १, फरवरी ५६ में १, अप्रेल ५६ में २, मई ५६ में ५, जून ५६ में ६, जुलाई ५६ में १३, अगस्त ५६ में १०६ और सेप्टेम्बर १६५६ में १५२।

श्री अध्यक्ष : काफी प्रगति हो रही है।

(हंसी)

डॉ० बहादुरसिंह : कोई महीना तो निश्चित करेंगे कि कब तक पे कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : Is the Government committed to pay this ?

श्री सम्पतराम: पेमेंट तो करना पड़ेगा। १० हजार रुपया तो उनके पर्सनल अकाउन्ट में जमा है, पर्सनल नाम से जमा थे जो ए० जी० की ऑथोरिटी आने पर चुका दिये जायेंगे, बाकी और दूसरा वाया मीडिया निकाल कर चुकारा किया जायगा।

डॉ० चन्द्रकला : पर्सनल अकाउन्ट के क्या माने हैं ?

श्री अध्यक्ष : पी० डी० अकाउन्ट है उसमें जमा हैं।

श्री शीशराम ओला: डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास पैसा होते हुए भी उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली और वे लोग नाज के लिये मारे-मारे रोते-फिरते रहे।

श्री अध्यक्ष : तभी तो खत्म किया गया।

नेक्स्ट।

लकड़ी एवं कोयले के विभागीय नाकों की समाप्ति

८६३. **श्री धन्नालाल हरित** (छबड़ा सु०) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) लकड़ी एवं कोयले का तमाम काम जब ठेके पर दिया जाता है, तब पिछले समय के स्थापित इन विभागीय नाकों का क्या उपयोग है?

(ख) क्या सरकार इन नाकों को तोड़ देने का विचार रखती है?

वन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) विभागीय नाके वन क्षेत्र से निकास को जाने वाली सभी प्रकार की उपज पर निगरानी रखने के उद्देश्य से रखे गये हैं। चाहे ऐसी उपज ठेकेदार द्वारा निकास की जावे या परमिट वालों अथवा इकदारों और कन्सेशन उपभोक्ताओं द्वारा निकास की जावे।

(ख) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मूलचन्द डागा।

पाली शहर के नगरपालिका क्षेत्र में मोची जाति द्वारा खरीद की गई गैर-आबादी की जमीन का आबादी की भूमि में परिवर्त्तन

८६४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या पाली शहर की नगरपालिका के क्षेत्र में गैरआबादी की जमीन मोची जाति के कुछ सदस्यों की खरीद शुदा बापी जमीन है?

(२) क्या इस जमीन को मोची जाति के सदस्यों ने खरीद कर आबादी में परिवर्तन कराने के लिये कलेक्टर कार्यालय पाली में दरख्वास्त दी है? यदि हां, तो कब, और उस पर कलेक्टर पाली ने क्या आज्ञा दी?

(३) क्या इस जमीन की आबादी में परिवर्तन करने के लिये म्युनिसिपल बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन ने भी मौका देकर अपनी सिफारिश भी की थी?

(४) क्या सरकार को यह विदित है कि मोची जाति के सदस्यों के रहने के लिये यहां मकान भी नहीं हैं? यदि हां, तो यह जमीन मोची जाति को आबादी में परिवर्तन कर कब सुपुर्द करदी जावेगी?

स्वायत्त शासन मंत्री (सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) जी हां, दिनांक १४.७.५६ को। उस पर जिलाधीश पाली ने २०.१०.५६ को राजस्व सचिव को इस भूमि को आबादी में परिवर्तन करने की सिफारिश की है।

(३) जी हां।

(४) जी हां, स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्व विभाग को कार्यवाही हेतु भेजा है।

Page No.16

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री धन्नालाल हरित।

बारां नगर की बुनकर सहकारी समितियां

८६५. **श्री धन्नालाल हरित** (छबड़ा सु०) : क्या सहकारी मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(क) बारां नगर में बुनकरों की कितनी सहकारी समितियां कब रजिस्टर हुई थीं ?

(ख) उक्त समय से अब तक उन सहकारी समितियों ने क्या कार्य किया है एवं विभाग द्वारा उनको कार्य-संचालन हेतु क्या सहायता एवं सुविधा प्रदान की जा रही है ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, अभी इसकी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : केवल बारा नगर के बारे में ही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने पूछा हैं कि (क) बारां नगर में बुनकरों की कितनी सहकारी समितियां कब रजिस्टर हुई थीं ?

(ख) उक्त समय से अब तक उन सहकारी समितियों ने क्या कार्य किया है एवं विभाग द्वारा उनकी, कार्य संचालन हेतु, क्या सहायता एवं सुविधा प्रदान की जा रही है।"

इसकी पूरी जानकारी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कब तक आ जावेगी।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह आ जावेगी।

श्री धन्नालाल हरित : इस सैशन में आ जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : आशा तो यही करनी चाहिये।

श्री धर्मपाल

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

संचालक, पशुपालन विभाग द्वारा किए गये स्थानान्तरण

८४०. **श्री भैरोंसिंह** : [श्रीमाधोपुर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बजार जयपुर) द्वारा पूछागया] : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर एनिमल हस्बेन्डरी ने विभागीय आज्ञा न० F. V. II (XXV) EStt/3571, दिनांक ३ फरवरी, १९६० के द्वारा विभाग के कुछ अधिकारियों के स्थानान्तरण किये हैं ?

(२) यदि हां, तो इनमें कौन कौन अधिकारी किस किस पद पर पंचायत समितियों में कब कब से कार्य कर रहे थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

Page No.17

(श्री भैरोंसिंह)

(३) क्या इन स्थानान्तरण की आज्ञा प्रसारित करने से पहिले पंचायत समितियों से सलाह ले ली गई थी ? यदि हां, तो किन किन से ? और अगर नहीं तो क्यों ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(४) इन स्थानान्तरण किये जानेवाले अधिकारियों में कौन कौन अधिकारी ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण अप्रेल सन् ५८ के बाद से एक बार से अधिक हुआ है तथा कहां से कहां कहां और कब कब ! कृपया सूची कारण सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५) प्रश्न (४) के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों में कौन कौन ऐसे हैं जिनका पंचायत समितियां बनने के बाद स्थानान्तरण किया गया तथा कहां से कहां और कब कब ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां, यह सही है कि संचालक पशु-पालन विभागीय आज्ञा न० F. V ११ (१५) FS tt. |३५७१ दिनांक ३ फरवरी १६६० के द्वारा विभाग के कुछ अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं।

(२) अधिकारियों के नामों की सूची संलग्न है।

(३) इस स्थानान्तरण की आज्ञा प्रसारित करने से पहिले पंचायत समितियों से सलाह नहीं ली गयी थी। क्योंकि को स्थानान्तरण जनसेवा आयोग की सिफारिश पर एवं सीनियोरिटी और केटेगराइजेशन यह देख कर किया गया है।

(४) सूची संलग्न है।

(५) सूची संलग्न है।

(कृपाया परिशिष्ट ३ देखिये।)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन ने केवल उनका सलेक्शन ही किया था और यह कहना गलत है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन की सिफारिश पर ये स्थानान्तरण किये गये।

श्री नाथूराम मिर्धा : जब उनको प्रमोशन मिला तो उनको दूसरी जगह पर भेजना जरूरी था। जहां पर एक्सटेन्शन ऑफिसरों की पोस्ट थी वहां पर उनको भेजा गया, तो उनको भेजा गया जो इन्सपेक्टर थे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ट्रान्सफर्स तो पब्लिक सर्विस कमिशन की रिकमन्डेशन से नहीं की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पी. एस. सी. में यह नहीं था। मगर उनके सामने यह मसला था कि कुछ पोस्ट खाली थी। पब्लिक सर्विस कमिशन के इन्टरव्यूज़ हुए और [illegible] खाली थी तो इन्सपेक्टरों को प्रोमोशन दिया और वे एग्जिक्युटिव ऑफिसर बना दिये गये। सिनीयोरिटी बेसिस पर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो यह कहना गलत है कि उनकी ट्रान्सफर पब्लिक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सर्विस कमिशन की सिफारिश पर की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने यह कहा कि इन्सपेक्टरों को प्रोमोशन दिये गये और जगह खाली थी उनको भरना जरूरी था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह उचित नहीं था कि जिन जिन स्थानों से ट्रान्सफर किया गया वहां के अधिकारियों से राय जानते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको बताया कि यह इसलिये आवश्यक नहीं था कि जगह खाली थी और इन्सपेक्टरों को प्रोमोशन दिये और एग्जिक्यूटिव ऑफिसर बनाये। अगर उनसे शुरू में पूछते तो बहुत देर हो जाती इसलिये पोस्टिंग्ज कर दिये और बाद में शिकायत हुई तो हमने एडजस्ट कर लिया बाकी बहुत से नये नये गये इसलिये कोई दिक्कत नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री गुरूदत्ता अधिकारी, भेड़ अनुसन्धान फार्म, जयपुर द्वारा अनियमितताएं

८४३. **श्री भैरोंसिंह** [श्री माधोपुर– श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) द्वारा पूछा गया]: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(क) क्या यह सही है कि गुरूदत्ता रिसर्च अधिकारी, भेड़ रिसर्च फार्म, जयपुर द्वारा फार्म की कई भेड़ बेचने अथवा बदलने की जानकारी विभाग में आई है ? यदि हां, तो कब और कितनी भेड़ बदलने अथवा बेचने की जानकारी मिली थी ?

(ख) क्या यह सही है कि जिस समय श्री हल्दिया रिसर्च ऑफिसर का कार्य कर रहे थे उस समय श्री हांडा, संचालक उक्त फार्म पर गये तथा कमज़ोर तथा बदली हुई भेड़ों का नम्बर नोट करके लाये ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(ग) क्या यह सही है कि श्री हांडा ने तत्कालीन कलिंग कमेटी, जिसमें डॉ०नारायण तथा डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेन्ड्री ऑफिसर थे को बदल कर एक नई कमेटी बनाई ? यदि हां, तो क्यों और कब तथा इसका किन किन को सदस्य बनाया गया ?

(घ) क्या यह सही है कि उस कमेटी ने यह रिपोर्ट की कि कुछ भेड़ों को जिनका नम्बर वही था, जो डाईरेक्टर नोट करके लाये थे, बेच दिया ? यदि हां, तो कब और क्यों तथा कितनी भेड़ों को ?

(ङ) क्या यह सही है कि डाईरेक्टर को २५०) रु० से ज्यादा अमाउन्ट . राईट ऑफ करने का अधिकार न होते हुए भी इन भेड़ों को बेचने की आज्ञा प्रदान कर दी ?

(च) क्या यह सही है कि डाईरेक्टर ने यह उपरोक्त कार्यवाही एन्टीकरप्शन द्वारा को जा रही इस ही संबन्ध की इन्क्वायरी की वजह सबूत गायब करने की दृष्टि से की ?

Page No.19

(श्री भैरोंसिंह)

(छ) क्या यह सही है कि इन्हीं कारणों से एन्टीकरप्शन विभाग ने डाईरेक्टर का दफा २०१ आई. पी. सी. में चालान करने के लिये सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो कब और उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया ?

(ज) इस संबन्ध में विभाग की ओर से यदि कोई जांच हुई है, तो उसका क्या नतीजा रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(क) जी हां, दिनांक २४–५–५८ को इस विषय में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) जी हां, जब श्री हल्दिया शीप रिसर्च ऑफिसर, शीप रिसर्च फार्म, जयपुर पर थे उस समय डाइरेक्टर श्री बी. एन. हान्डा रिसर्च फार्म को इन्सपेक्शन करने गये थे किन्तु यह सत्य नहीं है कि वे कमजोर तथा बदली हुई भेड़ों का नम्बर नोट कर लाये ।

(ग) जी हां, एक नई कमेटी बनाई गई क्योंकि पूर्व कलिंग कमेटी के सदस्य डॉ० नारायण, टैक्निकल असिस्टेन्ट मिसेज नारायण आदि सदस्यों का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया गया। नई कमेटी के सदस्य निम्नलिखित थे :

(१) श्री पटेल, लाईवस्टाक डेवलपमेंट आफिसर, जयपुर ।

(२) डॉ० देवराज बजाज, डी. डी. अजमेर डि० पशुपालन विभाग ।

(३) श्री गुरुदत्ता, प्रिन्सिपल राजस्थान शीप एन्ड वूल ट्रेनिंग स्कूल ।

(घ) जी नहीं, यह सत्य नहीं है कि डाईरेक्टर भेड़ों का नम्बर नोट करके लाये थे । यह सत्य है कि कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि उस समय के फार्म की बेकार भेड़ों को कलिंग कर दिया जावे ।

(ङ) जी नहीं, डाईरेक्टर को २५०) रु० तक की प्रत्येक वस्तुओं का राइट ऑफ करने का अधिकार है ।

(च) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(छ) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ज) मालला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दफा २०१ आई पी. सी. की तहत चालान करने के लिये कब लिखा ? आपने अपने (ख) के उत्तर में हां फर्माया है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह डेट तो मेरे पास नहीं है । यह २० या २५ दिन पहले की बात है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : महीना हो गया होगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : महीना भर हो गया होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा कि कलिंग कमेटी के सदस्य नारायण आदि थे उनके स्थान पर दूसरी कमेटी बनाई तो क्या उनके खिलाफ कोई शिकायत थी या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो डाइरेक्टर ने देखा कि कलिंग कमेटी का काम कुछ संतोषजनक नहीं हो रहा था इसलिये दूसरी कमेटी बनाई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने बताया कि पुरानी कलिंग कमेटी के खिलाफ शिकायत थी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि उनका काम संतोषजनक नहीं था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत थी और इस कारण से उनको बंद कर दिया गया तो क्या आपके डाइरेक्टर ने इन्सपेक्शन नोट में कोई बात लिखी थी या इसके लिये रिकमन्डेशन की थी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने यह नहीं कहा कि कोई शिकायत थी। मैंने कहा कि डाइरेक्टर को उनका काम संतोषप्रद नहीं मालूम हुआ इसलिये दूसरी कमेटी बना दी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

सीकर जिले में सरकार द्वारा संचालित एलोपेथिक व आयुर्वेदिक अस्पताल

८४५. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या स्वास्थ्य एवं जन चिकित्सा मन्त्री निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर देंगे :—

(क) सीकर जिले में सरकार द्वारा संचालित एलोपेथिक व आयुर्वेदिक अस्पतालों की कितनी संख्या है ?

(ख) उक्त अस्पतालो में 'बी' श्रेणी के अस्पताल कितने हैं ? यदि नहीं है, तो क्या सरकार सीकर के सरकारी अस्पताल को 'बी' श्रेणी का अस्पताल बनाने का विचार रखती है ?

(ग) क्या आयुर्वेदिक विधि से संचालित प्रथम श्रेणी का अस्पताल सीकर नगर में स्थापित करने का सरकार विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य एवं जन चिकित्सा मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) १६ एलोपेथिक अस्पताल व ५० आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियां हैं ।

(ख) 'बी' श्रेणी का अस्पताल कोई नहीं है । सीकर स्थित श्री कल्याण अस्पताल को 'बी' श्रेणी के अस्पताल में उन्नत करने का सरकार का विचार है । आयुर्वेदिक में दांता व रानोली, दो औषधालय 'बी' श्रेणी के हैं ।

(ग) जी नहीं । परन्तु जनता की ओर से प्रथम श्रेणीय चिकित्सालय के अनुरूप उपयुक्त भवन आदि की निशुल्क व्यवस्था होने पर सरकार इस पर विचार कर सकती है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' ।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम सुलाखियां ।

(अनुपस्थित)

ब्यावर नगरपालिका के अध्यक्ष, श्री चिमनसिंह लोढा के विरूद्ध कार्यवाही

८५१. श्री भैरोंसिंह : [श्री माधोपुर–श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि ब्यावर नगरपालिका के अध्यक्ष श्री चिमनसिंह लोढा के विरुद्ध गबन, रकम के दुरूपयोग, पक्षपात तथा नगरपालिका की सम्पत्ति का दुरूपयोग आदि के गम्भीर मामलों की शिकायत कई बार जनता द्वारा सरकार के समक्ष पेश हुई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिलसिले में कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो क्या और किसके द्वारा ? और नहीं तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (क) जी हां ।

(ख) जी हां । प्रादेशिक निरीक्षक, जयपुर द्वारा जांच की गई । जांच की रिपोर्ट अभी मिली है ।

डॉ० चन्द्रकला : आपने कहा कि कई बार शिकायतें आई तो कितनी बार आई ?

श्री सम्पतराम : मुझे नम्बर का पता नहीं, कई दफा आई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जांच कराई और रिपोर्ट आपको मिली है, तो सरकार ने रिपोर्ट पर क्या कदम उठाया है ?

श्री सम्पतराम : रीजनल ऑफिसर ने जांच करके रिपोर्ट भेजी है । उसकी पूर्णतया परीक्षा की जायगी और उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह रिपोर्ट कब प्राप्त हुई ?

श्री सम्पतराम : १७ मार्च, १९६०. को ।

डॉ० चन्द्रकला : पहले पहल कब शिकायत आई ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, कई शिकायतें होती हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरवलाल 'कालाबादल' ।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री हीराभाई ।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ८५४ का उत्तर होना चाहिये।

जयपुर ठेला हॉकर्स मजदूर संघ द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र पर कार्यवाही

८५४. **श्री हीराभाई** [कुशलगढ़ डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर नगरपालिका द्वारा फेरीवाले ठेलों पर प्रतिवर्ष लाइसेन्स के रूप में कितने रुपये वसूल किये जाते हैं ?

(२) राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर, भरतपुर, उदयपुर तथा अजमेर आदि की नगरपालिकाओं द्वारा प्रति वर्ष फी ठेले पर कितने रुपये और किस किश्त के रूप में लाइसेन्स के वसूल किये जाते हैं ?

(३) क्या जयपुर नगरपालिका ने शहर के समस्त बाजारों में ठेले (फेरीवालों) के खड़े होने के स्टेण्ड कायम किये हैं ? यदि हां, तो कितने और उनका गजट नोटिफिकेशन किस तारीख में हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह सत्य है कि स्टेण्ड न होने के कारण ठेला-चालकों को चलते फिरते अकारण ही भारी चालानों का शिकार होना पड़ता है ? यदि हां, तो १ अप्रेल, सन् ५६ से २६ फरवरी, सन् ६० तक फेरीवाले ठेलों पर कितने चालान हुए और उन चालानों पर जुर्माने के रूप में नगरपालिका ने कितना रुपया वसूल किया ?

(५) क्या जयपुर ठेला हॉकर्स मजदूर संघ द्वारा सरकार के समक्ष कोई मांग पत्र रखा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या विचार किया गया ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (१) ७२ रू० प्रति ठेला प्रति वर्ष।

(२) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) नगरपालिका ने शहर के भिन्न-भिन्न भागों में ठेले वालों के खड़े होने के लिये २१ स्थान निश्चित किये हैं। जिनकी सूची सुपरिन्टेन्डेट पुलिस को ट्रैफिक का ध्यान रखते हुए जांच के लिये भेजी गई है। उनकी सम्मति आने पर गजट नोटिफिकेशन की कार्यवाही की जावेगी।

(४) जी नहीं। पुलिस ने ट्रैफिक में अड़चन पैदा करने वाले ठेलों का ही चालान किया है। उक्त अवधि में ८७२ चालान किये गये और २,०३१) रु० जुर्माना वसूल हुआ।

(५) जी हां। वह सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिया जायगा।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : अब तक ठेले वालों के खड़े होने की जगह नहीं है और साइट के लिए सलाह मांगी है तो फिर उनका चालान किस आधार पर किया ?

श्री सम्पतराम : उनका चालान म्युनिसिपैलिटी की ओर से नहीं किया गया। लेकिन यदि कोई ट्राफिक रूल्स को भंग करे जब कि रुल्स के अनुसार यदि कोई आदमी ट्राफिक को रोकता है और वार्निंग देने के

Page No.23

(श्री सम्पतराम)

बाद भी नहीं मानता है तो पुलिस को हक है कि उसका चालान करे।

डॉ० चन्द्रकला : जब सरकार की ओर से ही उनको सही खड़े होने की जगह नहीं बतायी गई है तो फिर वे किस प्रकार से यह निर्णय कर सकते हैं कि यह सही जगह है और सही जगह नहीं है ?

श्री सम्पतराम : जगह नहीं बताने की बात नहीं है। वे जानते हैं कि उनको कहां खड़ा होना है, लेकिन उसके बावजूद भी वे ट्राफिक को रोकते हैं और इस तरह से ट्राफिक के नियमों का उल्लघंन करके ऑफेन्स करते हैं तो उनका चालान किया जाता है। जैसे मोटर के लिए भी नियम हैं कि इस प्रकार से यदि ट्राफिक को रोका जाय तो चालान किया जा सकता है।

डॉ० चन्द्रकला : मोटरों के लिए तो पार्किंग और खड़े होने के स्थान हैं लेकिन ठेले वालों के लिए अभी विचार किया जा रहा है। ऐसी सूरत में जिसके मन में आवे उस ठेले का वह चालान कर दे, तो यह किस तरह से उनके साथ न्याय है ?

श्री सम्पतराम : हॉकर्स के लिए न्याय करेंगे, आप चिन्ता न करें। उनके लिए ज्यादा स्थान देने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि कहीं पर खड़े होकर ट्राफिक को रोक कर खड़े हो जायं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : पार्किंग प्लेस डेफिनेट तौर पर अलॉट कर रखी है या नहीं ?

श्री सम्पतराम ; बहुत सी जगह बना रखी है; डेफिनेट जगह तो अभी नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला ; रोड्स के लिए बना रखी है कि यहां खड़े होंवे ?

श्री सम्पतराम : यदि आप उनसे पूछेंगी कि कहां खड़ा होना है तो निश्चित रूप से वे बता देंगे कि उनको कहां खड़ा होना है।

श्री पी० के० चौधरी : जब तक आपने डिमार्केट नहीं किया है कोई स्थान तब तक कैसे ऑफेन्स हो सकता है ?

श्री सम्पतराम : मेरे खयाल से इस सवाल को ही गलत समझा गया है। म्युनिसिपैलिटी द्वारा ठेले वालों के लिए अभी तक कोई निश्चित स्थान तो मुकर्रर नहीं किया है लेकिन उनको जगह बता रखी गई है कि वे वहां पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके वे लोग सड़क के बीच में खड़े हो जाते हैं और ट्राफिक को रोक कर खड़े हो जाते हैं। इस सूरत में वहां पर एक्सीडेन्ट्स होने की काफी सम्भावना रहती है; इसलिये ट्राफिक के नियमों के अन्तर्गत पुलिस द्वारा उनका चालान किया गया है न कि म्युनिसिपैलिटी की ओर से। सड़कों के बीच में वे खड़े हो जाते हैं और वार्निंग देने के बावजूद भी नहीं मानते।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया कि ठेले वालों से ही पूछिये कि कहां खड़ा होना है। उनके खड़े होने का उनको मालूम हो; लेकिन आम जनता को तो मालूम नहीं है।

Page No.24

श्री सम्पतराम : जनता ठेला चला कर देख ले, मालूम हो जायगा ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री नरोत्तमलाल जोशी ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

प्रान्त के अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड्स में रेश्नलाइज्ड पे स्केल्स

८५६. श्री मुरलीधर व्यास [बीकानेर सिटी—श्री बेनाराम गहलोत (खारची) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में कहां २ रेश्नेलाइज्ड पे स्केल हो चुके हैं ?

(ख) जिन स्थानों में ऐसा नहीं हुआ, उसका क्या कारण है ?

(ग) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के यूनिफाइड पे स्केल कहां २ हुए हैं और किन स्थानों पर नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या अन्य प्रकार के अलॉउन्स जो उन्हें पहले मिलते थे उन्हें सम्मिलित करके फिक्सेशन किया गया हैं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) राजस्थान में अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में सब जगह (जयपुर, उदयपुर, जोधपुर व बीकानेर) में रेश्नेलाइज्ड पे स्केल हो चुके हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पे स्केल राज्य सरकार द्वारा सब स्थानों पर लागू कर दी गई है ।

(घ) इस विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फिक्सेशन रूल्स के तहत उनका फिक्सेशन किया गया है ।

श्री बेनाराम : कब से लागू की ?

श्री सम्पतराम : बाकायदा गजट में बहुत दिनों पहले नोटिफिकेशन हुआ है, निश्चित तारीख तो मुझे नहीं मालूम है । अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में इसका इफेक्ट हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

श्री लक्ष्मीचन्द : इसका उत्तर दिला दिया जाय ।

सरपंच ग्राम पंचायत नगर द्वारा सामान की खरीद

८६०. रावराजा श्री सरदारसिंह [उनियारा—श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत नगर, तहसील देवली ने चौदह हजार रुपयों के एक इंजिन, तेल की घाणी

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

तथा बिजली के लिए डायनुमा आदि खरीद किये हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कहां से आज्ञा ली गई है ?

(२) क्या यह सही है कि सब सामान नगर पंचायत में आ गया है ? यदि हां, तो कब आया और अब इस काम की क्या प्रगति है ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) इंजिन, एक तेल की घाणी व एक चक्की, एक मशीन कुट्टी की खरीद किए हैं, बिजली का डायनुमा नहीं खरीदा, स्वीकृति नहीं ली गई ।

(२) जी हां, २२-१-६० को आया है । इंजिन, चक्की कुट्टी मशीन तथा तेल की घाणी फिट कर दी गई है । अलबत्ता इंजन का परीक्षण किया गया जिसमें जनता का अनाज निःशुल्क पीसा गया है । मिस्त्री नहीं मिलने से काम चालू नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री !

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ८६१ का उत्तर दिला दिया जाय !

जयपुर नगरपालिका में नियुक्त चलते-फिरते मजिस्ट्रेट्स

२६१. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री [आमेर-सु०-डॉक्टर चन्द्रकला (किशन पोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

जयपुर नगरपालिका में इस समय कितने चलते-फिरते मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की गई है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पत राम) : जयपुर नगरपालिका में अभी तक एक भी चलता-फिरता मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं किया गया है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का इरादा है ?

श्री अध्यक्ष : ठेले वालों का ?

(हंसी)

श्री सम्पतराम : इतने बड़े शहर की जिन्दगी में इतनी बड़ी उच्छृंखलता की उपेक्षा नहीं कर सकते ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मोटर यातायत से राज्य सरकार को कर

(६७. ए. टी. एम) **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

मोटर यातायात से राज्य सरकार को किस किस रूट से कितना कितना यात्री कर सन् १९५६ से अब तक मिला है ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

(२) क्या यात्री कर बराबर माहवार सरकारी खजाने में जमा हो जाता है ?

(३) क्या कहीं का यात्री कर बकाया है ? यदि हां, तो कहां कहां का ?

उत्तर

(१) इस विभाग द्वारा रूट वाइज़ यात्री कर वसूल होने की सूचना संकलित नहीं की जाती है । माह जनवरी, ६० तक यात्री कर ४०,५२,५०२.३२ रुपये वसूल हुआ है।

(२) जी हां, किन्तु कुछ मोटर मालिकों द्वारा यात्री कर समय पर जमा नहीं कराया गया है । इस विषय में उचित कार्यवाही की जा रही है ।

(३) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

चम्बल परियोजना और सिंचाई विभाग में राज्य सरकार के विरुद्ध ठेकेदारों के मामले

२(११.ए.टी.एम.) **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा) : Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

1. How many cases were filed by the contractors in the Chambal Project and the Irrigation Department against the Government during the last three years and with what result?

2. What is the cost and expenditure borne by the Government ?

3. Whether negotiations for compromise were made on receipt of notice under for under section 80 C. P. C. ? If not, why ?

4. Is it a fact that Security Deposit is not refunded to contractors after six months completion as per rules ?

5. Whether the final bills are paid as per agreement within a month from completion. If not, then what action is being taken by the Government against the Engineering Staff ?

6. Is it a fact that in 1954, 55, 56, 57 the rates quoted by contractors for Pacca works Were 10 to 20% below the old schedule of rates than the present schedule of rates resulting in cheap works ? What is the cause ?

7. Is it a fact that the rates for extra items once approved by the Chief Engineer, Irrigation are changed after 6 to 12 months of completion by the Superintending Engineer, Canal Section and contractors

(श्री रामेश्वरदयाल)

payments and refund of Security Deposits are with-held resulting in heavy losses to the contractors who could not undertake further works in the Chambal Department ?

8. Is it true that in the case of constructing drainage syphons (Pipe syphon) at R. D. 107800 and 105630 during the year 57-58, the deviations were made thrice in the nature of works and rates etc. and some evena after completion of the works by the Superintending Engineer, Canal Section, Chambal Project resulting in the refusal of the contractors to perform the work ? Does it not amount to the breach of contract on the part of Government ?

9. Is it not a fact that the rates in the case of ring under Water load and Earth load have been considerable Changed against agreements by the Canal Department of the Chambal Project ? Is it true that the contractors have served notices under section 80 of the C. P. C. ? what action the Government proposes to take in this matter ?

10. Is the Government prepared to appoint Enquiry Commission to investigate and report causes for higher rates and frequent changes and also the tribunal to decide cases of the contractors to avoid the cost of litigation ?

11. Is it a fact that the tenders for Digod Colony in the Chambal Project were invited 5 or 6 times but no tenders were received, if any was received, it was 40 or 50% above ? So is the case with tenders for Road Works? What is the cause ?

12. Is the Government prepared to act and implement the suggestion of the National Building Organisation set up by the Central Government that the payments of the contractors Bills should not be delayed ?

उत्तर

(1) 5 cases were filed on Chambal Project during the last 3 years: Cases filed in other circles were as under:—

(i) Jaipur Circle	1
(ii) Maintenance Circle, Kota.	8
(iii) Ganganagar Circle	18

(2) Cost of expenditure borne by Government on this account has not been reported by Law Department.

(3) In such legal cases Irrigation Department is guided by the advice of the Law Department and cases are contested when that department so recommends.

Page No.28

(सरकारी उत्तर)

(4) Security deposit is refundable to contractors as per terms of individual contract. The period of six months has been fixed by the Government, very recently and this cannot apply to old contracts. In old contract this period generally varied from 12 to 18 months.

(5) Final bills are paid after they are scrutinised and passed by the Central Accounting Organisation. As many of the works are large and important, scrutiny and obtaining of sanctions to deviations of extra items from competent authority takes time and payment cannot always be arranged within a month of recording of final measurements. As Engineering staff is not at fault no action has been taken against them.

(6) If is a fact that rates tendered by contractor for Pacca and other works are much higher than those tendered few years back. This is due to general rise in the cost of Steel, Cement, other material and labour.

(7) It is not a fact that rates for extra items once approved by Chief Engineer are changed by Superintending Engineer. In some cases final payments and refund of security have been delayed for reasons mentioned in (5) above.

(8) It is true that in case of syphon at R. D. 107800 and 105630 a deviation in nature of work was made in respect of R. C. C pipe only on consideration of economy and availability of Steel. The rate originally proposed had to be changed after scrutiny by audit and is awaiting sanction of Chambal Control Board. The Contractors did not refuse to complete the works and the works have already been completed According to clause 13 of the agreement the Project authority can make changes in design during execution and no breach of contract is involved.

(9) The rate for ring under water load:- There was no material change in rate and only slight adjustment due to variation in quantity of steel were made. The design of ring under Earth load had to be changed to economise in Steel and cost. and payment for this extra item will be made according to schedule of rates as laid down in the agreement. It is true that notice under 80 C. P. C. has been received from some contractors. Action will be taken on the advice of Law Department after they have examined the factual report in each case.

(10) The reasons for delay in payment and changes in design and rise in rates have been explained in replies to question (5) and (6) above.it is not proposed to appoint any tribunal.

(11) It is a fact that tenders fo Digod Colony were called several times. In many cases no tenders were received while out of those called on

(सरकारी उत्तर)

24. 3. 60 the lowest was 24% 14/ high. The tenders for Road Work at Kota was slightly higher than the estimated rate. This is on account of great building activity in and near Kota. Building contractors and Workers are not inclined to go into theinteror. The number of tender received is therefore small and high rates are quoted.

(12) The reference quoted is not available. Every effort is made to settle claims expeditiously consistent With the necessity of thorough scrutiny of all claims and amounts recoverable on account of stock, extra itemsetc.

अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड, जयपुर की बकायात

३. (१०. एम.एल.एम) श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड, जयपुर की किस किस वर्ष की कितनी २ रकम सरकारी अधिकारियों में भुगतान की तारीख पर जमा न कराने के कारण बाकी है ? भुगतान की तारीख, रकम सहित नामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ख) अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड, जयपुर की किस २ वर्ष की कितनी २ रकम प्राइवेट व्यक्तियों तथा संस्थाओं में भुगतान की तारीख पर जमा न कराने के कारण बाकी है ? भुगतान की तारीख व रकम सहित ऐसे नामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ग) इस बकाया के रहने के क्या कारण हैं तथा इसकी वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(क) तालिका सदन की मेज पर रखवा दी गई है ।

(ख) तालिका में ही सरकारी कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति पृथक २ दिखा दिये गये हैं ।

(ग) इन रकमों के बकाया रहने का मुख्य कारण यह है कि भूखन्ड लेने वाले व्यक्ति अधिकत्तर सीमित साधन वाले सरकारी अधिकारी वर्ग है जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण भूखन्डों का मूल्य जमा नहीं कर पाये हैं। कार्यालय से इन व्यक्तियों को तथा इनके कार्यालयाध्यक्षों को बार २ लिखा जाता रहा है ! तथा अब मन्डल पब्लिक डिमान्डस रिकवरी एक्ट के तहत कार्यवाही करेगा ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्राक्कलन समिति हेतु निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्राक्कलन समिति, १९६० -६१ के लिये निम्नांकित सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं:

१. श्री अब्दुलगफ्फारखां

(श्री अध्यक्ष)

२. श्री अनूपसिंह

३. श्री अमृतलाल यादव

४. श्री किशनलाल शर्मा

५. श्री घासीराम यादव

६. श्री चन्द्रसिंह

७. श्रीमती प्रभा मिश्रा

८. श्री पी. के. चौधरी

९. श्री बेनाराम गहलोत

१०. श्री भंवरलाल शर्मा

११. श्री भैरोंसिंह खेजड़ला

१२. श्री भोलानाथ

१३. श्री मुक्तिलाल मोदी

१४. श्री रामनारायण वर्मा

१५. श्री रामप्रसाद लड्ढा

राजस्थान विद्युत मंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण पर वाद-विवाद

विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है, जो माननीय सदस्य बोलना चाहें बोल सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो बजट बनाने की परम्पराऐं हैं और जो बजट बनाने का तरीका है उस तरीके को तो बलाये ताक रख कर और लोगों को एक भूल भुलैया में डाल कर जो वस्तु-स्थिति है उसको भी सामने नहीं रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट को अध्ययन करने के बाद मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि बजट तथ्यों की जानकारी देने के लिए या सही स्थिति सदन के सामने रखने के लिए जो कुछ करना चाहिये था वह नहीं किया अपितु कुछ लीपा-पोती करनी चाहिये, विभाग ने जो कुछ वहां किया, जितनी धन राशि जितने काम और अचीवमेंट्स प्लान प्रोजेक्ट्स के तहत डिपार्टमेंट को करने चाहिये थे वे नहीं किये इसलिए सारे फीगर्स को बजट में इस ढंग से रखा जाय जिससे सर्व साधारण, सामान्य बुद्धि के व्यक्ति उसको समझ न सकें। इस बजट को देखने के बाद, अध्यक्ष महोदय, हर एक आदमी और हर एक माननीय सदस्य कह सकते हैं कि जो राजस्थान सरकार द्वारा बजट मेन्युअल और प्रोफोर्मा दिया हुआ है कि बजट किस तरह से तैयार किया जाय, उसका क्या प्रोफोर्मा होगा, क्या रूप होगा, अगर बजट मेन्यूअल को देखा जाय, फार्म १ और फार्म २ को देखा जाय तो मैं कह सकता हूँ कि इन इन फोर्म्स के स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से यह बजट नहीं बनाया गया है। सन् ५७-५८ और ५८-५९ के एक्चुअल्स का कहीं पता नहीं है। कितना एस्टेब्लिशमेंट्स पर खर्चा हुआ, कितनी आमदनी और कितना एक्सपेन्डीचर और जितने भी प्रोविजन फार्म १ और फार्म २ में होने चाहिये जिस तरह से बजट बनाना

Page No.31

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहिये जिससे कि हर एक आदमी को पता चल सके, इस विभाग ने किस प्रकार की प्रगति की, कितना खर्चा हुआ, अनुमान क्या है और किस तरह से बढ़ाया गया, क्या आमदनी, आंकड़ों में परिवर्तन किस तरह से होगा और यह अन्दाज़, अनुमान एक व्यक्ति लगा सकता है, इस तरह का बजट बनाने का तरीका राजस्थान मेन्यूअल नामक पुस्तक में दिया हुआ है उसके अनुसार यह बजट नहीं बनाया हुआ है। ५८-५६ के एस्टीमेंट्स दे दिये, रेवेन्यू दे दिये, ६० के लिए धन राशि का प्रोविजन इसमें रख दिया। इस तरह का यह बजट प्रस्तुत किया गया है और मैं कह सकता हूं कि उस बजट से सही स्थिति का अन्दाज नहीं लगाया जा सकता है कि कितना हमने खर्च किया, कितना इसके लिये एक्सपेन्डीचर था और कितना इस मद में रखा जाय।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय एक दो मामले विद्युत मंडल के सम्बन्ध में रखे थे उसके बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था उसके सम्बन्ध में तो मैं बाद में निवेदन करूंगा। इसके अलावा जो बहुत बड़ी चीज़ इस बजट में है, जिसका प्रचार बहुत जोरों से हुआ है, जिसका नारा हर समय लगाया जाता है कि राजस्थान के अन्दर भाखरा नांगल योजना से बिजली मिलेगी, चम्बल बांध से, गांधी सागर डेम से राजस्थान को बिजली मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें हम काफी अर्से से सुनते आ रहे हैं इसको हम गहराई से देखें तो मैं यह निवेदन करूंगा कि भाखरा नांगल और चम्बल प्रोजेक्ट से जो बिजली प्राप्त होने की घोषणायें की जाती हैं उनसे जो आशायें दिलायी जाती हैं वे एक प्रकार से धूमिल आशायें हैं, कोई तथ्य इससे निकलने वाला नहीं। इन सबके बारे में, प्लान प्रोजेक्ट्स के बारे में द्वितीय योजना में जो धन राशि रखी है वह करीब २० करोड़ रुपये का प्रोवीजन है जो इन दो प्रोजेक्ट्स पर खर्च होने वाला है। हम सन् ५७-५८ और ५८-५६ और ६०-६१ में कुल मिला कर १५ करोड़ के लगभग धन राशि इस बजट के अन्तर्गत खर्च कर सकते हैं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि पांच करोड़ रुपये के टार्गेट्स यानि पांच करोड़ रुपये की धनराशि हम इस अर्से में खर्च नहीं कर सके।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १६५६-६० में ४४० लाख रुपये के टार्गेट्स हमने रखे थे। यह साल खत्म होने आया इस अर्से में हमने कितने अचीवमेंट्स किये, कितना खर्चा हुआ ये सब बातें बजट में नहीं हैं। १६५६-६० के अचीवमेंट्स कितने हुए, इसके सम्बन्ध में कोई आंकड़े इसमें नहीं हैं। आपको एक्चुअल एक्सपेन्डीचर का पता नहीं, आप छः महिने का, आठ महिने का हिसाब दे सकते थे। बजट को पढ़ने के बाद और इसको स्टडी करने के बाद यह पता नहीं पड़ता कि हमने १६५६-६० में कितने और क्या क्या टार्गेट्स अचीव किये। इन टार्गेट्सजानकारी इसलिये जरूरी है कि सन् ५६-५७ में जब कि हमारा एक्चुअल एक्सपेन्डीचर ५४ लाख का था, ५७-५८ में बढ़ कर वह ८८ लाख के करीब हो गया। उसके बाद सन् १६५६-६० में वह ४४० लाख के करीब हो गया। इतने टार्गेट्स हमने रखे हैं, इसमें मुझे सन्देह है कि हम इतने टार्गेट्स

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भी पूरी तरह से अचीव कर पायेंगे। ४४० लाख की जो धन-राशि सन् १९५९-६० में रखी थी वह खर्च नहीं हुई और इसी तरह से १९६०-६१ में ६८ लाख रुपये की धन-राशि जो हमने रखी है वह आज-कल के काम की प्रगति और प्रोग्रेस को देखते हुए और जिस तरह से काम चल रहा है, मैं समझता हूं, यह सम्पूर्ण राशि भी हम खर्च नहीं कर पायेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि जब आयन्दा साल हम ६०-६१ के बजट को डिस्कस करेंगे तो यह भी उसमें होगा कि हम इतनी धन-राशि को खर्च नहीं कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, भाखरा नांगल के सम्बन्ध में सदन में बड़े जोरों से कई बार चर्चायें होती हैं, मुख्य मंत्री भी इसी प्रकार के विचार रखते हैं कि हमें भाखरा और नांगल से बहुत जल्दी बिजली मिलने वाली है। जहां तक राजस्थान का ताल्लुक है भाखरा और नांगल से हमारे राजस्थान के एक चौथाई भाग को बिजली मिल सकेगी। जहां तक राजस्थान को बिजली मिलने का सम्बन्ध है अभी तक, मैं समझता हूं, श्री गंगानगर के इलाके के सिवाय इस प्रदेश के किसी भाग को बिजली प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में इतना ही कह सकता हूं कि वे तथ्य भी इस बजट में नहीं दिये गये हैं। इसके अलावा माननीय मंत्री महोदय इस बात की जानकारी करेंगे कि भाखरा नांगल से जो बिजली पिलानी को दी गई उसकी केवल रिसीट ७०० रुपये की हुई थी जो विभाग को हुई थी, लेकिन वह ७०० की रिसीट इस सारी किताब में कहीं नहीं बतायी गई है। बिजली सप्लाई करने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट को यानी इस विभाग को जो खर्चा करना पड़ा है वह करीब ४ हजार रुपये के हैं और इस तरह से चार हजार रुपये खर्च करके केवल ७०० रुपये की आमदनी रियलाइज़ कर सके हैं। इसी तरह से सारे काम इस विभाग द्वारा चलने वाले हैं उससे सारी आशायें धूमिल हो जायेगी। भाखरा नांगल के सम्बन्ध में कहा गया है कि राजगढ़ तक बिजली की लाइन बिछा दी गई है। अध्यक्ष महोदय, तीन साल हो गये राजस्थान को बिजली नहीं मिली किन्तु उधर पंजाब का इलाका तीन साल पहले से बिजली से जगमगा रहा है। इसमें जहां राजस्थान का ११४ कॉन्ट्रीब्युशन है जहां ४५ करोड़ रुपये की धन-राशि राजस्थान की लगी है लेकिन इतनी धन-राशि लगाने के बाद भी ६०-६१ में हमें बिजली का कितना लाभ होने वाला है? अध्यक्ष महोदय, जहां तक भाखरा नांगल का सम्बन्ध है उसके अन्दर जो आमदनी का अन्दाज़ लगाया गया है वह ४ लाख १३ हजार ८०० रुपये की रेवेन्यू रिसीट दिखाई गई है। यह आमदनी भाखरा-नांगल से जो बिजली मिलेगी उससे होने वाली है; जिस प्रोजेक्ट के अन्दर राजस्थान का ४५ करोड़ के करीब रुपया लगने वाला है, इतना खर्चा जिसका पड़ा है, कब जाकर इर्रिगेशन के चार्जेज़ के रूप में क्या मिलेगा, यह अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो आमदनी बतायी गई है उस हिसाब से अगर हम ४५ करोड़ रुपये का वार्षिक इन्टरेस्ट भी लगाते हैं तो करीब डेढ़ करोड़ रुपया तो केवल इन्टरेस्ट का ही हो जाता है। जहां तक पॉवर से होने वाली आमदनी का ताल्लुक है वह केवल ४,१३,८०० रुपये हैं। इसके लिये भी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता कि कहां तक यह आमदनी निश्चित तौर से हो जायगी। जहां तक राष्ट्रीय विकास योजनाओं का ताल्लुक है अधिकांश में यह विद्युत मंडल असफल रहा है, इसकी निष्क्रियता के कारण हमारा लाखों रुपया बचा रहता है उसको हम लगा नहीं पाते और इस तरह से हमारी राष्ट्रीय योजनायें पूरी नहीं हो पातीं। मैं समझता हूं कि जिन अधिकारियों के कारण हमारे प्लानिंग के टार्गेट्स पूरे नहीं होते उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। जहां तक भाखरा-नांगल से बिजली मिलने का सवाल है उसके लिये कहा गया है भिवानी, हिसार और राजगढ़ तक लाइन बिछाने का काम पंजाब सरकार के जिम्मे दिया गया था उसके द्वारा यह लाइन बिछा दी जायगी। लेकिन जहां तक पंजाब सरकार का ताल्लुक है हमें अपनी समान सरकार पर विश्वास करना चाहिये यह ठीक है, लेकिन जहां तक अपने राज्य की जनता को सन्तुष्ट करने का सवाल है हर एक राज्य अपनी जनता की सुख-सुविधा को पहले ध्यान में रखता है उसी प्रकार पंजाब सरकार ने हमारी तरफ एक्सपान्शन नहीं किया। उन्होंने अपने राज्य के हित की दृष्टि से पहले अपने राज्य में बिजली की लाइन दी और राजस्थान के राजगढ़ और हिसार के इलाके में लाइन नहीं बिछायी। नतीज़ा यह हुआ कि पंजाब ने यहां के इलाके में बिजली की लाइन डाली नहीं और इसी कारण राजस्थान तीन साल तक बिजली प्राप्त करने से महरूम रहा। मैं जानता हूं और कह सकता हूँ कि हम इस बारे में अभी तक निश्चित नहीं हैं कि राजस्थान के इलाकों को पंजाब से कब बिजली मिलने वाली है और यह भी मैं मानता हूं कि हमारा बिजली विभाग अभी तक इस स्थिति में नहीं है कि वहां से प्राप्त होने वाली बिजली का लाभ ले सके। इस बजट में तो जरूर लिख दिया है अध्यक्ष महोदय, कि वहां पर लाइन डालने का काम चालू हो गया। पर मैं बतादूं कि इसमें लिखा है कि भाखरा-नांगल से जो लाइन आई है वह १३२ मीटर की राजगढ़ से रतनगढ़ तक और रतनगढ़ से बीकानेर तक ६६ मीटर की डाली जा रही है। माननीय सदस्यों को इससे आभास होगा कि लाइनें डाली जा रही हैं, तो बिजली आजावेगी और बल्ब जल उठेंगे, सब जगह बिजली चमकने लगेगी। बीकानेर डिविजन से आने वाले माननीय सदस्य ने इस अंग्रेजी बजट को पढ़ा होगा तो शायद उन्होंने भी आशाएं बांधी होंगी। पर उन्होंने नहीं बताया कि वास्तव में होगा क्या? उन्होंने सब जनता को भ्रम में रखने की कोशिश की है। मैं बताऊं कि जो लाइन वे डाल रहे हैं, उससे बिजली नहीं मिलने वाली है, उससे बल्ब जगमगाने लग जावेंगे, ऐसी बात नहीं है। वे हाई टेन्शन लाइनें हैं। इस पर जनरल ट्रान्समिशन होगा, बिजली का डिस्ट्रिब्यूशन नहीं होगा, कन्ज़म्पशन नहीं होगा। यह तब होगा जब लो टेन्शन लाइनें डाली जावेंगी। तो यह कह कर लोगों को मुगालते में रक्खा जा रहा है कि लाइनें डाल रहे हैं। रतनगढ़ तक डाल दिया है, बीकानेर तक का काम पूरा किया जा रहा है क्योंकि हर आदमी इस हाई टेन्शन और लो टेन्शन लाइनों को जानता नहीं, के. वी. का मतलब जानता नहीं। पर इस तरह मुगालते में रखकर इम्प्रेशन लोगों को यह दिया जाता है इन हाई टेन्शन लाइनों

Page No.34

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के खम्भे गाड़ कर कि बिजली सरकार देने वाली है, ६०–६१ तक लाइनें डालकर काम पूरा हो जावेगा, चारों तरफ बिजली जगमगाने लग जावेगी। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और विशेष तौर से, और अन्य मन्त्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मुझ से इस बात में सहमत होंगे कि बिजली की सप्लाई का काम इससे नहीं होगा। इसके लिये आपने आगे कहा है कि ३३ के. वी. की लाइन डालने की scheme is in progress पर इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कब तक डाल दी जावेगी यह लाइन भी। इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन या संकेत जहां तक इस बजट का सम्बन्ध है, नहीं दिया गया। इसलिये नहीं कहा जा सकता कि आगामी वर्ष हम कितनी बिजली का उपयोग कर सकेंगे, किस हद तक कर सकेंगे, किस उपयोग में कर सकेंगे और उससे कितनी आमदनी हमें हो सकेगी। यह निश्चित रूप में, कम से कम कहने की स्थिति में मैं तो नहीं हूं।

दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा चम्बल प्रोजेक्ट। जहां तक उसका ताल्लुक है, अध्यक्ष महोदय, चम्बल प्रोजेक्ट से बिजली आने वाली है। उस पर लाइन डालने काम चालू है। उसमें लाइन डल रही है गांधीसागर से सवाई माधोपुर तक और सवाई माधोपुर से जयपुर तक। जहां तक लाइन डालने के ठेके का सवाल है मैं निवेदन करूं कि जिसको यह ठेका दिया गया है उसके बारे में मैंने पहले भी एक बार अपने विचार व्यक्त किये हैं, जिसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्री ने उत्तर भी दिया था। उसके बारे में मैं बाद में कुछ निवेदन करूंगा। अभी तक तो यह पहले निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली आनेवाली है गांधीसागर से और बिजली की लाइन डाली जा रही है सवाई माधोपुर से जयपुर तक। बिजली चलेगी गांधीसागर से, पर तारें डाली जा रही हैं कहीं और जगह, जनरेशन सेन्टर है कहीं और और डिस्ट्रिब्यूशन सेन्टर है कहीं और जगह। आप इनकी बुद्धि का परिचय देखें। आपको बिजली लानी है गांधीसागर से तो आप वहां से पहले तार की लाइन चालू करते। वहां से कोटा लाते, कोटा से फिर आगे चलते और बीच में जो जगह, जो स्थान मिलते जाते उनको डिस्ट्रिब्यूट करते चले आते, ज्यों ज्यों आपका जनरेटिंग और सप्लाई की स्थिति बढ़ती जाती आप आगे से आगे बढ़ते जाते और इस तरह कोटा से होते हुए झालावाड़ को देते हुए आप सवाई माधोपुर तक आ जाते और फिर वहां से जयपुर की तरफ बढ़ते। पर वहां से नहीं डाल कर पहले आप सवाई माधोपुर से जयपुर तक डालना चाहते हैं दिखावे के लिये। लोगों को भूलभुलैया में डालने के लिये कि हम आपके लिये बिजली ला रहे हैं। पर बिजली आवेगी कहां से ? आखिर बिजली के ये खम्भे और तार सवाई माधोपुर से आगे तो हैं नहीं। क्या बिजली गांधीसागर से उछल कर आ जावेगी, आसमान से लटक कर आ जावेगी, कहां से आ जावेगी ?

(हंसी)

आप जब तक गांधीसागर डैम से लेना नहीं चाहेंगे, वहां से जब तक बिजली के तार नहीं डालेंगे तब तक कैसे आवेगी ? आप पहले वहां से कोटा, झालावाड़ होते हुए सवाई माधोपुर लाते, सवाई माधोपुर से जयपुर का काम बाद में चलता रहता। झालावाड़ के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इलाके में, कोटा में सप्लाई कर सकते थे, बीच के एरिया को सप्लाई कर सकते थे।

अब मैं इसके ठेके के सम्बन्ध में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं कि मैंने इस ठेके के सम्बन्ध में पहले भी कुछ तथ्य रक्खे थे। उस बारे में आपका समय अधिक नहीं लेना चाहता। पर पिछली बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में सवाई माधोपुर से जयपुर के बीच लाइन डालने का काम चालू हुआ है उसके बारे में मैंने कुछ कहा था। वह एक क्रॉम्प्टन नाम की कम्पनी है। उसको ठेका दे दिया गया है और उस ठेके के सम्बन्ध में और और कामों के सम्बन्ध में कुछ बातें मैंने सदन में रक्खी थीं। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया था तो बड़े ही जोर के साथ कहा था और आपत्ति भी की थी कि सदन के सामने कुछ बातें ऐसी रखी जाती हैं कि जिससे लोगों को आभास हो और सदन को भी आभास हो कि क्रॉम्पटन कम्पनी एक मद्रासी फर्म है और बोर्ड के ऊपर भी मद्रासी हैं इसलिये कोई उसने फेवरेटिज्म किया है। मैं स्पष्टीकरण कर दूं कि न तो मुझे मद्रासियों से चिढ़ है और न विशेष जाति या प्रान्त से प्रेम है। फिर भी जो वस्तुस्थिति है, जो तथ्य है और जिनके जरिये ये सारी बातें सामने आती हैं वे सारी बातें सदन के सामने रखना विधान सभा के सदस्य का परम कर्त्तव्य है और इसी नाते मैंने वे बातें सदन में अब तक रखी हैं और आगे भी रखना चाहूंगा। आज भी रखूंगा और अधिक तथ्यों के साथ रखूंगा और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि वे तथ्य गलत हों तो वे स्वयं जाकर देखें, स्वयं जांच करें। ये वे तथ्य हैं जो किसी सूरत में छिपाये नहीं जा सकते, जिनके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं, अगर उनमें कहीं गलती हो तो वे स्पष्टीकरण करें।

क्रॉम्पटन कम्पनी को ठेका दिया गया। टेन्डर इन्वाइट किये गये। उनका टेन्डर स्वीकार किया गया और इसके बाद २६-६-५७ को ऑर्डर दिया गया, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। जो ऑर्डर प्लेस किया गया इस मद्रास की फर्म को उसमें यह लिखा गया कि ये तीन चार बातें हैं उनको आप मानें। २६ पेज का ऑर्डर है। और इसमें बहुत से क्लॉज़ हैं और उनमें जो रिलेवेन्ट क्लॉज हैं उनके बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें विशेष रूप से चार क्लॉजेज हैं। क्लॉज़ नम्बर ७, १५, १६ और ८०। इनमें एक क्लॉज में आपने पेनल्टी के बारे में प्रोविजन किया। आपने लिखा कि अगर आपने काम इतने समय में नहीं किया तो १।२ पर्सेन्ट पेनल्टी देनी होगी। दूसरे में बैंक गारन्टी के लिये लिखा पांच पर्सेन्ट ऑफ दी contract value, तीसरी कन्डीशन एक्सेप्टेन्स विदिन वन वीक की मांग की गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज उनसे पूछना चाहूंगा कि जिस कम्पनी को आपने लिखा और लाखों करोड़ों रुपया का माल जिसके डिस्पोज़ल पर करवाने वाले हैं क्या उस कम्पनी ने आपकी वे शर्तें अनकन्डीशनल मान लीं और कानून के अनुसार जो एग्रीमेन्ट किया जाना चाहिये वह कर लिया गया? क्या विद्युत मन्त्रीजी यह कह सकते हैं कि विद्युत मण्डल ने जो ऑर्डर प्लेस किया था और जिसकी एक्सेप्टेन्स

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विदिन ए वीक लेने की बात कही, क्या वह एक्सेप्टेन्स विदिन वन वीक आ गया और जो प्रेस्क्राइब्ड एग्रीमेंट था, आपने जो ऑर्डर के साथ भेजा उसे फर्म ने भर कर आपको भेज दिया ? क्या उस कन्सर्न ने पांच पर्सेन्ट की जो बैंक सिक्योरिटी आपने मांगी वह दे दी ? पेनल्टी के क्लॉज के बारे में जैसा आपने लिखा था उसको उसी रूप में एक्सेप्ट किया। मैं अमेन्डमेन्ट की बात नहीं चाहता। इफ और बट के साथ अगर आपने कुछ किया है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उसकी लीगल पोज़ीशन क्या है ? प्रोपर लीगल वे में एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया क्या आप यह कहने की स्थिति में हैं ? आप कानून समझते हैं, मैं निवेदन करूं कि आप कहते हैं कि हम इन टर्म्स पर ऑफर करते हैं, आप हां करते हैं या ना। यदि कोई उनमें टर्म्स और कन्डीशन्स लगाता है तो कभी भी इल्लीगल पोज़ीशन अराइज हो सकती है। इसलिये जानना चाहूंगा कि असल लीगल पोज़ीशन क्या है, आपने ऑर्डर दिया, क्या उसका उस रूप में एग्रीमेंट हो गया ? यदि ये सारी बातें नहीं की हैं तो आप कानूनी दृष्टि से विचार करिये। वहां काम चल रहा है। मैं माननीय मुख्यमन्त्रीजी से कहूंगा, इसमें प्रपोगेण्डा या पब्लिसिटी का सवाल नहीं है। आप चले जाइये, स्वयं देख लीजिये टौंक के इलाके में जहां काम हो रहा है। ५०० आदमी लेबर के रूप में वहां काम कर रहे हैं पर आपको देखकर ताज्जुब होगा कि कॉम्पटन कम्पनी के इन ५०० लेबर में एक आदमी भी राजस्थानी नहीं है, सब मद्रास से लाया है। क्यों लाया ? इसलिये नहीं कि लेबर राजस्थान में नहीं मिलता या काफी नहीं मिलते। इसलिये नहीं कि लेबर यहां अच्छे नहीं मिलते, टैक्निकली स्किल्ड नहीं मिलते। पर इसलिये लाया है मैं आपको जानकारी के लिये बतादूं चाहें तो पोल के नम्बर भी बता दूं। रात को दस बजे तक काम होता है, सारा काम जो किया जाता है, जो खम्भे गाड़े जाते हैं, जो गड्ढे खोदे जाते हैं, जो कन्क्रीट या सीमेन्ट भरी जाती है उसमें कोई भी काम स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं किया जा रहा है। जिसमें स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जितना कन्क्रीट और सीमेन्ट भरा जाना चाहिये उतना सीमेन्ट कन्क्रीट नहीं भरा जाता, कोरी मिट्टी भर कर दबवा दिये जाते हैं और कोई काम उनका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है। मैं खम्भों के नम्बर बता सकता हूं कि इन इन खम्भों के नीचे इस तरह की गड़बड़ी की गई है और इसमें यह घोटाला है। ऐसा न हो कि फाउन्डेशन उनकी कमजोर रह जावे और किसी दिन आंधी आवे और वे खम्भे आसमान में उड़ जावें। यह स्थिति आ सकती है। आप चाहें तो मैं आपको स्पोट पर ले चल सकता हूं। आप अपने एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को ले जाकर देख लें कि वस्तु स्थिति क्या है। आप केवल सदन में जवाब देकर टालना चाहें तो यह टलेगा नहीं। आखिर यहां सारी बातें इसलिये रखी जाती हैं कि उनको रखना हमारा कर्त्तव्य है, आखिर किसी से मेरा द्वेष नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है। पर जो बातें हमारे सामने आती हैं और जिनके कारण ये सारी बातें पैदा होती हैं, मैं समझता हूं कि हमारा यह परम पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उन सारी बातों को सदन के समक्ष रखें।

जहां तक इस फर्म के बारे में था, अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया। अब एक सवाल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय और खड़ा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हमने एक आटोनौमस बॉडी बनाई है यह आटोनौमस बॉडी है या आटोक्रेटिक बॉडी है। ओटोनोमस बॉडी इस माने में है कि हमारा उसमें कोई दखल नहीं है। वह काला करे या सफेद करे, कोई पूछने वाला नहीं है और इस बोर्ड का कोई धनी धोरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सदन को यह जानकर ताज्जुब होगा कि इस बोर्ड के बनने के बाद, फिर शायद यह न कहा जाये कि मैं विशेष प्रान्त के लिए कहता हूं, इस बोर्ड के बनने के बाद जितने एम्पलॉयमेंट इसमें किये गये, जितने रिक्रूटमेंट इसमें किए गए आज बीसियों ऑफिसर्स रिटायर्ड हैं, पेंशन होल्डर्स हैं उनको इसमें एम्पलॉय किया गया है। हमारी सरकार नारा लगाती है नौजवानों को आगे लाने के लिए और रिटायर्ड लोगों को फिर से एम्पलॉय करने की नीति को छोड़ने के लिए लेकिन फिर भी उन्हीं को इस राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एम्पलॉय किया गया है। सरकार चार पर्सेन्ट और पांच पर्सेन्ट के रिडक्शन की बात करती है और दूसरी तरफ अपने ही बोर्ड में जिसको आप ऑटोनोमस बोर्ड कहते हैं उसमें आपने दो साल के पीरियड में एम्पलॉय किया सारे रिटायर्ड आफिसर्स को। जितने भी पेन्शन होल्डर्स थे रिटायर्ड थे, उनको आपने भर लिया। क्या यह कोई गौशाला है कि जितने भी अपंग और असहाय लोग हैं उन सबको एक पिंजरा पोल में भरती करा दिया जाये। जो दूसरे प्रान्तों के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जो दूसरे प्रान्तों के पेन्शन होल्डर्स हैं जिनको उनके प्रान्तों में कोई स्थान नहीं मिला, जो उन प्रान्तों में री–एम्पलॉय नहीं हो सकते हैं उनको आपने अपने यहां भर लिया। क्या आपने बोर्ड को एक एम्पलॉयमेंट का ब्यूरो बना लिया है कि जिसको वहां की अपनी स्टेट ही री–एम्पलॉय नहीं करे, आप वहां के लोगों को अपने यहां एम्पलॉय करें। क्या यहां के लोगों में वह योग्यता नहीं, क्या यहां के नौजवान आगे बढ़ना नहीं जानते, आखिर क्या बात है ऐसी ? जैसे पहले राजस्थान में यह विभाग चलता ही नहीं था। मैं तो अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने वह आंकड़े रखूंगा कि पहले इस डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट पर कितना खर्चा था और आज वह कितना है ? मैं, यदि माननीय मंत्री महोदय जानना चाहें तो एक एक बता सकता हूं कि किस प्रकार से रिक्रूटमेंट किया गया। एक एक आदमी के बारे में मेरे पास पूरी जानकारी है। मेरे पास यह लम्बी लिस्ट मौजूद है। ऑडिटर, इन्टरनल ऑडिटर्स, सुप्रिन्टेन्डेन्ट, अकाउन्टस् ऑफिसर वगैरह सब को मेरे पास सूचना है। बजट बनाया वहां के सुप्रिन्टेन्डेन्ट ने। अब सुप्रिन्टेन्डेन्ट की क्या हैसियत हो सकती है यह हम समझ सकते हैं। वह बोर्ड का बजट बनाता है इसलिए यह सारी बातें एक्चुअल्स नहीं दिखाई। फिगर्स की सारी की सारी जगलरी है और यह तो अध्यक्ष महोदय एक तरह से कमर्शियल कन्सर्न है। जैसे बनिये की दुकान होती है उसका यदि हम हिसाब–किताब देखें तो इतना अपटूडेट होगा कि उसके पास प्रॉफिट एण्ड लॉस अकाउन्ट होगा, बैलेन्स शीट होगी और दूसरी सभी चीजें होंगी। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे यह बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कितने रुपये की वैल्युएशन के असेटस् राजस्थान गवर्नमेंट से लिए और क्या फाइनेन्शियल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पोज़ीशन है ? कितने की वर्थ प्रोपर्टी इस बोर्ड ने गवर्नमेंट से ली इसका कोई हिसाब और आंकड़े नहीं हैं मंत्री महोदय के पास। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय सदन को बतायें कि कितने की प्रोपर्टी और कितने का वैल्युएशन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने राजस्थान गवर्नमेंट से लिया ? वह नहीं बता सकते, उनके पास आंकड़े नहीं हैं कि कितने का वैल्युएशन कर लिया, कितने के पॉवर हाउसेज़ राजस्थान में थे और इतना ही नहीं इतना अजीब तमाशा है कि इसमें एक और प्रोवीज़न रखा है डेप्रीसियेशन का। कोई पॉवर हाउस था उसमें ५० हजार की मशीनरी थी। जिस समय राजस्थान गवर्नमेंट चलाती थी तो १० पर्सेन्ट डेप्रीसियेशन चार्ज करती थी और जैसे कोई मशीनरी १० साल तक चली तो उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है। इतने टाइम के अन्दर वह मशीनरी डेप्रीसियेट होती है अब वह बोर्ड ने टेकओवर कर ली और वही १० पर्सेन्ट का प्रोवीज़न बोर्ड ने भी कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब डेप्रीसियेशन की रकम बराबर हो गई तो आप डेप्रीसियेशन का प्रोवीज़न कैसे करते हैं। आप पेन्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, प्रोजेक्ट अलॉउन्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते, डेपूटेशन अलाउन्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते जब यह सारी स्थिति खड़ी होती है तो इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि बोर्ड है लेकिन उसके कोई रूल्स नहीं हैं। बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारी हैं लेकिन नियम नहीं हैं कोई रेग्युलेशन्स नहीं हैं। आखिर उनके प्रोमोशन के के रूल्स क्या होंगे, वे राजस्थान गवर्नमेंट में वापिस जा सकते हैं या नहीं, सर्विस रूल्स, ग्रेच्युटी के, प्रोवीडेन्ट फण्ड के, स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम के क्या रूल्स होंगे, कोई रूल्स नहीं हैं। नतीजा क्या होता है कि प्रोमोशन के रूल्स नहीं हैं इसलिए जिसको मन में आया प्रोमोशन दे दिया और नहीं दिया। ऐसे ऐसे आदमी हैं कि जिनको साल में दो दो प्रोमोशन्स दे दिये गये। एक प्रोमोशन के बाद तो उनको सुप्रिन्टेन्डेन्ट बना दिया और दूसरे प्रोमोशन से उनको अकाउन्ट्स ऑफिसर बना दिया। कोई रूल्स नहीं हैं, कोई मैरिट्स के लिए कन्सीडरेशन नहीं है। लेकिन किसी की खुशामद होनी चाहिए, किसी का हाथ अपने सर पर होना चाहिए, कोई हमारा पैटर्न होना चाहिए। इसलिए आज बोर्ड के कर्मचारियों में घोर असन्तोष फैला हुआ है। आज बोर्ड के कर्मचारियों में डिवीज़न है वह इस सस्पेन्स में हैं कि हमारे भाग्य का फैसला कौन से रूल्स से होगा।....

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री) : Rajasthan Service Rules are applicable to it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर राजस्थान सर्विस रूल्स एप्लीकेबल हैं और बोर्ड ने उनको एडॉप्ट कर लिया तो अभी चार-पांच दिन पहले मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने राजस्थान सर्विस रूल्स को एडॉप्ट कर लिया है, तो आपने कहा था कि उत्तर तैयार नहीं है, अभी बोर्ड के रूल्स बने नहीं। यह अभी दो तारीख की ही बात है। आखिर बोर्ड में कौनसे रूल्स लागू हैं, आपने उत्तर नहीं दिया और आपने कहा कि बोर्ड की मीटिंग करके फैसला करेंगे कि बोर्ड में कौन से रूल्स बनायें। आप कहते हैं राजस्थान सर्विस रूल्स लागू हैं तो क्या उनमें

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह लिखा हुआ है कि २५ साल से ऊपर की उम्र के आदमियों को एम्पलॉय किया जाये। आप ही बतायें कि आपने कितने ओवर एज आदमी एम्पलॉय किये हैं ? कोई इन्टरव्यू नहीं हैं, कोई रूल्स नहीं है अगर आपने उन रूल्स को एडॉप्ट कर भी लिया है तो आपने रूल्स का मर्डर कर दिया है। कोई रूल्स की तामील नहीं करते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन सारे लोगों के बारे में जब कि कोई रूल्स ऑफ प्रोमोशन नहीं हैं तो उनमें डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता है। बोर्ड के बारे में आप समझ लें कि जब तक यह फेवरेटिज्म चलेगा और डिस्क्रिमिनेटरी चीजें चलेंगी तो राजस्थान के लोगों में असन्तोष पैदा होगा। प्रोमोशन्स के रूल्स नहीं बनेंगे जब तक आप सर्विस को स्टेबिलाइज नहीं कर देंगे मैं समझता हूं जो चम्बल के बारे में और भाखरा के बारे में प्रोग्रेस हम चाहते हैं वह नहीं हो सकती। आपका एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई खर्चा कम नहीं है। आज मैं समझता हूँ कि जब बोर्ड नहीं बना था बोर्ड बनने से पहले हमारे यहां अध्यक्ष महोदय जो एम्पलॉईज़ थे वह इस तरह से थे कि बोर्ड बनने से पहले एक सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर काम करता था और अब ५ सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर काम कर रहे हैं। ४ एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर बोर्ड बनने से पहले काम करते थे और अब काम कर रहे हैं १६ एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर। पहले असिस्टेन्ट इन्जीनियर की पोस्ट थीं ४६, जिसमें १८ काम कर रहे थे और आज ३१ काम कर रहे हैं। पहले अकाउन्ट्स ऑफिसर की एक भी पोस्ट नहीं थी आज एक काम कर रहा है आपने इतना एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा बढ़ा लिया है। जब राजस्थान में बोर्ड नहीं बना था तो उस समय टोटल स्ट्रेन्थ थी उसमें लगभग २५० आदमी काम करते थे, इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल डिपार्टमेंट में ३०-४० का स्टाफ था, कुछ सेक्रेटेरियट में था। २५० आदमी ही इस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कन्ट्रोल करते थे और आज आपकी स्ट्रेन्थ एस्टेब्लिशमेंट की क्या है ? आज स्ट्रेन्थ ६४१ है। आज आपका बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट पर और चीफ इन्जीनियर पर जो कुछ खर्चा है वह ६३,६१,७७०) रु० है जब कि आमदनी है कुल १,७६,८६,३५०) रु०। अध्यक्ष महोदय, मैंने केलक्युलेट किया है कि कुल आमदनी का ३५ परसेन्ट हम एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च कर रहे हैं। अब बताइये, जिस बोर्ड में, जिस संस्था में ३५ पर्सेन्ट रुपया एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च होता है तो मैं समझता हूं कि उसका किस तरह से काम चलेगा ? यही नहीं, बल्कि बोर्ड की कुल आमदनी में से ७० लाख रुपये डाइरेक्शन और सुपरवीज़न पर इतना सारा खर्चा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वह किसी प्रकार न्यायोचित नहीं हो सकता है।

एक बात अन्त में, अध्यक्ष महोदय, और अर्ज करूंगा कि हमारे यहां कई जगह हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम लागू कर रहे हैं, लेकिन बजट में कुछ आंकड़ें ऐसे दिये हैं और बजट के एक्स्प्लेनेटरी मेमोरेन्डम में जो आंकड़ें दिये हैं उनसे इस बात का संकेत मिलता है कि हम झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर और जयपुर को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर देंगे; तो मेरी समझ में नहीं आता है कि जब कि इसी साल में आप बिजली झालावाड़

(श्री सतीशचद्र अग्रवाल)

को दे रहे हैं, मैं झालावाड़ का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि माननीय मन्त्रीजी वहां के हैं, जब झालावाड़ में बिजली पहुंच जायगी तो थरमल पॉवर स्टेशन पर ४ लाख रुपये खर्च क्यों कर रहे हैं ? दूसरे पॉवर हाउसेज़ में ४ लाख रुपये लगाने की क्या ज़रूरत है जब कि भाखरा से वहां पर बिजली पहुंचेगी....

एक माननीय सदस्य : भाखरा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भाखरा नहीं चम्बल से । बिजली आने वाली है और जिसकी आपको पूरी आशा है । आपको स्वयं को आशा नहीं है, इसीलिये आपने कहा डिपार्टमेंट को कहा कि झालावाड़ में जरूर लगा दें, क्योंकि चम्बल से बिजली आने वाली नहीं है । वह चीज़ बजट में लिखी हुई है । आपको स्वयं को कॉन्फीडेन्स नही है । अगर आपको कॉन्फीडेन्स था तो वह प्रोवीज़ो करते और यह कहते कि झालावाड़ में थर्मल पॉवर स्टेशन में रुपया इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, भीलवाड़े में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वहां पर थर्मल पॉवर स्टेशन्स पर लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है । अगर आप कर लेंगे और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर आ जायेगी तो यह होगा उनका कि इधर उधर बिखरते फिरेंगे । दूसरे पॉवर हाउस वाले कहेंगे कि हमको ज़रूरत नहीं है । मैं इस संबंध में इतना ही कहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, बजट के आंकड़ें जिस ढंग से रखे गये हैं तो वे किसी आदमी की समझ में नहीं आते हैं बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बजट इस ढंग का बनाये कि लोग अन्दाज़ लगा सकें कि इस कमर्शियल कन्सर्न में कितना प्रॉफिट किया है, कितने इसके एसेट्स हैं, कितनी डेफिसिट है, कितनी मशीनरी है, कितना डेप्रिसियेशन है, यह क्लिअर कट पिक्चर हमारे सामने आये तो अन्दाज़ लगा सकें । हमारे यहां राजस्थान में जितने पॉवर हाउसेज़ हैं उनके सब के बारे में नहीं कहकर एकाध एग्ज़ाम्पल उनके सामने रखना चाहूंगा कि किस तरह से बजट बनाते समय किस तरह के आंकड़ें रखते हैं । बीकानेर पॉवर हाउस का एक एग्ज़ाम्पल दूंगा । २६ लाख की इन्कम बजट में रखी थी ५९-६० में वह २१ लाख हो गई । यह बात निश्चय है कि २६ लाख की इन्कम कह दी लेकिन एक्चुअल २१ लाख हुई और एक्सपेन्डीचर ३२ लाख का रखा था लेकिन होगया ३५ लाख । १४ लाख का डेफिसिट बीकानेर पॉवर हाउस में है । वह क्यों है ? जांच कराइये इस बात की । जयपुर पॉवर हाउस में यह बात सही है कि १० लाख का फायदा हुआ लेकिन इस फायदे से कब तक दूसरे लोगों का घाटा पूरा होगा । आप उस पॉवर हाउस की एन्क्वायरी करवाइये, उनका एक्स्प्लेनेशन लीजिये कि यह लॉस क्यों है । वहां पर ऑफिसर्स भी कैसे हैं, अध्यक्ष महोदय ? वहां पर कोई साधारण ऑफिसर्स नहीं है । वहां पर एक बहुत बड़े, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं । वहां पर दो एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स और एक रेज़ीडेन्ट इन्जीनियर को वहां पर लगा रखा है । जिन रेज़ीडेन्ट इन्जीनियर को १०००) रु० की तनख्वाह मिलती है । जो वहां पर दो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर लगे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हुए हैं उनके बारे में इस समय कुछ नहीं कहना है। मगर जो रेज़ीडेन्ट इन्जीनियर हैं उनके खिलाफ ३६ केसेज़ एन्टीकरप्शन में चल रहे हैं। आप एन्टीकरप्शन में जांच मत करवाइये। लेकिन आप यह उनसे पूछ तो लें कि यह १४ लाख का घाटा क्यों है? ३६ केसेज़ उनके खिलाफ एन्टीकरप्शन में चल रहे है लेकिन फाइलें दबा दी गई हैं। भगवान जानें कहां रख दी गई हैं? वे प्रोमीनेन्ट फीगर्स हैं। जयपुर का हर एक आदमी बिजली घर के काण्ड की वजह से उनको जानता है। वे मि० भट्ट यहां पर पहले थे। उनके खिलाफ ३६ केसेज़ एन्टी-करप्शन में पेंडिंग हैं....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : ३६ नहीं ३५ हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ३५ और ३६ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ केसेज़ की एन्क्वायरी होगी तो मालूम पड़ेगा कि किस तरह की गड़बड़ हुई है। मैं तो यही निवेदन करूंगा उदाहरण के रूप में केवल कि माउन्ट आबू में गवर्नर साहब के इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ तो वहां पर चीड़ की लकड़ी लाई गई। लकड़ी लगाने का जब सवाल हुआ तो डिपार्टमेंट से पैसा चार्ज कर लिया गया कि लकड़ी गवर्नर साहब के लिए लानी है, लेकिन जब हिसाब गया तो गवर्नर साहब के सेक्रेटरी ने कहा कि इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम हुआ है उसमें सारा माल हमने सप्लाई किया था इसलिए इतना पैसा जो ज्यादा जोड़ा गया है। वह गलत जोड़ा गया है। यह गवर्नर साहब के सेक्रेटरी ने अपने लेटर में लिखा है। इधर बोर्ड मे पर्चेजेज़ दिखाये गये हैं तो या तो गवर्नर साहब के सेक्रेटरी झूठे हैं या डिपार्टमेंट का हिसाब-किताब झूठा है। लेकिन एन्क्वायरी• कराइये तो पता लगेगा। ३६ केसेज़ हैं एन्टीकरप्शन में उनके खिलाफ। मैं समझता हूँ कि इन पॉवर हाउसेज़ और बोर्ड में कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ केसेज़ हैं, एन्टीकरप्शन के केसेज़ हैं, डिपार्ट-मेंटल एन्क्वायरी के केसेज़ हैं, कोल के गबन के केसेज़ हैं, और डिपार्टमेंट के हिसाब-किताबों में फोर्ज्ड और फ्रिवुलस एन्ट्रीज़ के केसेज़ हैं। लेकिन फाइलें दबा दी गई हैं। अब कहा जाता है कि चूंकि बोर्ड ऑटोनोमस बोडी है इसलिए चेकिंग नहीं हो सकता है। क्या होगा? साल में एक दिन डिबेट होगी और डिबेट होने के बाद में मामला खत्म होगा। आप एन्क्वा-यरी करवाइये कि राजस्थान में चलने वाले थरमल पॉवर हाउसेज़ में कितने थरमल स्टेशन्स हैं, उनमें मशीनरी कितनी थी, और घाटे को किस तरह से पूरा किया जायगा?

प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस के बारे में निवेदन करूंगा कि जांच करवाइये कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है, उसका क्या कारण है, वह किस तरह से हो सकती है तथा कितने टार्गे-ट्स हैं? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्तिम वर्ष में ६ करोड़ का टार्गेट रखा है, लेकिन मशीनरी वही है, एम्प्लॉयमेंट वही है। ५६ में ५४ लाख खर्च किया, ५६-६० में ४, ४०, ००, ०००) रु० खर्च कर रहे हैं और ६०-६१ में ६, ०८, ००, ०००) रु० का टार्गेट किस तरह से पूरा होगा?। मैं, आखिर में माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यदि टार्गेट्स को पूरा करना है,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्लान प्रोग्रेस को सही रूप में चलाना है तो सर्विसेज़ में जो डिसकन्टेन्टमेंट है उसको दूर करना चाहिए, सर्विसेज़ का प्योरिफिकेशन करना चाहिए, सर्विसेज़ के लिए रूल्स बनाने चाहिए, सर्विसेज़ में स्टेबिलिटी की भावना पैदा करनी चाहिए, जब सर्विसेज़ में से सस्पेन्स की भावना मिट जायगी, जब वे उत्तरदायित्व की भावना से काम करने लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो टार्गेट्स है वे पूरा कर सकेंगें। जो ११ लाख का घाटा बोर्ड के अपने बजट में आपने दिखाया है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि इस डिपार्टमेंट में नुकसान हो। इसमें नुकसान होने का कारण नहीं है। इसके बजट में घाटा होने का कारण नहीं है। लाखों और करोड़ों रुपयों का इस डिपार्टमेंट से राजस्थान सरकार को मदद मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करता हुआ जितनी भी तथ्य की बातें इस संबंध में रखी हैं, माननीय मंत्री महोदय उनके बारे में व्यवस्थित, शान्ति और गहराई के साथ में विचार करेंगे। बोर्ड में सही ढंग से, सही मायने में काम करने के लिये इस प्रकार की स्थिति हो तो लाखों करोड़ों रुपये का सरप्लस बजट यह राजस्थान के लिए हो सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, आज हम राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का १९६०-६१ का जो बजट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो माननीय सदस्य जनसंघ के हैं उन्होंने अपने विचार सदन के सामने रखे, और जिन विचारों को रखते हुए जो बजट की आलोचना करी वह कम से कम मैं यह कह सकता हूँ कि मैं समझ नहीं सका और वह चीज़ समझने वाली नहीं हो सकी कि उन्होंने इस बजट में बताया कि यह जो ट्रेडिशनल बजट बनाया जाता है उस तरीके पर नहीं है। कुछ फैक्ट्स को इस बजट में हाइड किया है और इस तरह के कुछ शब्दों का उन्होंने उपयोग किया। मगर भाषण के दौरान में यह नहीं बता सके कि आखिर बजट किस तरह से बनता है और किस तरह से बनना चाहिए था। यह जो तरीका बोर्ड ने अपनाया है यह तरीका ठीक नहीं है। न यह बता सके कि क्या फैक्ट्स थे और किन फैक्ट्स को बजट में हाइड किया और क्या देना चाहिए या नहीं, बल्कि उन्होंने अंत में जो आलोचना की कि बजट घाटे का है और घाटे का नहीं होना चाहिए था। उनकी आलोचना को मैं यह कहूं कि वह बिल्कुल तथ्यों से परे है। जो हमारे यहां पॉवर हाउसेज़ हैं उनकी हम दशा देखें तो किसी भी भांति में शायद अगले ५ साल के अन्दर भी कोई स्टेट्यूटरी बोर्ड हो वह बजट को बेलेन्स्ड या सरप्लस बजट नहीं बना सकता। फिर भी हम जो अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एचीवमेन्ट्स की तारीफ करने की दृष्टि से या क्रिटिसिज्म की दृष्टि से देखें तो इतना जरूर है कि हमको अपने क्रिटिसिज्म या एप्रीशियेशन में सीमित रहना पड़ेगा। यह स्टेचुटेरी बोर्ड सन् १९५७ में कायम हुआ था, फिर भी उसके जो एचीवमेन्ट्स हैं यदि उनके बेक ग्राउन्ड को देखें तो या तो एप्रिसियेशन कर सकते हैं या क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। वह बेक ग्राउन्ड है फर्स्ट फाइव इयर प्लान। जब तक हम फर्स्ट

(श्री श्रीभानसिंह)

फाइव इयर प्लान को सामने नहीं रखते तब तक न हम इसकी तारीफ कर सकते हैं और न इसका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं।

जब राजस्थान बना था उस टाइम पर जो कि हमारे २४ पॉवर हाउसेज़ थे उनकी दशा किसी भी माननीय सदस्य से छिपी हुई नहीं है। कहीं पर पुराने इंजिन थे जो ब्रेक डाउन हो रहे थे, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी की इरेगुलर सप्लाई थी। उसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान में जो पॉवर पोजिशन या विद्युत की स्थिति थी वह बहुत खराब थी, अच्छी नहीं थी। फिर भी यह कहा गया कि फर्स्ट प्लान में राजस्थान सरकार ने कुछ तरक्की की, मैं इसको कतई मानने को तैयार नहीं हूं। राजस्थान सरकार ने फर्स्ट फाइव इयर प्लान में कोई २८८.०६६ लाख रु० इलेक्ट्रिसिटी या पॉवर के लिये एलॉट किये थे उन में से १६.६ लाख रु० फर्स्ट प्लान में खर्च किये गये। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये ११६.०५६ रु० रखे थे और अर्बन के लिये ११६.५६ लाख एलॉट किये थे उनमें से केवल ३ लाख रु० ही खर्च कर सके। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट प्लान में हमने पॉवर को प्रायोरिटि नहीं दी और पॉवर को प्रायोरटी दे भी नहीं सकते थे क्योंकि सबसे पहले एग्रीकल्चर को रीहेबिलिटेट करना था। जब तक एग्रीकल्चर रीहेबिलिटेट नहीं हो जाता तब तक हम किसी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते थे और जितने फंड्स एलोटेड थे उनको खर्च नहीं कर सकते थे। सन् ५७ में जब बोर्ड की स्थापना हुई तब तक राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी की वही हालत थी जो प्री-मरजर थी या प्री-प्लान थी। जब बोर्ड ने टेक ओवर किया तो उसने विद्युत की हालत में इम्प्रूवमेन्ट किया। मैं सभी पॉवर हाउसेज के बारे में तो नहीं बता सकता लेकिन कुछ के आंकड़े हैं उनसे सेटिस्फाइड होंगे कि बोर्ड के गवर्नमेंन्ट या रिनोवेट करने का कार्य था वह काफी तारीफ लायक था।

बिफोर इन्टीग्रेशन जयपुर का पॉवर हाउस ३,६८५ किलोवाट्स बिजली जनरेट करता था। उसको बोर्ड ने १०,५०० तक कर दिया। जोधपुर में २,८०० किलोवाट इलेक्ट्रिसिटि जनरेट होती थी उसके बजाय ४,५०० किलोवाट तक पहुंचा दी। टोंक में इन्टीग्रेशन से पहले १७५ किलोवाट होती थी, बोर्ड ने ५७ में ५८० किलोवाट कर दिया। भीलवाड़ा में १४७ किलोवाट बिजली जनरेट होती थी लेकिन बोर्ड ने १,१४० तक पहुँचा दिया। हम यह नहीं कह सकते कि चार साल के दौरान में बोर्ड ने बिल्कुल कार्य नहीं किया। यह जो रेटेड केपेसिटी ओल्ड पॉवर हाउसेज़ की थी उसको बोर्ड ने इम्प्रूव किया यह तारीफ लायक कार्य है और जब हम यह देखें कि फर्स्ट फाइव इयर प्लान में जिस जेलसनैस और सीरियसनैस से राजस्थान गवर्नमेंट को पॉवर प्रोब्लम को टेकल करना चाहिये था उस सीरियसनैस से नहीं किया और बोर्ड के निर्माण के बाद उसने जो कार्य किया उसके फिगर्स आपके सामने हैं। यही नहीं, इस बोर्ड का निर्माण सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में हुआ। सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के विद्युत के बारे में राजस्थान के लिये क्या? टार्गेट्स थे और उनको कहां तक एचीव किया जो अगर बोर्ड टार्गेट्स को एचीव नहीं कर सका तो कहना पड़ेगा कि बोर्ड की प्रगति ठीक नहीं है। जो अगर सेकिन्ड फाइव इयर

(श्री श्रीभानसिंह)

प्लान के टार्गेट बोर्ड ने एचीव किये हैं तो फिर यह कह कर उसको न डाउन करना कि उसमें करप्शन है, फेवरेटिज्म है, ठीक नहीं है। फेवरेटिज्म एक तरह से जनरल नेचर है, ह्यूमन नेचर है। कोई ऑफिसर फेवरेटिज्म करता है उस पर यह कहदें कि सारा बोर्ड ही खराब है तो यह ठीक नहीं होगा।

सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के टार्गेट्स थरमल पॉवर के २२,००० किलो वाट्स के थे और डिज़ल के ६,१४५ और हाइड्रल के ६६,००० किलो वाट्स के थे। मैं रफली ये फिगर्स बता रहा हूं। ये तीनों तरह के टार्गेट्स कायम किये गये थे। बोर्ड के टार्गेट्स को इसी दृष्टि से देखना पड़ेगा और बोर्ड ने बजट भी इसी दृष्टि से बनाया है। अंडर स्टीम उसने कहां तक एचीव किया, अंडर डिजल कहां तक एचीव किया है और अंडर हाइड्रल कहां तक एचीव किया है और उसमें जो शोर्ट फाल हैं, एचीव नहीं करने के कारण वे कहां तक हैं ? जो टार्गेट्स कायम किये हैं उनको एचीव नहीं किया है तो हम यह कह सकते हैं कि उसका काम सेटिस्फेक्ट्री नहीं है और जो अगर कर लिया है तो कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्ट्री है। थरमल या अंडर स्टीम पॉवर का टार्गेट २२,००० किलो वाट्स का रखा था। इसके बारे में मुझे कहना पड़ेगा कि बोर्ड का एचीवमेंट तारीफ लायक नहीं है और यह उनको पूरा नहीं कर सकता है। ५६–६० तक बोर्ड ने सिर्फ ५,००० किलोवाट का फिगर एचीव किया है। ८ हजार किलोवाट बोर्ड को जयपुर में करना चाहिये था उसके बजाय ३ हजार ही कर पाया है। २ हजार कोटा में किया है। २२,००० में से अब तक ५६–६० तक सिर्फ ५ हजार किलो वाट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है। इन फिगर्स को देखते हुए जहां तक थरमल स्टीम पॉवर पर खर्चा किया है वह खर्चा और प्रगति तारीफ लायक नहीं है। कहा यह जाता है कि राजस्थान में १८ या २४ या ३२ पॉवर स्टेशन्स है उनमें से बहुत सी जगह ट्रान्सफोर्मेशन लाइन्स लग रही हैं, कार्य में प्रगति हो रही है। हम देखें तो २४ पॉवर स्टेशन्स में से १४ ऐसे हैं जिन पर शायद अब तक स्पेड वर्क हुआ है और उसको हम यह लेकर चलें कि बोर्ड ने प्रगति की है, शायद ६० के एन्ड तक या एन्ड ऑफ दि प्लान पीरियड तक स्टीम का टार्गेट एचीव कर सके, तो मैं इतना ऑपटिमिस्टिक नहीं हूं क्योंकि ३ साल में ५ हजार किलोवाट ही कर पाये हैं तो रेस्ट २२,००० किलोवाट का टार्गेट किसी भी हालत में इस टाइम तक एचीव नहीं कर सकते। इस ओर बोर्ड को ध्यान देना पड़ेगा, चाहे पर्सनल इन्क्रीज करने पडें, चाहे खर्चा ज्यादा करना पड़े, चाहे किसी भी तरह से तेजी लाने के लिये कोशिश करनी पड़े तो करनी होगी और थरमल जनरेट करने को तेज करना पड़ेगा। डिजल का टार्गेट ६,१४५ किलोवाट का है। जहां थरमल पॉवर स्टेशन्स का कंस्ट्रेक्शन हो रहा है वहां डिजल का भी हो रहा है। अब तक डिजल में ५ हजार का टार्गेट एचीव किया है। लेकिन इसमें भी बहुत से ऐसे हैं जिनमें अब तक कंस्ट्रेक्शन वर्क चल रहा है। उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि जनरेट करने का काम या कमीशान शुरू हो गया है। जब तक थरमल और डिजल का २८,००० किलोवाट्स का टार्गेट पूरा नहीं हो जाता या जब तक एक्च्युअल

Page No.45

(श्री श्रीमानसिंह)

कमीशन नहीं हो जावे तब तक नहीं कहा जा सकता कि इतना एचीवमेंट कर लिया है। दुर्भाग्य यह है कि अब तक वर्क भी एक्सटेन्ड नहीं हुआ है। बोर्ड के टार्गेट्स को देखते हैं तो उससे डिससेटिसफाइ होना पड़ेगा।

तीसरी बात बोर्ड की प्रगति की है, हाइडल वर्क की। हाइडल वर्क्स पर आने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि कई म्युनिसिपैलिटीज़ के भी बिहाफ पर बोर्ड वर्क अंडरटेक करता है। जहां तक मेरी सूचना बोर्ड ने ५ म्युनिसिपैलिटीज़ के बिहाफ पर वर्क अंडरटेक किया है। लेकिन दुर्भाग्य से अब तक सिर्फ २ म्युनिसिपैलिटीज़ का वर्क कम्पलीट कर पाया है। तो जो म्युनिसिपैलिटीज बोर्ड को एन्ट्रस्ट करती हैं अपने वर्क्स से, उन म्युनिसिपैलिटीज के वर्क को बोर्ड कम्पलीट नहीं कर सका। तो म्युनिसिपैलिटीज की क्या हालत होगी, वे क्या अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी को पीपुल के प्रति निभा रही हैं, यह नहीं कहा जा सकता। वे हर दफा रिमाइन्डर भेजती हैं। तो तीन म्युनिसिपैलिटीज के वर्क कम्प्लीट नहीं होने-वाले हैं। यह सोचने की बात है। फिर भी हम देखें कि राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी टोटल ६२,४४० किलोवाट हाइडल पॉवर से जनरेट होगी। वह चम्बल और भाखरा दोनों की है। भाखरा की १६,४३७ किलोवाट और चम्बल की ४६,००० किलोवाट राजस्थान के शेअर में आने की है। अब जहां तक चम्बल का प्रश्न है, अभी तक राजस्थान सरकार ४,६०० किलोवाट युटिलाइज कर पाई है और जो युटिलाइज की है वह गंगानगर में की है। हम राजस्थान, वेस्ट राजस्थान, नार्थ वेस्ट राजस्थान के लिए कहें कि उनका मेन स्टे इलेक्ट्रिक पॉवर पर है, वह भाखरा पर है। जब तक भाखरा से पॉवर नहीं पहुंचेगी तब तक ये टाउन डवेलप नहीं हो सकते। शायद राजस्थान के छः डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर भाखरा की पॉवर जायेगी। ५८ टाउन्स, रूरल और अर्बन एरियाज के अबाउट ५८ टाउन्स हैं, उनको यह इफेक्ट करेगी। तो छः डिस्ट्रिक्ट्स, ५८ प्लेसेज का डवेलपमेंट भाखरा पॉवर पर निर्भर है और अभी तक भाखरा पॉवर के पहुँचने की कोई उम्मीद नहीं है। राजगढ़ के लिए कहा जाता है कि १९६० के एन्ड तक बिजली आ जायेगी। let us hope इस समय तक शायद वहां बिजली आ जाय। लेकिन राजगढ़ तक ही बिजली को रोकना ठीक नहीं है। रतनगढ़ को बिजली देना असेन्सियल है। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में जो छोटी छोटी जगह हैं उनमें से कितने ही टाउन्स रतनगढ़ से कनेक्टेड हैं। जब यह कहते हैं कि बीकानेर पॉवर हाउस है उसकी कन्डीशन बहुत खराब है, वह डेटीरियोरेट हो गया है, उसका एक इंजिन तो ब्रेक-डाउन हो गया है तब यह असेन्सियल हो जाता है कि रतनगढ़ को टोप प्रायोरिटी देकर पॉवर सप्लाई करें। तो भाखरा पॉवर की जो प्रगति है उसको देखें तो इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है पर हाप-फुल जरूर है। तो जब यह सब देखते हैं तो जिस बोर्ड का निर्माण हुआ है उस बोर्ड को यहां ही ब्रेक नहीं करना है। जैसा कि कहा जाता है कि भाखरा के राइट बैंक का पॉवर हाउस कन्स्ट्रेक्ट होगा फोर्थ, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसमें भी राजस्थान का शेअर है वह २८,००० किलोवाट है। यह राजस्थान के शेअर भाखरा के राइट बैंक के पॉवर हाउस से आयेगा। तो जब राजस्थान का जो १६,००० किलोवाट का शेअर था जनरेटेड

(श्री श्रीभानसिंह)

इलेक्ट्रिसिटी में यह जो शेअर है इसमें से तीन साल, चार साल, पांच साल के अन्दर केवल ४,६०० किलोवाट युटिलाइज कर सकें, तो जहां अभी २८,००० किलोवाट को युटिलाइज करने के लिए अभी ग्राउन्ड वर्क, स्पेड वर्क शुरू नहीं किया है तो आगे भी हम उतने ही पीछे रह जायेंगे। २८,००० किलोवाट को यूटिलाइज करने में जितने कि १६,००० किलोवाट को युटिलाइज करने में रहे हैं। फ्यूचर में जो २८,००० किलोवाट बिजली जनरेट होने को है उसको यूटिलाइज करने के लिए अभी से कोशिश करेंगे तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी दे पायेंगे और कुछ उम्मीद रहेगी यूटिलाइज करने के लिए। सेकिंड हाइडल वर्क चम्बल का है। चम्बल से ३७,००० किलोवाट बिजली, जो शायद तीन यूनिटस से जनरेट होने को है उसमें से राजस्थान का शेअर ३७,००० किलोवाट आयेगा और अपन प्लान के मुताबिक इसको युटिलाइज करना है चार ट्रान्सफोरमर लाइन्स को इरेक्ट करके पहली लाइन होगी गांधीसागर से सवाई माधोपुर तक, दूसरी लाइन होगी सवाई माधोपुर से जयपुर तक, तीसरी लाइन होगी कोटा से अजमेर तक और चौथी लाइन होगी नीमच से उदयपुर तक। ये चार [illegible] सारी लाइन सेकिंड फाइव इयर प्लान [illegible] अन्दर कम्पलीट होनी थी। इनमें से [illegible] जो प्रायोरिटी दी थी वह गांधीसागर [illegible] सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर से [illegible]पुर तक की लाइन को। फिर भी जयपुर [illegible] सवाई माधोपुर लाइन का थोड़ा वर्क शुरू [illegible] मगर जो मेन लाइन है गांधीसागर [illegible] सवाई माधोपुर तक वहां पर काम शुरू [illegible] हुआ है। कहा यह जाता है कि इसके अन्दर हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वह यह लिया है कि जो टावर्स हैं उनके लिए स्टील इम्पोर्ट करके किसी कम्पनी को दी जाय और वहां से टावर्स फेबरीकेट कराके उन्हें युटिलाइज किया जाय। मैं तो यह कहूंगा कि बोर्ड के पर्सनल सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इन्फ्लूएन्स नहीं कर सके, माननीय मंत्री महोदय सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इन्फ्लूएन्स नहीं कर सके कि वह अपने डिसीजन को चेंज कर दे। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि ३७,००० किलोवाट इलेक्ट्रिक राजस्थान में सेकिंड फाइव इयर प्लान के अन्दर अन्दर जनरेट होगी और सेकिंड फाइव इयर प्लान के एन्ड तक २८,००० किलोवाट ओब्सोलीट हो जायगी, अनइकॉनोमिक हो जायेगी और २८,००० किलोवाट युटिलाइज करने के लिए दूसरी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बेकवार्ड है। २८,००० किलोवाट बिजली ओब्सोलीट हो जायेगी, और इन-इकानोमिक हो जायगी, उसको रिप्लेस करने के लिए राजस्थान के ऊपर जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी लागू की है उसे लागू करना चाहिए मध्य प्रदेश पर या पंजाब पर क्योंकि राजस्थान को उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, पॉवर डिस्ट्रिब्यूसन की उतनी जरूरत है जिसके लिए कहा जाय that they are on their road to decay and death; तो इस स्टेट को सेन्ट्रल गवर्नमेंट प्रयोरिटी न दे, मगर यह कन्डीशन लागू करें। मैं वैसे लोकल इन्डस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं, मगर लोकल इन्डस्ट्री पॉवर की प्रोग्रेस को चेक करती है, और वह भी राजस्थान में चेक होगी और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश अपने टार्गेट्स

(श्री श्रीमानसिंह)

कम्प्लीट करे, पंजाब अपने टारगेट्स कम्प्लीट करे और राजस्थान के वास्ते यह रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि वह लोकल इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन दे । तो मैं इसके खिलाफ हूँ और चाहता हूं कि चाहे हमें टावर्स इटेलियन फार्म से मंगाने पड़े लेकिन हमें इसे इमीजियेट इम्पोर्टेन्स और प्रायोरिटी देकर इम्पोर्ट करना चाहिए और जो लोकेली टावर्स फेब्रीकेट हों उनको डाइवर्ट कर दिया जाय मध्य प्रदेश और पंजाब को । तो जो डिसीजन किया गया है उसको रिवर्स करने की जरूरत है ।

अब यह देखें कि चम्बल की प्रगति ठीक है या नहीं ? मैं आपको बताऊं कि बहुत सी चीज़ों के ऑर्डर प्लेस कर दिये और बहुत सी चीज़ों के ऑर्डर प्लेस नहीं किये और इसके साथ ही कहा जाता है कि बोर्ड के अन्दर टेक्निकल पर्सनल हैं । जो चम्बल से पॉवर दी जायगी वह राजस्थान के इम्पोर्टेन्ट टाउन्स हैं उनको दी जायगी, कोटा जो इन्डस्ट्रीयली डवेलप्ड है, और होगा उसका फ्यूचर आप चेक नहीं कर सकते । इसके साथ ही मैं जयपुर, जयपुर और उदयपुर को लेता हूं । तो चारों ऐसे मेन सिटीज हैं जो इन्डस्ट्रीयल सिटीज़ हैं, उनमें इन्डस्ट्रीज़ डेवलप्ड हैं, माइनिंग पोटेन्सियलिटी ज्यादा है ! फिर भी यह पूछा जाय कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कि आखिर इन चारों की कितनी लोड रिक्वायरमेंट है, जिन पर्टीक्यूलर टाउन्स को सप्लाई करेंगे, उनकी लोड रिक्वायरमेंट क्या है, तो शायद बोर्ड नहीं बता सकेगा, क्योंकि उसने वर्क आउट नहीं किया कि पर्टीक्यूलर टाउन को इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हैं उसकी लोड रिक्वायरमेंट क्या है । और इन्डस्ट्रीज़ का डवेलपमेंट करने के लिए पहले से क्वान्टिटी ऑफ पावर, क्वान्टम ऑफ पावर के लिए पहले घोषित कर दें कि हम इतनी इलेक्ट्रिक इस लो रेट पर देंगे तो उससे इन्डस्ट्रियलिस्ट अट्रेक्ट नहीं होंगे । वे तब अट्रेक्ट होंगे जब यह गारन्टी होगी कि पर्टीक्यूलर इन्डस्ट्री को जितनी इलेक्ट्रिक अनर्जी की जरूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है वह पर्टीक्यूलर प्राइस पर मिल जायगी । अभी तक जो इलेक्ट्रिसिटी उदयपुर में दे रहे हैं वहां वर्क आउट नहीं किया है और अगर वर्क आउट नहीं किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्रीजी जो जिंक स्पेल्टर प्लान्ट लगाने जा रहे हैं वह एक स्वप्न या ड्रीम न रह जाय क्योंकि कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहेगी, कितनी एक्चुअली जनरेट होगी, कितनी कन्ज्यूम होगी, कितनी इन्डस्ट्री की सप्लाई होगी; यह सब बोर्ड ने राजस्थान के पर्टिक्यूलर प्लेसेज़ में वर्क आउट नहीं किया है और जब तक हम पर्टिक्यूलर केसेज़ के लोड वर्क आउट नहीं करेंगे तब तक चम्बल प्रोजेक्ट से पूरा नहीं होने वाला है । लोड रिक्वायरमेंट्स वर्क आउट करना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसा न हो कि उदयपुर का कोटे का लोड रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाय और फिर कहा जाय कि लाइन को चेंज किया जाय, मोडिफाई किया जाय, और टॉवर्स हमें बाहर से मंगानी हैं । लोंग टर्म प्लानिंग कर दें तो भविष्य में जो फॉरिन एक्सचेन्ज हम खर्च करने जा रहे हैं उसको सेव कर लेंगे ।

अन्त में, मैं एक्सपेन्डीचर साइड की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं एक्सपेन्डीचर साइड का पिक्चर है उस के लिये यह कहा

(श्री श्रीमानसिंह)

जाय कि it is in keeping with the times है तो जिस तरह हाइडल पॉवर में, थरमल में पीछे हैं, डीज़ल में कमिशन्स को नहीं कर सके, इसी तरह एक्सपेन्डीचर साइड का खर्चा करने में बहुत ज्यादा कमी है। सबसे बड़ा ताज्जुब तो होता है इस बात को देख कर कि टोटल प्लान एस्टीमेट है बोर्ड का वह तीन पहले सालों में तो खर्च नहीं कर सके। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में भी प्रगति बहुत कम है। एक्सपेन्डीचर साइड में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का कहते हैं तो यह एक मिस्नोमर है। हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि किस रूरल एरिया को इलेक्ट्रिफाई करने जा रहे हैं। नागोर, जालोर, झुंझुनूं रूरल एरिया हैं; पर मैं उसे क्वाज़ी अर्बन एरिया कहता हूं। रूरल एरिया में जालोर, नागोर, झुंझुनूं, मालपुरा, टोडा भीम आता है; पर है वास्तव में वह क्वाज़ी अर्बन एरिया। रूरल अर्बन एरिया को इलेक्ट्रिफाई करना चाहते हैं तो डीग के लिये ३ लाख रुपया रखा है भरतपुर से कनेक्ट करने के लिये। डीग से नगर को कनेक्ट करना चाहिये। वह रूरल एरिया है उसको कनेक्ट करना चाहिये। एक्सपेन्डीचर साइड में पांच-दस करोड़ की बचत रहेगी उस सेविंग को आपको युटिलाइज इधर करना चाहिये। यही नहीं, हम डिमान्ड करते आये हैं कि भरतपुर से बयाना को कनेक्ट किया जाय, वहां स्टोन क्वेरीज़ हैं और पोटेन्शियेलिटी नागोर, जालोर, सिरोही से ज्यादा है; इसलिये इसको कनेक्ट करना चाहिये।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि बोर्ड का ४ साल का वर्क है वह सेटिस्फेक्टरी है। यों सेटिस्फेक्टरी है कि बोर्ड ने टार्गेट्स की तरफ स्टेप्स लिये हैं। इसमें जो शोर्टफाल नजर आता है वह यों आता है कि इसको एक्स्टर्नल करेंसीज़ ने चैक किया है, वह तो फॉरिन एक्सचेंज की कमी है, इससे रुकावट आई पर यह क्राइसिस हट जायेगा और सैक्स का हटा देंगे तो मैं आशा करता हूं कि बोर्ड की प्रगति बढ़ जायेगी।

एक सूचना मुझे मिली है, शायद निराधार हो; पर मैं कहना चाहता हूं कि बोर्ड की प्रगति को रखना चाहते हैं तो इस बोर्ड में रामजी काक को नोमिनेट करने की बात चल रही है, वह मत करिये....

(हंसी)

माननीय उप-मंत्री और विद्युत मंत्री श्यामी किटम्स की ओर ले गये हैं कि आप कितने इन्ट्रेस्टेड हैं। बोर्ड की प्रगति को रोकना हो तो ऐसा नोमिनेशन करें, बोर्ड से ऑनेस्टी, इन्टीग्रिटी और एफिशियेन्सी को हटाना है तो ऐसा करें। जो अगर बोर्ड से वर्क और रिजल्ट लेना है तो आपको ऐसे आदमियों से बोर्ड को दूर रखना चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : डॉ॰ बहादुरसिंह।

डॉ॰ बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, आज राजस्थान विद्युत मंडल का १९६०–६१ का आय–व्ययक हमारे सामने प्रस्तुत है। मैं इस सम्बन्ध में, और खास

(डॉ० बहादुरसिंह)

करके विद्युत मंडल के सेक्रेटेरियेट के खर्च के बारे में निवेदन करना चाहूँगा। जबकि विद्युत मंडल का पिछले साल का बजट आया था तो आलोचना की गई थी कि चीफ इन्जीनियर के ऑफिस का खर्चा बोर्ड के सेक्रेटेरियेट के बराबर पड़ रहा है। इसमें दो राय नहीं कि हमारा बोर्ड घाटे में चल रहा है। पिछले बजट को देखें तो ५ लाख से ऊपर का घाटा था और इस साल ११ लाख का रहा है। पर जब हमारा बोर्ड घाटे में है तो हमें यह देखना है कि घाटे के कारण क्या हैं ? विशेष कर बोर्ड बनाया गया। बोर्ड बनाने का कारण यह था कि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार सोचा कि स्टेट के पॉवर हाउसेज थे उनकी हालत खराब थी इसलिए कॉमर्शियल बेसिस पर इस बोर्ड की स्थापना की। जो व्यापारिक चीजें हों उनमें घाटा हो तो इस इस प्रकार की कन्सर्न कभी चल नहीं सकती। केन्द्र में रेलवे है और वह अच्छा सोर्स इन्कम का है। उसी प्रकार राजस्थान में विद्युत मंडल बनाया तो हमें अच्छी खासा आमदनी होगी, इस इरादे से बनाया। पर इसमें घाटा हो रहा है। लॉसेज के कारणों को देखें तो मालूम होगा कि हमें किन किन खराबियों के कारण घाटा पड़ता है। विद्युत मंडल के सदस्यों के भत्ते को देखें तो ५६,००० पिछले साल आया था और ७६,००० इस साल देंगे। बोर्ड के सचिवालय का ७,४६,००० का खर्चा था वहीं ६,६६,००० इस साल कर दिया है। ब्रेक-अप आपने ४ लाख की जगह ६ लाख कर दिया है। इस तरह हमारा ५ लाख का खर्चा बढ़ा दिया है। घाटा होते हुए बोर्ड में ही ५ लाख और बढ़ा दिये हैं।

हमारे विभागों में ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट कायम कर दिया जाता है तो काफी अच्छा लवाजमा खड़ा कर दिया जाता है। चीफ इन्जीनियर ऑफिस में कुछ कम किये हैं पर एक चीफ इन्जीनियर और बढ़ाने का ६१–६२ में प्रावधान किया है। बोर्ड का सेक्रेटेरियेट है उसमें ३४ पोस्ट्स हैं उनमें १७ फिर वृद्धि करने जा रहे हैं। इस तरह हमारे बोर्ड का ढांचा बराबर बढ़ता जा रहा है। एक जगह ऑफिस सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर बनाया। हमने फर्स्ट ग्रेड ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट रखा। अब बढ़ा रहे हैं सेकिन्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड बढ़ा रहे हैं, मीटर इन्सपेक्टर्स, सेंट्रल मीटर ट्रेनिंग लेबोरेटरीज़ स्टाफ था, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर था इसके बाद बहुत सारा स्टाफ बढ़ा दिया है। इस तरह हमारे बोर्ड का खर्चा बराबर बढ़ा और लॉस रहा है। इन बराबर बातों को देखने के लिये हमें बोर्ड की स्थिति पर विचार करना चाहिये।

मैं इस चीज़ का हामी हूं : हमारा एक आदमी काम करे तो बोर्ड का काम व्यापारिक दृष्टिकोण से करना चाहिये, इस प्रकार से न करें कि जिस प्रकार हमारा खैरती विभाग है। कितना लॉस हुआ है इस पर विचार नहीं किया है।

अब मैं पावर हाउसेज़ की स्थिति बताऊं तो ताज्जुब करेंगे। भाखरा नांगल को छोड़ दीजिये। दूसरे २४ पॉवर हाउसेज़ हैं। केवल ६ या ७ पॉवर हाउसेज़ में प्रोफिट है, बाकी सब लोस में हैं। जो प्रोफिट में हैं उनमें से खुशकिस्मती से मेरा एक पॉवर हाउस है...

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): आपका ?

डॉ० बहादुरसिंह : मेरा खुद का नहीं, धौलपुर का पॉवर हाउस है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलवर, भरतपुर, जयपुर, फलोदी और सवाई माधोपुर आदि कुछ ही पॉवर हाउसेज़ हैं जो मुनाफा देते हैं। बाकी सब पॉवर हाउसेज़ लोस के पॉवर हाउस हैं। अगर आप बीकानेर के पॉवर हाउस की स्थिति देखें तो आपको मालूम होगा कि बीकानेर पॉवर हाउस में जहां २१ लाख की आमदनी है वहां पर ३४ लाख का खर्चा है, यानि वहां पर करीब १२ लाख का घाटा। यानि सारा जयपुर का मुनाफा बीकानेर के घाटे में खत्म हो जाता है। आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि :

चित्तौड़ में २० हजार का घाटा

डूंगरपुर में १ लाख ७३ हजार का खर्चा और १ लाख, ६ हजार की आमदनी; तो इसमें भी ६६ हजार का लोस।

मैं यह कहूंगा कि कोई भी व्यापारी भारतवर्ष में जो व्यापार करता है कभी भी यह पसन्द नहीं करता कि उनको मुनाफा कुछ नहीं हो। मैं आपको आपके यहां ऐसे ऐसे पॉवर हाउसेज़ बताऊंगा जैसे नागोर का पॉवर हाउस है। उसकी आमदनी है ८०० रुपये और उस पर खर्चा है ५,३४० रुपये। जहां कम से कम १०० रुपये की इन्कम हो वहां पर पॉवर हाउस चलने चाहिये मगर जहां १०० की आमदनी और खर्चा ५०० से ऊपर हो तो वहां पर पॉवर हाउस रखना कहां तक उचित होगा? इसी तरह भीलवाड़ा का है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पॉवर हाउसेज़ हैं और घाटे में चलते हैं उनको बन्द कर देना चाहिये और जब वहां पर ऐसी स्थिति आ जाए कि घाटा नहीं रहेगा तो वे चालू कर दिये जावें। दूसरी ओर हम यह देखते हैं कि धौलपुर में १६ हजार का प्रोफिट पॉवर हाउस दे रहा है अगर इसको और बढ़ाया जावे तो यह बहुत दूर तक बिजली दे सकता है और इससे २ लाख या ३ लाख तक की आमदनी प्राप्त हो सकती है। अगर आप इस पॉवर हाउस की स्थिति देखें तो आपको मालूम होगा कि ग्लास फैक्ट्री के द्वारा जो पॉवर हाउस चल रहा है उसके बराबर बन सकता है। अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान दे तो अधिक पैसा कमाया जा जा सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ५० हजार की आमदनी हो सकती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उससे ५० हजार से ज्यादा का मुनाफा हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेकर यही निवेदन करना चाहता हूं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो विद्युत बोर्ड को सदन में आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिये थे कि कितने लोगों में कितने पैसे बाकी हैं। कोई भी कम्पनी जिसका बजट हमारे सामने हो तो इस बात का हमें मालूम रहना चाहिये कि कितनी रकम दूसरे व्यक्तियों में बकाया है, यह नहीं बता सकते हैं। मैं आपको किसी का नाम तो नहीं बताना चाहता लेकिन सदन के एक माननीय सदस्य हैं उनमें १३ हजार रुपये बाकी हैं। उनके खिलाफ डी. पी. आर. की कार्यवाही की जाती है तो उसको रोक देते हैं और दबा देते हैं और रुपया वसूल नहीं कर पाते। इस प्रकार से व्यापार नहीं चल सकता है। आपको करोड़ों रुपये इसके लिये चाहिये और आपका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि

(डॉ० बहादुरसिंह)

आपने उन लोगों को जो बिजली दी है उनके रुपये वसूल करने चाहिये। जो आप नहीं कर रहे हैं और इस तरह से हमारे बहुत से रुपये लोगों में बाकी हैं और जब हम ११ लाख के लॉस में हैं तो हमें वह रकम वसूल करनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या विद्युत मंडल इस तरह चुप रह कर सफल हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त यह भी संभव नहीं कि राजस्थान की पब्लिक पर आप बार बार टैक्स लगाते रहें और जिनमें रुपये हैं उनसे वसूल न करें। इसलिए ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करूंगा कि हमको सदन में सबसे पहले यह बताना चाहिये कि इतने रुपये बाकी हैं और इतने वसूल कर सकते हैं। आपके पास इस प्रकार की लिस्ट नहीं और जब आपके पास लिस्ट तैयार नहीं तो आप किस प्रकार से आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं? पिछली दफा मैंने आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए प्रश्न किया था। आज वे आंकड़े उपलब्ध होते तो ज्यादा अच्छा रहता। और माननीय मंत्री महोदय बताते कि हम किस तरह से बकाया रकम को वसूल कर सकते हैं।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री महोदय से धौलपुर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर से पॉवर हाउस की लाइन बाडी ले गये। वहां पर आप एक छोटा पॉवर हाउस या डीजल–सेट लगादें तो इससे अच्छी आमदनी हो सकती है क्योंकि इस इलाके में अच्छी मंडी है। यह नहीं कि धौलपुर में १०४ का युनिट लगा दें और आप यह चाहें कि इन्डस्ट्रीज की बिजली दी जावे और मुनाफा कमाया जावे, यह तो संभव नहीं है। मेरे पास जो लिस्ट मौजूद है उसको देखने से मालूम होगा कि आपके यहां कुल ७ पॉवर हाउस ही ऐसे हैं जो आपको मुनाफा देते हैं और यह मुनाफा दूसरों में खत्म हो जाता है। अगर यही रहा तो विद्युत बोर्ड सफल नहीं हो सकता।

अब मैं यह निवेदन करूंगा कि विद्युत बोर्ड में आदमियों को बढ़ाने की व्यवस्था की है उसके लिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम स्थानों की वृद्धि की जावे जिससे बोर्ड का खर्चा कम करके आमदनी का सीगा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। अगर राजस्थान विद्युत मंडल की आमदनी और खर्चा बराबर होता तो भी मुझे बड़ी खुशी होती कि विद्युत मंडल ने तरक्की की है।

अब मैं आपको लेबर के संबन्ध में कुछ अर्ज कर दूं। यह तजुर्बा मुझे अपने यहां के पॉवर हाउस का है। हम समझते हैं कि जिस समय यह राज्य सरकार द्वारा चलते थे वहां के मजदूर खुशहाल थे। जिस समय राजस्थान विद्युत मंडल बना और यह कार्य भार संभाला तो उल्टे लोगों की हालत खराब हो गई। वह क्यों हुई इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं? कि यह आपके इन्जिनियर की वजह से। उनका व्यवहार बहुत खराब है। मजदूरों के समय उनका व्यवहार इतना खराब है और अगर आप इस समय जावें तो आपको मालूम होगा कि उनका क्या हाल है। वे निश्चित रूप से आपको शराब के नशे में मिलेंगे।

१.४ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वे आपको होश में नहीं मिलेंगे। वे किस

(डॉ० बहादुरसिंह)

प्रकार से मजदूरों के साथ व्यवहार करते हैं क्योंकि वे होश में नहीं होते । मजदूरों को किस तरह से तंग किया जाता है? किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, नहीं किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन मजदूरों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना चाहिये जिनसे हम पॉवर हाउस में काम लेकर मुनाफा उठाना चाहते हैं। मगर आपका इन्जीनियर जो हर समय नशे में रहता है और मजदूरों के साथ बुरा व्यवहार करता है, किस प्रकार से सफल होंगे? मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमें मजदूरों से काम लेना है तो हमेशा मजदूरों के हित में सोचना चाहिये और उनको जितनी राहत देनी चाहिये। इस प्रकार के इंजीनियर को तत्काल छुट्टी देनी। चाहिए अगर उस इंजीनियर को छुट्टी नहीं दे सकते तो मजदूरों को राहत देने के लिये कोई न कोई इन्तजाम करना चाहिये। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनके लिए लेबर वैलफेअर की कोई व्यवस्था नहीं है । आप इसके लिये कहेंगे कि इस कार्य को लेबर वैलफेअर करेगा। मैं यह कहूंगा कि करोड़ों रुपयों का खर्चा होता है तो वहां पर इसके लिए भी लेबर वैलफेअर पर कुछ खर्च करने की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे वहां मजदूरों के लिए ऐसे कुछ कार्यक्रम हों जिनसे मजदूर अपने आपको यह कुछ महसूस करें कि विद्युत-मण्डल से जो इन्कम होगी वह हनने हित में होगी ।

मैंने दो तीन मुद्दे उठाये और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी माननीय मन्त्री महोदय उत्तर दें उस समय सदन को कम से कम इस बात से सूचित करें कि कितना रुपया लोगों में बाकी है और कितने बड़े-बड़े आइटम बाकी हैं और उनको वसूल करने के लिए कितने केसेज़ डी. पी. आर. में दिये गये हैं और वहां पर कितनी प्रगति हुई है। मैं यह समझता हूं कि सदन को इस सम्बन्ध में अन्धेरे में रखने की जरूरत नहीं। आपको ये सारी बातें सदन में लानी चाहिये कि इतना रुपया लोगों में बाकी है।

दूसरी बात यह कि विद्युत बोर्ड में सेक्रेटेरियेट में खर्चा बढ़ाया जा रहा है और १२ लाख के बजाय १७ लाख करने जा रहे हैं। आप ११ लाख के घाटे में हैं। इसलिये आपको चाहिये कि आप इन दोनों बातों के संबंध में सदन को संतोष करायें और अगर आप सदन को संतोष दिलाएंगे तो मैं समझता हूं कि यह विद्युत बोर्ड निश्चित रूप से सफल होगा और मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय विशेष रूप से इसका ध्यान रखेंगे कि कितना रुपया वसूल किया जाएगा और हमारा कितना खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन पर कम होने जा रहा है जिससे पॉवर हाउसेज की हालत सुधरे।

श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान विद्युत मंडल के आयव्यय के सम्बन्ध में विवाद के लिए बहुत कम समय निर्धारित किया गया है। यदि अधिक समय निर्धारित किया जाता तो इस विषय में काफी ब्यौरा प्रस्तुत किया जा सकता था, फिर भी सीमित समय में मैं कुछ चर्चा इस विषय में करना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : पत्र तो यहां पढ़ा नहीं जा सकेगा। उसमें से आप पॉइन्ट्स नोट

(श्री उपाध्यक्ष)

कर लें और उनके आधार पर आप भाषण दें तो यह उचित होगा।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की गांवों में काफी कमी है, खम्भे लग गये हैं लेकिन उनमें अभी तार नहीं खिचे गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : You will not read it.

श्री प्रभुलाल पुरोहित : उसके विषय में यही कहना है कि बजट स्पष्ट नहीं है। यह केवल रूप रेखा ही प्रकट करती है। मैं इस अन्धेरे के कारण बोर्ड को इसके लिए बधाई देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बधाई दे रहे हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड को !

कई माननीय सदस्य : ठीक है। देने दीजिये साहब, बधाई तो।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : यह बधाई तो अन्धेरे की है कार्यक्रम हो चुका है। इसके कारण कुछ बातों का अभाव बताया गया है। वास्तव में यह देखा जाय....

श्री उपाध्यक्ष : मेरी व्यवस्था है कि आप पढ़िये नहीं। हमारी परम्परा है यहां कि भाषण दिया जाय। नोट्स को रेफर कर सकते हैं। पढ़ने की इजाजत मैं नहीं दूंगा !

श्री प्रभुलाल पुरोहित : दौसा से लालसोट तक बिजली के खम्भे गाड़े, छ: वर्ष से अधिक का समय हो गया लेकिन उनमें तार नहीं खिचे गये हैं। बीकानेर से सीकर तक तो तार खींच दिये गये। वहां बगैर पॉवर के उन तारों की पहले यहां चोरी क्यों नहीं होती ? आश्वासन दिया गया था कि तुम्हारे यहां ५६–६० में बिजली लगा दी जावेगी लेकिन अब यह बताया गया है कि ६०, ६१ में बिजली दे दी जावेगी। लेकिन खम्भों पर तार खींचना तो अभी शुरू ही नहीं किया गया है। जनता को राज्य के इस अन्धेर को देख कर काफी परेशानी होती है। बजट की रकम भी कई वर्षों से लैप्स होती जा रही है। लेकिन अब तक वहां पर बिजली नहीं लगायी गयी है। बिजली से जनता को जो फायदा होना चाहिए था वह उससे वंचित है, नहीं हुआ। काश्तकार खेतों में अधिक उत्पादन करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। इससे काश्तकार महरूम रहे। इसमें करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है लेकिन वह गांवों की जनता के हित के लिए नहीं। केवल शहर वालों के आराम के लिए ही खर्च किया जाता है, बाहर की जनता के लिए नहीं किया जा रहा है। लाखों, करोड़ों की तादाद में गांवों से धन राशि ले ली जाती है लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं होता और केवल शहर वालों के हित के लिए बिजली का काम कराया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर बिजली की शीघ्र ही व्यवस्था की जावे। तुरन्त लाइन खेंची जावे, पॉवर के सब–स्टेशन का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जावे। गंगापुर में पॉवर हाउस के लोगों को बैठे तनख्वाह दी जाती है, लाखों रुपया इस तरह से दिया गया। वहां के लोगों को बिजली नहीं दी जा रही है पूरी तौर पर। इसलिये मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी बिजली दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम राजकीय विद्युत् मण्डल के वित्तीय-विवरण पर विचार कर रहे हैं । जैसा कि इस प्रतिवेदन से विदित है इस विद्युत मंडल की स्थापना सन् ५७ में हुई थी और इसकी स्थापना का कुछ औचित्य था । प्राय: हम सब लोग इस बात को अनुभव करते हैं कि राजस्थान के निर्माण के समय जहां जहां भी शक्ति साधन थे, पॉवर हाउसेज़ थे हर एक राज्य में अलग-अलग, उनकी अवस्था प्राय: अच्छी नहीं थी । राजस्थान बनने के बाद भी और विद्युत मंडल की स्थापना के पहले भी स्थिति प्राय: असंतोषजनक ही थी । एक, दो पॉवर हाउसेज को छोड़ कर, कोटा आदि को, प्राय: सब पॉवर हाउसेज घाटे में चल रहे थे और घाटे में चलने का कारण यह था कि उन पर खर्चा कुछ इस प्रकार से किया जाता था जो कि जितनी उनसे आय होती थी उससे अधिक खर्चा बढ़ जाता था । कोयला कितना, किस भाव से आता था आदि कितनी ही ऐसी अव्यवस्थायें थी जिनके कारण खर्चा बढ़ रहा था । साथ साथ खर्चा बढ़ने और आय कम होने का कारण यह भी था कि बहुत सा रुपया म्युनिसिपैलिटीज़ और दूसरी संस्थाओं और व्यक्तियों पर बाकी रहता था । जितना वसूल होना चाहिये था वह किसी न किसी कारण से वसूल नहीं हो पाता था । मैं समझता हूं, कुछ ऐसे ही कारणों से बाध्य होकर राज्य सरकार ने यह उचित समझा कि इसको एक राज्य के अन्य विभागों की भांति प्रशासनिक विभाग न रख कर सर्वथा स्वायत्त विभाग रखा जाय और उसमें राज्य का हस्तक्षेप कम हो । इस विचार को लेकर विद्युत मंडल की स्थापना हुई थी ! लेकिन अब तक जैसा कुछ कार्य रहा है और पिछले वर्षों और इस वर्ष भी जिस प्रकार इसकी आलोचना हुई है उससे प्रतीत होता है कि अभी विद्युत मंडल सफल नहीं हो पाया है, जितना होना चाहिये था ।

खास तौर पर शिकायतें इस सम्बन्ध में यह हैं कि खर्चा अधिक है और आय कम होती है । मैं समझता हूं कि किसी संस्था को व्यापारिक संस्था कहने का, कॉमर्शियल एन्टरप्राइज़ कहने का मतलब यह होता है कि यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि आय होती है उससे व्यय तो अधिक नहीं होता है । यदि किसी व्यापारिक संस्था में आय से अधिक व्यय होता हो तो आम तौर पर जो व्यापारिक लोग होते हैं वे यही कहेंगे कि उस संस्था और दूकान का दीवाला निकल गया । विद्युत मंडल से आशा है कि वह राजस्थान की प्रगति और विकास की ओर बढ़े । लेकिन अभी से अपने व्यय पर पूर्ण नियन्त्रण नहीं रखेगा तो आशंका है कि उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकेगा जिस उद्देश्य को लेकर यह स्थापित किया गया है । यह तो निश्चित है कि इस प्रकार के उद्योग होते हैं, जो विकासोन्मुख उद्योग हैं, निरन्तर बढ़नेवाले उद्योग हैं उनमें खर्चा भी निरन्तर बढ़ना चाहिये । लेकिन उस खर्चे का औचित्य अवश्य होना चाहिये । जैसे कतिपय माननीय सदस्यों ने प्रकट किया है कि हमारे एस्टेब्लिशमेन्ट में काफी खर्चा बढ़ता जा रहा है, स्टाफ बढ़ता है, सचिवालय में स्टाफ बढ़ा है, जगह जगह पॉवर हाउसेज़ हैं वहां भी स्टाफ बढ़ता जा रहा है । मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में प्रकाश डालेंगे कि

(श्री जुगलकीशोर चतुर्वेदी)

इतना खर्चा बढने का क्या कारण है? अधिकांश खर्चा होता जा रहा है तो उसके आय के साधन भी बढते जा रहे हैं या नहीं? यह जरूरी चीज़ है जो करनी चाहिये।

यह बिजली विभाग है। इसके खास तौर पर दो उद्देश्य हैं। एक तो, सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य यह है कि जनता की जितनी आवश्यकतायें हैं आज बिजली हमारे देश के लिए, अनविकसित देश के लिए सबसे आवश्यक है। हमारे प्रधान मंत्री भी विकास के लिए सबसे आवश्यक इन चीजों को मानते हैं बिजली, स्टील, फौलाद–ऐसी चीजें हैं। तो बिजली हमारे देश के लिये जरूरी है, न केवल इसलिये कि हमारे घरों के अन्दर प्रकाश हो या हवा पैदा करे बल्कि इसलिये आवश्यक है कि कुओं से किसानों को पानी उपलब्ध हो सके, हमारे छोटे बड़े उद्योगों के लिये बिजली का प्राप्त होना नितान्त आवश्यक है। बिजली एक ऐसी चीज़ है जो जितनी सस्ती बनाई जायगी उतना ही इसका प्रयोग सुगमता से हो सकेगा। इस दिशा की ओर विद्युतमंडल ने कार्य किया है या प्रगति की है? तो उसे चाहिये कि वह बतावें और उसको बताना उनका कर्त्तव्य है। आज जरूरत इस बात की है कि हम इसमें खर्चा इस प्रकार से करें जिससे हमारा आय और व्यय सन्तुलित हो सके। आज हम देखते हैं कि हमारा प्रशासनिक व्यय निरन्तर बढता जाता है, उसके अनुपात से आय हमारी कम है। जहां तक व्यापारिक संस्थान का प्रश्न है इसमें आय और व्यय का बराबर सन्तुलन होना चाहिये। इसके लिये जो खर्चे इस प्रकार के हैं जो प्रोडक्टिव नहीं हैं उन खर्चों में अवश्य कमी करनी चाहिये। सब से बड़ी चीज जो आवश्यक है वह यह है कि हमारे ड्यूज बहुत बाकी हैं इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि जब हमारा यह विभाग सरकार के अधीन था तब तो शायद इस प्रकार के ड्यूज वसूल होने में दिक्कत हो सकती होगी लेकिन आज जब कि हमारा विद्युतमंडल एक ऑटोनॉमस बॉडी है वैसी हालत में जितने भी ड्यूज हैं उनको रिकवर करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

सब से बड़ी चीज़ जो जरूरी है वह यह कि जितने भी पॉवर हाउसेज विद्युतमंडल के अधीन हैं उन पॉवर हाउसेज की अलग अलग आय और व्यय का लेखा जोखा होना चाहिये। हर एक पॉवर हाउस को इस दृष्टि से देखना चाहिये कि वह अपने खर्चे में और आय में कहां तक सन्तुलन रख पाता है। कई ऐसी जगहें भी हैं जहां खर्चा तो ज्यादा होता है और आय कम होती है। अभी अभी एक माननीय सदस्य ने बताया था: किसी एक शहर के बिजली घर में आमदनी बहुत कम होती है और व्यय उससे कहीं अधिक होता है। जहां ऐसा होता है वहां हमें देखना चाहिये कि आमदनी के हिसाब से व्यय क्यों अधिक है और वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे आय और व्यय में सन्तुलन हो सके। आज यदि कोई व्यापारिक संस्थान घाटे में चलता है तो यह उसके लिये गौरव की बात नहीं है।

बहुत से आंकड़े भी माननीय सदस्यों ने दिये हैं; मैं उनको दोहराना आवश्यक नहीं समझता। यह निश्चित है कि हमारे यहां कितनी ही मदें ऐसी हैं जिनमें खर्च कम

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

किया जा सकता है। एक और माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था, चाहे वे किसी भी संस्था के हों, उन्होंने यह कहा था कि यहां पर बाहर के लोगों को लाकर इस बिजली के कार्य में लगाया गया है। राजस्थान के लोगों की उपेक्षा करते हुए बाहर के लोगों को लगाना और वह केवल ठेकेदार का सवाल हो तो कोई बात नहीं लेकिन एक साधारण मजदूर तक भी बाहर का लाना, जिस प्रकार का श्रम यहां के लोगों से वे ले सकते थे किन्तु उसके लिये भी बाहर से लाना यहां के लोगों को मजदूरी से वंचित रखना, मैं समझता हूं इस प्रकार की व्यवस्था को किसी भी प्रकार से ठीक नहीं कहा जा सकता। हमारा ध्येय यह होना चाहिये कि यहां के लोगों को, राजस्थान के निवासियों को जितना लाभ मिलना चाहिये वह मिले, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम दिय गया हो या किसी अन्य तरीके का काम हो। विद्युतमंडल को यहां के निवासियों को लाभ पहुंचाने का अवश्य ध्यान रहना चाहिये।

इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है जो बिजली का उपभोग हम केवल शहरों में रोशनी देने और पंखों का लाभ पहुंचाने की नीति में नहीं होनी चाहिये, हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये एक गरीब किसान की झोंपड़ी तक बिजली पहुंचती और उससे भी वह सभी तरह का फायदा उठावे। किसानों के खेतों के लिये. छोटे छोटे उद्योग–धंधों के लिये हमें बिजली पहुंचानी है गांव गांव तक। यह हम आज की जो रेट्स हैं उन रेटस पर पहुंचायेंगे तो उससे गरीब किसान फायदा उठाने वाला नहीं। गरीब किसान को और कुटीर उद्योग के लिये हमें सस्ती बिजली उपलब्ध करानी होगी। बिजली की दरें जितनी सस्ती होंगी उतना ही ज्यादा लाभ गरीब जनता को मिल सकेगा। आज हम बंबई, कलकत्ता आदि बड़े शहरों में जाकर देखते हैं वहां पर छोटे छोटे उद्योग धंधे काफी बड़े चढ़े हैं। वह केवल इसलिये तरक्की कर रहे हैं कि वहां बिजली बहुत सस्ती मिलती है। राजस्थान में हम किसी को उद्योग धंधे खोलने के लिये कहते हैं तो वे यह कह कर इन्कार कर जाते हैं राजस्थान में बिजली की दरें बहुत ऊंची हैं इसलिये यहां मुनाफा वे कमा नहीं सकते। इसलिये विद्युत विभाग का सब से बड़ा काम है वह इस तरह से बिजली का उत्पादन करे जो सस्ती से सस्ती हो।

इसके अलावा जहां जहां हमें लोस होता है उस लोस के कारण को देखें और उसको निराकरण करने का उपाय ढूंढ़े। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि जो नये नये बिजलीघर हम कायम करने जा रहे हैं चाहे वे जल विद्युत द्वारा हो या थरमल पॉवर द्वारा हो जहां तक इनकी लाइने डालने का सवाल है इस प्रकार से लाइने डालनी चाहिये ताकि उससे अधिक से अधिक क्षेत्र में बिजली मिल सके। ऐसा न हो कि हम कुछ शहरों तक ही वह पहुंचाने का उपक्रम करें। जरूरत इस बात की है कि जहां हम शहरों तक बिजली की लाइन डालते हैं वहां हमें रास्ते में पड़ने–वाले गांवों और कस्बों को नहीं भूल जाना है। उदाहरण की तौर पर मैं आपसे निवेदन करूं भरतपुर में थरमल पॉवर स्टेशन बन रहा है। इसमें तो कोई स्पष्ट रूप से संकेत

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

नहीं है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है चार हज़ार किलोवाट का वह स्टेशन होगा। इसके कुल १७ हज़ार किलोवाट के लिये कहा है जिसमें अलवर, भरतपुर आदि मिला कर के हैं। भरतपुर अकेले शहर को जितनी विद्युत की आवश्यकता है उसको देखते हुए ४,००० किलोवाट बहुत अपर्याप्त होगा। वहां पर एक वेगन फैक्ट्री चलती है, वाटर वर्क्स चल रहा है, और भी उद्योग धंधे खुलने वाले हैं। जिस प्रकार इस इलाके के पास नमक की मात्रा बहुत है वहां पर सोडा कास्टिक पैदा हो सकता है। इन सब चीजों के लिये इतने पॉवर का स्टेशन बिल्कुल पर्याप्त नहीं होगा। चार हज़ार किलोवाट बिजली देने के बाद इतनी बिजली नहीं बच सकती कि सोडा कास्टिक आदि उद्योगों के लिये सप्लाई की जा सके। भरतपुर में जिस प्रकार आगे उद्योग धंधों की संभावना हो सकती है उसको देखते हुए इसकी शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसा कि बतलाया गया है भरतपुर से डीग तक जो करीब २३ मील है लाइन डाली जायगी। मेरा ऐसा ख्याल है कि बीच बीच में जितने भी गांव या कस्बे हैं उनमें भी इसका लाभ पहुंचाया जायेगा ऐसा मैं मानता हूं और यह होना आवश्यक भी है। रास्ते में जो बड़े बड़े कस्बे मिलें उनको भी बिजली दी जाय। इससे ऐसा है कि भरतपुर से ५क, डेढ मील पर गांव या कस्बा पड़ता ही है उसको भी इससे फायदा मिल सकेगा। वैसे डीग कस्बा भी बहुत बड़ा है। कितने ही गांव ऐसे है जहां छोटे छोटे उद्योग धन्धे चल सकते हैं और चल भी रहे हैं। इन सब को बिजली देना आवश्यक है। इसलिये भरतपुर बिजलीघर को जैसी कि संभावना नहीं है भाखरा नांगल से या चम्बल से विद्युत मिल सके। यह तो स्वाभाविक है कि जो विद्युत जल से पैदा की जायेगी वह थरमल प्रणाली से पैदा की जाने वाले विद्युत से काफी सस्ती हो सकती है। अगर वहां पर भी किसी प्रकार से जल विद्युत पहुंचाने की योजना हो तो बात दूसरी है नहीं तो वर्त्तमान में जो थरमल योजना है इसके लिये काफी बड़ा पॉवर हाउस बनाना चाहिये और वह भी कम से कम १५ हज़ार किलोवाट तक पैदा करने वाला हो। जब तक इतना प्रोविजन नहीं करेंगे तब तक भरतपुर की बिजली की आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकेंगे।

जिस वक्त हमारे मंत्रि-मंडल की बैठक भरतपुर में हुई थी उनके सामने भी वहां के बिजली के सम्बन्ध में अभाव-अभियोग रखे थे। स्थानीय जिस प्रकार की शिकायतें थीं वे भी रखी गई थीं। भरतपुर में बिजली की संभावना के साथ साथ डीग के बिजली के सम्बन्ध में भी बातें रखी गई थीं।

भरतपुर का जो बिजलीघर बन रहा है उसके बारे में तो यहां प्रश्न में भी बताया गया है कि किस प्रगति से वह चल रहा है। यद्यपि उत्तर यह दिया गया था कि ६१ तक बिजली मिल जावेगी। लेकिन आज भी अभी मैं देख कर आया हूं उसकी प्रगति इतनी धीमी है कि उम्मीद नहीं बनती कि ६१ तक बिजली मिल जाय। जहां तक मेरी दृष्टि में आया, जिस मार्ग से बिजलीघर पहुंचते हैं उस मेन रोड़ से बिजलीघर तक की एप्रोच रोड़ भी पूरी तौर से नहीं बन पाई है। हां, रेल से सामान आता है तो वह वहां पहुंच जाता है और

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

वहां थोड़ा स्ट्रक्चर सा नज़र अवश्य आ रहा है। पर इससे यह आशा लगाना मुझे तो सम्भव नहीं लगा कि अगले साल ही इससे बैगन फैक्ट्री को, शहर को, वाटर वर्क्स को, और कई प्रकार के उद्योग धन्धों को जिनके कि चलने की सम्भावना है उनको बिजली दे सकेगा। तो हमें इस प्रगति को इस रूप में भी देखना है।

इसके साथ ही डीग बिजलीघर के बारे में भी बहुत दिन से शिकायत रही है! छोटा सा वह स्टेशन है। कभी उसे भरतपुर के अन्तर्गत लगा दिया जाता है, कभी अलवर के और कभी स्वतन्त्र अधिकारी भी रख देते हैं उस पर। पर वहां के जो कर्मचारी हैं उनके बारे में आम तौर से शिकायत है कि आपस में वे सहयोग से मिल कर काम नहीं करते, पूरा ध्यान काम में नहीं देते, आपस में लड़ाई झगड़े की भी उनकी शिकायत आती रहती है। तो मैं चाहूंगा कि वहां इसे ठीक किया जाय। मन्त्रि मण्डल की बैठक के अवसर पर भरतपुर में वादा किया गया था कि इसको देखा जावेगा पर मुझे जहां तक पता लगा है वहां किसी ने जाकर देखा नहीं। उनके आपस के झगड़ों से नया इन्जिन होते हुए भी लोगों को इतनी बिजली नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिये। वहां चक्कियों के बन्द होने की भी नौबत आ जाती है। दिन में पंखों की भी यह नौबत आ जाती है। इस तरह की शिकायतें हैं। बिजलीघर में इन्जिन नया है, कैपेसिटी है, सब कुछ है, पर फिर भी शिकायत रहती है तो यह केवल व्यवस्था की कमी है। इसलिये चाहता हूं कि इस बिजलीघर को भी जाकर देखा जावे और इसकी व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की जावे। तो इस तरह से आज जब हम इस बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति पर विचार कर रहे हैं तो हम उससे आशा रखेंगे कि वे अपना व्यय और आय में सन्तुलन बैठावें। इस अनुपात से व्यय करें कि खर्चे से आमदनी अधिक मिल सके और उस स्थिति में हम लोगों को कुछ सस्ती दरें भी दे सकें। इस बिजली का उपयोग अभी तक केवल शहरों में ही होता रहा है, हमारे देहातों तक और किसानों तक और छोटे छोटे उद्योग धन्धों तक हम नहीं पहुंचा पाये हैं। अब उधर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां जहां हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पहुँचा सकने की स्थिति में हैं उन उन क्षेत्रों को छोड़ कर जहां उसे पहुँचाने की सम्भावनाएं न हों वहां थरमल स्टेशन बनाये जावें ताकि आसपास के जितने गांव और कस्बे हैं उनको भी मुहइया किया जा सके। क्योंकि यह तो सम्भव नहीं हो सकता कि हर गांव और कस्बे के लिये अलग पॉवर घर बनाया जावे।

यदि हमारा विद्युत विभाग इस प्रकार से काम करेगा और इस प्रकार से अपनी व्यवस्था को जमावेगा तो हमारा विद्युतघर सफल हो सकेगा और उचित स्तर तक खर्चा रख कर लाभ की स्थिति में पहुँच सकेगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह जो ६०-६१ का फाइनेन्शियल स्टेटमेंट रखा गया है उस सम्बन्ध में, जो जनसंघ के एक प्रमुख वक्ता ने कहा था कि यह जो बजट है उसका तरीका गलत है और यह लोगों को भूल-भुलैया में डालने वाला है, कहना चाहूंगा।

(श्री पी० के० चौधरी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से विस्तृत रूप में यह बज़ट इस साल हमारे सामने आया है आज तक नहीं आया। इसमें इतनी डिटेल्स दी हुई हैं कि ऐसा लगता है माननीय सदस्य उसको डाइजेस्ट कर पाये और इसी से कह दिया कि यह भूल-भुलैया है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : हाजमा खराब होगा उनका।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसको देखेंगे तो मालूम होगा कि इसमें न सिर्फ कैपिटल एक्सपेन्डीचर की ही डिटेल दी हुई है पर रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर में श्रोपरेटिंग और मेन्टीनेन्स की डिटेल तक दी हुई हैं। इसमें सारी डिटेल दी हुई हैं। ऐसी स्थिति में, मैं नहीं समझता कि इसको भूल-भुलैया का बज़ट कैसे कहा जा सकता है ? हो सकता है कि इसमें डिटेल इतनी अधिक दी गई हैं कि माननीय सदस्य को उसे पढ़ने में कुछ दिक्कत आई हो और इसी लिये इसे भूल-भुलैया कह बैठे हों। तो मेरा तो कहना है कि it is the first time that we have come across such a detailed Budget for this Department. जो आज तक इस सदन में पेश नहीं हुआ था।

अब इस पर आता हूं। दूसरी योजना का जो अलॉटमेन्ट था पॉवर के लिये it was 19,99,00,000 and few thousands, लगभग २० करोड़ रुपया। अब एक्सपेन्डीचर को देखते हुए मालूम होता है कि उसमें से खर्च ये कर पाये हैं सिर्फ १५ करोड़ ही। मतलब पांच करोड़ का हमारा शोर्ट फाल रहेगा। देट मीन्स २५ पर्सेन्ट शोर्ट फाल हुआ एक्सपेन्डीचर का। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जिम्मेदारी कहां तक इस बोर्ड की है और कहां तक पहले का है, यह नहीं बता सकता। पर उनका एन्युअल परफोर्मेन्स ५६-५७ से फर्स्ट इयर ऑफ दी प्लान में हमारा पॉवर के ऊपर खर्चा था १ करोड़, ४० लाख रुपये का अब ५७–५८ में ५६–५७ की जुलाई में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने टेक ओवर किया। ५७–५८ में हमारा एस्टीमेट था लगभग पांच करोड़ रुपये का, पर एक्सपेन्डीचर हुआ १ करोड़, ८५ लाख का। मतलब ५० पर्सेन्ट से भी कम, लगभग चालीस पर्सेन्ट कम हमारा एक्सपेन्डीचर अचीवमेंट था। इस तरह ५८-५९ में भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हाथ में स्कीम थी। इसमें भी ४ करोड़, ८ लाख का एस्टीमेट था जिसमें से खर्च किया ३ करोड़, दस लाख। ५९-६० में जाकर कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आया। इस साल एक्सपेन्डीचर था ५ करोड़, ८८ लाख और खर्च वास्तव में किया ६ करोड़, ३३ लाख। यह जो एक्सपेन्डीचर इन्क्रीज हुआ इस डिटेल में जाते हैं तो देखते हैं कि इसका श्रेय कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हो, ऐसी बात नहीं है। इसमें भाखरा–नांगल का हमारा कॉमन पूल का खर्चा भी जुड़ा हुआ है, जो पहले ३० लाख का था जिसको बढ़ा कर ५९-६० में ८५ लाख का कर दिया। तो इस तरह से ५५ लाख इन्क्रीज़ हुआ। तो यह इस बोर्ड के परफोर्मेन्स से नहीं हुआ, बल्कि पंजाब सरकार ने ज़्यादा कॉमन पूल में

(श्री पी० के० चौधरी)

एक्सपेन्डीचर का अलॉटमेंट मांगा इससे हुआ। मैं जानना चाहूंगा कि यह जो इन्क्रीज्ड अलॉटमेंट किया गया ५५ लाख का इसका कारण क्या है ? यह जो ५५ लाख का एडीशनल एक्सपेन्डीचर का अलॉटमेंट हुआ, इसके लिये what is the reason ? यह जानना चाहूँगा।

अब इस साल का बजट है ६०-६१ का। इसमें हमारा कैपिटल बजट जो है वह है ६,७६ लाख का, रेवेन्यू बजट है १,६५ लाख का। टोटल बजट है ८ करोड़ और ७२ लाख का और रेवेन्यू कोस्ट है हमारी १ करोड़, ८३ लाख की।

उपाध्यक्ष महोदय, जो करेन्ट ईयर का बजट है उसमें फाइनेन्शियल स्टेटमेंट में जो मेन्शन किया है उस सम्बन्ध में मुझे कुछ शंका है। इसमें यह बताया गया है कि एक तो हमारा एक्सपेन्डीचर ऑपरेटिंग साइड में ज्यादा बढ़ा। ५५ लाख की पंजाब में बढ़ोतरी हुई उसकी वजह से और कुछ हुआ। हमारे एक्सपेन्डीचर में कमी हुई थी। "The exces of Rs. 31.08 lakhs under Bhakra Nangal Scheme represents the excess anticipated under 'Common Pool' works less the savings under the 'Bulk Supply' and 'Local Distribution' works." बल्क सप्लाई एण्ड लोकल डिस्ट्रिब्यूशन वर्क में एक्सपेन्डीचर कम हुआ और कॉमन पूल में ज्यादा हुआ। तो ३१ लाख का एक्सेस एक्सपेन्डीचर करेन्ट इयर में हुआ था। अब बल्क सप्लाई में हमारा एक्सपेन्डीचर कम हुआ है एण्ड लोकल डिस्ट्रिब्यूशन वर्क में लगभग २४ लाख का कम एक्सपेन्डीचर हुआ है। यह बताया गया है for non procurement of transformers and other equipment etc. यह तो कह सकते हैं पेज ३ पर इसकी रिपोर्ट में कि करेन्ट इयर १६५६-६० में हमारी जो सेविंग हुई बल्क सप्लाई में which is almost to the tune of Rs. 24 lakhs. It was due to the fact that transformers and other equipments could not be procured. और इसलिए हमारी सेविंग हुई जब कि पेज ४ पर जाकर यह कहा जाता है कि next year में that means १६६०-६१ में बल्क सप्लाई के अलॉटमेंट की जरूरत नहीं है। पेज ४ पर यह कहा जाता है "Provision has been made in the year 1960-61 for the works detailed in schedule II in support of Statement I-B viz. details of works relating to Rajasthan executed under the 'Bulk Supply' and 'Local Distribution' Project of the Bhakra Nangal scheme. Most of the works under 'Bulk Supply' have either already been completed or are expected to be completed by the close of the current financial year as stated above" यहां तो यह कहा जाता है बल्क सप्लाई में नेक्स्ट इयर में यानि १६६०-६१ में कोई एलॉटमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि most of the work has been completed. और पेज ३ पर कहा गया है "less the savings under the 'Bulk Supply' and 'Local Distribution' works." वहां तो Savings are due to the fact that transformers and other equipments could not be procured in time.

part 2, page यह जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम है यह दोनों स्टेटमेंट्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ जब १६५६-६० का जिक्र

(श्री पी० के० चौधरी)

कर रहे हैं उसमें सेविंग बताई और इसलिए कि बल्क सप्लाई एण्ड लोकल डिस्ट्रिब्यूशन वर्क के लिए नॉन एवेलेबिलिटी ऑफ ट्रान्समीटर्स एण्ड इक्वीपमेन्ट्स हैं उनमें सेविंग हुई और १९६०-६१ में कहा जाता है कि बल्क सप्लाई एण्ड लोकल डिस्ट्रिब्यूशन वर्क के लिए अलॉटमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि most of the items in 'Bulk Supply' have already been supplied or are further expected to be supplied by the close of the current financial year. Whatever little provision is made for these works in the ensuing finaneial year is required to meet the outstanding liabilities against these works and other minor adjustments यानि मैं समझता हूं कि इस एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम में दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। माननीय मन्त्री महोदय उसके जवाब में एक्सप्लेन करेंगे कि how this contradiction is reconciled ?

उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा इलेक्ट्रिसिटी कन्ज़म्प्शन यानि डिस्ट्रिब्यूशन में जो प्रायोरिटी रखी है उसके सम्बन्ध में। मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रायोरिटी है उसकी तरफ हमें अपना ज्यादा अटेन्शन पे करना चाहिए क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है that supply is short and the demand is large. जब ऐसी हालत होती है शोर्ट सप्लाई एण्ड लार्ज डिमाण्ड, तो हमको प्रायोरिटी फिक्स करके उसका डिस्ट्रिब्यूशन फिक्स करना चाहिये। अब जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है किस प्रायोरिटी से उसका डिस्ट्रिब्यूशन होता है, उसका कोई डिटेल्ड स्टेटमेन्ट हमारे पास नहीं है। लेकिन मैंने एक तरीका निकाला है और वह है उनका सेल ऑफ पॉवर। पॉवर का जो सेल करते हैं और किस सेक्टर में कितना पॉवर देते हैं उससे प्रायोरिटी का अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, पेज १५२ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां आप सेल ऑफ पॉवर में देखेंगे तो मालूम होगा डॉमेस्टिक एण्ड रेजीडेन्शल पर्पज़ के लिये ६२,१६,६०० रु०, कामर्शियल पर्पजेज़ के लिये ३३,३४,७२० रु., इन्डस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिये ३५,६८,४६० रु., पब्लिक लाइटिंग के लिये ५,७६,८५० रु. और इर्रिगेशन एण्ड एग्रीकल्चरल पर्पजेज़ के लिए ६,८१,७०० रु.। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रायोरिटी है वह पर्सेन्टेज से मैं आपको बताना चाहता हूं। उनकी टोटल सेल ऑफ पॉवर है वह १०१ करोड़, ५६ लाख के करीब है। यह जो कॉस्ट उससे proportion of energy supplied to various sectors can be estimated, उससे होता है। डॉमेस्टिक एण्ड रेजीडेन्शल पर्पजेज़ के लिए हमारी ४० पर्सेन्ट इनर्जी सप्लाई होती है, कॉमर्शियल पर्पजेज़ के लिए २०.८ पर्सेन्ट, इन्डस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए २३ पर्सेन्ट। लेकिन मैं समझता हूँ उससे ज्यादा है क्योंकि इन्डस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए जो इनर्जी सप्लाई होती है ऑन ए लैसर रेट करते हैं। अगर इसी रेट को मान कर चलें तो २३ पर्सेन्ट उससे लेकर करें तो even then it would not be more than 30 percent और इर्रिगेशन एण्ड एग्रीकल्चरल पर्पजेज़ के लिए ४ पर्सेन्ट ऑफ दी इनर्जी एवेलेबल कन्ज़्यूम होती है। पब्लिक

(श्री पी० के० चौधरी)

लाइटिंग के लिए हम ३.६ पर्सेन्ट इनर्जी सप्लाई करते हैं। मेरा इसमें जो ऑब्जेक्शन है इस प्रायोरिटी में वह यह है कि डॉमेस्टिक पर्पजेज़ के लिए सप्लाई करना तो उचित है लेकिन जहां तक कॉमर्शियल और पब्लिक लाइटिंग के किये सप्लाई किया जाता है वह कॉमर्शियल के लिए २०.८ पर्सेन्ट और पब्लिक लाइटिंग के लिए ३.६ पर्सेन्ट है और इतना इम्पोर्टेन्ट सेक्टर एग्रीकल्चर है उसके लिए सिर्फ ४ पर्सेन्ट ही इनर्जी सप्लाई किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह इरेशनेलाइजेशन बेसिस का डिस्ट्रिब्यूशन है। मैं तो इस राय का हूं कि जहां तक पब्लिक लाइटिंग की सप्लाई है it is a luxury supply. उसकी बेसिक नीड नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जहां तक पब्लिक लाइटिंग की सप्लाई है जब कि हमारे पास पॉवर की स्केयर्सिटी है it is a supply for satisfying the vain needs of the people. There should be restriction on it. इसलिए यह जो ३.६ पर्सेन्ट सप्लाई करते हैं इसके लिए मैं इस राय का हूं कि पब्लिक लाइटिंग के लिए सप्लाई को बिलकुल रोक दिया जाये। जहां तक डॉमेस्टिक और रेजीडेन्शयल सप्लाई होती है उसमें भी कुछ पब्लिक लाइटिंग आती है। मैरेज सेरेमनी है जो डोमेस्टिक मीटर इन्स्टाल्ड है उसमें काफी इल्युमिनेशन करते हैं, उसमें काफी सप्लाई करते हैं। सिर्फ पब्लिक लाइटिंग के नाम से सर्टेन ऑकेज़न्स में जो पॉवर सप्लाई किया जाता है उसको डाइवर्ट करना चाहिए इर्रिगेशन एण्ड एग्रीकल्चरल पर्पजेज़ के लिए।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि कमर्शियल पर्पजेज के लिए जो २० पर्सेन्ट of the power is supplied वह भी मैं समझता हूं अनुचित है। कॉमर्शियल हाउसेज़ को, जो दूकानें हैं उनको लाइट की जरूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि for the time loeing कुछ सालों के लिए जब तक हमारे पास सफिशियेन्ट पॉवर एवेलेबल नहीं हो तब तक के लिए वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए इन पॉवर सप्लाइड टू दी कॉमर्शियल हाउसेज़, जो शॉप्स हैं या दूसरी शॉप्स हैं कॉमर्शियल पर्पजेज़ के लिए, डेकोरेशन पर्पजेज़ के लिए, लाइटिंग पर्पजेज़ के लिए, फैन्सी डेकोरेशन के लिए, कुछ रेस्ट्रिक्शन्स रखना चाहिए लुकिंग टू दी साइज़ ऑफ दी शॉप कि इस दूकान में या इस तरह की दुकान में इतनी लाइट और इतने फेन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि वह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है, और इस तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए जब कि हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में सिर्फ ४ पर्सेन्ट ही पॉवर सप्लाई करते हैं। मैं समझता हूं कि यह एग्रील्चरल सेक्टर है जिसमें फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है और हमारे सामने फुड प्रोडक्शन का क्वेश्चन रहता है, हमारे सामने इर्रिगेशन का क्वेश्चन रहता है। जयपुर के आसपास हम देखते हैं कि कुओं पर इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है पम्प्स के लिये वह सिर्फ रात को दी जाती है। दिन को उनको पॉवर सप्लाई नहीं होती है यानि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए सप्लाई में रेस्ट्रिक्शन रख दी है। उनके लिए हम बराबर सप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन कॉमर्शियलहा उसेज़ के लिए फॉर कॉमर्शियल पर्पजेज़ के लिए एक की जगह

(श्री पी० के० चौधरी)

४ लाइट देते हैं । वे ट्विन्कलिंग लाइट लगाते हैं यानि जो कभी जलती है और कभी बुझती है, इस प्रकार की फैन्सी लाइट लगाते है उसके लिए 20 percent of the energy we are supplying. मैं समझता हूं यहां बिल्कुल अनुचित है । गवर्नमेंट को इस सम्बन्ध में सोचना चाहिए और कॉमर्शियल हाउसेज़ के लिए कम से कम how many points they can maintain in their shops यह तय कर देना चाहिए । फैन्सी लाइटिंग के लिए पॉवर सप्लाई नहीं करना चाहिये । उसमें से जितना रिडक्शन होगा, यानि २० पर्सेन्ट इनर्जी मिलती है उसमें ५० पर्सेन्ट कम कर दें, यानि कम से कम १० पर्सेन्ट रखें तो मैं समझता हूं कि यह १० पर्सेन्ट और पब्लिक लाइटिंग में ३.५ पर्सेन्ट पॉवर खर्च करते हैं इस तरह से १३.५ पर्सेन्ट या ४ पर्सेन्ट इर्रिगेशन पर्पजेज के लिए, पम्प्स के लिये जो पॉवर सप्लाई करते हैं उसको मिला कर २० पर्सेन्ट उसको बना सकते हैं । इनमें कट करके भी that will also be an achievement. उसमें एग्रीकल्चरिस्ट्स को बेनिफिट पहुँचेगा। यही नहीं बल्कि उससे देश को फायदा पहुँचेगा । और देश को फायदा इस तरह से पहुंचेगा कि उसमें फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रायोरिटी मैंने आपको बताई यह प्रायोरिटी स्टेटमेंट हालांकि मैं चाहूंगा कि पॉवर सप्लाई में प्रायोरिटी कोई फिक्स की, कि नहीं ? मेरी जहां तक जानकारी है डिपार्टमेंट के पास में इस प्रकार की सप्लाई की कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है और जब नहीं है तो हम देखते हैं कि What priority has been evolved? यह जो प्रायोरिटी बताई है वह होने से पॉवर्स को यूज़ करने में जो प्रायोरिटी इवोल्व्ड हो गई है कि ४० पर्सेन्ट डॉमेस्टिक पर्पज़ के लिए, २० पर्सेन्ट कॉमर्शियल पर्पजेज़ के लिए, इस प्रकार की जो प्रायोरिटी डवेलप की गई है, मैं देखता हूं कि कॉमर्शियल पर्पजेज़ के लिए और पब्लिक लाइटिंग के लिए जो दी है वह बिल्कुल गलत है । उसमें रिडक्शन होना चाहिये ।

तो मैं मिनिस्टर इनचार्ज और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दोनों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि they must revise their policy of distribution,जहां प्लान में प्रायोरिटी होती, हर एक चीज़ में प्रोयोरिटी चलती है क्योंकि हमारी डिमान्ड और सप्लाई एक दूसरे से मीट नहीं कर पाती है। The demand is excessive and supply is short. और मैं समझता हूं कि आज हमारी इलेक्ट्रिसिटी कन्ज़म्पशन की भी एक डेफिनेट प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिये । वह प्रायोरिटी फिक्स करना चाहूंगा और मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि जो प्रायोरिटी फिक्स करें उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पोर्टेन्स दें ।

उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो डबल सर्किट लाइन गांधी सागर से सवाई माधोपुर आने वाली है उसके संबन्ध में कुछ कहना चाहूंगा । उसमें जो डिले हुई है उस डिले के संबन्ध में पेज़ ४ ऑफ दी बजट में कहा गया है :

(श्री पी० के० चौधरी)

"The erection work of 132 KV Sawai Madhopur-Jaipur Transmission line has since been commenced and about 198 towers have already been erected. The erection of 132 KV Double Circuit line from Gandhi Sagar to Sawai Madhopur will be taken in hand and probably completed in the year 1960-61. The delay in this work has been due to non-supply of steel for indigenous fabrication of steel towers. Steel which was promised to be deliverd some time by the end of 1958 has only been partially received and more than 400 tons yet remained to be supplied to enable fabrication of the towers for this Double Circuit line." यह जो डबल सर्किट लाइन है इसका कन्स्ट्रक्शन कम्प्लीट इसलिए नहीं हुआ कि इन्डीजिनस इरेक्शन टॉवर्स के कन्स्ट्रक्शन के लिए स्टील प्राप्त नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात से इम्प्रेस्ड हुआ था १६५५ में। १६५५ में बुल्गानिन और ख्रुश्चेव हिन्दुस्तान में आये थे और ख्रुश्चेव को भाखरा नांगल बताने ले गये थे तो he made a very pertinent remark there. He said, "Why are you wasting your steel in having these iron pillars and towers for your electric transmission lines ?" उनका कहना था कि रशिया में भी हम स्टील टॉवर्स नहीं लगा रहे हैं, आयरन पोल्स नहीं लगा रहे हैं, हमने सीमेन्ट पोल्स यूज़ किये हैं, वुडन पोल्स यूज़ किये हैं। उन्होंने सुझाव दिया था १६५५ में। मैं समझता हूं कि Mr. Khruschev is a practical man एक प्रेक्टिकल व्यक्ति हैं, वे कहते हैं कि रशिया में जहां कि steel production is many times more than India वहां पर they have left the luxury of having steel towers and iron poles for transmission lines. वह छोड़ सकते हैं तो मैं समझता हूं कि हमें सोचना चाहिये कि हमारे यहां डिले इस वजह से ही गई है, इस बात से नहीं हुई है कि पॉवर एवेलेबल नहीं थी, the power is available लेकिन सप्लाई इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हमारे इरेक्शन टॉवर्स नहीं बन सके हैं क्योंकि हमारे पास स्टील नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सीमेंट से बना देते। सीमेंट कॉन्क्रीट टावर्स बना देते, वुडन पोल्स यूज़ करते। जब कि रशिया जो कि हमारे से १०० पर्सेन्ट मोर इन्डस्ट्रियेलाइज्ड है वह सीमेंट टॉवर यूज़ कर सकता है, वुडन टॉवर यूज़ कर सकता है तो हिन्दुस्तान की नाक नहीं कट जाती है; वुडन टॉवर्स या सीमेंट टॉवर्स यूज़ करते। लेकिन एक बात की जो रट है, जो एक सेट बात है, हम उससे कभी इधर उधर नहीं होना चाहते हैं। हमारी जो थिंकिंग है it always goes in the same path, यानि नये तरीके से सोचना नहीं चाहते, नये रास्ते पर नहीं जाना चाहते हैं। जो ट्रेडिक्शन आज तक चला आ रहा है उसी पर हम चले हैं चाहे उससे हमारे काम आगे बढ़े, चाहे डिले हो, चाहे प्लान का बराबर एक्जीक्यूशन नहीं हो। तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। १६५५ में ख्रुश्चेव जैसा आदमी आपका काम देख कर यह रिमार्क पास करता है "You are wasting your iron and steel" XXXX

we don't pay any attention

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No.65

(श्री पी० के चौधरी)

to it, मैं उसको उचित नहीं समझता हूं। His remarks should have received enough attention from the Government when their Plan was delayed simply because of these steel towers.

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी ४०० टन की डिलीवरी बाकी है ! स्टील की तो हो सके तो आप सीमेंट टॉवर्स इरेक्ट करायें। सीमेन्ट का सवाई माधोपुर में ग्लट हो रहा है, वहां से नहीं उठ रहा है, लाखेरी में सीमेंट glut ो रहा है। सीमेंट एक तरफ एक्स्ट्रा है वह लैफ्ट-अप नहीं किया जाता है, Why don't you think of utilising it ? आप युटिलाइज़ करें और हमारे यहां की डबल सर्किट लाइन पूरी करें। यह सिर्फ बजट में मेन्शन किया है ! हो सकता है कि आपकी और भी कई ट्रान्समिशन लाइन स्टील की वजह से रुकी पड़ी हैं या रुकी पड़ी रहेंगी, they could not have been completed for lack of these steel towers. यह सवाल आपके सामने आयेगा और थर्ड प्लान में पॉवर के लिए एक्सपेन्डीचर है, it will be three times. सकिन्ड फाइव इयर प्लान में २० करोड़ तो थर्ड फाइव इयर प्लान में, we are thinking of spending about three times this amount in the power sector. तो इतने आयर्न पोल्स और इतने ही ट्रान्समिशन टॉवर्स की इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए स्टील की ज़रूरत होगी वह नहीं मिलेगी, क्योंकि थर्ड फाइव इयर प्लान में अभी यह बात चल रही है कि वह टार्गेट १० मिलियन टन का रहे या ८.५ मिलियन टन का रहे। उसके ऊपर अभी कन्ट्रोवर्सी चल रही है। मान लें कि अगर ८.५ मिलियन टन्स ही रहा तो मैं समझता हूं कि स्टील ट्रान्समिशन टॉवर्स के लिए मिलनेवाला नहीं है ; then why don't you start thinking ? आप आज से क्यों नहीं सोचना शुरू कर देते ताकि थर्ड फाइव इयर प्लान में आपने जो बताया है it will be to the tune of nearly 55 lakhs ? उस वक्त आपको ज्यादा स्टील की जरूरत॰ पड़ेगी तो, Why don't you start re-thinking and switch on? स्टील मिल जाय तो यूज़ करिये लेकिन जहां नहीं मिले तो आप काम को रोकिये नहीं। सीमेंट फैक्ट्री आपके पास है और थर्ड फाइव इयर प्लान में और सीमेंट फैक्ट्रीज़ खोलने का सोच रहे हैं तो उसको आप काम में लाइये।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आता हूं एलॉटमेंट फॉर रूरल एन्ड अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन पर। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल इस हैड में एलॉटमेन्ट था हमारा २७ लाख रुपयों का करेन्ट इयर में और उसके पहले साल में २५ लाख रुपयों का था और इस साल है १५ लाख रुपयों का यानि १९६०-६१ में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का एलॉटमेंट कम हो गया जब कि हम एक्सपेक्ट करते थे कि ज्यादा होगा। सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में उसके लिये एलॉटमेंट हुआ था ८० लाख रुपयों का ए ड What was the objective? The Objective was:-"In addition to this, under the Second Five Year Plan, a sum of Rs.80 lakhs has been provided for rural electrification. Under this scheme, electrification of the towns and villages upto population of 5,000 has to be taken up. A detailed note for Rajas-

(श्री पी० के० चौधरी)

than will be taken up..." आपका यह प्रोग्राम था कि ५ हजार की आबादी वाले सारे गांव और शहर हैं उनमें सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में विद्युत पॉवर सप्लाई कर देंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस टार्गेट के मुताबिक अब तक हमने in the last year of this Plan Period कितने गांवों को कवर किया है और कितने ऐसे गांव या कस्बे हैं जिनकी ५ हजार से ज्यादा की आबादी है उनको how many villages we have covered and how many are still to be covered ? इस चीज़ की जानकारी मैं मंत्रीजी से चाहूंगा और यदि आप जानकारी नहीं दे सकते तो मैं समझूंगा कि १५ लाख का एलॉटमेंट इस साल किस बेसिस पर किया है, पिछले साल से १० लाख रु० कम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का एलॉटमेंट है, On what basis, whether they have achieved their target ? Whether they have covered in the entire State all the villages and towns having a population of 5000 ? जो ऐसा कर लिया है इस वजह से है और गांव बाकी नहीं रह गये हैं, कोई कस्बा बाकी नहीं रहा है जिसमें ५ हजार की आबादी है और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है इसलिए कम कर दिया है तब तो जस्टिफाइ होगा और अगर बाकी रह गया है तो I don't see any justification for reduction in allotment for rural electrification.

इसके बाद, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक, दो बातें अपनी कॉन्स्टिट्युएन्सी की कहना चाहूँगा। जयपुर मकराना लाइन प्लान में है। फर्स्ट फाइव इयर प्लान में ऐसा था कि चंबल प्रोजेक्ट से बिजली लायेंगे और उसको जयपुर से मकराना तक ले जायेंगे और फुलेरा में ३३ किलोवाट का एक सब-स्टेशन होगा जिससे फुलेरा शहर को बिजली मिलेगी। मैंने इस साल के बजट का एक एक पन्ना पढ़ा लेकिन इसमें फुलेरा का नाम नहीं मिला ....

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : अदृश्य साइन में है।

श्री पी० के० चौधरी : अदृश्य साइन में आप बताते हैं लेकिन शायद यह भूल से रह गया है। पहले चम्बल से सप्लाई करने का प्लान था वह पूरा नहीं हुआ। अब यह प्लान हुआ कि जयपुर में ५ हजार किलोवाट का थरमल टरबो इन्जिन लगायें उससे ले जायेंगे। लेकिन इस थरमल पॉवर स्टेशन को भी सन् ६१ से पहले कम्पलीट करना था। During the second plan period it has to be completed. यदि प्लान में कम्पलीट करना था तो it is high time the construction of transmission lines, the erection of the sub-station at Phulera should have been started, लेकिन आज तक नहीं हुआ तो मन्त्रीजी से कम से कम इतना आश्वासन चाहूंगा कि बजट के हैडिंग्ज़ में नहीं आया, लेकिन इन प्रेक्टिस he will start working right from this month इस महीने से काम शुरू हो जायगा, ऐसा आश्वासन देंगे....

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : कैसे देंगे ?

श्री पी० के० चौधरी : जब प्लान में है और बजट में नहीं रखा है, it is an omiss-

Page No.67

(श्री पी० के० चौधरी)

ion in the Bndget, इस ओमिशन को सदन में ठीक करदें, यह प्रार्थना करूंगा ।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, चौमू की हिस्टोरिक लाइन है, चार साल से....

डॉ० चन्द्रकला : आप यह हिस्ट्री खत्म करना चाहते हैं क्या ?

श्री पी० के० चौधरी : मैं नहीं खत्म करना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि मन्त्रीजी, चौमू की हिस्ट्री है, he should bring an end to that history of transmitire and towers without power. मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि चौमू की लाइन को पूरा किया जाय और कालाडेरा तक ले जाने का जो प्लान है उससे भी आगे किशनगढ़-रेंनवाल तक बढ़ाया जाय । लालसोट की भी सेम स्टोरी है ।

एक बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इस प्लान में जावर माइन्स, उदयपुर में बिजली सप्लाई करने की बात थी । पहले पंचवर्षीय प्लान में भी यह बात थी लेकिन इस बजट में यह बात नहीं है, इसके लिये मुझे अफसोस है । जावर माइन्स में जिन्क स्मेल्टर लगाने की योजना है लेकिन without power hone will it work ? इसलिये इस ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आता हूं राणा प्रताप सागर पॉवर स्कीम के ऊपर । उपाध्यक्ष महोदय, इस स्कीम में सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में २॥ करोड़ रुपये रखे गये थे, लेकिन उसमें से आज तक एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है । सिर्फ नेक्स्ट इयर ५० लाख का एलॉटमेंट था । सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में जो इन्डीकेशन राणा प्रताप सागर बांध के लिये था वह यह था: " The power generated at Gandhi Sagar Dam will not be sufficient to meet the requirements of areas in Rajasthan, Ajmer and Madhya Bharat. In view of the increased demand from all these States for mining, agriculture and industry, it is necessary that the development of Rana Pratap Sagar power Station should take place simul taneously with Gandhi Sagar Power Station." प्लान में जो विज्युअलाइज किया था वह गांधी सागर एन्ड राणा प्रताप सागर बांध थे Development work should have been simultaneous लेकिन बजट को देखते हुए और प्लान की-प्रोग्रेस रिपोर्ट जो पब्लिश होती है उसको देखते हुए यह जानकारी होती है कि ढाई करोड़ में से एक पाई भी एलॉट नहीं हुई है, नेक्स्ट इयर ५० लाख का किया है, that means this entire Scheme will drag on, will become a part of the Third Plan. इस प्लान में कुछ नहीं हुआ और यदि यह हो जाता तो पॉवर सप्लाई जयपुर-मकराना लाइन जयपुर के थरमल पॉवर स्टेशन से लेनी पड़ती है, उससे न लेकर चम्बल या राणा प्रताप सागर पॉवर स्टेशन से ले सकते थे । इसलिये मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि चार साल तक डिपार्टमेंट प्रताप-सागर डवेलपमेंट में लिथार्जी दिखा रहा है, they have defaulted there. मैं चाहूंगा कि ५० लाख से ज्यादा करके दि वर्क शुड बि इन्टेन्सिफाइड और लास्ट इयर ऑफ दि

(श्री पी० के० चौधरी)

प्लान में कितना ज्यादा ध्यान दे सकें उतना देने की कोशिश करनी चाहिये।

इसके बाद मैं आता हूँ गवर्नमेंट की एनर्जी सप्लाई के बारे में, इन्डस्ट्रीज़ के लिये जो पॉलिसी डिक्लेरेशन है उसकी तरफ। उपाध्यक्ष महोदय, here is the basic policy of the Government regarding the supply of powers-

"At present we have various rates for industrial loads and existing rates for industries consuming more than 20,000 units is -/2/- per unit. This rate is quite high for this purpose and when compared to other States in India, prohibitive also.

२ म० प०

It was, therefore, decided that in respect of medium and large scale industries of the following categories, i. e. textiles, ceremics, glass, cement, engineering, sugar, metal, industries based on agriculture etc. the existing rate may be reduced to-/1/6 per unit for those units which consume more than 20,000 units of energy. This rate will be charged at all places in Rajasthan subject to the availability of power. Where we have steam generators in our power houses, the existing rates will continue even when the Hydel Power is available and till the losses are recouped." तो यह जो स्टेटमेंट है, यह जो रेट है that will continue even when the Hydel Power is available till the losses are recouped. यह गलत है क्योंकि यह जो रेट से सप्लाई करते हैं उसको जो मीट करते हैं उसको सब्सिडी देते हैं। जो कन्सेशनल रेट से सप्लाई करते हैं उसका ५० पर्सेन्ट सब मेन्सन सेन्ट्रल गवर्नमेंट देती है। उसके बाद लोस को रिकूप करने के लिए हाइडल पॉवर को उस रेट से सप्लाई करें तो मैं समझता हूं it is an unimaginative policy. The question is not of the cost, the question is of the development of the country. अब इस रेट से पॉवर सप्लाई रखेंगे, डेढ़ आना के हिसाब से, डेढ़ आना पर-यूनिट। जब दूसरी स्टेट्स हैं, उनमें जो हाइडल पॉवर की रेट है, वह चीपर रेट है। They will supply power to their own industries. उसका नतीजा क्या होगा, क्या industries in Rajasthan will not be able to compiete with other States? इसलिए यह जो स्टेटमेंट है that statement must be immediately amended. आज उसको अमेंड कर देना चाहिए, कह देना चाहिए कि हाइडल पॉवर होगी, then at a much cheaper rate we will supply the energy. यह आपको स्टिक नहीं करना चाहिए कि हाइडल पॉवर देने के बाद जो लोस होगा उसको रिकूप जब तक नहीं कर लें तब तक डेढ़ आना रखेंगे।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह जो कन्सेशन दिया है यह उन इन्डस्ट्रीज़ को दिया है जो २०,००० युनिट यूज़ करती हैं। जो रियली स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ हैं उनका कन्जम्पशन २०,००० यूनिट से कम है उसको फायदा नहीं दिया। उसके लिए दो आना रेट रखी है। मैं कहना चाहता हूं कि २० हजार यूनिट से कम यूज़

(श्री पी० के० चौधरी)

करती है तो there should be no restriction about the concessional rate on the minimum consumption. There should be no restriction on it. Any amount of energy, even if it is less than 20,000 units. जो पांच हजार यूनिट यूज़ करता है, उसको भी कन्सेशनल रेट मिलनी चाहिए। Why should there be a Step-motherly treatment to the smaller units as compared to medium and larger size units? तो आपकी जो पॉलिसी है, आपको रिवाइज़ करना चाहिए।

उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, सारी बातें होने के बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर को ४ पर्सेन्ट ऑफ अनर्जी आज मिलती है in comparison to 20 percent for commercial lighting, 3 6 percent for public lighting, 40 percent for domestic lighting. उसके लिए इतनी अनर्जी मिलती है, एग्रीकल्चर सेक्टर को ४ पर्सेन्ट अनर्जी मिलती है, उसकी रेट है तीन आना, तीन आना पर यूनिट। मैं नहीं समझ सकता कि एक तरफ यह कहा जाता है इन्क्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ाओ, उसके लिये तरह तरह की तवज्जोज दीजिये, फर्टीलाइजर यूज़ कीजिये, ट्रैक्टर यूज़ कीजिये, पम्पिंग सेट्स लगाइये, ये सारी बातें कहते हैं; there is no concession for them. मैं यह कहना चाहता हूं that it is high time कि एग्रीकल्चर के लिए डेढ़ आना यूनिट से अनर्जी सप्लाई करनी चाहिए। मैं इस लोजिक को समझ नहीं सका। I am utterly at a loss to understand the logic of it. पम्पिंग सेट्स के लिए, लिफ्ट इर्रिगेशन के लिए क्यों न एनर्जी दी जाय डेढ़ आना पर यूनिट के हिसाब से, जब कि इन्डस्ट्रीज़ के लिए दे सकते हैं? एग्रीकल्चर के लिए तीन आना पर यूनिट क्यों रखा जाय यह मेरी समझ में नहीं आता There is no logic behind it. Why this Government does not take these things seriously? मैं कहूंगा कि जब देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का इन्तजाम क्यों नहीं करते? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में डॉमेस्टिक लाइटिंग के लिए इम्पोर्टेन्ट नहीं समझता, जितना कि एग्रीकल्चरल पर्पजेज़ के लिए जरूरी है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन घर में जलाने के लिए नहीं चाहते, कुएं में पम्पिंग सेट्स के लिए चाहते हैं। लेकिन आपने उसके लिए तीन आना पर यूनिट रखा है। आज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की डिमान्ड इतनी है, आज लोग यूज करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इक्विटी की डिमान्ड है, इसका तकाजा है कि जो इन्डस्ट्रियलिस्ट हैं, और जो बिजनेसमैन हैं, उनको आप डेढ़ आना रेट से देते हैं। और जो काश्तकार हैं, जो आपके लिए अनाज पैदा करता है, जिसको खाकर आप जिन्दा रहते हैं, और एक इन्डस्ट्रियलिस्ट केवल प्राइस गुड्स पैदा करता है, कपड़ा, टाइलेट वगैरह आपके लिए, और कई चीजें बनाता है उसको आप डेढ़ आना की रेट से देते हैं, लेकिन जो खुराक पैदा करता है, जो चांवल गेहूँ, गन्ना पैदा करता है उसको डेढ़ आना रेट से नहीं देते, उससे डबल चार्ज करते है मैं समझता हूं

(श्री पी० के० चौधरी)

it is not epuitable. इसको आपको रिवाइज करना चाहिए, इमीजियेटली आपको डिक्लेअर करना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर के लिए wherever available जहां पर अवेलेबल हो सकती है अनर्जी, वहां डेढ़ आना रेट से पम्पिग सेट्स के लिए, इर्रिगेशन प्लान्ट के लिए अनर्जी देंगे, फोडर काटने के लिए जो अनर्जी दें, जो प्रोसेसिंग के लिए दें वह डेढ आना पर यूनिट के हिसाब से देनी चाहिए। आपने अब तक जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट एग्रीकल्चरिटस के साथ रखा है वह उनके साथ गलत ट्रीटमेंट रहा है। It is a wrong treatment you are giving to your eutire econmy. आप रोंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसलिए you must re-consider. और उसको at the same time उस रेट से अनर्जी सप्लाई करनी चाहिए।

उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात फाइनेन्शियल मेमोरन्डम में कही है, जिसको मैं स्टाउटली अपोज़ करता हूं। फाइनेन्शियल मेमोरन्डम के एन्ड में कहा गया है, "No provision has been made on account of interest either in the revised Budget Estimate for the year 1959-60 or in the Budget Estimate for the year 1960-61, as the valuation of assets to be transferred to the Board is not yet finalised by the Government nor has any decision been taken with regard to interest free loan to the Board, atleast in the initial stages." अब आप चाहते हैं कि बोर्ड इन्ट्रेस्ट पर लोन ले। मैं उसको स्टाउटली अपोज़ करना चाहता हूं। जब बोर्ड बनाया गया था तो ऑटोनोमस बोर्ड बनाया गया था। वह इसलिए बनाया गया था कि यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो प्रान्त में जो स्टेट ओन्ड पॉवर हाउसेज़ हैं; स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिक अन्डर-टेकिंग हैं; जैसे हाइडल, थरमल, डीज़ल प्रोजेक्ट्स वगैरह उनके लिए हम चाहते थे कि उनको कॉमर्शियल बेसिस पर चलना चाहिए। अगर किसी इन्स्टिट्यूशन को, किसी ऑटोनोमस बोर्ड को कॉमर्शियल बेसिस पर चलाना है तो बेगिंग नहीं करना चाहिए। They must not go to the State Government with a begging bowl. जो इन्ट्रेस्ट फ्री लोन देंगे it will be a discredit on the entire body, एफीशियेन्टली चलाने की कोशिश करेंगे। ज्यों ही आप इन्ट्रेस्ट पर लोन देंगे तो खर्च कम होगा और वह इनएफीशियेन्टली खर्च करेगा। इसलिए मैं इस बात के खिलाफ हूं कि इन्ट्रेस्ट पर लोन दिया जाय। मैं चाहता हूँ कि जो लोन दिया जाय, उसकी पाई-पाई, एक-एक पैसा in instalments the interest should be recovered from them. It should be a test of the efficiency of the Board that they must pay the normal rates of interest to the Government. तब तो इसमें कुछ क्रेडिट है और बोर्ड बनाने की हमारी मंशा पूरी होती है, otherwise the Board does not deserve to remain a Board. इसका कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे आज तक गवर्नमेंट पहले चलाती थी उसी तरह चलाये। क्यों ऑटोनोमस बोडी चलाये और क्यों कहे कि कॉमर्शियल बेसिस पर चला रहे हैं?

Page No.71

(श्री पी० के० चौधरी)

अब इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और भी कहना चाहता हूं कि बोर्ड का इस साल का बजट ७,३४,००० का डेप्रेसियेशन फंड में रखा है, ज्यादा इसलिए नहीं रखा है कि the Valuation of the assets on 30-6-1957 has not yet been done.

जिस दिन बोर्ड को प्रोपर्टी ट्रान्सफर की गई, जिस दिन बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ उस दिन जो पॉवर हाउसेज़ और अन्डरटेकिंग ट्रान्सफर किया। उसका आज तक कोई वेल्युएशन नहीं हुआ। तीन साल हो गये आज, इसके orders June 30th, 1957 पर किये गये, पर जो वेल्युएशन था वह आज तक तय नहीं हुआ। इसमें दो चीजें होती हैं। एक चीज तो यह कि बोर्ड का डेप्रिसियेशन फंड (Depreciation Fund) नहीं बन पाता है। ७ लाख रुपया रख दिया है इसके लिये। It is discreditable on the part of the Board as well as the Government, whoever is responsible for this delayed valuation of the assets as they were on that date, 30-6-1957. तो मैं चाहूँगा कि टोप प्रायोरिटी इसको देकर, within this year, 1960-61 यह जो वर्क था, तीन साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है इसको कम्पलीट कर दिया जाना चाहिये ताकि हमारे सामने क्लियर पिक्चर आ जाय कि What are the existing assets of the Board and what were its assets on 30-6-1957? क्योंकि बोर्ड को कॉमर्शियल प्रिंसिपल्स पर चलाना है तो डेप्रिसियेशन फंड बहुत जरूरी है और इसमें एडीक्वेट फंड जमा होना चाहिये। इसलिये जरूरी है कि वेल्युएशन का असेसमेंट लगा दें।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूँ कि जो डिस्प्यूट चल रहा है गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटीज के बीच में, regarding Conservancy charges from Jodhpur Municipality. मैं, बोर्ड का रिमार्क है सिर्फ वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं and that will show how much bitter the Board is on this point. इसके बाद भी कोई फैसला नहीं होता। मैं वह पढ़ कर सुनाऊंगा और मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह २ लाख रुपया है वह उसको फौरन चुका दिया जाय :

" The Revised Budget Estimate for 1959-60 and the Budget Estimate for 1960-61 also includes a provision of Rs. 2,10,440/- and 2,29,070/- respectively in respect of expenses for establishment etc. for Conservancy and pumping at Jodhpur. This expenditure is not legitimately chargeable to the Electricity Board. In fact orders were issued by the Government in respect of conservancy that the work should be transferred to the Municipal Board, Jodhpur, some years ago. The Municipal Board, however, did not take over the work for various reasons and when the Board insisted on the Municipal Board taking over these works and gave notice of discontinuance of conservancy work with effect from a particular date, the Collector & Commissioner intervened, with the request that the work should be continued to enable the Municipal Board to make alternative arrangem-

(श्री पी० के० चौधरी)

ents within a prescribed period. The period has elapsed, but the work has not yet been taken over."

तो मैं चाहता हूं कि यह जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको खतम कर दिया जाय। The Municipal Board should be forced to bear the expenses. यह जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई है, the Municipality charges the citizens for these services, street lighting or supply to the individual houses.

अब जब यह करते हैं तो कन्ज़र्वेन्सी और पम्पिंग की रेस्पोन्सिबिलिटी म्युनिसिपैलिटी की है. It is the responsbility of the Muuicipal Board, because the people staying there, the people taking advantage of the conservancy, they pay their charges to the Municipal Board and it is the responsibility of the Municipal Board to pay. So it should be forced and compelled and I hope that in the next year's Budget we will not find this dispute still pending. इस डिस्प्यूट को इसी साल खत्म कर दिया जायगा।The Municipal Board will be compelled to do it. क्योंकि जो ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको हम कॉमर्शियल बेसिस पर चलाना चाहते हैं, तो इस तरह का बर्डन इस पर नहीं डालेंगे।

अब माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक बात जयपुर के मीटर रीडर हैं, उनके बारे में कहना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : मिस्टर चौधरी, बात पर बात बहुत निकल रही है।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : जयपुर के मीटर रीडर हैं उनका मुझे एक्सपीरियेन्स है, यहां असेम्बली में भी देखा है। ५० नये पैसे का बिल आता है, इसका दो, तीन महीने बाद बिल आता है और इस तरह ५० नये पैसों का फाइन कन्ज्यूमर पर आ जाता है। एक नहीं दस बिल अलग अलग ५० नये पैसों के आये थे। मीटर रीडर ने लिख दिया कि दी मीटर वाज़ क्लोज्ड, पर असेम्बली का मीटर कैसे क्लोज़ रहता है, जो यहां भी ५० नये पैसों का बिल आता है ? पिछले महीने मेरे पास ५० नये पैसे का बिल आया था, at any odd time you find that the 50 N. P. Bill has come and the reason is that the Meter Reader has not cared to read the meter. उसने नोट लगा दिया खाते में कि मीटर बन्द था। यह ५० नये पैसे का दण्ड है। कोई रिकवरी देता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर आता है। उसको पूछते हैं तो कहता है कि इन्जीनियर को लिखिये। ५० नये पैसे के लिये कौन लिखेगा। हर दूसरे तीसरे महीने ५० नये पैसे का बिल आ जाता है। असेम्बली में आ जाता है, यहां मैंने डिप्टी सेक्रेटरी के हाथ में ऐसा बिल देखा था। हम सर्विस मैन के साथ सिम्पेथी चाहते हैं पर at the same time we want them to be dutiful. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, we are their patrons and they are giving us services. They must see that we are not inconvenienced and penalised unnecessarily.यह उनकी ड्यूटी

(श्री पी० के० चौधरी) .

है and They must be more strict with Meter Readers regarding these matters. यह ५० नये पैसे का बिल आता है, देखना चाहिये कि how many Bills every month are issued for these 50 N. P.

इसके बाद एक सजेशन मैं देना चाहता हूं, वह यह है कि मैथीन गैस के प्रयोग के लिये हमें कोशिश करनी चाहिये। यह काउ डंग से बनता है और इसकी मशीनरी अवेलेबल है। ५०-५१ में डाइरेक्टर थे उन्होंने सुझाव दिया था कि रूरल लाइटिंग के लिये मैथीन गैस को प्रयोग में लाना चाहिये। काउ डंग से गैस प्रोड्यूस करके लाइटिंग के पर्पज़ के लिये यूज किया जाय और The machinery for this purpose is available. It can be converted into electricity also for power to run the pumps etc. इसकी कोस्ट कम होती है और....

(श्री अमृतलाल यादव को सार्वजनिक निर्माण मंत्री के पास बैठे देख कर उनको लक्ष्य करते हुए)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): I think, Sir, the privilege to occupy the Treasury Benches was accorded only to the Hon'ble lady Member and now another Hon'ble Member is occupying the Treasury Benches.

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : But the Hon'ble Member has historicity behind it.

श्री पी० के० चौधरी : But he has renounced, Sir. So the Hon'ble Member need not be afraid it.

अन्त में, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैथीन गैस से रूरल लाइटिंग के लिये गवर्नमेंट को पुरानी फाइल्स देख कर कोशिश करनी चाहिये। It has become successful in Delhi. दिल्ली में सेवेज है उसमें गैस बनता है और उसको लाइटिंग के लिये प्रयोग करते हैं। काउ डंग से गैस पैदा करने के दो फायदे हैं, या तो लाइटिंग के पर्पज़ में प्रयोग किया जाय, it can be used for lighting.......

डॉ० चन्द्रकला : भैंसों के गोबर से बनता है।

श्री पी. के. चौधरी : मेन्योर....

श्री उपाध्यक्ष : Is it relevant to the issue, Mr. Chaudhary ?

श्री पी. के. चौधरी : This is Electricity, Sir. It is meant for lighting.

श्री उपाध्यक्ष: But does this come under this Board's Jurisdiction ?

श्री पी. के. चौधरी : This Board comes under the Hon'ble Minister sitting there and he can give his thought to it and with these words I end my debate.

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राणावतजी।

श्री जयसिंह राणावत : राणावतजी ?

श्री उपाध्यक्ष : I am very sorry, Mr. Ranawat.

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान राजकीय विद्युत मंडल का सन् १९६०-६१ का वार्षिक वित्तीय विवरण एवं सन् १९५९-६० के अनुपूरक वित्तीय विवरण पर आज हम वाद-विवाद कर रहे हैं। मैं सरकार के इस काम की सराहना करता हूं जो उन्होंने जनता की भलाई के लिये अब तक प्रयास किया है और उनका यह प्रयास उत्तरोत्तर सफल होता जा रहा है लेकिन केवल सरकार की प्रशंसा करने से ही हम सफल नहीं हो सकते, उसके साथ साथ हमें उनकी कमजोरियों पर भी प्रकाश डालना होगा। मैं आज अपने संक्षिप्त भाषण में सरकार का ध्यान इस विद्युत मंडल के कारनामों की तरफ दिलाना चाहता हूँ और यह निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो यह मंडल आटोनोमस बोडी है और सरकार ऐसी परिस्थिति के निर्माण में एक ही लफ्ज़ रखती है कि वह सरकार से बहतरीन तरीके पर काम कर सके। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ उदाहरण आपके समक्ष पेश करते हुए दुःख होता है कि जिस सतर्कता से और सफलता से इसे काम करना चाहिये जो नहीं कर सके हैं।

मैं जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आंकड़े यहां प्रस्तुत किये हैं उन आंकड़ों के जाल में नहीं पड़ता और न पड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें इस बात पर ध्यान अवश्य देना होगा जैसा पब्लिक सीधा सोचती है कि हमको बिजली कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी और किस रेट से मिलेगी, इसकी तरफ आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

मैंने जब इसी अधिवेशन में, थर्ड फाइव इयर प्लान फ्रेम जो हमें मिला उसको देखा तो उसको देखने से मुझे खुशी हुई। मगर उसको देखने से जो खुशी मुझे हुई वह आज के इन आंकड़ों को देखने से गायब हो गई है। उन आंकड़ों को देख कर मैं खुश हुआ था कि हमारे जिले में भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जोधपुर वाया पाली और अजमेर बिजली आएगी। मगर मुझे यहां पर जो आंकड़े इसमें दिये हैं उनको देखने से वह बात नहीं पाई गई और यह पता नहीं लगता कि भीलवाड़ा की वही स्थिति है या कम कर दी गई है। जहां तक मैंने इसमें देखा है उससे यही मालूम होता है कि कम कर दिया गया है। इसलिये इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय से थोड़ा सा स्पष्टिकरण चाहूँगा कि भीलवाड़ा के इलेक्ट्रीसिटी के स्तर को कैसे कम कर दिया है ?

इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान उन आंकड़ों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो हिन्दी में दिये गये राजस्थान राज्यकीय विद्युत मंडल के सन् १९६०-६१ का वार्षिक वित्तीय विवरण एवं सन् १९५९-६० की अनुपूरक वित्तीय विवरण के पेज ८ में दिया हुआ है कि जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सीकर और शाहपुरा के श्रमिकों के लिए पखाना, पेशाबघर, विश्रांमगृह, साइकिल रखने के स्थान इत्यादि बनाने के लिए ७०,००० रु० की राशि रखी गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बड़े शहरों के

(श्री जयसिंह राणावत)

लिये, श्रमिकों के लिये पेशाब-घर, विश्राम-गृह आदि के लिये यह रकम किस प्रकार काफी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि इस बारे में दो-ढाई वर्ष पहले एक इर्रिगेशन एण्ड पॉवर कमेटी बनी थी। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मेरा भी नाम उसमें था। मुझे निवेदन करते बड़ा दुःख होता है कि उस कमेटी ने या तो कोई मीटिंग नहीं बुलाई और अगर बुलाई तो उसके बुलाने की सूचना के पीछे ही तीर की तरह टेलीग्राम पहुँचे हैं कि मीटिंग केन्सल कर दी गई है। यदि उसी रफ्तार से यहां पर भी काम होता रहा तो पॉवर और पॉवर हाउस दोनों का काम बर्बाद सा रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान यहां की स्थानीय, राजस्थान की बात को छोड़िये, बात बताता हूं कि यह संस्था जिस तरह से विकसित रूप से काम कर रही है, उसके मैं दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने तो अपनी छोटी सी अव्यवस्था न आने के फर्क की आपके सामने रखी। मैं आपका ध्यान उस ओर जिसमें हजारों रुपयों की अव्यवस्था हुई, आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह कि यहां से सांगानेर दरवाजे के बाहर एक कम्पनी है, जहां मीटर की खराबी के कारण १० युनिट नहीं सैकड़ों और हज़ारों युनिट एक साथ उछल पड़े और उसके मालिक को हजारों का बिल दे दिया गया। उसने जांच के लिये लिखा और जिस समय कर्मचारी लोग घटनास्थल पर आये तो उसने यह मांग की कि इस मीटर की सील आदि ठीक तरह से है इसके लिये इसकी केमरा से फोटो खिंचवा ली जाए। वह केमरा ले आया, मगर फोटो नहीं खींची गई और उसको परेशान किया गया और फोटो खींचे बगैर ही उस मीटर को वहां से हटाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कन्ज्यूमर की कोई गलती हो तो उसको तत्काल ही मौके पर बताना चाहिये और फिर मीटर को हटाना चाहिये। लेकिन मातहत कर्मचारियों को बचाने के लिये उसको इतना हैरेस किया गया जिसकी कोई हद नहीं। मैं आपका ध्यान दूसरी इस बात की तरफ खींचना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : मेरा ध्यान एक ही मर्तबा खींचिये बारबार खींचते हैं तो उचित नहीं है।

श्री जयसिंह राणावत : तो मैं गवर्नमेंट का ध्यान तरफ इस खींचना चाहता हूं कि सहकारी समितियों को कितनी सहायता और प्राथमिकता मिलनी चाहिये मगर किशनपोल दर्वाजे के पास जाटा वाली विश्व कर्मा उत्पादन सहकारी समिति है, जो चर्खे बनाती है उसने मांग की कि हमको पॉवर मिलना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी कई महिनों तक लिखा-पढ़ी चलती रही और लिखा-पढ़ी चलने के बावजूद भी उनको पॉवर नहीं दिया गया और यही कहा गया और टालते रहे कि पॉवर का इन्तजाम नहीं हो सकता। लेकिन मैं बड़े दुःख के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बाद कई व्यक्तिगत इन्डस्ट्रीज़ को पॉवर मिला और वह सहकारी समिति अभी तक पॉवर से वंचित है। तो इस प्रकार

(श्री जयसिंह राणावत)

की बातें इस बोर्ड में होना अच्छी चीज़ नहीं है।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो लेखा-जोखा दिया है उसमें कई गांवों के नाम दिये हैं जहां विद्युत का निर्माण होगा। लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप पहले तहसील स्तर पर बिजली पहुँचाने का प्रबन्ध करें और उसके बाद छोटे छोटे गांवों में बिजली पहुंचाने का प्रबन्ध करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

बस इन्हीं बातों के साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि राजस्थान में शाहपुरा दो हैं इस सारे लेखे जोखे में यह कहीं नहीं बताया गया है कि यह अमुक शाहपुरा है। इसलिए शाहपुरा को मैं भीलवाड़ा का शाहपुरा समझूं या दूसरी जगह का यह इससे प्रतीत नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : लिफाफे भी रद्दोबदल हो जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : दूसरा भीलवाड़ा से काफी दूर पड़ता है।

श्री जयसिंह : राणावत तो इन थोड़ी सी बातों का मैंने निवेदन किया है और आशा है कि इसमें जो गल्तियें रही हैं उनको ठीक करेंगे और जब गल्तियें ठीक होंगी तो काम ठीक तरह से होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल।

श्री चन्दमल वैद (सरदारशहर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्युत मण्डल का सन् १९६०-६१ का आय-व्यय, जो हमारे सामने पेश किया गया हैं उसके बारे में मैं दो-चार बातें कहना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : आय व्यय क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : आय व्यय पत्रिका, अब तो संतोष हुआ आपको ? मैं इस बात का संतोष जाहिर करता हूं कि विद्युत मण्डल बनने के बाद हमारे बिजली विभाग में काफी सुधार हुआ है और तत्परता आई है और जो आंकड़े बताये गये हैं उसमें यह बताया गया है कि हर साल हमको जो नुकसान होता था उसमें भी कमी हुई है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक बात यह कही गई कि विद्युत-मण्डल के नीचे काम करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम हर साल करोड़ों रुपयों का खर्चा करते हैं और पुराने पॉवर हाउसों की मरम्मत कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कर्मचारी तो हों। जब हम किसी चीज को इनोवेट करते हैं तो उसमें कर्मचारियों में वृद्धि तो होगी ही। मेरा तो यह सुझाव है कि आज हमारे यहां टैक्निकल स्टाफ की कमी है। उससे टैक्निकल काम लिया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए आर. ए. एस. और आई. ए. एस. रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। हमने यह देखा भी है कि जहां पर हमने इन्जीनियर्स को, टैक्निकल ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सौंपा हैं वहां वहां पर

(श्री चन्दनमल वैद)

उन्होंने गल्तियां की है, कामयाब या सफली-भूत नहीं हुए हैं । किसी को बिजली का कनेक्शन देना, ट्रान्सफर करना है, इस प्रकार की कई बातें हैं छोटी २ जिनके लिए हमने टैक्निकल ऑफिसर के जिम्मे, सुपरवाइज़र्स के द्वारा ये काम कराये हैं । इन कामों में अधिक गल्तियां भी हुई हैं और ये काम तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आसानी से आर. ए. एस. और आई. ए. एस. ऑफिसर्स नियुक्त करवा सकते हैं। मान लीजिये कि बीकानेर का पॉवर हाउस है उसके लिए सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर है । इस प्रकार के ऑफिसर्स को तो टैक्निकल कार्य हमको सौंपना चाहिये न कि एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य। तो यह मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के कामों के लिए तो आप आर. ए. एस. या आई. ए. एस. ऑफिसर को नियुक्त कर सकते हैं और जैसा कि बताया गया है कि हमारे यहां टैक्निकल स्टाफ शोर्ट पड़ रहा है उसको भी आप मीट आउट कर सकते हैं।

दूसरी बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के विषय में । मेरी बगल में बैठे हुए बयाना से आये माननीय सदस्य को शिकायत थी कि गांवों को बिजली नहीं मिल रही है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्षजी, गलत वर्णन दे रहे हैं। मैंने यह कहा कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मिस नोमर है, राजगढ़ तक बिजली दे रहे हैं तो चुरु रतनगढ़ को क्यों नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : वे आपकी बगल में बैठे हैं ।

श्री चन्दनमल वैद : Any way, मैं तो सुझाव देना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के अन्त तक या थर्ड फाइव इयर प्लान में हर एक जगह बिजली दे सकेंगे। भाखरा नांगल से पॉवर आ रहा है, राजगढ़ से रतनगढ़, बीकानेर लेजाते हैं तो बीच में जितने गांव पड़ते हैं तो उन गांवों में एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, पीने के पानी को खींचने के लिए, बिजली दे सकते हैं। इसी तरह से चम्बल की बिजली एक जगह से दूसरी जगह आ रही है। कोटा से उदयपुर उसको ले जा रहे हैं, कोटा से झालावाड़ भी लेजावेंगे। तो इनके बीच में जितने भी देहात पड़ते हैं, तो उन देहातों में एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, पानी को खींचने के लिए, और अन्य कामों के लिए आप बिजली दे सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि बिजली उनको इस वास्ते दीजिये कि उनके झोंपड़ों में बल्ब लग सकें । आज तो यह लग्ज़री हो सकती है, फ्यूचर के लिए यह उपयुक्त हो सकती है लेकिन आज तो यह लग्ज़री हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन गांवों में जहां कि वे बीच में पड़ते हैं बिजली आसानी से दे सकते हैं ताकि वह बिजली उनके जमीन से पानी खींचने और एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए काम आ सके । इससे उनको यह अहसास भी होगा कि नया ज़माना आ रहा है। खेती के काम में लेकर उसको वे बढ़ा भी सकते हैं और इस दृष्टि से गांवों का रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो सकता है। चम्बल से बिजली देने की बात आयी। हमारा जोधपुर शहर है, वहां पीने के

(श्री चन्दनमल वैद)

पानी की काफी दिक्कत है। कोटा की बिजली उदयपुर तो ले जाना ही है, इस पर फिर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि क्या हम इस बिजली को जोधपुर नहीं ले जा सकते हैं। मैं समझता हूं और मेरा यह निश्चित मानना है कि यह संभव है। इसके लिए गम्भीरता से विचार करें और प्लान आउट करें। मेरा यह निश्चित रूप से मानना है कि यह असंभव नहीं है, इसको असंभव माना जाता है तब भी इसको संभव किया जा सकता है और इससे जोधपुर के पानी की शिकायत दूर हो सकती है।

इसके अलावा एक बात इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि मुझे इस बात के लिए काफी एतराज है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यह मान कर चलता है कि हम इसको कमर्शियल बेसिस पर चला रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसी बातें देखी हैं कि जिनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कमर्शियल बेसिस के नजदीक भी नहीं फटक रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हमने यह देखा है कि ५७ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना और राजस्थान सरकार से जो असेट लिये, पॉवर हाऊसेज़ लिये, सामान लिया, उसकी वेल्यू आज तक भी असर्टेन नहीं की गई है। हमें यह भी पता नहीं है कि कितना डेप्रिसियेशन चार्ज कर रहे हैं। कितना हमको असेट मिला है, क्या वेल्यूएशन थी उस वक्त में और आज उसकी कितनी है, तीन साल हो गये लेकिन यह मालूम नहीं है कि राजस्थान सरकार से इस बोर्ड ने जो चीजें लीं, असेट लिये, वे अच्छे थे या खराब हालत में थे। उस वक्त राजस्थान सरकार ने सोच लिया कि १ लाख की चीज़ है लेकिन अब कहे कि १० लाख की है तो यह नहीं कहा जा सकता। डिपार्टमेन्टल तौर पर यह बताया जाना चाहिये था कि कितने असेट्स थे, कितने किस हालत में मिले, मान लीजिये कि बीकानेर कन्टरबाइन है, उसकी कितनी कीमत है, तीन साल में कितना खराब हुआ या अच्छा है। यह कुछ भी मालूम नहीं होता। कमर्शियल बेसिस पर यह चीज़ चलने वाली नहीं है। आज बोर्ड यह बताने की स्थिति में नहीं है क्या चीजें बोर्ड को मिलीं हैं और किस हालत में मिली हैं। इसके साथ साथ यह भी नहीं बताया कि क्या इन्ट्रेस्ट बोर्ड देने वाला है या दे रहा है। मैं केपिटल एक्सपेन्डीचर का इस समय जिक्र नहीं कर रहा हूं। रेवेन्यू की जो डेफिशियेन्सी है, डे पर डे बढ़ रही है। राजस्थान गवर्नमेन्ट से कर्जा ले रहे हैं और यह कोशिश की जा रही है कि वह कर्जा इन्ट्रेस्ट फ्री दिया जावे लेकिन कहीं भी डेप्रिसियेशन नहीं रखा गया है। बड़े ताज्जुब की तो बात यह है कि जमा और कर्जे की पूंजी तो सामने रखी रहती है और यह पता नहीं है कि कितना ब्याज देना पड़ेगा। कमर्शियल बेसिस पर हिसाब रखने वाला कोई भी यह नहीं सोच सकता कि चूंकि इन्ट्रेस्ट फ्री करावेंगे इसलिए इसको मद्देनज़र नहीं रखें कि कितना ब्याज देना पड़ेगा यह हो नहीं सकता, कर्जा ले रहे हैं, इन्ट्रेस्ट फ्री होगा या नहीं यह अभी जाने दीजिये लेकिन साहूकारी ब्याज होता है उसको तो इसमें सामने रखना ही चाहिये। इस हिसाब से इसमें यह क्लीयर पिक्चर रखी जानी चाहिये कि इतना तो राजस्थान सरकार से ले चुके हैं, १० लाख, १५ लाख, और

(श्री चन्दनमल वैद)

साहुकारी ब्याज के हिसाब से. कर्जा बिना ब्याज नहीं किया गया है, इसलिए १,२ लाख लाख ब्याज के होंगे, ११ का तो यह घाटा है और १. २ लाख का यह घाटा होगा, कुछ इस तरह से मिला कर १३, १५ लाख का घाटा होगा । जो कमर्शियल बेसिस पर कन्सर्न को चला रहा है यह कोई भी व्यापारी इस प्रकार से पसन्द नहीं करेगा कि ये चीजें उसमें न रहें ।

एक ताज्जुब की बात यह भी है कि बजट की प्रत्येक चीज़ को देखने के बाद यह कहीं भी नहीं मालूम होता कि हमारा कितना रुपया कन्ज्युमर्स में बाकी है । इसका कहीं भी इस बजट पत्रक में पता नहीं चलता । मेरी नोलेज में है, मुझे इसकी जानकारी है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह रकम करोड़ों तक नहीं है तो ३०. ४० लाख तो जरूर है । इसमें कोई शंका नहीं है । एक तरफ तो इस बोर्ड को कमर्शियल बेसिस पर चला रहे हैं और राजस्थान सरकार से दया प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कर्जा ले वह इन्ट्रेस्ट फ्री हो और दूसरी तरफ यह पता नहीं कि कन्ज्युमर्स में कितना रुपया बाकी है । कमर्शियल बेसिस पर रन करने वाला व्यौपारी को यह पहले जानना होगा कि कितना रुपया कर्ज लिया, कितना ब्याज दिया, किस किस में बाकी है और कुल क्या असेट्स हैं । यह पता लगा कि एक माननीय सदस्य हैं सदन के, उनमें १३ हज़ार रुपया बाकी है। माननीय सदस्य कौन हैं, किस वजह से उनमें बाकी हैं, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता । लेकिन यह सही है कि उनमें बाकी है, बहुत से गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स हैं, आई. ए. एस. में बाकी है, राजा महाराजाओं में बकाया है, बहुत से व्यक्तियों में बकाया है । माननीय सदस्य जो जयपुर से आते हैं वे फर्मा रहे थे कि आय–व्यय के आंकड़े स्पष्ट पेश नहीं किये गये हैं । इसी वास्ते यह पेश नहीं किये गये । मैं मानता हूं कि हमें यह नहीं बताया गया कि हमारे कितने एरीयर्स, किन २ में, कितने बाकी हैं । हमको यह निश्चित रूप से बताना चाहिये था कि कितने बाकी हैं । मैं समझता हूं कि इसके लिए एक कमेटी बनानी चाहिये, इसके लिए एक ऑफिसर नियुक्त करना चाहिये ताकि वह देखे कि कितने एरीयर्स वसूल कर सकते हैं ! यदि वसूल नहीं कर सकते हैं तो उनको राइट ऑफ करना चाहिये । जो बाकी वसूल किये जा सकते हैं उनको कड़ाई के साथ वसूल किये जाने चाहिये । मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी के एक मामले में मैं आपको बताऊं कि पांच नये पैसे बाकी होने से कनेक्शन काट दिया गया, परेशान किया गया और न जाने किन किन एप्लीकेशन्स के नाम पर १०) २०) रुपया वसूल किया गया । एक तरफ पांच पैसे के लिए हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं, दूसरी तरफ हजारों लाखों रुपया लोगों से लेना बाकी पड़ा है, कारण पेश नहीं करते, बताते नहीं । मैं समझता हूं कि यह कॉमर्शियल बेसिस पर कन्सर्न चलाने का तरीका नहीं है । इसको आप सुधारिये और निश्चित रूप से इस ओर ध्यान दीजिये ।

इसके अलावा मुझे बीकानेर पॉवर हाउस में जो गड़बड़ी होती है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना है । मैं नहीं समझता कि वहां का पॉवर हाउस कमर्शियल बेसिस पर चलता है या डेमोक्रेटिक बेसिस पर चलता है उसको देखते हुए तो यह पता

(श्री चन्दनमल वैद)

चलता है कि वह आटोक्रेटिक बेसिस पर चल रहा है। यहां से जो कोई ऑफिसर भेजा जाता है वह वहां जाकर यह समझने लग जाता है कि यह तो एक प्रकार से उनको जागीर मिल गई है जिस तरीके से चाहे जो रेट वसूल कर सकता है, चाहे जिसका कनेक्शन ट्रान्सफर हो जाता है। यहां तक कि टी० बी० के रोगियों को टेम्परेरी कनेक्शन तक नहीं दिया जाता और दूसरी तरफ जो अपना कनेक्शन सेल करते हैं उनका ट्रान्सफर मन्जूर हो जाता है। एक आदमी जो कहता है कि मुझे इसका कनेक्शन इस मकान से दूसरे मकान में ले जाना है तो वह सैंक्शन नहीं होता दूसरी तरफ कोई इन्फ्लुएन्सल आदमी है चाहे वह कमेर्शियली हो या इकोनोमिकली हो वह यदि कनेक्शन चाहता है तो उसको फौरन मिल जाता है। डाक्टरों के सर्टिफाइ करने के बावजूद भी टी० बी० के रोगियों को कनेक्शन वह भी टेम्परेरी नहीं मिल पाता। कुए से पानी खींचने के लिये कनेक्शन नहीं मिल पाता। मैं नहीं समझता बीकानेर पॉवर हाउस के साथ यह दुर्भाग्यपूर्ण रवैया क्यों हो रहा है यह इसलिये कि बीकानेर जयपुर से दूर है इसलिये उस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता या मुझे अन्य जगहों पर होने वाली खामियां दिखाई नहीं देती होंगी। चूंकि मैं बीकानेर के पास का रहने वाला हूँ इसलिये बीकानेर पॉवर हाउस की खामियां तो नज़र आ जाती हैं जयपुर की नहीं। कुछ बात ऐसी हैं कि बीकानेर पॉवर हाउस के लिये जितना ध्यान दिया जाना चाहिये उतना ध्यान दे नहीं रहे हैं इसलिये मंत्री महोदय से व उप मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस तरफ ध्यान देकर वहां पर जो गड़बड़ियां हैं उन्हें दूर करने की चेष्टा करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा, सन् ५६ में वहां के लिये सुपरवाइज़र्स का एग्ज़ामिनेशन हुआ था और वह भी रिटन एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसमें कुछ रिटन पेपर्स भी थे और उनके आधार पर उनको पास किया गया। मैंने इस संबन्ध में १९५६ के पेपर्स भी प्राप्त किये; उनको देखा जाय तो जो लोग इसमें पास होकर सुपरवाइज़र्स की पोस्ट पर आये हैं उनमें से कई तो ऐसे हैं जो इस पेपर को पढ़ तक नहीं सकते, लेकिन वे सुपरवाइज़र के इम्तिहान में पास हुए हैं और अभी तक कार्य कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि उनके एग्ज़ामिनेशन किस आधार पर हुए इस तरह की बीकानेर पॉवर हाउस में काफी गड़बड़ियां हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे मंत्री महोदय उन गड़बड़ियों की तरफ ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर के पॉवर हाउस का जहां तक ताल्लुक है मैं समझता हूं वह इतना अन–फोर्चुनेट और निगलेक्टेड रहा है जितना शायद ही कोई पॉवर हाउस रहा हो। बीकानेर पॉवर हाउस में घाटा क्यों हो रहा है ? जहां कम्फर्ट्स और लग्ज़ारी का सवाल है वहां बीकानेर के पॉवर हाउस को मैं महत्व नहीं देता इसका खास महत्व इसलिये है कि यह वहां की बेअर नेसेसिटी को सप्लाई करता है। बीकानेर का पॉवर हाउस न केवल शहरों तक बल्कि देहातों को भी बिजली देता है। बीकानेर पॉवर हाउस कम से कम तीस चालीस कस्बों और देहातों में बिजली सप्लाई करता है और खास तौर से ज्यादातर कुओं से पानी निकालने के लिये। वहां पर पानी एग्रीकल्चर के लिये काम में

(श्री चन्दनमल वैद)

लाया जाता हो या बाग बगीचों की सिंचाई के लिये काम में लाया जाता हो, यह बात नहीं, वहां का पॉवर हाउस बेअर नेसेसिटी की पूर्ति करता है जैसे पीने के पानी की तकलीफ को चूरू और बीकानेर जिले में दूर करता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि केवल इस आधार पर कि यहां पर भाखरा से बिजली आने वाली है इसलिये उसकी मरम्मत तक नहीं की जाती। चेप सांध कर काम चलाया जाता है और भाखरा की बिजली आने में निरन्तर विलम्ब होता जा रहा है, पहले यह था कि ५५ में बिजली मिल जायगी फिर ५७ हुआ उसके बाद ५६ और ६० और अभी अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इस बात का उल्लेख था कि मार्च के प्रथम सप्ताह में वहां पर भाखरा से बिजली उपलब्ध हो जायगी। लेकिन आज अप्रेल का प्रथम सप्ताह चल रहा है लेकिन अभी तक बिजली के उपलब्ध होने की कोई आशा दिखाई नहीं देती। एक तरफ तो भाखरा से बिजली मिलने की आशा में बीकानेर पॉवर हाउस की मरम्मत नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ हालत यह है कि बीकानेर पॉवर हाउस से जहां ३०-४० कस्बों को बिजली मुनस्सर होती है वहां यदि हालत इसी प्रकार रही तो ज्यों ज्यों गर्मी का प्रकोप बढ़ता जायगा वहां के लोगों को पीने के लिये पानी का मिलना मुश्किल होता जायगा। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से खास तौर निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर गंभीरता से सोचें और जो भी गड़बड़ हो, उसको ठीक करने की कोशिश करें। भाखरा से बिजली आने में अभी देरी हो तो उनको चाहिये कि बीकानेर पॉवर हाउस को कम से कम इस योग्य तो रखें कि पीने के लिये पानी निकाला जा सके। अगर वहां पानी की स्थिति खराब हो गई तो बीकानेर और चूरू जिले में बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है, जान और माल का खतरा होने वाला है; इसलिये निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देंगे। इतना ही निवेदन कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विद्युत मंडल के सम्बन्ध में बहस चल रही है, मैं इस सम्बन्ध में अपने थोड़े से विचार रखना चाहती हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जब हमने देखा कि किशनगढ़ ब्लॉक, जो सन् ५२ में इन्डिया में खुलने वाले ब्लॉकों में से पहला ब्लॉक था वहां पर बिजली ले जाने की बात थी, यह स्कीम प्रथम पंचवर्षीय योजना में ली गई थी। लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि क्या हुआ, प्रथम योजना काल में पूरा होते होते दूसरी पंच वर्षीय योजना तक पहुंच गया। वह स्कीम अभी तक पूरी नहीं हो पायी वहां हम देखते हैं कि पोल्स लगे हुए हैं, कुछ जगहों पर तार लाइन भी आगई है लेकिन अभी तक वह स्कीम जब कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल समाप्त होने आया है वह योजना पूरी नहीं हो पायी है और न हमें इस बारे में जानकारी मिल सकी है कि आया यह कार्य किस गति में है और आगे क्या गति होने वाली है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह स्कीम इतनी पुरानी है कि इसको कार्यान्वित होने में इतना समय नहीं लगना चाहिये था। इतना समय क्यों लग रहा है इस बारे में वे ही जानकारी दे सकेंगे मेरा तो यह निवेदन है कि श्रीमती रामेश्वरी नेहरू वहां आयीं तो उनका भी

(श्रीमती गंगादेवी हाटा)

यही ख़्याल था कि यह स्कीम कार्यान्वित होनी चाहिये क्योंकि इस ब्लॉक के अन्तर्गत करीब चालीस गांव हैं जो इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। अब जो नया टरबाइन वहां अगस्त तक चालू होने वाला है उससे हम उम्मीद करते हैं कि किशनगढ़ की जो स्कीम है वह कामयाब हो सकेगी। लेकिन इसके साथ साथ यह भी है इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो कहीं यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना से तृतीय योजना में न चला जाय यह, शंका पैदा होती है। इस स्कीम की तरफ ध्यान दें और जल्दी से जल्दी इसको कार्यान्वित किया जाय, यही मेरा निवेदन है।

(२. ५२ म० प०)

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : चेयरमैन महोदय, आपके द्वारा मैं मन्त्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जोबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज के वास्ते चार लाख रुपये का कई अर्से से, साल का साल इलेक्ट्रिसिटी देने के लिये हुक्म हो जाता है और वह धन राशि यों ही खतम हो जाती है। राजधानी के सबसे नजदीक बल्कि बीच में होते हुए भी, जयपुर सांभर और फुलेरा के बीच में होते हुए भी, अत्यन्त आवश्यक होते हुए भी यह मामला अभी तक खटाई में पड़ा है। अगर यह चीज पूरी नहीं होती है तो ताज्जुब नहीं कि संस्था का अस्तित्व में भी फरक पड़ जावे। ऐसी स्थिति में अत्यन्त आवश्यक है यह कि जल्दी से जल्दी चाहे वहां अलग से प्लान्ट न लगाकर जयपुर से ही बिजली जोड़कर या भाखरा की नहर यहां तक आये तो उससे जोड़ कर इस काम के वास्ते रखी गई रकम काम में ली जावे। खास तौर से मेरा यही निवेदन है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय–व्ययक ६०–६१ का स्टेटमेंट वाद विवाद के लिये सदन में प्रस्तुत है। उस पर मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं। हम सब जानते हैं कि इसकी स्थापना जुलाई ५७ को हुई और यह बजट इसका दूसरा बजट है। अपने शैशव काल में इस विद्युत मण्डल ने जो काम किया है जो अपना विकास किया, वह बहुत आशाजनक है। इसके विषय में घाटे की बात कह कर या जितनी हमारी आय है व्यय के मुकाबले में वह थोड़ी कम पड़ती है, इसको देख कर कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहली बात तो यह है कि शैशवावस्था के अपने दो तीन साल में इसने जो कुछ किया वह काफी सन्तोषजनक है और बच्चे का जब विकास का समय होता है उस समय खर्चा थोड़ा ज्यादा भी करते हैं तो कोई बात नहीं होती, बड़ा होकर वह उसे पूरा कर देगा, आज के इस खर्चे का आगे बदला मिलेगा। आगे चलकर हमको वह बदला अच्छा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं और इसमें जो ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बच्चा घाटे में चल रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : बड़ा होगा तो पूरा कर देगा। आप धैर्य रखियेगा थोड़ा सा।

(डॉ० चन्द्रकला)

विद्युत मंडल की दो-तीन तरह की स्कीम्स हैं; हाइड्रोइलेक्ट्रिक थर्मल और दूसरी तरह की। इससे साफ मालूम होता है कि यह विद्युत मण्डल किसी तरह से अपने सब साधनों से विकास की ओर प्रयत्नशील है और इसके सम्बन्ध में जो दूसरी छोटी-मोटी बातें कही गई, मेरा खयाल है कि वह उन पर ध्यान देगा और उन खामियों को यह मण्डल जल्दी से जल्दी दूर करते हुए आगे अच्छा काम कर सकेगा।

सन्तोष की बात है कि भाखरा-नांगल से जल्दी बिजली प्राप्त होने लगेगी लेकिन जिस तरह कि सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि हमारे विद्युत मण्डल को चाहिये कि वह अपने आश्वासन पूरे करे तो आशा और आश्वासन को पूरा करना चाहिये।

मुझे विशेष सन्तोष इस बात का हुआ कि इस आर्थिक वर्ष के अन्त तक जयपुर को भी बिजली मिलने लगेगी।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर –सु०) : आशा ही करिये।

डॉ० चन्द्रकला : आशा तो बड़ी चीज़ है।

३. म० प०

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बताया कि हमारा पॉवर जयपुर शहर और उसके आसपास ही खर्च होता है और जब चम्बल की बिजली आ जावेगी और यहां का थर्मल एंजिन भी काम करता रहेगा तो दोनों मिल कर बहुत कुछ फायदा जनता को दे सकेंगे। तो इस तरह जहां तक पॉवर के उत्पादन का सवाल है तो इस दिशा में हमारा विद्युत मण्डल सन्तोषजनक प्रगति कर रहा है; पर विद्युत के वितरण का जहां सवाल है उसकी ओर मण्डल का ध्यान मैं अवश्य ही दिलाना चाहूंगी। इसकी ओर उसका कम ध्यान है। ऐसा लगता है कोई ठोस स्कीम इसकी उसके पास नहीं है।

जिस तरह अन्न उत्पादन की समस्या बहुत बड़ी है उसके साथ साथ वितरण का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से पॉवर भी उतना ही उपयोगी है कि इसके उत्पादन के साथ साथ वितरण का भी ध्यान रखा जावे।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मण्डल की ओर से जो पॉवर का वितरण हो रहा है वह उचित नहीं हो रहा है। हमें देखना पड़ेगा कि पॉवर का सबसे अधिक कहां उपयोग करना है। अभी तो हमारा विद्युत शक्ति का बहुत कुछ प्रतिशत लग्ज़री में खतम होता है। मतलब गर्मी सर्दी में लोगों के पंखों के लिये और अन्य कार्यों के लिये शहरों में बहुत अधिक खर्च होती है। जहां तक यह जरूरी हो वहां तक तो इसका खर्चा कर सकते हैं लेकिन यह देखना होगा कि लग्ज़री हमारी नेसेसिटी नहीं है, नेसेसिटी हमारी और है। किसानों को आज कितना कम पॉवर मिल रहा है। अगर रोटी नहीं मिलेगी तो हम इस लग्ज़री को भूल जायेगें। इस दृष्टि से सबसे अधिक उपयोग इसका उद्योग धन्धों में किसान के

(डॉ० चन्द्रकला)

कामों में हो इसके लिये मुझे मण्डल का ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जयपुर में यह मण्डल है, यह राजधानी है, हमारे मन्त्रीगण यहां रहते हैं, पर वितरण का सबसे खराब नमूना भी यहां ही देखने में आता है! कहीं तो यहां बिजली का इतना सारा उपयोग होता है कि लग्ज़री भी नेसेसिटी बन गई है और उसके लिये सारे साधन उपयोग में आ रहे हैं लेकिन जयपुर शहर में ही अभी भी मेरा खयाल है कि पचास प्रतिशत से भी अधिक जनता अन्धेरे में रहती है। उनके घरों में नहीं हो यह दूसरी बात है पर पूरी उनकी बस्ती की बस्ती में अन्धकार पड़ा है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : दिये तले अन्धेरा है।

डॉ० चन्द्रकला : वह आपके लिये। विद्युत मण्डल यह भी सोचे कि लोगों की आवश्यकता को किस तरह से पूरा किया जावे, इसकी योजना बनावे। बड़ा विरोधाभास सा लगता है जब कि आप एक ओर तो हम लोगों को आधुनिकतम साधन दे रहे हैं, नये से नये ढंग की बत्तियां देने को जा रहे हैं और दूसरी तरफ बिजली का उजाला तक उपलब्ध नहीं है। यह ध्यान देने की बात है। जयपुर शहर में आज दिन तक भी ऐसी बड़ी बड़ी बस्तियां, सड़कें और गलियां ऐसी पड़ी हैं जो बिल्कुल अन्धेरे में अपनी गुज़र कर रहे हैं। वहां एक बत्ती भी सरकार मुहैय्या नहीं कर पा रही है। हम जौहरी बाज़ार को एकहरा, दुहरा और तिहरा बिजली से प्रकाशित और जगमग करना चाहते हैं, दूसरी दूसरी सड़कों पर अच्छी अच्छी बत्तियां लगा रहे हैं पर दूसरी तरफ बस्तियां की बस्तियां अन्धेरे में पड़ी हैं। वहां के लोग एक एक बल्ब की मांग करते रहते हैं पर आप उनको तो एक छोटा सा बल्ब भी मुहैय्या नहीं कर सकते। तो इसका क्या कारण है। मेरी समझ में नहीं आता। इसके साथ मैं आपका ध्यान जयपुर शहर की नगरपालिका की सीमा के भीतर और उसके आस पास रहने वाले किसानों की कठिनाइयों की ओर भी खींचना चाहती हूं। उनको बिजली मिलती है उसमें अधिकांश ऐसी है जिनको सरकार रात्रि के घण्टों में देती है।

रात्रि को दस बजे जब सारी दुनियां का कारोबार बन्द हो जाता है तब आप किसान को कहते हैं कि तुम अपना काम अब करो। जो सबसे अधिक अच्छा काम करता है, आपके लिये अन्न की समस्या में हाथ बंटाता है, साग सब्जी आदि पैदा करता है और बहुत सा अन्य अन्न पैदा करता है, जन जीवन के पालन-पोषण में बहुत बड़ा हाथ बंटाता है उनको रात्रि के घंटों में बिजली मिलती है। यह कोई भी बड़ी आसानी से अनुभव कर सकता है कि किसान को रात्रि में काम करने में कितनी कठिनाई आती होगी। कहीं पानी का नाला टूट गया तो अन्धेरे में देख नहीं सकता, पानी नहीं जा रहा है। तो मैं कहूंगी कि आपको चम्बल से बिजली मिलने वाली है। आप सबसे पहले इनकी ओर ध्यान दें।

(डॉ० चन्द्रकला)

इसके साथ ही बिजली की दरों की बात है। जहां तक मुझे मालूम है दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में, आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, हमारे यहां आठ आने और छः आने यूनिट है। तो हमको अभी पैसे की जरूरत है तो और ज्यादा भी ले रहे हैं तो अभी कुछ ऐतराज किसी को नहीं हो सकता, पर जब आपके पास चम्बल आदि जगहों से बिजली आने लगे तो जल्दी से जल्दी हमें सस्ती बिजली भी उपलब्ध कराने का प्रयत्न करना पड़ेगा। इसके साथ ही उद्योग धन्धों को सस्ती रेट पर देने की बात कही गई इसका मैं भी समर्थन करती हूं और मैं आशा करती हूं कि सरकार सस्ती से सस्ती दर पर देने का इनके लिये प्रयत्न करेगी।

इसके साथ ही वितरण पर और गौर करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास इसका कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं है। हम किसी एक के कहने से कहीं काम ले लेते हैं, तो किसी दूसरे खयाल से दूसरी जगह का काम ले लेते हैं। किसी तीसरे खयाल से तीसरी जगह ले लेते हैं। अस्तु, वितरण की एक बड़ी अच्छी योजना बना कर आप सबको समान वितरण करें और इस ओर ध्यान देना चाहिये।

जोबनेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जोबनेर के बारे में बताया, इसी सदन में बताया गया था कि कॉलेज में एक छोटा सा जनरेटर लगेगा। यहां तक तो शायद विभाग से....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): वह भी अभी तक तीन वर्ष से खटाई में पड़ा है।

डॉ० चन्द्रकला : मैं तो विद्युत मण्डल की व्यवस्था के लिये कहना चाहती हूं। वह जब चार लाख कॉलेज के लिये खर्च करना चाहते हैं तो थोड़ा और उस में मिलाकर क्यों न ज़रा सी बड़ी स्कीम बना लें और जयपुर-जोबनेर का रास्ता जो करीब २५-३० मील होगा....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : २० मील ही है।

डॉ० चन्द्रकला : इस बीस मील के रास्ते में खम्भे गाड़कर यहां से बिजली ले जावें और उससे आसपास के लोगों को भी इसका फायदा दें। इससे आमदनी भी होगी। तो, इस तरह की योजना बनाते समय यह सोचकर कि एग्रीकल्चर कॉलेज में तो देना ही है वहां के नागरिकों को भी उसकी जरूरत हो सकती है दे सकते हैं आप। तो इन बातों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और यह विभाग को देखना पड़ेगा। इसके साथ ही जो बकाया की बात कही वह सचमुच चिन्ता का विषय है। समझ में नहीं आता कि कैसा यह विभाग है और कैसी हमारी सरकार है कि उसके इतने बड़े बड़े बकाया हैं और उसे उनका ध्यान भी नहीं है। तो इसके विषय में ज्यादा न कह कर इतना ही केवल कहना चाहती हूं कि विद्युत मण्डल को इस तरफ ध्यान देकर अपनी बकाया रकम की वसूली करनी चाहिए नहीं तो यह तो बीमारी है। यदि बकाया रह गया तो वह और भी बढ़ता चला जायेगा और बड़ी बड़ी बकाया तो आप बाकी रखते हैं और छोटे छोटे बकायों के लिए रोज़ कनेक्शन्स काटते रहते हैं। किसानों को सबेरे ८ बजे तक का समय काम करने का मिला हुआ

(डॉ० चन्द्रकला)

है अगर उनको ५ मिनट भी ज्यादा समय लग जाता है और किसी दिन यदि ज्यादा मशीन चला लेता है तो उनका कनेक्शन दूसरे ही दिन कट जाता है और काफी पेनल्टी के बाद और दौड़-धूप के बाद फिर कनेक्शन मिलता है। पर जो बड़ी बड़ी बकाया है यह विद्युत मण्डल को कैसे बर्दाश्त होती है। तो यह जो असेट्स मिले हैं उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया। उनको दोहराकर मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूं। लेकिन मैं तो, सभापति महोदय, आपके द्वारा एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारी सरकार 'अधिक अन्न उपजाओ' और अन्न बचाओ का आन्दोलन करती रहती है और मितव्ययता के लिए या अल्प बचत योजनाओं की बात कहती रहती है। उसी तरह से हमारे विद्युत मंत्री को जनता से अपील करनी चाहिए कि बिजली का अधिक से अधिक सदुपयोग करें और बिजली को बचायें यानि इस तरह का आन्दोलन सरकार की तरफ से आना चाहिए। मैंने सुना है कि लड़ाई के बाद जबकि इंग्लैंड की हालत बहुत खराब हुई, तो वहां की सरकार ने जनता से कहा कि हीटर्स को मत जलाओ; लग्ज़री को छोड़ दो ताकि जो शक्ति बचे उसका उपयोग उद्योग धंधों में हो सके और उनका विकास हो सके। जैसा अपने देश का नैतिक चरित्र है, जैसी हमारी जनता है, हम लोग हैं उस में हम आशा नहीं कर सकते हैं कि इसके द्वारा शत प्रतिशत सफलता प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन कुछ न कुछ असर जरूर पड़ सकता है। हम रोज़ देखते हैं बिजली का अपव्यय बहुत होता है और वह अपव्यय मैं तो राजकीय प्रवास में देखती हूं कि किस तरह से बिजली बेकार में जलती रहती है। वही बिजली दूसरी जगह हो तो बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है....

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, कभी कभी अंधेरा भी हो जाता है।

डॉ० चन्द्रकला : इस तरह से जनता का ध्यान बिजली को बचाने की ओर या उसके सदुपयोग की ओर नहीं है तो जनता में इस तरह की थोड़ी जागृति पैदा करने की जरूरत है कि पॉवर भी हमारे लिए अन्न के बाद दूसरे नम्बर की उपयोगी चीज़ है। इसलिए इसका भी सदुपयोग करें और जहां तक हो सके अधिक से अधिक बिजली की बचत की ओर ध्यान देना चाहिए। अभी हमारी लॉबीज़ के अन्दर चार कूलर्स लगे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इनकी जरूरत ही क्या है? हम सात-आठ दिन ही यहां और रहने वाले हैं और गर्मी पड़ने वाली है नहीं, फिर हम चले जाने वाले हैं और फिर जब दुबारा आयेंगे तो सर्दी पड़ने लग जायेगी।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो भाषण देकर चली जाती है और सदस्यों को बैठे रहना पड़ता है।

डॉ० चन्द्रकला : अगर यह कूलर, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास के लोग जो कि बारह महीने काम करते हैं उनके यहां लगते तो वे अधिक सुख का अनुभव करते। यह भी हमारे विद्युत के वितरण का नमूना है। मैं तो यही कहती हूं कि उत्पादन की ओर तो हम सन्तोष प्रकट करते हैं लेकिन वितरण

(डॉ० चन्द्रकला)

व्यवस्था की ओर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। साथ ही उसके सदुपयोग की ओर भी ध्यान देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपव्यय बचाने की ओर कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो अपनी शक्ति को विकसित करेंगे और दूसरे लोग उसका अधिक से अधिक उपयोग कर पायेंगे।

श्री सभापति : श्री हरिप्रसाद यादव।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर–सु०) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राजकीय विद्युत मण्डल के बजट पर बहस हो रही है तो मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं भी विद्युत मण्डल के बारे में कुछ बयान करूं। राजस्थान राज्य बहुत बड़ा प्रदेश है जबकि मुझसे पूर्व वक्ता ने काफी कहा। कुछ लोगों ने जोधपुर के लिए कहा और कुछ लोगों ने जयपुर के लिए कहा कि हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने उन करोड़ों प्राणियों की आवाज़ को रखूं....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कोई यह कहते हैं कि जोधपुर को बिजली नहीं मिलती', 'मैं कहता हूं कि आपको 'माननीय सदस्य' कहना चाहिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : किसी भी ग्रन्थ में नहीं लिखा है कि कोई एवं कुछ भी कहें, मैं माननीय डागा साहब से अपील करूंगा कि वे सुनें। माननीय सभापति महोदय, तो मैं राजस्थान के विद्युत मण्डल की ओर आपका ध्यान खींचूं कि सन् ५७ से इस मण्डल की स्थापना हुई। अभी जयपुर से ही आने वाली माननीय सदस्या ने अपने बयान में यह बताया कि मण्डल का अभी यह बचपन है तो मैं आपको राजस्थान में जो बड़े बड़े बन्ध हैं। राजस्थान के पड़ौसी राज्य मध्यप्रदेश में भी हमारे पडोस में जो बड़ा बन्ध बना है मैं आपको एक उदाहरण पेश करूं कि हमारी मेवाड़ की वीर भूमि उदयपुर डिविज़न के चित्तौड़ जिले के पड़ौस में गांधीसागर डेम है और उससे हमारे राजस्थान के कई जिलों को बिजली उपलब्ध होगी। चित्तौड़ के पास चित्तौड़ जिले में जो बन्ध है जिसमें हमारी हजारों एकड़ जमीन डूबी और चतौड़ जिले के पास पहाड़ी एरिया है और वहां आदिवासी लोग निवास करते हैं और वह अपनी हमेशा गुज़र बसर उस जमीन से अन्न पैदा करके करते हैं। हम यह आशा लगाये बैठे थे कि हमारे राजस्थान के विद्युत मंत्री और इस विद्युत मण्डल के कुछ माननीय सदस्य मेरे अजीज़ दोस्त और जिन्होंने कि योजना तैयार की तो माननीय सभापति महोदय, गांधीसागर से जो बिजली मिलेगी उस बिजली का वितरण किया है गोटड़ा, झालावाड़, सवाई- माधोपुर और उदयपुर को। उदयपुर में एक करोड़पति फर्म जावर माइन्स लग रही है। उदयपुर में मेरे क्षेत्र वल्लभनगर, भोपालसागर के बीच में होकर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जायेगी। तो पानी और बिजली हमारे पास से निकलते हैं मगर फायदा हमको नहीं मिलता है। पहली बात तो मैं यह कह रहा हूं कि विद्युत मण्डल के सदस्यों ने यह नहीं देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की लाइन कहां होकर जा रही है। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि चित्तौड़ जिले के आदिवासी ....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): गांधीसागर चित्तौड़ जिले में नहीं बना।

श्री हरिप्रसाद यादव : वह तो मध्य-प्रदेश में है। आपको थोड़ी अक्ल रखनी चाहिए। हां, तो सभापति महोदय, मैं विद्युत मण्डल के विषय में निवेदन कर रहा था कि उदयपुर डिविज़न में जो बिजली मिलेगी तो केवल जावर माइन्स के कारखाने को और इस वर्ष नहीं मिलकर अगले वर्ष में मिलेगी, उसमें लिखा है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचूं कि आप उस रिपोर्ट को पढ़ें और रिपोर्ट को पढ़ कर जावर माइन्स को जो बिजली देना चाहते हैं उसके लिए उदयपुर तक ले जायेंगे तो जिस रास्ते से वह गुज़रती है उस एरिया को आप दे दें तो वहां के किसानों और मज़दूरों को और छोटे छोटे कृषकों को फायदा मिलेगा। वे इलेक्ट्रिक मोटर लगाकर और पानी खींचकर हमारे देश की तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन बढ़ायेंगे।

दूसरा, जहां पर मध्य-भारत की ओर से जहां एक बहुत बड़ा बांध बनाया जा रहा है तो राजस्थान राज्य के मंत्री महोदय से मैं यह अपील करूंगा कि हमारे राज्य की ओर से मध्य-प्रदेश की सरकार से लिखा पढ़ी करे। यह बान्ध नर्बदा के कुछ हिस्से को लेकर बनाया जा रहा है।

श्री सभापति : बान्ध की बात नहीं है यहां पर बिजली की बात है। आप हाउस में आपस में बात नहीं करें।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं बिजली के संबन्ध में ही बोल रहा था। अगर ऑर्डर, ऑर्डर, को परमार हो गई तो अलग बात है।

(हंसी)

श्री सभापति : आप उनसे बात नहीं करें। बिजली की बात पर बोलें। यह मेरा ऑब्जेक्शन था कि आप उनसे सीधी बात नहीं करें।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, उदयपुर डिविज़न के पहाड़ी इलाकों में बिजली देने की बात कह रहा था। जब कि हमारी सरकार ने बान्ध बनाये हैं और भाखरा से सब जगह जब बिजली काफी उपलब्ध हो रही है तो फिर दूसरे आम लोग यह सोचते हैं कि हमारा यह मंडल है यह निर्णय देता है कि हमारे २,३ जिलों में बिजली काफी मिल सकती है, परन्तु गरीब पहाड़ी इलाकों के आदिवासियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कहां सवाई मधोपुर, कहां झालावाड़ और कोटा को लेलें। तो मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि इलेक्ट्रिक लाइन होकर निकल रही है, वल्लभनगर भोपालसगार, भदेसर, इन गांवों के कृषकों को, मज़दूरों को, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक मेनों को बिजली मिलनी चाहिए।

दूसरी एक बात मुझे और कहनी है। जैसा कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जयपुर सिटी, राजस्थान की राज-धानी की तुलना करते हुए अपने बयान में कहा कि यहां बिजली मिलनी चाहिए तो इसको सोचिये कि राजस्थान के उन २४ ज़िलों में से जहां कि बिजली की आवश्यकता है, जहां पर कोई पूंजीपति नहीं है, वहां कोई कल

(श्री हरिप्रसाद यादव)

कारखाने नहीं हैं, जिनके लिए बिजली कोई मुश्किल नहीं है, उन्होंने कई एन्जिन लगा रखे हैं तो उन्हें मिल जाती है, किन्तु कई हजारों वर्षों से पिछड़े हुए इलाके राजस्थान के हैं जिनको बिजली की आवश्यकता है, छोटे छोटे उद्योग चलते हैं, यदि उनको बिजली दे दी जाय तो राजस्थान राज्य का भविष्य बहुत जल्दी सुधर सकता है ।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुन्झुनूं): सभापति महोदय, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से १९६०-६१ का बजट जो प्रस्तुत हो रहा है उसके ऊपर बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने कहीं । दुर्भाग्य से मैं उस जिले से आ रहा हूं, राजस्थान के उन २४ या २६ जिलों में मेरा ही ज़िला एक ऐसा है जहां कि ज़िले के हैडक्वार्टर पर बिजली नहीं है । बहुत वर्षों से इस विधान सभा के प्रांगण के ऊपर इस बात का आश्वासन दिया जा चुका है कि झुन्झुनूं ज़िले में भाखरा से बिजली ५५ में, ५६ में और ५९ के मार्च तक आ जायगी । ये सारी तिथियां निकल गईं और ६० का मार्च भी निकल गया, लेकिन झुन्झुनूं ज़िले में जो लोग बराबर वर्षों से उत्सुकता से देख रहे थे कि बिजली हमारे यहां आयेगी वह नहीं आई । बहुत दौड़-धूप के बाद शायद केन्द्रीय सरकार के ऊपर बहुत दबाव पड़ा उसके बाद पिलानी के टैक्निकल कॉलेज को बिजली मिली और वह बिजली वहां तक महदूद रही । बहुत बार पिलानी जाने का अवसर हुआ तो वहां पर यह देखा जाता है कि दिन में जब कि पंखे चलते हैं और रोशनी के अन्दर काम होता है तो एक दो बार नहीं कोई १५,२० बार बिजली फेल होती है और वहां के स्टाफ के लोग और जनता के लोग यह महसूस करते हैं कि यह नई भाखरा की बिजली लेकर नई आफत मोल ले ली है । इतना ही नहीं जब दो रोज़ तक बराबर बिजली फेल हुई तो उनको अपना पुराना पॉवर हाउस वापिस चलाना पड़ा । यह तो इनएफिशियेन्सी की बात रही । हम कह सकते हैं कि यह उत्तर मिल सकता है कि अभी नया नया काम चालू हुआ है और एस्टेब्लिश होने में थोड़ा समय लगता है, एफिशियेन्सी आने में थोड़ा समय लगता है, किन्तु वह भी हमको देखना है । पिछले एक वर्ष में वहां खम्भे खड़े कर दिये गये हैं और उसकी जानकारी कर दी गई कि पिलानी से चिड़ावा बिजली आयेगी और चिड़ावे से झुन्झुनू आयेगी । कहा यह जाता है कि २६ जनवरी को में झुन्झुनूं में बिजली आ जयेगी । २६ जनवरी निकल गई, मार्च निकल गया और अब कहा यह जाता है कि मई के एन्ड तक या जुलाई तक बिजली आ जायेगी । लेकिन और जो जानकारी की गई तो उस जानकारी से पता चला कि वह बिजली झुन्झुनूं नगर तक ही महदूद रहेगी । झुन्झुनूं नगर में भी सारे नगर को बिजली नहीं दी जायगी । दो वर्ष के बाद या कुछ समय के बाद बिजली काफी आ जायेगी तो झुन्झुनूं के मान नगर टाउन इम्प्रूवमेंट स्कीम है उसके अलावा पुराने शहर को बिजली दी जायेगी । इतना ही नहीं चिड़ावे से झुन्झुनूं तक बिजली आती है तो उसके बीच में और देहात पड़ते हैं तथा और भी म्युनिसिपल टाउन्स पड़ते हैं उनका उस स्कीम में कोई उल्लेख नहीं है । वे लोग बराबर जब कि उनके गांवों के अन्दर बिजली के खम्भे लगे हुए हैं, लेकिन वे बिजली दिये जाने की स्कीम में नहीं हैं, इसके लिए कह रहे हैं । झुन्झुनूं ज़िले का पूर्वी भाग

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

अधूरी बिजली पायेगा और पश्चिमी और उत्तरी भाग जहां पर म्युनिसिपल टाउन्स हैं, पंचायतें हैं या ब्लॉक्स का काम हो रहा है वहां पर बिजली दिये जाने की स्थिति कोई नहीं है, न कोई स्कीम है, क्योंकि बिजली इतनी कम मात्रा में है कि वे कहते हैं कि बिजली देने में असमर्थ रहेंगे। इस प्रकार से भाखरा से आने वाली बिजली की हालत है।

मंडावा, बिसाऊ, डूंडलोद, इस प्रकार के जो म्युनिसिपल टाउन्स हैं वे बराबर उम्मीद करते थे कि भाखरा से जो बिजली झुन्झुनुं दिये जाने की बात है तो फिर इन लोगों को क्यों महरूम रखा गया है? क्यों उनको वंचित रखा जाता है? किन्तु जब पूछताछ की जाती है तो विभागीय अधिकारियों को यह पता नहीं कि ये इस प्रकार के म्युनिसिपल टाउन्स हैं जो बिजली से वंचित रहेंगे।

इस सारे ग्रन्थ को देखा, अवलोकन किया तो इसमें सिवाय अधिकारियों की तनख्वाहों के, उन लोगों के स्टाफ की पे के आंकड़ों के अलावा और कहीं कुछ है नहीं लोकल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जिले के अन्दर कहां कहां होगी, कौन कौन ब्लॉक हैं, कौन कौन म्युनिसिपल टाउन्स हैं और कहां पर बिजली जायेगी? इस बात का उल्लेख नहीं है।

मैं यह प्रार्थना करूंगा, सभापति महोदय, आपके ज़रिये से कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि इस ज़िले के अन्दर जो कि मैं समझता हूँ बिजली के लिहाज़ से सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला है, जिसमें एक वर्ष में एक बार फसल होती है और जिसमें कोई नहर नहीं आने वाली है, उस ज़िले के अन्दर उद्योग धन्धे बढ़ाने का और खेती को उपज को बहुतायत में लाने का कोई उपाय है तो वह उपाय बिजली के ज़रिये से है, आज बिजली हमारे कस्बों को मिले, हमारे खेती के कामों के लिए मिले और उससे जो नहर की कमी है वह पूरी कर सकते हैं। वह हो सकता है। नहर की कमी इस तरह से पूरी हो सकती है कि हमारे ज़िले के अन्दर केवल एक ही साधन है और वह साधन है कि कुए खोदकर बिजली के ज़रिये पानी को निकाल कर सिंचाई करें और एक फसल जो बरसात में होती है उसके अलावा और फसल का भी हम उत्पादन करें और यहां के लोगों की बेहबूदी के लिए वहां पर जो यह स्थिति है उसके बारे में मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार ध्यान देगी।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था और मैंने कही कि डेस्पेरिटी बड़ी भारी है। चुरू ज़िले से सटे हुए जो गांव हैं, जो म्युनिसिपल टाउन्स हैं और देहात हैं तो चुरू में बिजली है लेकिन झुन्झुनू ज़िले में नहीं है। इसी तरह से सीकर के साथ हुआ, वहां के म्युनिसिपल टाउन्स को भी बिजली नहीं मिलने की स्कीम है। बिजली कब मिलेगी इसका भी पता नहीं है मैं आशा करूंगा कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को इन्टेन्शिनली देखकर बिजली का इन्तज़ाम करेंगे।

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : सभापति महोदय, जो विद्युत मंडल

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

का हमारे सामने ६०–६१ का बजट पेश हुआ है उसको हमने देखा, उससे विदित है कि यह विद्युत मंडल का बजट घाटे का है । लेकिन इस घाटे के बजट के पीछे की तरफ यदि ध्यान दें, इसका विष्ट पेषण करें तो विदित होगा कि जब अलग अलग राज्य थे तब वहां पर अलग अलग बिजलीघर थे और राजस्थान बनने के बाद वे बिजली घर ही राजस्थान सरकार की तरफ से चलाये जाते थे और वे बिजली घर घाटे में चल रहे थे। उन्हीं बिजली घरों को राजस्थान विद्युत मंडल ने ग्रहण किया और उसी हालत में ग्रहण किया। तब यह कहना कि कमर्शियल बेसिस पर यह विद्युत मंडल स्थापित हुआ था। मैं इसको अतिशयोक्ति समझता हूं क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा चलाये जाने वाले बिजली घरों में पहले से ही घाटा चला आ रहा था और घाटे की हालत में ही विद्युत मंडल को दिया गया, तो अभी से यह आशा करना कि घाटा मिटा कर मुनाफा कमा लेंगे, यह समझ में नहीं आता। इससे यह माना जाय कि घाटे का बजट है, उसको देखकर यह कह दें कि विद्युत मंडल का कार्य ठीक नहीं है, यह उचित नहीं प्रतीत होता है। यदि यह बात होती कि राजस्थान सरकार से यह कार्य विद्युत मंडल को देते समय मुनाफा होता या बराबर में चलता रहा होता तो समझ में आता कि मंडल द्वारा ठीक तरह से नहीं चलाया जा रहा है और घाटे में जा रहा है, लेकिन पहले से ही यह स्थिति है तो देखना यह है कि विद्युत मंडल कायम होने के बाद घाटे में कमी करने की कोशिश की गई है या नहीं।

अब यह कहा जाय कि कर्मचारियों को कम करके घाटा पूरा करना चाहिये था तो मैं इसे उचित नहीं समझता क्योंकि बिजली का मामला टैक्निकल है और जब तक टैक्निकल मेन ठीक तरह से व्यवस्था नहीं करेंगे तो यह काम ठीक तरह से नहीं हो सकेगा. इसलिये यह कहना कि कर्मचारियों को कम किया जाय, मैं उचित नहीं समझता।

मैं यह अवश्य कहूंगा कि विद्युत मंडल की ओर से छोटे उद्योगों पर दो आना फी युनिट लगाया गया है जब कि २० हजार युनिट से अधिक बिजली जो उद्योग लेते हैं उनको सिर्फ डेढ आना पर युनिट ही देना पड़ता है। छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये क्योंकि गांव गांव और घर घर में छोटे उद्योगों को पनपाना चाहते हैं। उनके लिये दो आना पर युनिट रखना और बडे उद्योगों के लिये डेढ आना रखना उचित नहीं है। मैं आशा करता हूं इस ओर विद्युत मंडल ध्यान देगा और छोटे उद्योगों को पनपाने का प्रयत्न करेगा।

हम एक तरफ घाटे की ओर तो देखते हैं लेकिन दूसरी तरफ भी हमें दृष्टि डालनी होगी। विद्युत से जो कृषि, उद्योग आदि को फायदा होता है उन सब को देखें तो समझ में आयेगा कि हम घाटे में नहीं, ठीक दिशा में चल रहे हैं। बहुत से छोटे उद्योग चल रहे हैं, बहुत सी जगह बड़े बड़े उद्योग खोले जा रहे हैं, कई जगह वाटर वर्क्स चल रहे हैं, कई कस्बों में म्युनिसिपेलिटीज़ द्वारा बिजली का प्रबन्ध किया जा रहा है कम पैसों से, ऐसी स्थिति में यदि हम सब पर भार चढ़ा देंगे और उनका भार म्युनिसिपल बोर्ड और

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

उद्योगों पर पड़ेगा तो कहेंगे कि घाटे में चल रहे हैं। इसलिये इन्हें बंद किया जाय तो उत्पादन कम हो जायगा। यदि म्युनिसिपल बोर्ड गांवों में सुविधा का काम करते हैं तो वे कम हो जायेंगे, इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा। राजस्थान में उद्योग बढ़े या नहीं और जनता का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है या नहीं, इस दृष्टि से देखेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि विद्युत मंडल ठीक कार्य कर रहा है, इस ओर ध्यान देगा।

पुराना कर्जा था उसके बारे में, मैं समझता हूं विद्युत मंडल को एसेट्स और लाइबिलिटीज का पता नहीं चला है। पुराने बिजलीघरों के किस किस में कितने कितने रुपये बकाया हैं इस सब की लाइबिलिटी विद्युत मंडल ने ले ली है तब तो विद्युत मंडल को वसूली का काम करना पडेगा और पता लगाना पड़ेगा कि किन किन में बकाया है और यदि उसने लाइबिलिटी नहीं ली है तो राजस्थान सरकार का काम है कि पहले की बकाया वसूल करे और जमा करे। क्योंकि इसमें इसका उल्लेख नहीं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ विद्युत मंडल को दी गई है या नहीं। खाली कारबार उनको संभलाया है।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि अजमेर में सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में कोटा से चंबल की बिजली अजमेर तक लाने की योजना थी। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उसका पैसा खर्च नहीं किया गया है। यही नहीं; बल्कि मुझे मालूम हुआ है कि पहले कोटा से भीलवाड़ा तक बिजली की लाइन ले जाने का प्रयत्न चल रहा है और भीलवाड़ा से अजमेर लाने का प्रयत्न चल रहा है। मैं यह कहूंगा कि अजमेर का पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग रखा है उसमें जल्दी करनी चाहिये क्योंकि सेकिन्ड फाइव इयर प्लान का समय चला गया तो अजमेर का यह पैसा नहीं मिलने वाला है। इसलिये यह पैसा इसी में खर्च होना चाहिये और कोटा से अजमेर तक बिजली सैकन्ड फाइव इयर प्लान में ही लानी चाहिये।

इसके बाद मैं किशनगढ के बारे में बताना चाहता हूं। किशनगढ़ का बिजलीघर पूर्ण उपयोग में नहीं आ रहा है। सन् ५३–५४ से एप्लीकेशन दे रखी है। एक तरफ तो कहते हैं कि छोटे उद्योगों को पनपाना चाहते है और दूसरी तरफ ज्यादा पैसा चार्ज करना चाहते हैं तो छोटे उद्योगों को बिजली नहीं देंगे तो राजस्थान में उद्योग नहीं बढ़ेगा। इसलिये किशनगढ़ में जो छोटे उद्योग हैं उनको जल्दी से जल्दी बिजली देनी चाहिये।

इसी प्रकार से वहां का वाटर वर्क्स तैयार हो चुका है और वह पानी देने के लिये तैयार है लेकिन उसको बिजली नहीं मिलने से वह बन्द है। मैं आशा करता हूं कि इस बात का जिम्मा किशनगढ़ बिजलीघर ने ले लिया है कि हम पानी के लिये बिजली देंगे लेकिन उन्होंने बिजली नहीं दी इसलिये १४ लाख रुपये जिस वाटर वर्क्स पर लगे हैं वह यों ही बन्द पड़ा है। मैं आशा करता हूं कि इस ओर ध्यान देंगे और वाटर वर्क्स को बिजली देकर उसको चलाने का प्रयत्न करेंगे।

अभी यहां एक माननीय सदस्या ने कहा कि जय
चलाये जाते हैं, यह एक तरह की लग्ज़री है।

(श्री पुरूषोत्तललाल शर्मा)

लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह लग्ज़री नहीं है बल्कि नेसेसिटी है। वही प्रदेश उन्नतिशील कहा जा सकता है जिसमें दूसरे देशों के लोग आते हैं और देखते हैं और यह सोचते हैं कि यहां के लोगों का रहन सहन कैसा है, देश का वातावरण कैसा है ? इस लक्ष्य को भी सामने रखना है। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यहां पर एक्सीडेन्ट्स बहुत होते है, यहां दिये जलाये जायं। जहां पर मरकरी लाइट के बजाय लगाई जावें, क्या उससे एक्सीडेन्ट्स कम हो जायेंगे ? मरकरी लाइट से भी एक्सीडेन्ट्स हो जाते हैं तो दियों से तो और भी ज्यादा होंगे। रोशनी और हवा काफी हो, यह लग्ज़री नहीं है, बल्कि शादी-विवाह और फंक्शन्स में जो बिजली लगाई जाती है वह कम होनी चाहिये।

इसके साथ ही एग्रीकल्चर के बारे में बिजलीघर ज्यादा उन्नतिशील नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनको चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा खेती, उत्पादन के लिये काश्तकारों को जो बिजली लेना चाहते हैं उनको अवश्य देनी चाहिये। मैंने खुद ने देखा है कि किशनगढ़ में काश्तकारों ने एप्लीकेशन्स दी हैं कि उनको बिजली दी जाय लेकिन उनको बिजली नहीं मिली। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि छोटे उद्योगों व किसानों के साथ न्याय होना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सभापति महोदय, पाली राजस्थान का एक प्रमुख जिला है। उसकी चालीस हजार की आबादी है और यह एक औद्योगिक शहर है। यह सब जानते होंगे कि पाली में कितने कारखाने चल सकते हैं, वहां एक बड़ी मिल भी चलती है। लेकिन वहां पर बिजली न होने से छोटे छोटे कारखाने नहीं चल पाते हैं। मैं यह समझता हूं कि जिस जिले में ज्यादा बिजली है, जिसमें ज्यादा ताकत है, वह जिला ज्यादा धनाढ्य बन सकता है, वहां ज्यादा काम-काज चल सकते हैं। पाली जिले के लिए कई बार प्रार्थना की है कि वहां पर जो मैनेजिंग एजेन्ट द्वारा बिजलीघर चलाया जाता है वहां साढ़े नौ आने यूनिट लेते हैं, १० आने यूनिट लेते हैं। पाली के बिजलीघर के लिए कई बार प्रार्थना की है कि इस बिजलीघर को सरकार अपने कब्जे में ले ले, इससे काफी आमदनी हो सकती है क्योंकि वहां के लोग काफी बिजली खर्च करते हैं। मैंने एक प्रार्थना-पत्र पाली की ओर से चार वर्ष पहले पेश कर दिया था कि वहां जो मैनेजिंग एजेन्ट रहता है वह १० हजार, १५ हजार, २० हजार का वजन शेअर होल्डर्स पर डालता है, उसने इस प्रकार की हालत कर रखी है। हमने कहा कि पाली जिले के लिए कोरेस्पोन्डेन्स करके किसी प्रकार शहर को भी बिजली दिला दें, लेकिन यह नहीं कर पाये हैं। इसके अलावा यह भी कोशिश की थी कि रेलवे ने बिजली लगाई है स्टेशन पर, उससे बातचीत करनी चाहिए, राजस्थान गवर्नमेंट को बातचीत करनी चाहिए कि जो स्टेशन को बिजली दी है उसके अलावा सड़कों वगैरह के लिए बिजली दे दे। न तो हमारी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से बातचीत की है और न मैनेजिंग एजेन्ट से जो शेअर होल्डर्स को इतने घाटे में डाल रहा है। भगवान् जानता है कि इतने उस शहर के नागरिक शेअर होल्डर्स हैं लेकिन अभी तक बिजली घर की यह

Page No.94

(श्री मूलचन्द डागा)

हालत है और इसी कारण वहां उद्योग पनप नहीं सकते । आपने घोषणा की है कि पाली शहर में इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम करना चाहते हैं । इसके लिए हजारों रुपयों की मशीनें मंगा चुके हैं । लेकिन होता क्या है कि वे मशीनें चल नहीं सकती, क्योंकि बिजली उपलब्ध नहीं है । आप उन जगहों को बिजली दीजिये जिससे बेकारी दूर हो सकती हो, जहां काम काज शुरू हो सकते हों, गांवों में ज्यादा खेती हो सकती हो। वहां दीजिए जिससे कि बेकारी मिटे और गरीबी भी दूर हो । हमने पाली के लिए बहुत कहा कि इतना बड़ा शहर है, चालीस हजार जिसकी आबादी है, वहां तीन हजार मजदूर उम्मेद मिल में काम करते हैं और मजदूर भी हैं उन्होंने भी कई बार प्रार्थना की है कि महाराज उम्मेद मिल है, उसके मैनेजिंग एजेन्ट हैं, उनसे बातचीत करके बिजली शहर को दिला दी जाय ताकि शहर के व्यापारी लोग उन्नति कर सकें, लेकिन यह नहीं हो रहा है । जोधपुर डिविजन के मकराना की बात वहां के माननीय सदस्य कहेंगे लेकिन मैं इतना कह दूं कि वहां पर तीन साल हो गये हैं खम्भे खड़े हैं, वहां के लोग लाइन का इन्तजार करते हैं और चाहते हैं कि किसी के साथ जोड़ दिया जाय, लेकिन वे खम्भे नीचे पड़े हैं, खड़े नहीं हुए हैं, रो रहे हैं अपने भाग्य को । तो वहां सामान पड़ा हुआ है । हम यह चाहते हैं कि बिजली के मामले को प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि हर आदमी चाहता है कि बिजली जल्दी मिल जाय, इससे उद्योग भी चलते हैं, पनपते हैं । जोधपुर के पॉवर हाउस के बारे में मन्त्री महोदय को मालूम होगा, वहां क्या हुआ, छोटी सी गल्ती से सरकार के कितने रुपये का नुकसान कर दिया, जो बिल्डिंग बनी थी वह ढह गई । जोधपुर-वाले बड़े उत्साह के साथ इन्तजार कर रहे थे लेकिन इन्जीनियर साहब आये और उन्होंने अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया और सारा मामला गोल हो गया । उसमें कितना नुकसान हो गया, इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया, यह तो माननीय मंत्री जी के उत्तर से मालूम होगा । जोधपुर वाले बड़े उत्सुक थे, क्योंकि वहां पर बिजली की हालत बड़ी खराब है । जब बिल्डिंग बनने लगी और उसमें जो मेहनत की थी, वह एक दिन में ढेर हो गई । उसमें किसकी गलती है, उस पर क्या एक्शन लिया गया, गवर्नमेंट का जो लाखों रुपये का नुकसान हुआ, पब्लिक का नुकसान हुआ, उसके बारे में क्या किया गया ? हम चाहते हैं कि बिजली के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त हो कि जो उद्योग के क्षेत्र हैं उनकी उन्नति हो, खेती पनप सके, गांव के लोग लाभ उठा सकें, इसके साथ ही बेकारी भी दूर हो सके ।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है वह कहीं लागू नहीं होता । मैंने कहीं भी इसको लागू होते नहीं देखा, उन पर फैक्ट्री एक्ट भी लागू नहीं होता बिजली घरों में । मैंने ताज्जुब से देखा कि ये एक्ट लागू नहीं होते । जो लेबर लॉज़ बन चुके हैं उनकी उनको सहूलियत दी जाय, उनकी जो मांगे हैं, उन पर ध्यान दिया जाय, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार मकान बने हुए हैं या नहीं और व्यवस्था है या नहीं, लेबरर्स को छुट्टी मिलती है या नहीं, यह देखना चाहिए । इलेक्ट्रिसिटी

(श्री मूलचन्द डागा)

एक्ट बना हुआ है उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती राजस्थान में। इसके साथ ही आप प्रोजेक्शन देखिये। कोई खम्भा कहीं रुपा हुआ है कि किसी को कहीं रोप दिया है, कहीं किसी के मकान की भीत में घुसा दिया है, बिना पूछे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ठूंस देता है। उनसे पूछिये, यह कैसे आ गया है, बिना बुलाये मेहमान की तरह। मकान मालिक कहता है तो कहते हैं कुछ नहीं कानून–वानून। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, उसके सम्बन्ध में मैं पूछूंगा कि उसकी किसी धारा के तहत सरकार ने कितने चालान किये? जो लीकेज होता है उसके लिए क्या करते हैं? वायर सीधे सीधे निकल जाते हैं, उनमें से लीकेज होता है बरसात के मौसम में। वहां के मजदूर मांग करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, जो फैक्ट्री लेबर ऑफिसर है वह फैक्ट्री में जाता नहीं। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना किसके लिए है? एक एक्ट बना दिया है, उसको लागू कर दिया लेकिन उसकी धाराओं का पालन होता है या नहीं? यह मजदूरों का सवाल है। जितने मजदूर काम करते हैं वे चाहते हैं कि जो कानून बन चुका है, जो प्राग्रेसिव लॉ बन चुका है उसको लागू कीजिए। उनको कोई सहूलियत नहीं दी जाती, जो मैनेजिंग एजेन्ट चाहता है वह वही काम करता है। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारायें हैं उनके अनुसार काम नहीं होता।

एक बात और है कि जो बिजली की लाइन डाली जा रही है, जो खम्भे गाड़ते है, उनमें प्रोजेक्शन का ख्याल नहीं है। कौनसी जगह लाइट वगैरह है, यह विचार नहीं। नये नये इंजीनियर्स आ रहे हैं, इम्तिहान पास करते हैं और नौकरी में ले लिये जाते हैं। उनको पुराना अनुभव होता नहीं है, बिजली के खम्भे गाड़ते समय उनको यह मालूम नहीं है कि ट्रैफिक की क्या हालत होगी। इसलिए बड़ा नुकसान हो रहा है। छोटे छोटे मेले लगते हैं, मुसलमानों का मेला आता है–ताजियों का मेला उसकी वजह से सारे बिजली के तार खोलने पड़ते हैं, दो–तीन दिन पहले से परेशानी होती है। इसी तरह रथ–यात्रा आदि के मेले निकलते हैं उनमें वायर अटकते हैं, खम्भे अड़ जाते हैं। इसके साथ ही जो खम्भों के लिए खड्डे खोदे जाते हैं वे वैसे ही पड़े रहते हैं। मेरा अर्थ यह है कि जो काम हो वह बड़े इन्जीनियर्स की देख–रेख में होना चाहिए। जो नये नये इन्जीनियर्स आते हैं, कॉलेज से निकलते हैं उनको एम्प्लॉय करते हैं, लेकिन पहले उनको बड़े इन्जीनियर्स की देख–रेख में काम करना चाहिए, यह नहीं कि पूरी पॉवर्स उनको ही दे दी जाय। मैंने सुमेरपुर और दूसरी जगहों की हालत देखी है, जहां काम हो रहा है।

यह बात मैंने आपके सामने पेश की है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के १९५९-६० के रिवाइज्ड बजट और १९६०-६१ के बजट पर काफी चर्चा सदन में हुई है। मैं उन सारी चर्चाओं को न दोहराते हुए जो मुख्य दो, तीन बातें मेरे दिमाग में आई हैं वे निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक विद्युत का सवाल है, इस बात से इन्कार नहीं करा जाता कि कुछ काम राजस्थान में हुआ है, कुछ हो रहा है। लेकिन किस क्षेत्र में कितना काम होना चाहिए और उस दिशा में विद्युतमंडल काम

Page No.96

(श्री शंकरलाल)

कर रहा है या नहीं, अनुपातिक ढंग से, कहीं ज्यादा काम हो रहा है आवश्यकता से और कहीं आवश्यकता है और काम नहीं हो रहा है ।

मैं समझता हूं कि दो क्षेत्रों में, एक तो देहात और नगर विकास के काम है, जैसा कि इसमें बताया है रूरल एन्ड अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन, इसके जो आंकड़े इसमें बताये गये हैं इनको देखने से बड़ा दुख होता है। दूसरे प्राइवेट बिजली घरों की तरफ गवर्नमेंट का क्या ध्यान है, इन दोनों के सम्बन्ध में, मैं कुछ बातें सदन के सामने रखूंगा।

देहात व नगर विद्युत की योजना है, इसमें सरकार ने बताया है कि ९८० किलोवाट बिलाड़ा, नागोर, जैतारण, सुमेरपुर में ६०–६१ में १५ लाख रुपया रखा है। जहां इतनी बिजली की मांग है वहां केवल इतना सा रुपया रखना कम ही नहीं बिल्कुल अपर्याप्त है। ६,७६,७५,२०० रु० का बजट है। इसमें केवल १५ लाख देहात व नगर विद्युत विकास के लिये रखा गया है, यह बिल्कुल अपर्याप्त है। इस सम्बन्ध में विद्युत मण्डल ने जनता की मांग और देहात व नगरों की आवश्वकता की तरफ ध्यान नहीं दिया है और इस सम्बन्ध में जो रुपया खर्च हुआ है वह भी ठीक तरह से खर्च नहीं हुआ है। सुमेरपुर और बिलाड़ा का बताया है वे पाली डिस्ट्रिक्ट में हैं इसलिये मुझे अच्छी तरह मालूम है। बिलाड़ा से सोजत तक बिजली ले जाने का है वहां केवल खम्भे ही गड़े हुए हैं। तो मुझे कहना पड़ेगा कि राजस्थान विद्युत मंडल का कार्य जो इसके लिये धन राशि रखी है उसके लिहाज़ से भी बहुत कम धन-राशि रखी है, संतोषप्रद नहीं हुआ है और जो कार्य हुआ है वह भी सेटिस्फेक्टरी नहीं हुआ है इ। न दोनों दृष्टियों से संतोषजनक काम नहीं हुआ है।

जब तक इस क्षेत्र में योजनाबद्ध सारा कार्य यह विद्युत मंडल अपने हाथ में नहीं ले लेता तब तक प्राइवेट बिजलीघरों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, पर बहुत से बिजलीघर ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत खराब है....

श्री भीमसेन : Mr. Chairman, I think there is lack of quorum in the House.

(गण–पूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री शंकरलाल : तो माननीय सभापति महोदय, मैं गैर सरकारी पॉवर हाउसेज़ की बात सदन के समक्ष रख रहा था। ऐसे बहुत से प्राइवेट बिजलीघर हैं जिनकी बहुत दुरावस्था है और उनसे जनता संतुष्ट नहीं है। वहां लेबर भी असंतुष्ट है। ऐसे बिजलीघरों को सरकार को तुरन्त हाथ में ले लेना चाहिये, जैसे पाली का उदाहरण बताया। वह इतना बड़ा शहर है, करीब चालीस-पैंतालीस हज़ार की पोपुलेशन है पर वहां ४०० किलोवाट प्राइवेट पॉवर हाउस होने के कारण वहां दूसरे शहरों के मुकाबले में बिजली की ज्यादा रेट है और श्रमिकों की बड़ी दुरावस्था है, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया। तो प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ के लिये, गैर सरकारी पॉवर हाउसेज़ के लिये ६०–६१ के बजट में १० लाख की धन राशि रखी है, पूरे राजस्थान के लिये रखी है वह अपर्याप्त है। राजस्थान विद्युत मंडल इतना शक्तिशाली नहीं है कि यहां जितने पॉवर हाउसेज़ चल रहे हैं उनको हाथ में लेकर कार्य कर

(श्री शंकरलाल)

सके। अगर वह सारे पॉवर हाउसेज़ को अपने हाथ में नहीं ले सकता तो कम से कम उनकी दशा को ठीक करके तो चलाना चाहिये। बहुत सी जगह प्राइवेट सेक्टर्स बिजली योजनाओं के लिये इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। एक तरफ तो प्राइवेट सेक्टर ठीक काम नहीं कर रहा है दूसरी तरफ उनको मशीनरी वगैरह उपलब्ध कराने की सुविधा नहीं दी जाती है। पाली जिले के लिये निवेदन करूं कि बिजली की योजना तीन तरह से अलग अलग विभाजित है; सोजत। बाली, सुमेरपुर, फालना, रानी और जैतारण, नीमाज, रायपुर जो कि मेरी कॉस्टीट्युएन्सी है इन तीन क्षेत्रों के लिये अलग बिजली-योजना बनी हुई है। बहुत से लोग पॉवर हाउसेज़ लगा कर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वे लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं पर मशीनरी की जरूरत होती है। न तो सरकार खुद मशीनरी लेती है और न उनके लिये उपलब्ध कराती है। मशीनरी लाने के लिये सरकार सुविधा दे और इन्वेस्टमेंट के लिये पूल बना दे और आधे से कम शेअर सरकार खरीद ले तो पाली जिले में बिजली की योजना पूरी तरह सफल हो सकती है। इसी तरह और दूसरे जिलों में भी हो सकती है। हमारे पास पैसा नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर पैसा देने को तैयार है, पर वहां लाइसेंस और मशीनरी का सवाल आता है। सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिये कि जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजली लाना चाहते हैं, उद्योग धंधों को पनपाना चाहते हैं उनको सरकार मदद दे।

मैं निवेदन करूं कि जो राजस्थान विद्युत मंडल का यह बजट बना है और जो गई साल का बजट बना और इस साल का बजट सामने आया इन दोनों बजट्स में इन दो बातों की कमी पाई गई; न तो इसमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये समुचित प्रबन्ध है और न प्राइवेट सेक्टर को इम्पेटस है। तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों बातों की तरफ ध्यान दें।

चम्बल-भाखरा की योजनाएं हैं वे बड़े पैमाने पर योजनाएं हैं। पर छोटी छोटी योजनाओं से छोटे पैमाने पर विद्युत का प्रसार नहीं करेंगे तो गांवों में और राजस्थान के कोने कोने में बिजली का प्रसार नहीं होगा। हम चाहते हैं कि छोटे छोटे उद्योग पनपें, गांव गांव में बिजली पहुँचे, किसानों को बिजली मिले और लोग प्रचुरता में बिजली पा सकें, इस ओर विद्युत मंडल को ध्यान देना चाहिये। इस समय जो किया जा रहा है वह कतई संतोषजनक नहीं है। अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि सरकार इस दिशा में कदम बढ़ावे।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, सदन में राजस्थान विद्युत मंडल के ६०–६१ के बजट पर बहस चल रही है। कई माननीय सदस्यों ने, सबसे पहले हमारे जनसंघ के माननीय सदस्य ने राजस्थान विद्युत मंडल के चेअरमैन पर आरोप लगाये, वेग आरोप लगाये। किसी अफसर पर वेग एलिगेशन्स लगायें कि भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, आम बात कहने से हम कोई

(श्री भीमसेन)

न्याय नहीं करते। किसी प्रकार के खिलाफ शिकायत है तो स्पेसिफिक एलिगेशन लगायें। पर इस प्रकार के वेग एलिगेशन लगाना हमारे हाउस के लिये और हमारे हाउस के सदस्यों के लिये कोई अच्छी बात नहीं है।

४ म. प.

जहां तक वर्तमान विद्युत मंडल के चेअरमैन का सम्बन्ध है, मैं कहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वे ऑनेस्ट हैं और उनकी इन्टीग्रिटी पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता। ऐसे ऑनेस्ट और सिन्सियर काम करते हैं उनके खिलाफ इस प्रकार के वेग एलिगेशन्स लगाने पर मैं समझता हूं कि उनके इनिशियेटिव लेने के माद्दे को कम करना है। हमारे वर्तमान चेअरमैन हैं वे बड़े ऑनेस्ट और सिन्सियर हैं और उनके खिलाफ इस तरह के वेग एलि–गेशन्स लगाना कतई वाजिब नहीं है। उनके खिलाफ यह कहा जाता है कि कोम्पटन कम्पनी को उन्होंने ठेका दिया है चूंकि वे भी मद्रासी हैं और यह कम्पनी भी मद्रास की है, इसलिये उसको ठेका दिया गया है। सभापति महोदय, यह एलिगेशन लगाना कतई गैर-मुनासिब है। उन्होंने जो भी एक्शन लिया है वह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में लिया है। वह कम्पनी अच्छी कम्पनी है और टेक्निकली साउन्ड है, इस खयाल से उन्होंने उसको ठेका दिया है और विदिन टाइम उन्हें काम को पूरा करना है इसलिये ठेका दिया गया है। इस-लिये यह कहना कि वे मद्रासी हैं और कम्पनी भी मद्रास की है और ठेका दिया गया है, सभापति महोदय, इस तरह के एलिगेशन्स लगाना वाजिब नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि बिजली हमारे जीवन के लिये बहुत उपयोगी वस्तु है, इसके लिये दो राय नहीं हो सकती और बिजली की हर इलाके को आवश्यकता हैं और वह यही महसूस करता है कि हमारे इस सम्बन्ध में क्या रिसोर्सेज़ हैं। हम किस इलाके के लिये क्या कर सकते हैं, यह सोचने की बात है। सभापति महोदय, हमने प्रोग्राम बनाया था उसके अनुसार भाखरा से हमको सन् १६५६ में बिजली मिलने वाली थी। हमारा प्रोग्राम था कि दिसम्बर, ५६ तक हमको भाखरा की बिजली मिल जानी चाहिये। लेकिन आज पूरे चार वर्ष समाप्त हो गये हैं और अभी भी पूरी बिजली उपलब्ध नहीं हुई है, आज गंगानगर और पिलानी को ही उपलब्ध हुई है। हमें तो अभी भी शक ही है कि राजगढ़ को बिजली जल्दी मिलेगी। गवर्नर के भाषण में बताया गया था कि मार्च या अप्रेल के फर्स्ट वीक में वहां बिजली मिल जाएगी लेकिन वह राजप्रमुख का अभिभाषण भी निरर्थक गया। अब भी न मालूम उनको कब बिजली मिलेगी। वहां के लोग ५६ से इन्तजार करते हैं, आज उनको इन्तजार करते करते ४ वर्ष हो गये। मैं नहीं समझता कि हमारे यहां इलाकों में बिजली कम मिलेगी। कई माननीय सदस्यों ने बीकानेर के पॉवर हाउस को लेकर बड़ी आलोचना की। बीकानेर का पॉवर हाउस हमारे देश का सबसे ओल्डेस्ट पॉवर हाउस है और वहां की मशीनरी आउट ऑफ डेट है और वहां की हालत को देखते हुए कन्ज़म्पशन पर–युनिट बहुत ज्यादा आता है। इसलिये पॉवर हाउस में ज्यादा खर्चा होता है क्योंकि अब हमें भाखरा की बिजली मिल

(श्री भीमसेन)

जावेगी: और यह कहा जाता है कि वह घाटे में चलता है, वह शिकायत दूर हो जावेगी। कई माननीय सदस्यों ने हमारे चेयरमैन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने बाहर के पेन्शन होल्डरों को यहां नौकर किये हैं। अगर हमारे यहां राजस्थान में कोई टेक्निकल हैंड एवेलेबल नहीं हो तो बाहर का आदमी बुलाया जा सकता है।

श्री शंकरलाल : आप क्या गवर्नमेंट रिप्लाई दे रहे हैं ?

श्री भीमसेन : बाहर के आदमी मिल जावें तो ऐसे आदमियों को एपॉइन्ट करने में कोई गैर वाजिब बात नहीं होगी। सभापति महोदय, मैं हमारे इलाके की बात कह रहा था। हमारा इलाका लूणकरणसर और कालू कस्बे को सन् ५६ में भाखरा से बिजली आने वाली थी उस योजना में शामिल किया गया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि लूणकरणसर और कालू भाखरा प्लान से उपलब्ध होने वाली बिजली के लिये नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने ५६ में सर्वे किया और उस समय आपने इनको बिजली देना उपयुक्त समझा। अब क्या कारण हैं कि उनको बिजली नहीं दी जा रही है और उनको नहीं रखा गया है ? सभापति महोदय, बड़े इम्पोर्टेन्ट कस्बे हैं, इनको बिजली मिलनी चाहिये। इसके साथ साथ रतनगढ़ से बीकानेर को लाइन आ रही है उसकी हालत सुधरी है। गड़वाल वगैरह बड़े बड़े कस्बे और गांव हैं जो बिल्कुल लाइन के पास हैं उन स्थानों को भाखरा से बिजली मिलने में शामिल करना चाहिये।

इसके अलावा हमारे यहां, सभापति महोदय, डेज़र्ट एरिया है। वहां कुओं में पानी बहुत गहरा है। बड़े बड़े कुओं में पानी निकालते हैं तो २४ घन्टे पानी निकालने पर भी लोगों को पूरा पानी नहीं मिलता है। कुओं में पानी होते हुए भी लोगों को पानी नहीं मिलता है। इसलिये बड़े बड़े गांवों को जो लाइन पर हैं उनको बिजली मिलनी चाहिये ताकि कुओं से पानी निकालने में खर्चा कम हो जावे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नये कुंए बनवाने पड़ेंगे क्योंकि एक कुए में २४ घन्टे पानी खींचने में भी लोगों को पूरा पानी नहीं मिलता है। इसमें गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेन्डीचर ज्यादा होगा। इसलिये जहां पानी बहुत गहरा है वहां के लोगों को बिजली दी जावे जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्त्ति हो सके। इसलिये सभापति महोदय, मैंने कुछ अपने विचार सदन में प्रस्तुत किये हैं।

श्री सभापति : श्री सम्पतराज जैन।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप ५ मिनट में ही अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री सम्पतराज जैन : सभापति महोदय, ५ मिनट में समाप्त नहीं हो सकता। इससे तो आप समय ही न दें और मैं न बोलूं....

श्री सभापति : आप बोलिये।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : सभापति महोदय, राजस्थान विद्युत बोर्ड ने जो बजट पेश किया है उसको देखने से यह तो निश्चित तौर से मालूम होता है कि राजस्थान में जहां तक बिजली का सम्बन्ध है

श्री सम्पतराज जैन)

उत्तरोत्तर विकास करने की ओर गतिशील है। १६५६-६० और १६६०-६१ के आंकड़ों को देखने से यह स्पष्ट है कि विकास की ओर गतिशील है। १६५६-६० के बजट में जहां जल विद्युत योजना पर ३,११,८४, ७३० रुपये बजट में खर्च किये गये थे वहां ६०-६१ में ४ करोड़, ८१ लाख खर्च किये जा रहे हैं। जहां थर्मल विद्युत योजना में १,४७,५१,६६० रखा गया था वहां आज ६०-६१ के लिये १,६०,४०,२०० रुपया रखा है। इस तरह अन्य योजनाएं भवन इत्यादि में भी १६५६-६० के मुकाबले में ६०-६१ में ज्यादा व्यय रखा गया है। जहां १६५६-६० में ४,६२,२५६२० था वहां पर ६०-६१ में ६,७६,७५,२०० रखा गया है। तो ऐसी सूरत में जहां तक भाखरा का सम्बन्ध है निश्चित तौर से हम प्रगति कर रहे हैं। बिजली के विषय में प्रगति अवश्य हो रही है लेकिन यह जो प्रगति हो रही है वह सारे बजट को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रगति शहरी क्षेत्र में अधिक हो रही है और देहातों में कम हो रही है। शहरों का जहां तक सम्बन्ध है, मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पहले ही बिजली मौजूद है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मगर आज हम देखते हैं कि शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और देहातों के लोग शहरों में आ रहे हैं क्योंकि शहरों में इन्डस्ट्रीज़ बढ़ती हैं। इस चीज को केवल मैं ही नहीं कहता देश के नेता कहते हैं। देश के नेता वक्तन-फ-वक्त यही कहते हैं कि शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है और गांव वीरान हो रहे हैं। इस सब का, सभापति महोदय, कारण यही है कि गांवों में कोई साधन नहीं, वहां पर लोग रह कर क्या करें? जहां रोटी-रोजी मिले वहीं पब्लिक जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की नीति है कि देहातों को न उजाड़ा जावे। इसलिये अगर हम चाहते हैं कि शहरों में आबादी गांव वालों की न आए तो हमें गांवों की ओर ध्यान देना होगा। जहां तक बिजली देने का सम्बन्ध है मैं निवेदन करूं कि इसमें भी मुख्यतया शहरों का अधिक ध्यान रखा जाता है, गांवों की उपेक्षा की गई है। थोड़ा बहुत ध्यान रखा भी गया है पर अधिक ध्यान दिया गया हो, ऐसी बात नहीं है। इसकी नजीर मैं आपको दूं। झालावाड़ जिले से चम्बल बांध २७ मील की दूरी पर है। इतनी बड़ी योजना पास में रहते सिवाय झालावाड़ शहर के और किसी आसपास के गांव को या तहसील हैडक्वार्टर तक को स्कीम में नहीं रखा गया। भवानी मण्डी को थोड़ी दी गई है और झालावाड़ शहर को दी गई है। यह घोर अन्याय है। तहसील और सब-तहसीलों की ४,१२,००० की आबादी है। झालरापाटन और भवानी मण्डी को जहां ऑलरेडी भी थर्मल पॉवर स्टेशन हैं छोड़ कर अन्य नगरों को जब नहीं दी गई तो उनका क्या होगा? हमारे यहां ८ तहसीलें हैं। एक में भी न बड़ी योजना है, न नहर है। जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है पानी हमारे यहां बहुत है। ६ नदियां हैं। कुदरती तौर पर वैसे भी बांध बनाये हुए से हैं। एक एक मील लम्बे और पचास से सौ गज गहरे खड्डे हैं, उनमें काफी तादाद में पानी भरा है। उससे हजारों। लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है।

डॉ० चन्द्रकला : यहां सिंचाई का क्या काम है?

Page No.101

श्री सभापति : यहां सिंचाई का सवाल नहीं है।

श्री सम्पतराज जैन : आप धैर्यपूर्वक सुनिये तो सही। मैं बिजली की ही बात कह रहा हूं। पानी बहुत है उस एरिया में, नदियां भी हैं पर उनके किनारे बहुत ऊंचे हैं, बिजली की सहायता के बिना उनसे पानी निकालने में कामयाबी नहीं हो सकती। यह प्रश्न हमारे कृषि मन्त्री के सामने भी है। वहां एक सबसे बड़ी नदी है काली सिन्ध। वह अकेली ही बहुत है, काफी एरिया को पानी दे सकती है, पर उसके किनारे ऊंचे हैं। बिना बिजली की सहायता के उसका उपयोग सिंचाई में नहीं किया जा सकता। तो वहां आपको चम्बल योजना से निश्चित तौर से बिजली देनी होगी। यह हमारे पेट का सवाल है। इसमें हम सन्तोष नहीं मान सकते कि आपने कह दिया कि बस झालावाड़ या भवानीमण्डी को हमने बिजली दे दी तो बस सब हो गया। वहां आवे, हमें इसकी खुशी है। पर सारे राजस्थान की उन्नति होगी। झालावाड़ शहर और उसके पास का भवानीमण्डी तरक्की करेगा और रावतभाटा जहां से आप बिजली ला रहे हैं जो वहां से २७ मील की दूरी मात्र पर है उसके आसपास का एरिया झालावाड़ का जिला इसके बिना तरसता रहे, वह बिजली के अभाव में अपनी तरक्की न कर सके, दूर दूर के राजस्थान के इलाके उससे लाभान्वित हों और पास का इलाका भूखा पड़ा रह जावे, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या उसके लिये कोई दूसरा बांध बनाया जावेगा, क्या कोई दूसरी बिजली योजना आप तैयार करेंगे ? २७ मील पर बड़ी भारी योजना होते हुए भी हमें महरूम रखा जावे और झालावाड़ ज़िला सूखा रहे, उसकी उपेक्षा कर दें आप, यह अन्याय, यह उपेक्षा मेरे जिले की पंचायतें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। मैं विनती करूंगा कि आप झालावाड़ जिले के मन्त्री हैं और आप तो अब सारे राजस्थान के हैं कि आप इस ओर ध्यान दें और सारे जिले को सब गांवों को नहीं तो कम से कम तहसीलों को, उनके सदर मुकामों को और उनके आसपास रहने-वाले छोटे मोटे उद्योग-धन्धों को एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिये भी किसानों को बिजली अवश्य प्रदान करेंगे। इसके साथ ही निवेदन करूंगा कि ३२ मील की दूरी पर भी जहां पत्थर की खानें हैं वहां भी आप बिजली देंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप झालावाड़ जिले को भवानीमण्डी को चम्बल की योजना से बिजली देने की योजना करेंगे।

श्री बरकतुल्लाखां (उप-मन्त्री, विद्युत): चेयरमैन महोदय, सबसे पहले तो मैं सदन के मेम्बरों का शुक्रिया अदा करूंगा और ईमान-दारी के साथ यह कहूंगा कि जो आज क्रिटि-सिज्म हुआ है, इसके लिये मैं बहुत आभारी हूं उनका। खास तौर से इसलिये आभारी हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, कई ने कई ऐसी रीज़न्स रखी हैं जो वाकई में बहुत उमदा हैं और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि उनको समझूं और उन पर अमल कर सकूं।

लेकिन एक बात यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस इलेक्ट्रिकल बोर्ड के वर्किंग को जितना आज के आपके इस क्रिटिसिज्म के अन्दर मैंने समझा है उतना शायद मैं दो महीने में भी नहीं समझ पाता। जहां तक बोर्ड के फॉर्मेशन का ताल्लुक है उससे आप वाकिफ हैं कि बोर्ड कहने को हो सकता है कॉमर्शियल कन्सर्न हो पर यह प्योरली कॉमर्शियल मोटिव से नहीं चलता, यह भी

(श्री बरकतुल्लाखां)

आप अच्छी तरह जानते हैं और फिर बोर्ड कभी इस तरीके से नहीं चल सकता कि फायदा हो वहां तो बिजली दी जावे और जहां नुकसान हो वहां बन्द कर दी जावे। अगर हमारा इस बोर्ड का प्योरली प्रोफिटियरिंग मोटिव हो तो मैं समझता हूं कि इसको गवर्नमेंट के अन्दर में रखने में, एक तरीके से ताल्लुक रखने में कोई फायदा नहीं होता। फिर तो इन्डिविजुअल को मौका दे दिया जाता कि वे स्वयं चलावें और प्रोफिट बनावें। पर यह बोर्ड सरकार के मातहत इसलिये बनाया गया कि गवर्नमेन्ट के साथ रहते हुए भी कम्पलीटली गवर्नमेंट का डिपार्टमेन्ट बन कर न रहे। थोड़ा बहुत नुकसान बर्दाश्त कर ले, पर बिल्कुल घाटे में भी न चले, यह मान कर इस बोर्ड को चलना है। इसलिये बोर्ड के फंकशन्स को इस तरह से भी नहीं देखा जा सकता कि जोधपुर में फायदा हो सकता है या भरतपुर में फायदा हो सकता है या बीकानेर में फायदा नहीं मिल रहा है या जयपुर में फायदा हो सकता है। तो जहां फायदा हो वहां चलाया जावे और जहां फायदा न हो वहां बन्द कर दिया जावे? मैं तो समझूंगा कि यह हमारी बड़ी बदकिस्मती होगी कि जब वापिस हम छोटे-छोटे दायरों में बंटने लग जावें और यह सोचने लग जावें कि चूंकि जयपुर का पॉवर हाउस फायदा देता है इस वास्ते चालू रखा जावे और बीकानेर का या जोधपुर का फायदा नहीं देता है तो उन्हें बन्द कर दिया जावे। इसका मतलब यह होगा कि हम वापिस उसी जगह जाना चाहते हैं कि जहां १९४९ में हम पहुँचे थे। इसलिये मैं आपसे अर्ज करूं कि जहां तक कुछ जगहों का ताल्लुक है वे वाकई बदकिस्मत हैं, जहां तक बीकानेर और जोधपुर के पॉवर हाउसेज़ का ताल्लुक है दोनों बदकिस्मत हैं। इसलिये कि उनके पास जो मशीनरी लगी है वह कभी की खतम हो जानी चाहिये थी। दुनियां के किसी और हिस्से में वे मशीनरी होतीं तो अब तक स्क्रेप करके बेच दी गई होती। पर चूंकि हमें मशीनरी नई मिली नहीं, मुतवातिर लगाई चलती रही है और जब लड़ाई खतम हुई तो एक्सचेन्ज की प्रोब्लम सामने आई और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि जो उन मशीनों को चला रहे हैं उनका दिल जान रहा है। जब यह पोर्ट-फॉलिया मेरे पास आया तो मैंने यह सारी हालत देखी और मेरा दिल दहलता जाता है जब जोधपुर और बीकानेर का ख्याल करता हूं। पर साथ साथ एक उम्मीद रख कर भी चलता हूं कि हालतों में सुधार होगा। आपके सामने मैं व्योरा रखना चाहता हूं कि जिस वक्त दूसरी प्लान शुरु हुई उस वक्त इन्स्टालेशन कैपेसिटी राजस्थान भर की ३४,६०० किलोवाट की थी। पर उसकी वर्किंग कैपेसिटी १५,३६६ किलोवाट ही थी। जब दूसरी प्लान बनी तो उसके अन्दर थर्मल पॉवर की यह पोज़ीशन थी: जयपुर में पांच हजार, जोधपुर में ३ हज़ार, कोटा में एक एक हज़ार किलोवाट का टर्बाइन लगेगा, अलवर में दो हजार का, भरतपुर में दो हजार का और भीलवाड़ा में दो हजार किलोवाट का टर्बाइन लगेगा। यह हमारे टार्गेट्स थे। टोटल मिला कर १६,००० किलोवाट होगी थर्मल की जरूरत।

मैं आपको इस मौके पर यकीन दिलाने कि कोशिश करूंगा कि ये जो फिगर तय किये थे वे पूरी उम्मीद रख रहा हूं कि इस

(श्री बरकतुल्लाखां)

सेकिन्ड फाइव इयर प्लान की डेट खत्म होते होते हम इस ओब्जेक्ट को अचीव कर लेंगे।

इसके साथ साथ डीज़ल स्टेशनों के भी जो प्लान्ट लगाये गये थे उसका टार्गेट २,६०४ किलोवाट रखा था। इस तरह से थर्मल और डीज़ल मिला कर कुल २१,६०४ का टार्गेट आता है, जिसको भी हम करीब करीब अचीव कर लेंगे, यह पूरा आशा है।

दूसरा रहा रूरल और अर्बन एरिया का इलेक्ट्रिफिकेशन का सवाल। इसमें ३ हजार का जयपुर में सेक्शन टर्बाइन लगेगा और डीज़ल का अलग अलग जगहों पर। इनका टोटल ६,२४१ आता है। इस चीज़ की भी आशा करते हैं कि पूरा कर लेंगे।

आज जितनी सदन में बहस हुई उसके अन्दर सबसे ज्यादा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में कहा गया और मैं समझता हूं कि इसके लिये कहा जाना भी जरूरी था। इसलिये कि पिछली प्लान जो बनी थी वह प्लान खत्म होने आई और उसके खत्म होने तक जो टार्गेट हमने अपने सामने रखे थे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में उनको अचीव कर लेंगे और एक छोटी सी रकम आप देख रहे हैं बाकी, ज्यादा रकम तो नहीं रहती है। इसलिये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में चूंकि शुरु में यह तय हुआ था कि दस हजार या इसके आसपास के कस्बों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जावे, आठ हजार और पांच हजार की आबादी का कस्बा भी हो सकता है। उसके आसपास के कस्बे लिये गये थे। जैसे जैसे प्लान का पीरियड बढ़ेगा वैसे वैसे बिजली विलेज तक पहुंचती रहेगी। जब शहरों से चल कर कस्बे में आयी है वैसी हालत में थर्ड प्लान के अन्दर कहीं न कहीं गांव तक अवश्य ले जाई जायगी ?

श्री सम्पतराज जैन : सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में कितने गांवों को बिजली मिल जायेगी ?

श्री बरकतुल्लाखां : तीसरी योजना तो अभी बनी नहीं है। मैंने अर्ज किया कि जब शहरों से चलते चलते कस्बों में आई है तो एक स्टेज आता है जब शहरों से चालू होती है, कस्बों में आ जाती है, उसके बाद गांवों की तरफ जायेंगे।

श्री सम्पतराज जैन : मैं कुछ जानकारी चाहूंगा....

श्री सभापति : No interruption please.

श्री बरकतुल्लाखां (जारी) : मेरे एक दोस्त ने जो सामने बैठे हैं और जयपुर से रिटर्न होकर आये हैं, जो जनसंघ के मेम्बर हैं, उन्होंने जो कुछ बातें कहीं उनको समझने की कोशिश की है। मैं रूल्स के बारे में निवेदन करूं कि जब तक राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने नियम नहीं बना लेता तब तक राजस्थान सरकार के जितने भी रूल्स हैं वे सब लागू होते हैं।

जहां तक प्रोमोशन का ताल्लुक है वैसे तो बोर्ड ऑटोनोमस बोडी है और वह देखता है कोई आदमी काबिल है उसको कोऑपरेट करता है तो बिना किसी इन्टीग्रिटी

(श्री बरतकुल्लखां)

के वह उसको एनकरेज करता है और जहां वे काम करने के काबिल हैं वहां उनको एन्करेजमेंट दिया जाता है ।

एक मामले का जिक्र किया गया और कहा गया कि एक इन्जीनियर के खिलाफ ३५ मामले हैं जो एन्टी करप्शन द्वारा लगाये हुए हैं; जहां तक मुझे मालूम हुआ है एन्टी करप्शन द्वारा कोई इन्क्वायरी चल रही हो लेकिन एन्टी करप्शन ने चालान नहीं किया, जब तक एन्टीकरप्शन विभाग चालान नहीं करे, एन्टी करप्शन की रिकमन्डेशन के ऊपर डिपार्टमेंन्ट इन्क्वायरी करके स्ट्रिक्चर पास नहीं करे तब तक कोई भी फैसला करना एक तरह से प्री-मेच्योर होगा और वह विक्टीमाइ-जेशन की तरह माना जायगा ।

दूसरी बात, यह भी कही गई कि स्टील के खम्भों की जगह सीमेन्ट के खम्भे गाड़े क्यों नहीं जाते, उसके बारे में ख्रुश्चेव जैसी ऑथोरिटी को भी कोट किया गया था ? मैंने इस बारे में जानकारी हासिल की, मुझे यह मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान के अन्दर कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां १३२ के० डब्लू० लाइन पर सिवाय स्टील के खंभे के और कोई दूसरी तरह के खंभे लगाये गये हों । यह हो सकता है कि जितनी टेक्निकली-प्रोग्रेस हमें करनी चाहिये उतनी नहीं कर पाये हों । जितने भी प्लान होते हैं वह सेन्टर से और प्लानिंग कमीशन द्वारा मन्जूर शुदा होते हैं । उसमें सेन्ट्रल पी० डब्लू० की राय होती है । उसकी राय के बिना हम इन्ट्रोड्यूस नहीं कर सकते । इसके लिये स्टील के खंभे के अलावा दूसरी प्रकार के खंभे लगाने की राय नहीं है । जब तक इस प्रकार की स्कीम को सेन्टर एप्रूव नहीं कर लेता है या टेक्निकली उसको एग्ज़ामिन नहीं कर लेता है हम सीमेन्ट के खम्भे लगा नहीं सकते ।

श्री चन्दनमल वैद : ख्रुश्चेव का एप्रूवल नहीं होगा ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या आपने इसके लिये सेन्टर को और प्लानिंग कमीशन को एप्रोच किया था ?

श्री बरकतुल्लाखां : (जारी) आज तक हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में किसी भी स्टेट ने इसके लिये एप्रोच नहीं किया । अब जानकारी मिल गई है, मैं कोशिश करूंगा डाइरेक्टली-इन्डाइरेक्टली इस बारे में एप्रोच करूं ।

श्री पी० के० चौधरी : That was in 1955.

श्री बरकतुल्लाखां : Well, the suggestion has come now and we shall now try directly, indirectly, formally and informally, and I can assure the Hon'ble Member that his suggestion has not fallen on deaf ears.

जहां तक लकड़ी के खम्भों का ताल्लुक है, लकड़ी के खम्भे कहां कहां लगाये जा सकते हैं उसके लिये ऑलरेडी ऑर्डर्स प्लेस कर दिये हैं । ज्योंही लकड़ी के खम्भे मिल जायेंगे शहर और देहातों के आसपास इन खम्भों को लगा दिया जायेगा ।

एक मेरे दोस्त ने इन्डस्ट्रीज़ को कन्सेशन देने के बारे में कहा । मैं उनसे कहना चाहता

(श्री बरकतुल्लाखां)

हूं कि कन्सेशन देने का ताल्लुक बोर्ड के हाथ में नहीं है । कन्सेशन गवर्नमेंट के हुकम से दिया जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसको बोर्ड इम्प्लीमेंट करता है ।

श्री पी० के० चौधरी : But the Government should instruct them.

श्री बरकतुल्लाखां : The Hon'ble Members need not worry on that account. If they convince the Government about the industries where concession should be given and agriculture is one of them, and if the Government allows that concession the Electricity Board will be most willing to do it.

इसके साथ साथ कुछ कॉन्ट्राडिक्शन की बात भी आई थी । मेरे मित्र ने बताया कि कॉन्ट्राडिक्शन है । असल में देखा जाय तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है । हुआ ऐसा था कि एक्चुअल लेबर वर्क जो था वह तो कम्प्लीट हो चुका और सब–स्टेशन का जो इक्विपमेंट था वह कम्पलीट नहीं हुआ । इस तरह से इम्प्रूवमेंट का जो रुपया था वह बच गया, बाकी लेबर आदि का जो काम था वह तैयार हो गया, इस स्टेज में मेनुअल वर्क तो कम्पलीट था और सेमी–टेक्निकल वर्क कम्पलीट हो गया मशीनरी का वर्क नहीं हो सका इसलिये इस कालम से हटा कर दूसरे कालम में रख दिया गया। इससे कुछ कन्फ्यूजन जरूर हो गया है इसके लिये मैं माफी चाहता हूं, जिस तरह से यह रखा गया है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन जरूर है।

इसके अलावा एक मेरे दोस्त ने यह भी फरमाया था कि सुपरवाइज़र्स एग्ज़ामिनेशन हुए वे ठीक प्रकार से नहीं हुए । जहां तक सुपरवाइज़र्स के एग्ज़ामिनेशन का ताल्लुक है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं । सुपरवाइजर्स के इम्तिहान इलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर जो गवर्नमेंट का एम्पलॉई होता है उसके द्वारा लिये गये हैं । इसके अन्दर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का किसी प्रकार का दखल नहीं है ।

श्री चन्दनमल बैद : आप कन्ट्रोल करते हैं या नहीं ?

श्री बरकतुल्लाखां : मुझे मेरे मित्र माफ करें यहां हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नमेंट को नहीं, पंचायत और पब्लिक हैल्थ को डिस्कस नहीं कर सकते ।

जहां तक ताल्लुक है आपने जब गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ दिलाया है तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी, जानकारी करेगी ऐसे कितने वाकेआत हुए हैं और किस तरह से इम्तहान लिया गया, इस बारे में और कुछ जानकारी मुझे देंगे, मैं इस मामले में उनके पास बैठकर बातचीत कर सकता हूँ और उनको कन्विन्स करके जो भी एक्शन लिया जाना चाहिये वह लूंगा और उनको जानकारी दूंगा ।

एक माननीय सदस्य ने जोधपुर पॉवर हाउस के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कहीं थी उसके लिये मैं उनको बताऊं, एक मेकेनिक और एक इन्जीनियर को सस्पेन्ड कर दिया गया, जोधपुर में पोल्स था, वह गिर गया था कुछ नुकसान भी हुआ था । इसके लिये

(श्री बरकतुल्लाखां)

ओवर अल पिक्चर मैंने आपके सामने रखी है और यह आशा लेकर चला हूं कि हम सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के जो टार्गेट्स हैं हम उनको अचीव कर लेंगे। हमें इस अर्से में जो भी एक्सपीरियन्स हुआ है उसको हम आगे आने वाली प्लान में दूर कर सकेंगे। हम देखते हैं कि शुरू शुरू के अन्दर प्रोग्रेस कम हुई है। यह इसलिये कि हमने टेन्डर्स इन्वाइट किये थे उसके लिये हमें स्पेसिफिकेशन के मुताबिक सामान नहीं मिला। बहुत सी जगहों से टेन्डर आये उनमें भी इक्विपमेंट ९० पर्सेन्ट ठीक थे और दस पर्सेन्ट अकोर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं मिलते थे। नतीजा यह हुआ १० पर्सेन्ट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं होने से वह ज्यादा यूज़फुल नहीं हुए। जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस बढ़ती गई ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च करते गये। इस बारे में माननीय सदस्य सदन में या सदन से बाहर जो भी बातचीत करना चाहें, मैं उनसे बातचीत करूंगा, उनकी राय लूंगा। इस बारे में हमारी जो भी कमजोरियां हों वे दिखावें, उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने को खुशकिस्मत समझूंगा आप मुझे क्रिटिसाइज़ करते रहें और समझाते रहें ताकि मैं अपने काम को सही रास्ते पर ले जा सकूं।

श्री सम्पतराज जैन : मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री सभापति : पहले आप मिनिस्टर कन्सर्न्ड का जवाब सुन लीजिये, बाद में कोई प्रश्न करिये।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री) : चेयरमैन साहब, मैं अपनी ओर से और मेरे डिप्टी मिनिस्टर साहब की ओर से आप स को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने आज जो यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट पेश हुआ है और उस पर जो बहस हो रही है उसके सम्बन्ध में बड़े अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पूर्ण रूप से कोशिश करेगा कि उन सुझावों पर अमल करे जहां तक हो सके। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जो लड़ाई है वह अगेन्स्ट टाइम है और इसके अलावा हम इस कोशिश में हैं कि राजस्थान की जनता को जल्दी २ पॉवर की फेसिलिटीज़ मिले। इसमें हमें कई अड़चनें भी आ रही हैं। मेटीरियल की अड़चनें आती हैं, फॉरिन एक्सचेन्ज की अड़चनें आती हैं, लेबर प्रोब्लेम्स आते हैं। तो हम इस सब को देखते हुए हम आपके सामने यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जहां तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट का सवाल है हमारा सवाल है, बोर्ड का सवाल है, हमारे बॉएज़ फील्ड में काम कर रहे हैं उनका सवाल है, हम आश्वासन देना चाहते हैं कि काम होगा, जो फिट होगा, क्विक होगा ताकि राजस्थान का भला हो सके।

(करतल–ध्वनि)

इस विषय में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान बना था तो उस वक्त १९ रियासतें थीं। १९ रियासतों में कई रियासतें बड़ी थीं, कई छोटी थीं, जैसे झालावाड़ है, छोटी रियासत थी। उनकी प्रोब्लम्स थीं। वे अलग अलग प्रोब्लेम्स थीं। उनकी इकॉनोमिक प्रोब्लम्स भी अलग अलग थीं। जैसे बीकानेर स्टेट थी। पैसा ज्यादा था,

(श्री हरिश्चन्द्र)

झालावाड़ स्टेट थी तो पैसा कम था। जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है एक तरीके से राजस्थान के लिए भला नहीं कर सकते थे, कोशिश की थी। यह कह सकते हैं छोटी रियासतें कोशिश करती थीं कि जनता की भलाई हो सके। नॉनअवेलेबिलिटी ऑफ फन्डस के कारण इतनी भलाई नहीं कर सकती थीं जितनी बड़ी रियासतें कर सकती थीं।

राजस्थान का एकीकरण हुआ उस वक्त पॉवर की पोजिशन है वह इन्ट्रेस्टिंग हैं। उस समय हमारे पास राजस्थान में कुल १६ हजार किलोवाट बिजली थी। यह इन्स्टाल्ड पोज़िशन थी। उसकी ८ हजार फर्म केपेसिटी थी। यह बताती है कि राजस्थान के इन्टीग्रेशन के वक्त क्या पोजिशन थी और उसके बाद फर्स्ट फाइव इयर प्लान के आखिर में और सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के शुरू में जो पोजिशन सामने आयी है वह यह आयी क ३४,६०० किलोवाट इन्स्टाल्ड केपेसिटी हो गई और १५ हजार फर्म केपेसिटी। आपको यह जान कर खुशी होनी चाहिए कि इन्टीग्रेशन के वक्त से लेकर एन्ड ऑफ दी फर्स्ट फाइव इयर प्लान और बिगिंग ऑफ दी सेकिन्ड फाइव इयर प्लान हमने जहां ८ हजार किलोवाट फर्म केपेसिटी थी वहां १५ हजार फर्म केपेसिटी कर ली। अगर हम यह कहें कि तरक्की नहीं हुई थी उन दिनों में भी तो वह भी मैं कहूंगा कि फैक्ट्स एन्ड फीगर्स यह जरूर कह रहे हैं कि और हम तरक्की कर सकते थे, यह मैं भी मानता हूं। जो डिफिकल्टीज़ हमारे सामने आती हैं उनको ओवर-कम करने लिए और डिफिकल्टीज़ को देखते हुए जो प्रोग्रेस उस जमाने में हुई थी वह भी क्रेडिटेबल है।

यह बात तो हम सब को माननी होगा कि राजस्थान की तरक्की के लिए चीप पॉवर एसेन्शियल है। चीप पॉवर के बिना, मैं मान कर चलता हूँ कि राजस्थान का डेवलपमेंट नहीं हो सकता और आज कल के युग में यह निहायत जरूरी हो जाता है कि चीप पॉवर जनता के पास अवेलेबल हो ताकि उसके आधार पर वह अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ा सकें। यह मान कर चलना चाहें कि अगर किसी शहर में लाइट आ जाती है और सिर्फ लाइट का काम घर को रोशनी देने का है तो मैं यह कहूंगा कि यह ठीक नहीं है। क्योंकि अब अगर एक आदमी की आर्थिक स्थिति १०), १५) की है, उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति तो वहीं की वहीं रहे, हमारा खर्चा बढ़ जावेगा कि हमको घर में बल्ब लगाना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम उस बिजली का किस तरह से उपयोग करें। आर्थिक हालत बढ़ती जावे और उस बिजली के मार्फत हमारे उद्योग-धन्धे चलें और आज जनता १००) कमा रही है तो उससे १५०) कमा सके। जहां तक हमारी तरक्की का सवाल है, मैं मान कर चलता हूं कि इसमें बिजली का बड़ा हाथ है। आप सब के सामने यह बात पेश करते हुए मुझे खुशी होती है कि जहां तक अपना प्लान प्रोविज़न है, राजस्थान ने टोटल प्लान प्रोविजन में से पॉवर प्रोजेक्ट के लिए २० पर्सेन्ट रखा है। This is a big amount, 20 percent

इस प्लान के तहत सेकिन्ड फाइव इयर

(श्री हरिश्चन्द्र)

प्लान में जो अचीवमेंट्स हुए हैं वे मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। प्लान को तीन हिस्सों में बांटा है: डीज़ल, स्टीम और हाइडल। इन तीन हिस्सों में जहां तक डीज़ल का सवाल है, सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के जो टार्गेट्स हैं वे हमारे सामने हैं। वह है ६,१४५ किलोवाट। इसको ब्रेक-अप वेल्यू भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। डीज़ल की 6,145 Kilowatt-total capacity to be generated during the cecond Five year plan. उसमें से हम अब तक ५,१८५ किलोवाट बिजली डेवलप कर चुके हैं। उसकी ब्रेक-अप वेल्यू भी मैं देने के लिए तैयार हूं और वह इस तरह है :

भरतपुर में	५१२	किलोवाट
अलवर में	३००	,,
किशनगढ़ में	२००	,,
टोंक में	२५०	,,
जैसलमेर में	६२	,,
सागवाड़ा में	१२०	,,
भीलवाड़ा में	५००	,,
डूंगरपुर में	२२५	,,
डीग में	१२०	,,
रतनगढ़ में	३००	,,
चित्तोड़गढ़ में	३०४	,,
बिलाड़ा में	२५०	,,
नागोर में	२५०	,,
जालोर में	२५०	,,
सुमेरपुर में	३०४	,,
विजयनगर में	१५०	किलोवाट
केकड़ी में	१००	,,
मालपुरा में	१२५	,,

आंकड़े बोल रहा हूं वे किलोवाटस में हैं।

इस तरह से ४,४६२ किलोवाट इसकी टोटल केपेसिटी आती है।

श्री श्रीभानसिंह : Are you generating all this ?

श्री हरिश्चन्द्र : Yes.

श्री श्रीभानसिंह : No, I think, at Sumerpur, you are not generating this.

श्री हरिश्चन्द्र : 304 it is.

श्री श्रीभानसिंह : It is a wrong figure.

श्री हरिश्चन्द्र : I don't think so. I will be interested to know if this is wrong.

श्री श्रीभानसिंह : Even at Malpura, one engine has gone to Kashmir.

श्री हरिश्चन्द्र : There may be another set but the total output is this. In addition to that 200 Jhalawar, 300 Karauli, 232 at Rajsamand.

in addition to that यह है। डूंगरपुर में २८५ किलोवाट। अब कमीशन होगा। They are under preparation.

डीडवाना २५० किलोवाट

टोडा भीम २५० किलोवाट

(श्री हरिश्चन्द्र)

ये तीनों आइटम्स will be complete by the end of 1960.

बाकी ये मैंने जो आपको दिये हैं ये फिगर्स फिगर्स ऑलरेडी कमिशन्ड हैं....

श्री श्रीभानसिंह : Does the Hon'ble Minister mean to say that the electricity has been commissioned to Rajsamand ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : At Shahpura, it has not yet.

श्री श्रीभानसिंह : Probably the switch gear has not reached to Rajsamand.

श्री हरिश्चन्द्र : It has started working.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It is not commissioned...

श्री हरिश्चन्द्र : I would certainly be very glad to talk with the Hon'ble Member and find out. But the information I have is that out of 6,140 Klwt. that was due in the Second Five year Plan 5.85 have already started. इसके अलावा आउट ऑफ प्लान अलग हुआ है। जैसे इमरजेंन्सी आ गई या कहीं ब्रेक डाउन हो गया, छोटे सैट्स को वहां भेज दिया है वह जो है जोधपुर में ४००, बीकानेर में २२४, २०८ और ४०१, कोटा में ४०१ और सिरोही में ४०१ और एक २५ का और फलोदी में १०४ किलोवाट। यह जो टोटल मैंने आपके सामने अर्ज किया यह इन एडीशन टू दी प्लान था। प्लान के अलावा यह आपके सामने जो फिगर्स रखी हैं वह हैं। इसके अलावा जो स्टीम का है वह मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। टोटल केपेसिटी ऑफ स्टीम टर्बाइन २२,००० की थी और इस २२,००० की ब्रेक-अप वेल्यू यह है जयपुर में ८,००० किलोवाट का, कोटा में २,००० का अलवर में २,००० का, जोधपुर में ६,००० का और भरतपुर में ४,००० किलोवाट का। इसमें से एक ३,००० का ६ मई, १९५९ को जयपुर में चला और २,००० का अभी ३१ मार्च, १९६० को कोटा में चला। बाकी का जो बेलेन्स है जयपुर का ५,०००, अलवर का २,०००, जोधपुर का ६,००० और भरतपुर का ४,००० यह हम आशा करते हैं कि बाई दी एण्ड ऑफ दी सेकिण्ड फाइव इयर प्लान तक कमीशन होकर चालू हो जायेगा।

इसके अलावा जो भाखरा-नांगल की पोज़ीशन है उसके सिलसिले में मैं सदन के सामने कुछ अर्ज करना चाहूंगा। वह यह है कि वैसे तो सब लोगों को मालूम है कि भाखरा-नांगल सतलज के ऊपर डेम है। वहां से जो बिजली उत्पन्न होगी उसमें राजस्थान का हिस्सा १५. २२ पर्सेन्ट का है। तो जो मेक्जिमम केपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी वह है १६,४३७ किलोवाट। यानि राजस्थान को भाखरा-नांगल से इतनी पॉवर उपलब्ध होगी। यह जो पॉवर आ रही है यह दो लाइनों में आ रही है। एक लाइन पंजाब से चलेगी और ६६ के० वी० और ६४ माइल लम्बी चलेगी जो कि मुकट-शहर से गंगानगर जायेगी। दूसरी जो है वह आयेगी हांसी से हिसार और राजगढ़ वह होगी १३२ के० वी० की, दोनों लाइनें और

(श्री हरिश्चन्द्र)

४३ मील लम्बी होगी। अब इसके सिलसिले में मैं आपके सामने कुछ शिड्यूल पेश करना चाहता हूं। गंगानगर तो मैं खुद होकर आया था और वहां के इन्सटालेशन मैंने देखे हैं, हनुमानगढ़ के भी देखे हैं और हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ कॉलोनी में लाइट जो है गंगानगर से पहुंच गई है और जो बाकी के हैं जैसे केसरीसिंहपुर, पृथ्वीराज-सिंहपुर, करणपुर, पद्मसिंहपुर, रायसिंह नगर आदि के लिए आशा करते हैं कि अप्रेल के आखिर तक वहां का जो एरिया है उसमें लाइट दे सकेंगे। अब जहां तक सवाल राजगढ़ का रहा तो राजगढ़ की स्थिति ऐसी है कि वहां पर अभी फुल केपेसिटी पंजाब से नहीं मिली है। हमें अभी लिमिटेड क्वान्टिटी में लाइट मिल रही है। तो हमको सप्लाई भी लिमिटेड क्वान्टिटी में ही करना है। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उससे मैंने पूछा था कि कौन कौन सी जगह इमीजियेटली लाइट की जरूरत है राजगढ़ में है....

श्री भानसिंह (बयाना) : On a point of clarification. Punjab Government has been supplying limited quantity because the hoist chamber has been destroyed and previously it was agreed, but the Board of the Government was not prepared to utilise.

श्री हरिश्चन्द्र : What I was saying is as soon as the light comes from Punjab. It has not come. When it comes it will be supplied. It has not arrived and we were hoping to get it by March, but now we hope to get it by 20 th of April.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपने कहा था कि लिमिटेड क्वान्टिटी में पंजाब से बिजली मिल रही है....

श्री हरिश्चन्द्र : गंगानगर के लिए कह रहा हूं। जैसे हमें १६ हजार किलोवाट मिलने वाली है उसमें से ४ हजार तो उधर जा रही है और बाकी की राजगढ़ में आयेगी....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपको डिप्टी मिनिस्टर साहब कुछ खबर दे रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : अभी जब तक कि भाखरा का फुल डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक फुल लाइट नहीं आयेगी। जितनी आयेगी उसी का डिस्ट्रिब्युशन होगा, यह मैंने निवेदन किया था। जितनी आयेगी वह ग्रेजुएली बढ़ती जायेगी और मेक्जिमम क्वान्टिटी १६ हजार की है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता था कि गंगानगर की पोज़ीशन मैंने रख दी कि by the end of April we hope to supply. यह जो टाउन मैंने बताये, जब लाइट राजगढ़ में आ जायेगी तो हम रतनगढ़, चुरू, रामगढ़, सुजानगढ़, सांडवा, डूंगरगढ़, दुलचासर, सरदारशहर, राजलदेसर, ताल छापर, बीदासर नापासर और सूड़सर इन जगहों पर हम इमीजियेटली लाइट दे सकेंगे। अब रही रतनगढ़ से बीकानेर की लाइन, उसके लिए माननीय सदस्यों ने पूछा था, उसमें यह है कि लाइन कम्पलीट है लेकिन स्विच बोर्ड जो होते हैं वे अभी तक नहीं आये हैं। तो जब तक स्विच बोर्ड नहीं आ जायेंगे तब तक हम उस लाइन को ऑपरेटिव नहीं कर

(श्री हरिश्चन्द्र)

सकते । तो अभी भी बीकानेर से रतनगढ़ में ३३ के० वी० लाइट आती है तो इमर्जेन्सी में बीकानेर को भी सप्लाई कर सकते हैं अ् रतनगढ़ । तो हाई-टेन्शन लाइन के लिए जब तक स्पेशलाइज़ स्विच बोर्ड नहीं आ जायेंगे तब तक हम आॅपरेट नहीं कर सकते, but in cases of emergency, we can supply even today. हम उसको बीकानेर तक भी पहुँचा सकते हैं, ऐसी हालत में हम हैं। अब बीकानेर में पोजीशन राजगढ़ में लाइट आने के बाद क्या होगी ? जब इन जगहों पर बिजली सप्लाई हो जायगी तो बीकानेर का लोड रिड्यूस होगा । बीकानेर में कम से कम ७०० या ८०० किलोवाट लोड रिड्यूस होगा । उस रिडक्शन से हमारा यह अन्दाज है कि जो इस वक्त प्रिकेरियस कन्डीशन चल रही है वह थोड़ी बहुत स्टेबिलाइज़ होगी और इस स्टेबिलाइजेशन का इफेक्ट यह होगा कि हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारा स्विच बोर्ड आ जाएगा तो राजगढ़ से बीकानेर को सप्लाई कर देंगे....

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर-सु०) : जयपुर से चौमू तक क्या है ?

श्री चन्दनमल वैद : Is the Hon'ble Minister sure that we will receive the electricity at Rajgarh by 15th of April ?

श्री हरिश्चन्द्र : This is the information, we have received, that we have been trying to...

श्री सभापति : I think this clarification, you can receive by means of a question. Yes please, continue.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Member is seeking enlightenment of Rajgarh and Sardarshahar...

श्री सभापति : Hon'ble Minister, please continue.

श्री हरिश्चन्द्र : इसके अलावा अब चम्बल की जो बिजली आने का है उसके सिलसिले में आपसे निवेदन करना चाहूँगा। चम्बल की पोज़ीशन यह है कि राजस्थान को अगर ३ सेट चलते हैं गांधीसागर पर, तो ३७,५०० किलोवाट जो है लाइट मिलेगी, पॉवर मिलेगी ।

४.५१ म०प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अगर ४ सेट चलते हैं गांधी सागर पर तो ४६,००० किलोवाट इलेक्ट्रिक पॉवर जेनरेट होगी । अब यह जो ४६,००० या ३७,५०० किलोवाट है इनको चार लाइन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जायगा ।

गांधीसागर टू सवाई माधोपुर १३० किलोवाट डबल सर्किट लाइन ११७ मील,

सवाई माधोपुर से जयपुर १३२ किलोवाट सिंगल सर्किट लाइन ८७ मील,

कोटा से अजमेर १३२ किलोवाट सिंगल सर्किट लाइन ११७ मील,

नीमच से उदयपुर १३२ किलोवाट सिंगल सर्किट लाइन ८१ मील ।

(श्री हरिश्चन्द्र)

ये ४ मैन लाइनें होंगी। अब इनमें मेरा यह निवेदन करना है कि कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि लाइन हमारे ऊपर जा रही है लेकिन बिजली नहीं मिल रही है, तो इसके सिलसिले में आपसे निवेदन यह करना है कि जब हाई टेन्शन पर पॉवर जाती है तो उसको लोअर स्टेज पर डाउन करने में, यानि जब कि १३२ किलोवाट की लाइन जाती है तो उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा और यदि नॉर्मल कन्ज़म्पशन १,००० के ऊपर जाता है तो ट्रान्सफारमर लगाया जायगा वे इतने हाई कॉस्ट के होते हैं कि फिर बिजली रेम्युनिरेटिव नहीं रहती है। तो उसके लिए यह हो सकता है कि अगर यह यहां पर इतना पॉवर जेनरेट होता है कि वे कम्पेन्सेट कर दें इतने इन्स्टालेशन के लिए तब तो आदमी स्टेप, डाउन कर सकता है। आगे हमने यह कहा कि the agreement has been arrived at between Madhya Pradesh and Rasjasthan. जैसे हमारे यहां राजस्थान के ऊपर से मध्य प्रदेश की लाइन जा रही है तो मध्य प्रदेश के स्टेशन से नज़दीक वाले जो गांव हैं उनको वे सप्लाई कर देंगे और मध्य प्रदेश के ऊपर से राजस्थान की लाइन जा रही है तो आसपास के गांवों को राजस्थान के स्टेशन से सप्लाई कर देंगे। इस तरह से कोऑर्डिनेशन करने के लिए उनको लिखा and they have agreed और मेरे ख्याल से जो नेबरिंग टाउन्स और विलेजेज़ हैं और जहां मध्य प्रदेश हमको सराउन्ड करता है या हम मध्य प्रदेश के हिस्से को सराउन्ड करते हैं वहां हम उनकी मदद करेंगे और वे हमारी मदद करेंगे। इस तरह से कोऑर्डिनेशन करते हुए जो एरियाज़ इस तरह के हैं उनमें हम पॉवर सप्लाई करेंगे। स्टेपिंग डाउन इतना कॉस्टली हो जाता है कि हम इतना स्टेपिंग डाउन नहीं कर सकते हैं।

अब मैं आपको इसके अलावा, यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने एक अप-टू-डेट लिस्ट बनाई है....

श्री उपाध्यक्ष : But at the same time, I will request the Hon'ble Minister to wind up the debate before 5 O clock. I want the sense of the House. We can sit a little longer.

श्री हरिश्चन्द्र : 15 minutes more I want.

कई माननीय सदस्य : १०, १५ मिनट और बैठ जाइये। यह कम्पलीट हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : That's all, I wanted. I have taken the sense of the House. Continue, please.

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने यह कोशिश की है। यह हम भी मानते हैं कि गांधी सागर से जो लाइट उत्पन्न होनी चाहिए वह आप लोग जितनी उम्मीद लगा कर बैठे हैं हम लोग भी बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी वह आये। लेकिन इसके अन्दर हो सकता है कि डिफिकल्टीज़ हमारे सामने आ रही हैं। तो मैंने एक अप-टू-डेट स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की है कि हर लाइन पर जो इलेक्ट्रिसिटी देने वाले हैं उनकी हरेक की क्या पोज़ीशन है। मैं यह चाहूँगा कि इसको सदन के सामने रख सकूं।

(श्री हरिश्चन्द्र)

इसके ऊपर मैं इतनी बात चाहूँगा कि मैं इसको पढ़ूंगा, क्योंकि यह टेक्निकल मामला है और बिना पढ़े मैं आपके सामने नहीं रख सकता हूं।

ऐसा है कि सवाई माधोपुर से जयपुर १३२ किलोवाट सिंगल सर्किट लाइन की क्या पोज़ीशन है? उसकी पोज़ीशन यह है कि: "Supply orders for the towers for this line were placed on M/s S. A. E. Milano. Italy. These towers have since been received and the erection work has been taken in hand. Out of a total of 404 towers to be erected for this line execavation for 323 stub setting and concreting for 323 earthing for 109 stubs and erection of 295 towers has been completed." यह इसकी पोज़ीशन है।

अब गांधी सागर से कोटा और कोटा से सवाईमाधोपुर की क्या पोज़ीशन है, यह आपके सामने आ जायेगी। वह यह है कि: "Steel required for the fabrication of towers for this line has been arranged and fabrication of A.Type towers is being carried out by M/s. Harrison and Crosfield at Quilon through M/s Crompton Engineering Co., Madras. Out of a total of 519-A-Type towers required for this line, the first consignment of 230 stubs for these towers along with 8 sets of stub-setting templates has also been despatched by the fabricators to Kotah" अब ऐसा है कि टॉवर्स होते हैं और टॉवर्स के अन्दर स्टब्स लगाने पड़ते हैं, उसके ऊपर टावर खड़ा होता है। तो अन्दाज यह है कि स्टब्स का काम शुरू हो जाय तो इतने टाइम में हमारे पास टॉवर आ जायेंगे और टॉवर्स का काम भी फिर साथ के साथ चालू करके लगते जायेंगे।

कोटा से अजमेर और नीमच से उदयपुर, इसके लिए We require about 3,400 tons of steel for fabrication of towers required for the above 2 transmission lines. Nearly 1,240 tons of steel is to be received from the imported Russian steel, 30 tons under D. L. F. import, and 2,100 tons will be procured from indegenous sources, i. e. from M/s. Tata Iron & Steel Co. and Indian Iron & Steel Co. The imported steel has already been received. As per present schedule the deliveries of the indegenous steel is expected to be completed by May, 1960. Confirmation of date is, however, awaited from the suppliers. अपने यहां दो कंपनियां हैं: एक तो टाटा आयर्न एण्ड स्टील कंपनी और दूसरी इंडियन आयर्न एण्ड स्टील कंपनी। तो इन्डीजिनस सोर्सेज़ से स्टील लेकर और बाहर से हाई ग्रेड का स्टील मंगाया जाकर उनसे टॉवर्स फेब्रिकेट होकर फिर इन लाइन्स पर लगेंगे।

As regards the fabrication of towers for these lines, orders have already been placed on M/s Structural Engineer, Bombay. The design of the towers has been received from the C. W. P. C. and has been forwarded to the Fabricators. Fabrication will start as soon as steel is received.

श्री श्रीमानसिंह : When is the steel expected to be received ?

श्री हरिश्चन्द्र : It is coming. We have already received some. Latest 800 tons we have received. डिवाइस के लिए भी हमने लिखा है। As regards Tower Accessories-All accessories other than the barbed wire required for anticlimbing devices have been ordered on M/s. Crompton. who will supply the same along with the towers. Eight tons or of barbed wire for this line would be received from the Iron & Steel Controller by the end of June, 1960.

(ii) SAWAI MADHOPUR-JAIPUR LINE

Barbed wire for this section has to be arranged from the supplies already placed on the Iron & Steel Controller. Danger, Number and Phase plates will be procured in time from indigenous sources.

(iii) KOTAH-AJMER & NEEMUCH-UDAIPUR 132 KV LINES

The accessories will be procured from the indigenous sources. Action is being taken.

INSULATORS

Insulators required for Gandhisagar-Sawai Madhopur double circuit line and part requirement of Sawai Madhopur-Jaipur single circuit line have already been procured and are available at Kotah. Tenders for insulators required for 132 Kv Kotah-Ajmer and Neemuch Udaipur transmission lines, and the balance requirement for 132 KV Sawai Madhopur-Jaipur line have been received, and are now under scrutiny. The delivery of the insulators (for which orders are to be placed) is expected by the end of 1960.

GROUND CABLE

The order for the ground cable required has been placed with M/s. E. M. C. Calcutta. The inspection of 65 tons of the ground cable for Gandhisagar-Kotah Section has been entrusted to M/s Loyds, and the delivery is expected to start within the next 4/5 months.

GROUND CABLE ACCESSORIES

The supplier on whom the order for these accessories was initially placed had backed out, and as such the matter was referred to the Chambal Control Board for permitting us to purchase from other supplier. Necessary decision is expected in about 8/10 days time.

Foreign exchange has already been released and Import Licence obtained. In the light of the decision to be taken by the Chambal Control Board, the Import licence will have to be revalidated and letter of authority changed. Delivery is 3/4 months from the date of import Licence and order.

(श्री हरिश्चन्द्र)

यह मैं इसलिये आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कई चीजें हैं जो आप लोगों को और हमें भी मालूम होनी चाहिये कि क्या हुआ है व क्या नहीं हुआ है। इसलिये हर आइटम का मैंने नोट बनवाया है। आप यदि इसमें इन्ट्रेस्टेड हों तो मैं सब को पढ़ा जाऊं....

श्री श्रीभानसिंह : It may be circulated.

श्री हरिश्चन्द्र : कोई माननीय सदस्य किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में जानकारी चाहें तो मैं इन्फॉर्मेशन देने को तैयार हूं।

जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने चन्द बातें इम्पोर्टेन्ट रखीं। उस सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि जो टेन्डर इन्वाइट होते हैं उनके बारे में शायद यह ख्याल हो कि राजस्थान गवर्नमेन्ट या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन्वाइट करता हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जितने भी टेन्डर्स इन्वाइट किये जाते हैं ये चंबल कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा इन्वाइट किये जाते हैं और उसके अन्दर चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं। मि. हैयात फाइनेन्शियल एडवाइजर मि. बसोल और चीफ इंजीनियर, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बैठते हैं। इनकी जो सब-कमेटी है वह डिसाइड करती है और उसकी रिकमेन्डेशन बोर्ड के सामने जाती है और बोर्ड डिसाइड कर देता है। इसमें किसी इन्डिविज्युअल आदमी के हाथ की बात नहीं है It is a collective thing in which High Power Board is there.

अब जहां तक हाई पॉवर केबल का सवाल है उसका जवाब चीफ मिनिस्टर साहब ने सदन के सामने पेश किया था, वही मैं भी कहना चाहता हूं कि टेन्डर्स बोर्ड ने इन्वाइट किये थे और जब बोर्ड ने टेन्डर्स इन्वाइट किये थे तो मैं नहीं समझता कि क्या ऐसी बात देखते हैं माननीय सदस्य कि जिससे उनके दिल में भय है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि कॉम्पटन एन्ड कम्पनी ने राजस्थान का ही काम लिया हो, ऐसी बात नहीं है। They are completing the work in Madhya Pradesh. They have done electrical work in Kerala and they have done even in Burma. तो हम यह कहें कि यह कम्पनी भी इनएफिशियेन्ट है इसलिये आपको भय हो तो मैं कहना चाहता हूं कि यह बात नहीं है। They are experienced people, they are doing not only in Rajasthan but in other parts of India also.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा ऑब्जेक्शन यह नहीं था, बल्कि मेरा ऑब्जेक्शन यह था कि उसने गारेन्टी दी है या नहीं for finishing the work in time ?

श्री हरिश्चन्द्र : अब मैं माननीय सदस्यों के सामने यह बात पेश करना चाहूंगा वेरी क्लियरली कि यदि हम रिजिड फोर्म में काम करने लगेंगे, according to law, I can assure the House that the Chambal Power will not be received even within another five years. If this is the intention of the House...

श्री श्रीभानसिंह : No. I am afraid we don't want that assurance.

श्री हरिश्चन्द्र : Because after all

(श्री हरिश्चन्द्र)

some latitude has to be given to the workers.

इसमें हमको सिर्फ यह गार्ड करना है कि कोई लूप होल तो नहीं रहता है इसके लिये एक हाई पॉवर्ड कमेटी अपॉइन्ट कर रखी है। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि ठीक तरह से खर्च हो रहा है या नहीं। टेन्डर्स इन्वाइट करते हैं लेकिन क्लॉज बाइ क्लोज देखा जाय कि यह क्लॉज ठीक है या नहीं। मध्यप्रदेश में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिना चंबल बोर्ड की अॉथिरिटी के इरेक्शन तक शुरू कर दिया था ! वहां पर जो थे उन्होंने खुद पर लिया कि काम शुरू करिये, हम देखते हैं with the result that they have cut down their plan by one year. अब हम इस बहस में पड़ जांय कि एक एक क्लॉज में कोमा, फुलस्टोप को देखने लगें, तो उसका असर यह होगा कि हम जहां थे वहीं रहेंगे और जो काम थोड़ा बहुत हुआ है वह भी आप नहीं देख पाते। क्योंकि हम कहते हैं कि इस क्लॉज में यह कमी है और उसमें यह कमी है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बड़ी फर्म्स होती हैं उनसे निगोशियेशन्स चलते रहते हैं और उसके आधार पर हम इस बात का विश्वास रखते हैं कि हमारे साथ इन्जस्टिस नहीं हो रहा है। क्रॉम्पटन एन्ड कम्पनी जितने टॉवर्स लगाये थे उसका पेमेन्ट नहीं हुआ है फिर उन्होंने नोटिस दिया कि आप कोड़ी भी नहीं देंगे तो हम अपनी लेबर को ले जायेंगे और मध्य प्रदेश जायेंगे with the result that they have gone and our work is again held up. तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें यह जरूरत है कि हमारे जो बॉयज़ काम करते हैं उनका एप्रिसियेशन होना चाहिये, उनकी पीठ पीछे बेकिंग होनी चाहिये, तुम काम करो, राजस्थान में लाइट आनी चाहिये। आप जांच करें ऐसी बात न हो कि जिससे आपको भय हो कि पैसा खाते हैं। लेकिन जब तक उनके पीछे बैकिंग नहीं होगा तब तक वे काम नहीं कर सकेंगे। हमारे जो इंजीनियर्स हैं, बॉयूज हैं, जो फील्ड में काम करते हैं उनको हम यह कहना चाहते हैं कि हमारा पूरा बैकिंग है। राजस्थान में जल्दी से जल्दी काम हो, जल्दी से जल्दी बिजली मिले।

(करतल–ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : प्रपोर्शनेट।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं और कोई अर्ज आप से इस वक्त नहीं करना चाहता, सिर्फ यही है कि जो बातें माननीय सदस्यों ने रखी हैं according to strict कानून की बात कही जाय तो ही it is completely right लेकिन हम इन फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ें। आपके सामने कोई बात हो तो आप मुझ से डिस्कस कर सकते हैं, केबिनेट मेम्बर्स से कर सकते हैं, हम समझाने को तैयार हैं। आप और हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी राजस्थान में बिजली आवे....

श्री श्रीभानसिंह : आपने यह नहीं बताया कि चंबल से आने वाले पॉवर की कितनी क्वान्टिटी हम युटिलाइज कर सकेंगे, how much power you will be able to utilise ?

श्री हरिश्चन्द्र : I said some thing in the beginning that if three sets are installed, we would get 37, 500 K.V.

श्री श्रीभानसिंह : How much we will be able to utilise in Rajasthan? Out of 36, how much we will be able to utilise by the end of Second Five Year Plan?

श्री हरिश्चन्द्र : This statement I cannot make at this juncture. मैंने पहले कई प्रश्नों के उत्तर में कहा है कि इसकी सर्वे दो दफा हो चुकी है, एक दफा १९५७ में हुई और फिर १९५९ में। सेन्ट्रल पॉवर सप्लाई कमीशन ने लोड की सर्वे की है। उसके आंकड़े नहीं आये हैं, उसके पहले मैं सदन के अन्दर कह दूं कि जयपुर का लोड सर्वे हो गया है I have not got the figures. As soon as the figures are there. I will be able to inform the House.

श्री पी. के. चौधरी : जयपुर–फुलेरा लाइन कब तक हो जायगी?

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इलेक्शन के बाद।

श्री हरिश्चन्द्र : पांच मिनट और लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक, दो पाइन्ट और थे which I think are interesting.

माननीय सदस्यों ने यह कहा कि बीकानेर पॉवर हाउस में बड़ा लोस है। यह हम मानते हैं कि लौस है, मगर लोस के कारण भी हैं। पहला यह है कि जब बोर्ड ने पॉवर हाउस को टेक ओवर किया तो केटेगेरिकल यह स्टेटमेंट किया था कि जो आदमी इस इलेक्ट्रिक पॉवर हाउस में हैं उनको नहीं हटायेंगे। इस वक्त उस पॉवर हाउस में एक हजार आदमी काम कर रहे हैं। जो अजमेर में पॉवर हाउस है उसके बारे में मैंने पता लगाया तो वहां पर १३० से १५० आदमियों के बीच में काम करते हैं। कहां एक हजार और कहा १५० आदमी? तो या तो इस बात को प्रेस करें कि बिल्कुल कॉमर्शियल लाइन पर काम किया जाय और जो अनइकॉनॉमिक प्लेसेज हैं, जैसा डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा, उनको क्लोज़–डाउन करना पड़ेगा, and I don't think this is the sense of the House या दूसरे यदि इकॉनॉमिक बनायें तो आदमियों को रिट्रेंच करें और अगर रिट्रेंच करते हैं तो एक अलग समस्या खड़ी हो जाती है ....

श्री पी. के. चौधरी : ट्रान्सफर कर दीजिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : फुलेरा में।

(हंसी)

श्री हरिश्चन्द्र : वह कह रहे हैं, जैसे जैसे उनको जगह मिलती जा रही है, एब्जोर्ब करते जा रहे हैं। तो यह कहना कि लोस में जा रहा है, उसकी वजह है लोस में क्यों जा जा रहा है। एक कारण यह भी है कि पुराने सेट्स हैं, तेल आदि बहुत खाते हैं, दूसरी वजह यह है कि स्टाफ बहुत ज्यादा है।

एक और पोइन्ट रेज़ किया गया सदन में, वह यह था ....

श्री पी. के. चौधरी : एग्रीकल्चर के लिए पॉवर।

श्री हरिश्चन्द्र : कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊप बड़ा खर्चा हरो रहा है। यह कई मान

(श्री हरिश्चन्द्र)

नीय सदस्यों ने कहा। इसके सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि पहले पहल जब स्टेट डिपार्टमेंट था उस वक्त यह पॉवर डिपार्टमेंट which used to be looked after administratively under the Power and Irrigation Department, थोड़ा खर्चा वे करते थे। उसके अलावा जो खर्चा होता था, लॉ सेक्रेटरी और लीगल रिमेम्ब्रेन्सर पर, इसमें यह भी खर्चा जुड़ता था। उसके अलावा फाइनेन्स डिपार्टमेंट के ऊपर भी खर्चा पड़ता था, अपॉइन्टमेंट डिपार्टमेंट पर भी खर्चा पड़ता था, जनरल एडिमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी खर्चा पड़ता था। ये सब खर्चे थे वे सब खर्चे थे, अब कन्सोलिडेटेड हो गया है तो सब की निगाह में आ गया कि बड़ा खर्चा हो गया। लेकिन इनको वर्क आउट करेंगे तो मैं आपके सामने कहूं कि जो ओवर ऑल अमाउन्ट है, overall percentage of Establishment Charges of the Board's Secretariat including audit and accounts comes to 1.015 percent. Say 1.02 percent.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : For what?

श्री हरिश्चद्र : जी, overall percentage of the Establishment Charges of the Board of the entire plan तो मेरे ख्याल से यह अनुचित तो नहीं है....

डॉ० बहादुरसिंह : अनुचित तो है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा: अनुचित तो है।

श्री हरिश्चन्द्र : पहले यह बंटा हुआ था, अब इकट्ठा हो गया है....

डॉ० बहादुरसिंह : घाटे को देख कर अनुचित है।

श्री हरिश्चन्द्र : घाटा, १ घाटे के लिए मैं बताऊंगा। घाटे के लिए अर्ज करना है कि जब बोर्ड ने टेक ओवर किया तो, १६५६ के फिगर्स में आपके सामने रख रहा हूं। १६५६ के फिगर्स यह हैं कि रूलर्स में २५,८६,६७० आउट स्टेन्डिग था, म्युनिसीपैलिटीज के पास २६,६१,४७५ रुपये आउट स्टेन्डिग, स्टेट गवर्नमेंट के पास १३,७२,२२७ रुपये, सेन्ट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंटस के पास ११,८५,४३६ रुपये और प्राइवेट पार्टीज़ के पास १८,२४,११७ रुपये आउट स्टेन्डिग थे....

श्री चन्दनमल वैद : It is more than a crore...

श्री हरिश्चन्द्र : It works to 91,374. This was the total figure when the Board took over. Now the position is different. Rulers 1,14,682 from 25 thousand. Nearly 50 percent has been recovered. Municipalities, from 21 lacs, it has gone down to 18 lacs.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वसूल नहीं हुआ है रूलर्स से।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !!

श्री चन्दनमल वैद : एडजस्ट हो गया है।

श्री हरिश्चन्द्र : It is nearly 50 percent. म्युनिसिपैलिटीज़ में २१ था, उसके

(श्री हरिश्चन्द्र)

बदले १८ हो गया है, स्टेट डिपार्टमेंटस के पास १३ के बदले १४ हो गया है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंटस के पास ११ के बदले १० हुआ है और प्राइवेट पार्टीज के पास १८ के बदले १८ रहा है। यह करके ओवर ऑल पिक्चर है कि ६१ थाउजेन्डस के बदले ७१ थाउजेन्डस आया है....

श्री चन्दनमल वैद : लैक्स।

श्री हरिश्चन्द्र : लैक्स। तो यह ओवर ऑल पोजीशन आउट स्टेंडिंग की है। इसमें धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि यह वसूल हो। अब प्राइवेट पार्टीज़ के लिए कहा कि १८ के बदले १८ है। इसमें ऐसा है कि कोई अपटूडेट स्टेटमेंट नहीं बन सकता। जो कन्जम्पशन होता है, उसके बिल भेजते हैं, वे आते हैं, बिल भेजते जाते हैं, आते-जाते हैं। इसमें ऐसा अमाउन्ट नहीं है कि १८ का १८ रह गया हो, प्राइवेट पार्टीज़ में आउट स्टेंडिंग के तौर पर मगर ऐसा है कि कुछ आउट स्टेंडिंग प्लस जो बिल भेज रखे हैं उनका अमाउन्ट है। हम कोशिश करें कि यह अमाउन्ट जल्दी रिकवर हो।

अन्त में, मैं, माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि क्योंकि टाइम हो गया है यह बजट स्वीकार किया जाय।

श्री सूबेदारसिंह : एक स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! अब कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा।

श्री सूबेदारसिंह : पहले, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सुन तो लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

प्राक्कलन समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र

मैं, माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्रीमती प्रभा मिश्रा ने प्राक्कलन समिति १९६०–६१ की सदस्यता से अपना त्याग–पत्र दे दिया है। नियम १८० (३) के अन्तर्गत इस रिक्त स्थान की पूर्ति की जायगी। अतः मैं, माननीय सदन के नेता से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री श्रीभानसिंह : क्यों दिया है, रीजन ?

प्राक्कलन समिति के एक रिक्त स्थान की पूर्त्ति करने सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम २३२ के उप नियम (१) में निर्दिष्ट अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार समस्त सदस्यों की संख्या में से, प्राक्कलन समिति १९६०–६१ के एक रिक्त स्थान की पूर्त्ति के लिए १ सदस्य का निर्वाचन किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम २३२ के उप नियम (१) में

(श्री उपाध्यक्ष)

निर्दिष्ट अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार समस्त सदस्यों की संख्या में से, प्राक्कलन समिति १९६०-६१ के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए १ सदस्य का निर्वाचन किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

प्राक्कलन समिति, १९६०-६१, के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, १ सदस्य के चुनाव के सम्बन्ध में, निम्न कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित किया गया है :

१. नामजदगी के पर्चों को पेश करना ।

७ अप्रेल १९६० को ३ बजे मध्यान्होत्तर तक ।

२. नामजदगी के पर्चों की जांच उन सदस्यों के समक्ष जो उस समय उपस्थित रहना चाहें ।

७ अप्रेल, १९६० को ४ बजे मध्यान्होत्तर से ।

३. नामजदगी के पर्चों को वापस लेना ।

११ अप्रेल, १९६० के प्रश्नोत्तर के तुरन्त पश्चात् ।

४. चुनाव, यदि आवश्यक हो ।

१२ अप्रेल, १९६० को १० बजे प्रातः से २ बजे मध्यान्होत्तर तक ।

५. मतों की गणना ।

१२ अप्रेल, १९६० को २ बजे मध्यान्होत्तर से ।

नामजदगी के पर्चों के खाली फॉर्म सूचना कार्यालय से प्राप्त हो सकेंगे तथा उन्हें भर कर सचिव, विधान सभा को निर्धारित समय के पूर्व देने की कृपा करें ।

नामजदगी के पर्चों की जांच रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव, राजस्थान विधान सभा, द्वारा विधान सभा भवन के समिति कक्ष में की जायगी ।

नामजदगी के पर्चे दिनांक ११ अप्रेल, १९६० को सदन में प्रश्नोत्तर के तुरन्त पश्चात् सम्बन्धित सदस्यों द्वारा वक्तव्य के द्वारा, जिनमें केवल इस तथ्य को ही व्यक्त किया जाना चाहिए, वापस लिये जा सकते हैं ।

Now the House is adjourned to meet tomorrow at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बज कर २१ मिनट पर, कल, दिनांक ७ अप्रेल, १९६० के ११ बजे म. पू. तक स्थगित हुई ।)

———

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, ६ अप्रेल, १९६०)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ६४१७

खादी ग्रामोद्योग मंडल द्वारा प्रदत्त ऋण एवं सहायता ।

संचालक, पशुपालन विभाग द्वारा किये गये स्थानान्तरण ।

सदर हॉस्पिटल, धौलपुर की एक्स-रे मशीन ।

पाकिस्तान से आये रेगरों से गणेशमलजी की धर्मशाला (पाली) खाली नहीं कराने के सम्बन्ध में ।

श्री गुरुदत्त, अधिकारी, भेड़ अनुसन्धान फार्म, जयपुर द्वारा अनियमितताएं ।

लूणकरणसर (बीकानेर) में रेल द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था पर खर्चा ।

सीकर जिले में सरकार द्वारा संचालित एलोपैथिक व आयुर्वेदिक अस्पताल ।

चाकसू नगरपालिका का पंचायत में परिवर्तन ।

श्रम विभाग के सहायक जिला नियोजन अधिकारी ।

कोटा जिले में रबी की फसल में लगे 'फड़का' की शिकायत पर कार्यवाही ।

ब्यावर नगरपालिका के अध्यक्ष श्री चिमनसिंह लोढ़ा के विरुद्ध कार्यवाही ।

पशु नस्ल सुधार योजना के अन्तर्गत बारां विकास खंड द्वारा प्रदत्त अनुदान एवं ऋण ।

जयपुर ठेला हॉकर्स मज़दूर संघ द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र पर कार्यवाही ।

जोरपुर पंचायत में हुए गबन एवं भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही ।

भरतपुर गांधी पार्क में रेडियो की पुनः व्यवस्था ।

प्रत्येक जिले में सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों का कार्यालय एवं सहकारी बैंक खोलने की योजना ।

स्तम्भ

प्रान्त के अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड्स में रेशनलाइज्ड पे स्केल्स ।

सरपंच, ग्राम पंचायत नगर द्वारा सामान की खरीद ।

जयपुर नगरपालिका में नियुक्त चलते-फिरते मजिस्ट्रेट्स ।

भूतपूर्व झुन्झुनूं जिला बोर्ड के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान ।

लकड़ी एवं कोयले के विभागीय नाकों की समाप्ति ।

पाली शहर के नगरपालिका क्षेत्र में मोची जाति द्वारा खरीद की गई गैर-आबादी की जमीन का आबादी की भूमि में परिवर्तन ।

प्राक्कलन समिति १६६०-६१ के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा ६४७४

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्राक्कलन समिति, १६६०-६१ के निर्वाचित सदस्यों के माम घोषित किये गये जो इस प्रकार हैं:—

१. श्री अब्दुल गफ्फारखां (१)
२. श्री अनूपसिंह (७)
३. श्री अमृतलाल यादव (५४)
४. श्री किशनलाल शर्मा (७७)
५. श्री घासीराम यादव (४६)
६. श्री चन्द्रसिंह (२६)
७. श्रीमती प्रभा मिश्रा (१२३)
८. श्री पी. के. चौधरी (१२१)
६. श्री बेनाराम गहलोत (१७४)
१०. श्री भंवरलाल शर्मा (१६)
११. श्री भैरोंसिंह खेजड़ला (१५)
१२. श्री भोलानाथ (२१)
१३. श्री मुक्तिलाल मोदी (१०६)
१४. श्री रामनारायण वर्मा (१३८)
१५. श्री रामप्रसाद लड्ढा (१४०)

स्तम्भ

राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के आयव्ययक अनुमान, १६६०-६१ के विवरण पर वाद-विवाद ६४७५

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आयव्ययक), १६६०-६१ जो दिनांक ११ मार्च, १६६० को सदन की मेज पर रखा गया था, पर आज वाद-विवाद किया गया । बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

२. श्री श्रीमानसिंह

३. डॉ० बहादुरसिंह

४. श्री प्रभुलाल पुरोहित

५. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

६. श्री पी. के. चौधरी

७. श्री जयसिंह राणावत

८. श्री चन्दनमल वैद

९. श्रीमती गंगादेवी डाटा

१०. रावल श्री नरेन्द्रसिंह

११. डॉ० चन्द्रकला

१२. श्री हरिप्रसाद यादव

१३. श्री नरोत्तमलाल जोशी

१४. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा

१५. श्री मूलचन्द डागा

१६. श्री शंकरलाल

१७. श्री भीमसेन

१८. श्री सम्पतराज जैन

सरकार की ओर से श्री बरकतुल्लाखां, उप-मन्त्री व श्री हरिश्चन्द्र, विद्युत मन्त्री ने बहस का उत्तर दिया।

घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि श्रीमती प्रभा मिश्रा ने प्राक्कलन समिति, १९६०-६१ की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है।

तदुपरान्त श्री मोहनलाल सुखाडिया (सदन के नेता) ने इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने चुनाव सम्बन्धी कार्यक्रम पढ़ कर सुनाया।

सदन की बैठक ५ बज कर २१ मिनट पर गुरुवार, दिनांक ७ अप्रेल, १९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

बृहस्पतिवार, दिनांक ७ अप्रेल, १९६० की कार्य-सूची

१. राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६० (विचारार्थ)।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८३६ का उत्तर देखिये)

RAJASTHAN KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD, JAIPUR.
STATEMENT SHOWING THE DISBURSEMENT OF FUNDS TO THE VARIOUS VILLAGE INDUSTRIES UPTO 31st August, 1957.

S. N.	Name of the Institutions. and Societies	Year.	Oil Ind.		leather Ind.		Soap Ind.		Amber Ind.		H. P. of Rice		Hand made Paper		Palm Gur		Pottery		Fibre.		Total	
		55-56	Loan	Sub.	Loan	Sub.	Loan	Sub.	Loan	Sub.	Loan	Sub.	Loan	Sub.	Loan	Sub.	Loan	Sub.	Loan	Sub.	Loan	Sub.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23.
1.	Seva Sadan Bhilwara.	55-56	6,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,000	—
2.	Sarvodaya Kendra, Khinel	„	3,000	—	—	—	9,187. 50	4,187.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,187.50	4,187.50
3.	Rajasthan Khadi Vikash mandal, Govindgarh.	„	35,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,000	—
4.	Keandrya Sarvodaya S.S. Ltd, Jaipur.	„	—	—	—	—	12,375	8,375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,375	8,375
5.	Gramothan, Jaipur.	„	—	13,220	—	10,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,220	10,500
6.	Khora Regaran S.S. Ltd., Khora	„	—	5,000	—	7,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	7,500
	Total		44,000	18,220	--	18,000	21,562.50	12,562.50	—												83,782. 50	30,562. 50
1.	Seva Sadan, Bhilwara	56-57	5,750	900	—	—	--	—	11,000	13,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,750	22,200
2.	Sarvodaya Kendraya, Khimal	„	3,750	1,050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,750	1,050
3.	Kendriya Saryodaya S S. Ltd., Jaipur	„	10,000	1,500	--	—	6,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,000	1,500
4.	Khora Ragaran S.S. Ltd. Khora.	„	—	—	2,200	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,200	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13.	Choumu Tel Upt. S.S. Ltd. Choumu.	56-57	5,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	—
14.	Marwar Khadi Sangh, Jodhpur.	„	23,250	3,250	—	—	19,250	10,450	22,000	11,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,500	25,400
15.	Shri Kalu Teli, Nainva.	„	150	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	150
16.	Shri Abdul Gani Teli, Nainva,	„	150	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	150
17.	Shri Abdul Gafar.	„	150	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	150
18.	Shri Kamla Gupta.	„	150	13,7,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	137.50
19.	Gramodyog Samiti, Banswara.	„	6,300	1,800	—	—	—	—	—	—	5,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,300	1,800
20.	Banswara Zila Seva Sangh, Partapur.	„	5,000	—	—	—	—	—	11,000	8,585	2,000	2,000	—	—	—	—	—	—	—	—	18,000	10,585
21.	Nav Nirman Sangh, Udaipur.	,	34,750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,750	—
22.	Kalinzara Tel Utpadak S. S. Ltd., Kalinjara	„	4,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,500	—
23.	Shankar Ghani Tel Utpadak S. S. Ltd., Jaipur.	„	7,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,000	—
24.	Ghani Tel Utpadak S. S. Ltd., Nagaur.	„	9,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000	—
25.	Arthuna Ghani Tel Utpadak S.S. Ltd., Arthuna.	„	2,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,700	—
26.	Tel Ghani Utpadak S. S. Ltd., Partapur.	„	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	900	—
27.	Padam Tel Utpadak S. S. Ltd., Jaipur.	„	10,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	—
28.	Garhi Tel Utpadak S. S. Ltd., Garhi	„	2,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,400	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
36.	Kutter Udhyog S. S. Ltd., Alwar	56-57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000	—	—	—	—	—	—	—	4,000	—
37.	Tad Gur Utpadak S. S. Ltd., Alanpur	„	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	2,860	—	—	—	—	500	2,850
38.	-do- Hamirgarh	„	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,900	2,860	—	—	—	—	1,900	2,860
39.	-do- Devagaon	„	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,300	2,860	—	—	—	—	1,300	2,860
40.	Khari Tat Sarvodaya Sangh, Shahpura	„	—	1,500	—	—	10,250	6,150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,250	7,650
41.	Harijan Tanners Cooperative Society Ltd., Hindaun	„	—	—	3,720	3,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,720	3,000
42.	Valmiki Bah. S. S. Ltd.,	„	—	—	3,720	3,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,720	3,000
43.	Bhandpura „ „	„	—	—	3720	3,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,720	3,000
44.	Nanva „ „	„	—	—	3,720	3,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,720	3,000
45.	Rajasthan Gau Seva Sangh, Jaipur	„	—	—	3,720	3,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,720	3,000
46.	ShriGanga Charm Utpadak S. S. Ltd., Bisalpur	„	—	—	3,720	3,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,720	3,000
47.	Vayana „ „	„	—	—	2,400	3,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,400	3,000
48.	Karauli „ „	„	—	—	3,720	3,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,720	3,400
49.	Kishorpura „ „	„	—	—	3,720	3,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,720	3,400
50.	Badliyas „ „	„	—	—	3,720	3,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,720	3,000
51.	Khadi Gramodhyog Prathishthan, Bikaner	„	—	—	—	—	—	—	11,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,000	—
52.	Ajmer Merwara Gram Seva Mandal, Ajmer	„	—	—	—	—	10,250	6,150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,250	6,150
[redacted]																				—	9,250	9,250

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
61.	Khora Bisal Tad Gur Utp. S.S. Ltd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,860	—	—	—	—	—	2,850
62.	Chavandia Tad Gur Utp. S. S. Ltd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,860	—	—	—	—	—	2,800
63	Hindaun Khadi Utp. S. S. Ltd.	—	—	—	—	—	—	—	—	13,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,200
64.	Bharat Udyog S. S. Ltd.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,100	—	1,100
65.	Management Charges.	—	—	22,245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,245
	TOTAL		238,815	60,367.50	116,390	62,600	101,750	80,137.50	99,000	86,285	22,000	7,000	4,000	—	3,700	14,300	19,000	9,000	—	2,200	6,04,655	321,890
1.	Ajmer Merwara Gram Seva Mandal, Ajmer.	57-56 Upto August	—	—	—	—	—	—	5,500	3,250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,500	3,250
2.	Delwarn Regaran Coop. Multipurpose Society.	„	—	—	3,000	3,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	3,000
3.	Gramodyog SamitiBans wara.	„	—	—	—	—	—	—	11,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,000	—
4.	Jobner Ghani Tel Utp. S. S. Ltd.	„	—	—	—	—	10,250	6,150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,250	6,150
5.	Khora Bisal Regaran S. S. Ltd. Khora Bisal.	„	—	—	2,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,300	—
6.	Khariat Sarvodaya Sangh, Shahpura	„	2,000	—	—	—	—	—	17,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,000	—
7.	Shri Krishan Tel Chani Utp. S. S. Ltd.,	„	2,625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,625	—
8.	Khadi Karyakarta Samiti Dausa	„	5,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	—
9.	Rathor Ghani Tel Upt. S. S. Ltd. Baran	„	2,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,100	—
10.	Laxmi Bahudhundhi S. S. Ltd., Dungari	„	150	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	150
11.	Vimukt Jati Multipurpose Co-op.	„	—	—	3,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20.	Gandhi Vidhyalaya High School, Gulabpura	Upto August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	900	—	—	—	—	—	—	—	900
21.	Hindaun Khadi Utpadak S. S. Ltd., Hindaun	,,	—	—	—	—	—	—	—	2,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,600
22.	Khadi Gramcdhyog Prathisthan, Bikaner	,,	—	—	—	—	—	—	—	6,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,500
23.	Gram Nirman Sangh, Hasteda	,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,100	—	1,100
24.	Jan Sevak Bahudhadhai S.S. LtD.,Mohi	,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,100	—	1,100
25.	Hebate on sale of Ghani Oil.	,,	—	58,025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,025
Total 31st Aug., 57		,,	23,625	58,875	5,550	8,250	10,250	6,150	33,500	25,350	—	—	—	900	—	—	—	—	—	2,200	72,925	1,01,725.
																		Grand Total.			7,61, 362. 50	4,53,177.50

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८४४ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE EXPENDITURE INCURRED UNDER HEAD 39 PUBLICUTILITY WORKS EXECUTED THROUGH THE AGENCY OF COMMISSIONERS AND COLLECTORS FOR THE YEAR 49-50 TO 58-59 PERTAINING TO BIKANER DISTRICT EXPENDITURE OF WATER TANK SENT AT LUNK-ARANSAR.

S. No.	Year.	Expenditure incurred.	Remarks.
1.	1949-50	7,507.00	
2.	1950-51	15,433.00	
3.	1951-52	3,145.00	
4.	1952-53	-	No amount was alloted during the year.
5.	1953-54	360.00	
6.	1954-55	3,313.00	
7.	1955-56	15,027.00	
8.	1956-57	7,500.00	
9.	1957-58	-	
10.	1958-59	18,504.00	
	Total :—Rs.	70,789.00	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८४० का उत्तर देखिये)

क्र० सं०	नाम	स्थान	दिनांक
१	२	३	४
१.	श्री बी० के० सिंह भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी	कोलायत	सितम्बर ५८
२.	,, पुश्करसिंह ,,	उदयपुरवाटी	,, ,,
३.	,, बद्रीप्रसाद पारीख ,,	सरदारशहर	,, ५६
४.	,, जी० एल० पचौली ,,	चिरावा	,, ५८
५.	,, दुर्गासिंह ,,	शिव	,, ५८
६.	,, शम्भूसिंह ,,	मान्डल	,, ५८
७.	,, भभूतराज ,,	सोजत	,, ५८
८.	,, बी० एम० शर्मा ,,	लाडनू	,, ५८
९.	,, मोहनसिंह ,,	खारची	,, ५८
१०.	,, बिशनसिंह ,,	सूरतगढ़	,, ५८
११.	,, रघुवीरसिंह ,,	ओसयान	,, ५८
१२.	,, के० सी० शर्मा ,,	शाहपुरा	,, ५८
१३.	,, आर० सी० शास्त्री ,,	टौंक	अगस्त ५८
१४.	,, नारायणसिंह ,,	नोखा	मई ५९
१५.	,, आर० सी० बटवर ,,	पोकरन	जुलाई ५८
१६.	,, बी० के० पुरोहित ,,	किशनगढ़	जुलाई ५८
१७.	,, ए० एच० पिन्टो ,,	केकरी	मई ५८
१८.	,, चुन्नी लाल ,,	बिलारा	सितम्बर ५८

१		२		३	४	
१९.	,,	एम० एस० के० टार्जन	इन्सट्रेक्टर मेड़ व ऊन	रायसिंहनगर	जुलाई	५८
२०.	,,	आनन्दसिंह	,,	सुमेरपुर		
२१.	,,	डी० पन्डिट	,,	डीडवाना		
२२.	,,	जे० एन० त्रिवेदी	,,	हिन्डौन		

———

OFFICE OF THE DIRECTOR OF ANIMAL HUSBANDRY RAJASTHAN JAIPUR.

No. F. V. 11 (XXV) Estt/ | Dated Jaipur the 3rd Feb,60.

OFFICE ORDER.

As per recommendation of the Rajasthan Public Service Commission, Ajmer vide his letter No. F. V. 7(182) RECT/59/RPSC/1288 dated 24. 11. 59 and No. 1320 dated 5. 12. 59, the following persons at present holding the posts as shown against each in column 3 are hereby appointed temporarily in order of their preference on the posts noted against each in Column No. 4 in the grade of Rs. 110-5-135-EB-10-225 with immediate effect:—

Name 1	Present post 2	New posting & Place of posting. 3	REMARKS. 4
INSPECTORS (5)			
1. Shri C. B. L. Mathur.	Offg. Suppdt., I. C. A. R. Ajmer.	Inspector, Sheep & wool Ext. Jaipur.	He will continue on the post at No. 2 till further orders.
2. ,, Shanker Lal Dave.	Offg. Suppdt., Sheep & Wool Ext. Jaisalmer.	,, ,, Jodhpur.	Vice Shri Inder Singh not selected. Shri Dave will continue on the post at No. 2 till further orders.

1	2	3	4
3. Shri Narayan Singh.	Sheep & Wool Ext. Officer, Nokha.	Inspector, Sheep & W^o^ol Ext. Bikaner.	Vice Shri Govind Singh not selected.
4. ,, Ramchandra Tanwar.	,, ,, Pokran.	,, ,, Jaisalmer.	Vice Shri B. S. Bhati not selected.
5. ,, Brij Mohan Sharma.	,, ,, Ladnu.	,, ,, Udaipur.	Vice Shri Bhagwan Singh not seleced.
SHEEP & WOOL EXTIENSION OFFICERS (19)			
6. Shri Narbda Shankar.	A. H. E. O., Bichhiwara.	Sheep & Wool Ext. Officer, Sojat.	Vice Shri Bhabootraj not selected.
7. ,, Raghunath Singh	R. A. IND. & Eco.	,, Mandal.	Vice Shri Shamboo Singh at No. 8. He will work as Inspector S. W. Ext. Jaipur Vice Shri C. B. L. Mathur.

1	2	3	4
8. Shri Shambhoosingh.	S. W. E. O. Mandal	Sheep & Wool Ext. Officer. Kharchi.	Vice Shri Mohan Singh at No. 18.
9. ,, Raghubir Singh.	S. W. E. O. Osian.	,, Osian.	
10. ,, Laxman Singh	W. G. S. Lathi.	,, Jaisalmer.	
11. ,, Jagan Nath Kalra.	A. H. E. O. Hanumangarh	,, Suratgarh.	Vice Shri K. C. Sharma at No. 16
12. ,, Ram Prakash Sharma.	—do— Bandikui.	,, Udaipurwati.	Vice Shri Pushkar Singh at No. 26.
13. ,, Kishan Singh.	—do— Dhariawad.	,, Shiv	Vice Shri Durga Singh not selected.
14. ,, R. N. Otia.	Inspector, S. W. Jaipur.	,, Nokha.	Vice Shri Narain Singh at No. 3.
15. ,, R. C. Shastri.	S. W. E. O. Tonk	,, Tonk.	
16. ,, K. C. Sharma.	—do— Suratgarh.	,, Chirawa.	Vice Shri G. L. Pancholi not selected.
17. ,, B. K. Purohit.	S. W. E. O. Kishangarh.	S. W. E. O. Kishangarh.	

1	2	3	4
18. ShriMohan Singh	S.W.E.O. Kharchi.	Sheep & Wool Ext. Officer Ladnu.	Vice Shri Brij Mohan at No. 5
19. ,, Satya Narain Rathi.	A. H. E.O. Srinagar.	—do— Shahpura	Vice Shri B. K. Singh at No. 25.
20. ,, Upendra Ballabh Pant.	—do—Hindaun.	—do— Kolayat.	Vice Shri Bishan Singh not selected.
21. ,, A. H. Pinto.	S. W. E. O. Kekri.	—do— Kekri.	
22. ,, B. P. Pareek.	—do—Sardarshahr.	—do— Sardarshahr.	
23. ,, Durga Prasad Pandit	Instructor, S. W. Didwana.	—do— Pokran	Vice Shri Ramchandra at No. 4.
24. ,, Chunni Lal.	Manager, S. B. F. Pokran.	—do— Bilara.	He will continue as in Col. 3 till further orders.
INSTRUCTORS (4)			
25. Shri V. K. Singh	S. W. E. O. Shahpura.	Instructor Sheep & Wool Didwana.	Vice Shri Durga Prasad at No. 23.

परिशिष्ट

1	2	3	4
26. Shri Pushkar Singh.	S.W.E.O. Udaipurwati.	Instructor Sheep & Wool Raisinghnagar.	Vice Shri M. S. K. Tarzen not selected.
27. „ Sureshchandra Jain.	A. H. E. O. Chittor	—do— Sumerpur.	Vice Shri Anand Singh not selected.
28. „ Satya Narain Asopa.	—do—Sirohi.	—do— Hindaun.	Vice Shri J. N. Trivedi not selected.
29. „ Chagan Lal.	New candidate	S. W. E. O. Bilara	Vice Shri Chunni Lal at No. 24.
30. „ Ram Chandra.	U. D. C. Office of the D. A. H. O., Ajmer-	—do— Mandal	Vice Shri Raghunath Singh at No 7.

All the above Officials will draw their existing emoluments in the grade mentioned above with effect from the date they take-over charge of the post, and will hold lien on the post as shown in column No. 3.

The appointment of M/s Chagan Lal and Ramchandra at No. 29 and 30 are purely temporary.

All the above persons to report their places noted under column 3 and 4 after handing over their charge to their next subordinates immediately.

परिशिष्ट

Non selected candidates should report to the District Animal Husbandry Officers concerned who will make their further postings on their original posts in consultation with the Dy. Director, Sheep and Wool, Jaipur and Vikas Adhikaris concerned.

(B. N. HANDA)
Director of Animal Husbandry,
Rajasthan, Jaipur.

No. F. V. 11 (XIV) Estt/3571-69/ Dated 3. 2. 60.

Copy forwarded to the:—

1. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
2. All Regional Dy. Directors, Animal Husbandry, Rajasthan.
3. Dy. Director, Sheep and Wool, Jaipur.
4. All the Distt. Animal Husbandry Officers, Rajasthan.
5. Pramukh Zila Parishad............................
6. Vikas Adhikari, Panchayat Samiti,...
7. Shri..
   Inspector/Ext. Officer/Insructor Sheep and Wool...........................
   for information and necessary compliance.

Director of Animal Husbandry,
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट

OFFICE OF THE DIRECTOR OF ANIMAL HUSBANDRY RAJASTHAN JAIPUR.

No. F. V. 11 (XXV) Estt/6081 Dated 3-3-60.

OFFICE ORDER

In supersession to this office order No. F. V. 11 (XIV) Estt/3571-69 dated 3. 2. 60 anf F. V. 11 (XIV) Estt/4852-64 dated 23. 2. 60 the following postings are hereby ordered with immediate effect:—

Name. 1	Present Post. 2	New Posting & Place of posting. 3	REMARKS. 4
(INSPECTORS 5)			
1. Shri C. B. L. Mathur,	Offg. Supdt., I. C. A. R. Ajmer.	Inspector, S. W. Extn. Jaipur.	He will cotinue on the post at No. 2 till further orders.
2. Shri Shanker Lal Dave.	Offg. Supdt., Sheep & wool Extn. Jaisalmer.	Inspector, S. W. Extn. Jodhpur.	He will continue on the post at No 2 till further orders.
3. „ Narayan Singh.	S.W. E. O. Nokha	„ „ Bikaner.	-do-
4. „ Ram Chandra Tanwar.	„ Pokran	„ „ Jaisalmer.	-do-
5. „ Brij Mohan Sharma.	„ Ladnu.	„ „ Udaipur.	-do-

1	2	3	4
SHEEP & WOOL EXTENSION OFFICERS (19)			
6. Shri Narbada Shanker.	A. H. E. O. Bichhiwara.	S. W. E. O. Udaipur-Wati.	He will continue as A. H. E. O. Bichhiwara till further orders.
7. ,, Raghunath Singh.	R. A. Ind. & Eco.	,, ,, Mandal.	He will contiune on the post at No. 2 till further orders.
8. ,, Shambhoo Singh.	S. W. E. O. Mandal	,, ,, Sheo.	
9. ,, Raghubir Singh.	,, Osian.	,, ,, Osian.	
10. ,, Laxman Singh.	W. G. S. Lathi.	,, ,, Jaisalmer.	
11. ,, Jagannath Kalra.	A. H. E. O. Hanuman-garh.	,, ,, Suratgarh.	He will continue as A. H. E. O. Hanuman Garh till further orders.
12. ,, Ram Prakash Sharma.	,, Bandikui.	,, ,, Sojat.	
13. ,, Kishan Singh.	,, Dharwad.	,, ,, Shiv.	He will continue as A. H. E. O. Dharwad till further orders.

परिशिष्ट

1	2	3	4
14. Shri R. N. Otia.	Inspector S. W. Jaipur	„ „ Nokha.	He will continue as on the post No. 2 till further orders.
15. „ R. C. Shastri.	S. W. E. O. Tonk.	„ „ Tonk.	
16. „ K. C. Sharma.	„ Suratgarh.	„ „ Chirawa.	
17. „ B. K. Purohit.	„ Kishangarh.	„ „ Kishangarh.	
18. „ Mohan Singh.	„ Kharchi.	„ „ Kharchi.	
19. „ Satya Narain Rathi.	A. H. E. O. Srinagar.	„ „ Shahpura.	He will continue as A. H. E. O. Srinagar till further orders.
20. „ Upendra Ballabh Panth.	„ Hindoli.	„ „ Kolayat.	He will continue as A. H. E. O. Hindoli till further orders.
21. „ A. H. Pinto.	S. W. E. O. Kekri.	„ „ Kekri.	
22. „ B. D. Parik.	„ Sardarshar.	„ „ Sardarshar.	
23. „ Durga Prasad Pandit.	Instructor, Didwana.	„ „ Pokrana.	He will continue as Instructor Didwana till further orders.

1	2	3	4
24. „ Chunni Lal.	Manager, S. B. F. Pokran.	„ „ Bilara.	He will continue Manager, S. B. F. Pokran.
(INSTURCTORS 4)			
25. „ V. K. Singh.	S. W. E. O. Shahpura.	Instructor, Didwana.	He will continue on the post at No. 2 till further orders.
26. „ Pushkar Singh.	„ Udaipurwati.	„ Raisingnagar.	—do—
27. „ Suresh Chandra Jain	A. H. E. O. Chittor.	„ Sumerpur.	
28. „ Satyanarain Asopa.	„ Sirohi.	„ Hindaun.	He will continue as A. H. E. O. Sirohi till further orders.
29. „ Chagan Lal	New candidate.	S. W. E. O. Bilara.	Vice Shri Chunni Lal.
30. „ Ramchandra.	U. D. C. in the office of D. A. H. O. Ajmer.	„ Mandal.	Vice Shri Raghu Nath Singh at No. 7

All the above officials will draw their existing emoluments in the grade of 110-5-135-EB-10-225 with effect from the date they take over chrage of the posts and will hold lien on the posts as shown in column No. 3.

परिशिष्ट

The appointment of M/s Chagan Lal & Ramchandra at No. 29 & 30 are purely temporariry.

Against the existing vacancies the following non selected officials are hereby appointed temporarily till they are finally absorbed on their substantive posts:—

1.	Shri Bhaboot Raj.	S. W. E. O. Sojat	S. W. E. O. Kolayat.
2.	„ G. L. Pacholi	„ Chirawa.	„ Suratgarh.
3.	„ B. S. Bhati.	Inspector, Jaisalmer.	Inspector, Jalsamer.
4.	„ M. S. K. Tarzan.	Instructor, Raising-Nagar-	Instructor, Raising Nagar.
5.	„ Bishan Singh.	S. W. E. O. Kolayat.	Inspector, S. W., Bikaner.
6.	„ J. N. Trivedi.	Instructor, Hindaun.	Instructor, Hindaun.
7.	„ Durga Singh.	S. W. E. O. Sheo.	Inspector, S. W. Udaipur.
8.	„ Inder Singh.	Inspector, Jodhpur.	„ „ Jodhpur.

All the above officials will draw their existing emoluments in the grade of 110-225.

The Dy. Director, Sheep and Wool, Jaipur should arrange to absorb the above officials in consultation with the Vikas Adhikaris immediately and report to this office. He sohuld also arrange to absorve M/s Govind Singh, Anand Singh and Bhagwan Singh Inspector Bikaner, Instructor Sumerpur and Inspector Udaipur respectively (Non selected).

(B. N. HANDA)
Director of Animal Husbandry,
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट

No. F. V. 11 (XIV) Estt/6081-222 Dated 3-3-60.

Copy forwarded to the:—

1. All Regional Dy. Director, Animal Husbandry, Rajasthan.
2. Dy. Director, Sheep & Wool, Jaipur.
3. All the Distt. Animal Husbandry Officers.
4. Pramukh, Zila Perishad.................................
5. Vikas Adhikari, Panchayat Samiti,....................................
6. Shri...

Inspector/Ext. Officer/Instructor Sheep and Wool..
for information and necessary compliance.

Director of Animal Husbandry,
Rajasthan, Jaipur.

अप्रेल सन् १६५८ से निम्न लिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण एक बार से अधिक हुए, वह इस प्रकार है :-

क्र० सं०	नाम	स्थान से स्थान को	कारण
(१)	श्री के० सी० शर्मा	सुमेरपुर से शाहपुरा को सितम्बर १६५८	इन्सपेक्टर भेड़ व ऊन से भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी बना दिये गये अतएव यह परिवर्तन; उनकी तरक्की के हेतु था।
(२)	,, ,,	शाहपुरा से सुरतगढ़ा को अक्टूबर ५६ में	इस अधिकारी के विरुद्ध कुछ शिकायत प्राप्त होने पर ज्वाइन्ट डवेलपमेन्ट कमिश्नर की सिफारिश पर यह स्थानान्तरण किया गया।
(३)	बी० के० सिंह	सूरतगढ़ से शाहपुरा को अक्टूबर १६५६ में	क्रमांक १ के स्थान की पूर्ति हेतु।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८५४ का उत्तर देखिए)

जोधपुर : चार चक्कों के ठेले वालों से ६ रु० वार्षिक लाईसेन्स फीस ली जाती है। यह फीस ३–३ रुपये की किश्त में ली जाती है व छमाही लाईसेन्स के लिये होती है।

बीकानेर : हाथ ठेलों पर वार्षिक १२ रु० तथा १ रुपया दो आना एक मास के लिये बतौर लाईसेन्स फीस लिया जाता है।

कोटा : ठेलों पर १ रु० फीस रजिस्ट्रेशन व १२ रु० सालाना किराया कुल १३ रु० सालाना फी ठेला वसूल किया जाता है।

अलवर : खोमचे ठेलों पर ५ रु० वार्षिक, हाथ ठेलों पर ३ रु० वार्षिक व चौपाये ठेलों पर १० वार्षिक लाईसेन्स फीस वसूल की जाती है।

भरतपुर : प्रति ठेला (ढकेल) १ रु० ८ आ० प्रति वर्ष लाईसेन्स फी वसूल की जाती है।

उदयपुर : वे ठेले जो मजदूरी पर चलते हैं उनसे ३ रु० प्रति वर्ष व उन ठेलों पर जिनमें फ्रूट्स व मनीहारी का सामान बेचा जाता है उनसे ६ रु० प्रतिवर्ष लाईसेन्स फीस वसूल की जाती है।

अजमेर : घूमते हुए ठेलों पर २ रु० व एक ही स्थान पर खड़े रहने वाले ठेलों पर २॥ रु० माहवार लाईसेन्स फीस वसूल की जाती है।

———

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६७ ए. टी. एम. का उत्तर देखिये)

यात्री कर के बाकीदारों की सूची

क्रम संख्या	जिला	मोटर स्वामियों की संख्या जिन्होंने कर जमा नहीं कराया।
१.	२.	३.
१.	अलवर	३८०
२.	भरतपुर	४३६
३.	झुंझनू	२७८
४.	सीकर	४८०
५.	बाड़मेर	१५१
६.	जैसलमेर	१०
७.	जोधपुर	४६०
८.	नागोर	७६
९.	पाली	३६१
१०.	सिरोही	१६५
११.	बांसवाड़ा	२२
१२.	भीलवाड़ा	२२४
१३.	डूंगरपुर	१२५
१४.	चित्तौड़गढ़	२१७
१५.	झालावाड़	४
१६.	कोटा	२६३
१७.	सवाई माधोपुर	३२५

१	२	३
१८.	टोंक	५२६
१६.	बीकानेर	६
२०.	चूरू	२०७
२१.	गंगानगर	२०३

———

शुद्धि-पत्र

(बुद्धवार, दिनांक ६ अप्रेल, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६४१९	शीर्षक	अप्रल	अप्रेल
६४२३	२	व्यस्था	व्यवस्था
६४४०	प्रथम पंक्ति	श्री नाथूराम मिर्धा (आसीन)	श्री नाथूराम मिर्धा
,,	३	श्री परसराम मदेरना	श्री परसराम मैदरीना (आसीन)
६४४६	२१	(सम्पतराम)	(श्री सम्पतराम)
६४४९	अन्तिम	क्योंकि को	क्योंकि यह
६४५९	५	(कुशलगढ़ डा: चन्द्रकला	(कुशलगढ़–डा० चन्द्रकला
६४६१	१३	उल्लघंन	उल्लंघन
६४६५	शीर्षक	अप्रल	अप्रेल
६४६६	अन्तिम से ७	यातायत	यातायात
६४६६	६	(६७, ए. टी. एम)	१०(६७ ए. टी. एम)
६४६९	१२	evena	even
,,	२२	bave been	have been
६४७१	२२	of is	It is
६४७२	२०	Cosf	Cost
६४७३	२	24 %14 /high	24. 14% high
,,	१६	itemsete	items etc
६४७६	अन्तिम से ७	इन फोर्म्स	इन दोनों फोर्म्स
६४७८	२१	अ चीवमेंट्स	अचीवमेंट्स
६४७८	७	टार्गेट्सजानकारी	टार्गेट्स की जानकारी
६४८४	७	ाबुद्ध	बुद्धि
६४९७	शीर्ष	(श्री सतीशचद्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
६५००	१४	न यह	न वे यह
६५०४	२१	करने पडें,	करने पड़े
६५०५	११	सूचना बोर्ड	सूचना है बोर्ड
६५०६	२६	हाप–फुल	होप–फुल
६५१३–१८	शीर्षक	वार्षिक	वित्तीय
६५१८	२४	वह क्यो हुई	वह क्यों हुई ?
६५१९	१८	देनीं । चाहिये	देनी चाहिये
,,	अन्तिमसे ३	हनने	हमारे
६५२०	,, ,, ८	आययव्यय	आय–व्ययक

(२)

१.	२	३	४
६५२०	१७	दिलाएगे	दिलाएंगे
६५२३	अन्तिम	ग्ांतिं	भांति
६५२७	१८	दिय गया	दिया गया
६५२७	अन्तिम से२	रेटस	रेट्स
६५२८	१६	ढ ड़े	ढ ढ़ें
६५३७	१५	finaneial	financial
६५४०	११	फुड	फ़ूड
"	अन्तिम से २	कॉमर्शियलहा उसेज	कॉमर्शियल हाउसेज़
६५४१	प्रथम पंवित	ट्रिवन्कलिंग	ट्विन्कलिंग
६५४४	६	av ailable	available
६५४५	१२	glut ो। रहा है	glut हो रहा है
		सकिन्ड	सैकिन्ड
"	२४	कॉन्टिट्युन्सी	कॉन्स्टिटयुएन्सी
६५४७	अन्तिम से२	की हिस्ट्री है	की जो हिस्ट्री है
६५४६	६	Transmitire	Transmitters
"	१०	hone	how
"	अन्तिम से७	36 percent	3.6percent
६५५३	२०	epuitable	equitable
६५५५	प्रथम पंक्ति	डिक्ले	डिक्लेयर
"	२	एग्रीकल्चरिटस	एग्रीकल्चरिट्स
"	११	eutire econmy	entire economy
६५५६	११	वेगिग	वेगिंग
"	२२	पाई–पई	पाई–पाई
६५५७	अन्तिम से३	एडीक्ट	एडीक्ट
६५६२	२	afraid it	afraid of it
६५६३	शीर्षक	वित्तीव	वित्तीय
६५६७	"	५७३९	६५६७
"	अन्तिम से७	श्री जयसिंह: राणावत	श्री जयसिंह राणावत:
६५७३	४	लाख ब्याज	ब्याज
६५७६	अन्तिमसे११	लग्ज़ारी	लग्ज़री
६५८४	" ४	पानी नहीं,	पानी कहीं
६५६५	६	विषय में	विषय में
६६००	अन्तिम से२	जयपुर	जयपुर में लाइट दी जाती है और पंखे
६६०२	५	धनाद्य बन	धनाढ्य बन
६६०५	३	आप प्रोक्शन	आप प्रोडक्शन

(२)

१	२	३	४
६६११	शीर्ष	(श्री भीनसेन)	श्री भीमसेन
६६१५	,,	श्री सम्पतराज जैन)	(श्री सम्पतराज जैन)
६६२०	अन्तिम सेर	कि कोशिश करूंगा	की कोशिश करूंगा
६६२३	शीर्ष	(श्री बरतकुल्लखां)	(श्री बरकतुल्ला खां)
६६२७	प्रथम पंक्ति	अल	ऑल
६६२९	२५	बिनिंग	बिगिनिंग
६६३०	३	माननी होगा	माननीय होगी
६६३३	४	फिगर्स	—
६६३७	३	थ	थ्
६६३९	२०	Rasjasthan	Rajasthan
६६४५	६	पढ़ाजाऊ ...	पढ़ जाऊं ...
६६४७	११	ऑथेरिटी	ऑथोरिटी
६६५३-५४	शीर्षक	वार्षिक	वित्तीय
,,	४	पाटींज	पार्टीज़
६६५७	५	क्रिपे गये	किये गये